राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक: 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या: 8

गुरुवार,

10 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार।

प्रश्नकाल। श्री हीरालाल।

निवाई के रोडवेज बस सेवा से वंचित गांव

131. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के कितने गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सुविधा से जुड़े हुए हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के निगम बस सुविधा से वंचित गांवों को निगम बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के 64 गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़े हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र निवाई के बस सेवा से वंचित गांवों को जोड़े जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे यहां 322 गांव हैं उनमें से केवल 64 गांव जुड़े हुए हैं, तो

(श्री हीरालाल)

आप बाकी के गांवों को कब तक जोड़ने का इरादा रखते हैं? मेरे यहां कुछ बसें बंद की गयीं हैं वर्तमान में। पिछली सरकार से तो पीपलू, निवाई प्रताड़ित रहा ही है। माननीय मंत्री बाबूलालजी, आप निवाई क्षेत्र से परिचित हो, निवाई में बसें बंद कर दी हैं, आप यह बताएं कि इनको कब चालू करने का इरादा रखते हैं?

मैं आपको पहले ही बता दूं कि गौरव पथ के नाम से बंद कर दीं। गौरव पथ बन चुके हैं, एक महीना हो गया है, जो बसें बंद की हैं, वे कब तक चालू करने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): 64 गांव बताये हैं, बाकी 268 गांव बचे हैं। पीपलू उपखंड में सबसे ज्यादा परेशानी है। जीपों से यात्रा करते हैं, उनसे यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं। ग्रामीण परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दूसरा सवाल और कर लेना। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पूर्व में कितनी बसें बंद की गयीं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पिछले 2 साल में निवाई विधान सभा क्षेत्र में 2 बसें बंद की गयीं। एक तो थी टोंक-टोडा वाया बावड़ी और एक टोडा-जयपुर वाया बगड़ी। एक बस में तो रेवेन्यू 15 रुपये से कम आ रहा था, लेकिन जो दूसरी बस है टोंक-टोडा-जयपुर वाया बगड़ी, इसके बदले वहां की आवश्यकता के अनुसार दूसरे रूट से जो कि जन प्रतिनिधियों की मांग थी, वह बस चालू कर दी गयी है। इसमें तो सिर्फ एक ही बस बंद की है।

लेकिन पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में 5 बसें शुरू की गयी हैं। 5 बसों की जो सेवाएं शुरू की गयी हैं, वे माननीय विधायक महोदय के विधान सभा क्षेत्र में ही हमने की हैं। बसें मैं आपको निवेदन कर दूं जो पिछले 2 वर्ष में जोड़ी गयी हैं- टोंक-टोडा वाया डोडाबड़ी माननीय विधायक महोदय की ही अनुशंसा पर हमने चालू की थी। टोंक निवाई-सिरस-जयपुर, टोंक-निवाई-पीपलू-जयपुर, टोंक-जयपुर वाया फागी, टोंक-निवाई-दत्तवास। ये 5 बसें तो चालू की गयीं और मात्र एक ही बस ऐसी है जो कि बंद की गयी है। वह भी गौरव पथ की वजह से।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस बस के बारे में भी हम लोग सर्वे कराकर जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन गौरव पथ को तो बने हुए एक महीना हो गया। अब तो जो-जो बंद की हैं, उनको चालू कर दें। मंत्रीजी, मेरे यहां निवाई से डिग्गी कल्याणजी को बसें जाती थीं, वे बंद कर दी गयी हैं। श्रद्धालु माधोपुर से, गंगापुर से निवाई आते हैं, वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं है। डिग्गी कल्याणजी तक बस तुरन्त चालू की जाए।

दूसरी पीपलू-रानौली-फागी होकर संचालित थी, उसे भी बंद कर दिया गया है। वर्तमान में पीपलू उपखंड पर कोई बस नहीं आती है। ये बसें जो बंद की हैं, चालू की जाएं। पीपलू उपखंड पर भी जो बस बंद की है, वह 3 किलोमीटर दूर से जाती है। पीपलू उपखंड पर कोई बस नहीं आती है। साथ ही मेरा निवेदन है कि सोहिला जो कि पंचायत हैडक्वार्टर है, सोहिला में एक्सप्रेस बसें नहीं तो कम से कम लोकल बसें तो आएं। वह पुराना एन.एच. है। लेकिन वहां से निकल जाती हैं।

इसी प्रकार निवाई में कई नान स्टाप बसें बाइपास से ही निकल जाती हैं जबकि निवाई बस स्टाप है। मेरा अनुरोध है कि बसें वापस इधर से ही चालू की जाएं। जयपुर-सोहिला-नाथड़ी-पीपलू-कठमाड़ा-समेलिया और फागी तक बसें चलायी जाएं ताकि जयपुर तक जाने में सुविधा हो।

श्री अध्यक्षः कर चुके आप।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि एक बस कौथून-खरेड़ा-दत्तवास-लालसोट-गंगापुर-करौली तक चलायी जाए। दूसरी गंगापुर से करौली, डिग्गी वाया निवाई-झिराणा-बगड़ी बस चलायी जाए।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल (निवाई): साथ ही मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्षः आ गया।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड बोलूंगा।

श्री अध्यक्षः एक मिनट।

श्री हीरालाल (निवाई): हां। लो फ्लोर बसें चाकसू में 3 घंटे पड़ी रहती हैं। अगर आप लो फ्लोर बसों को, आधा घंटे का रूट है, निवाई तक कर दें तो कई एक्सप्रेस बसें जो उधर निकलती हैं, उनकी सवारियां उसमें बैठकर चली जाएं। इससे लोड भी नहीं रहेगा एक्सप्रेस बसों में। मेरा अनुरोध है कि लो फ्लोर बसों को निवाई तक किया जाए, जो कि अभी 3 घंटों तक चाकसू में पड़ी रहती हैं। इन बसों से यात्रियों को तथा ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है टोंक-निवाई-पीपलू वाली बस के लिए, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि टोंक से निवाई, पीपलू एक तो शाम को 5 बजे है और निवाई से पीपलू अलग बस है। टोटल 4 बसें पीपलू से जयपुर और जयपुर से टोंक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फागी वाले रूट के लिए भी कहा है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूट पर भी जयपुर होकर बसें चल रही हैं। फिर भी जो बसें माननीय सदस्य मुझे बता रहे हैं, पिछले 2 साल में बंद तो एक ही बस की है, गौरव पथ की वजह से वह बंद हुई है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय मंत्री महोदय बताएं कि यह कब तक चालू कर देंगे? बंद बसें कब तक चालू कर देंगे?

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): जो रुकावट आ रही थी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके बारे में पता करके मैं उसको भी चालू करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। शुद्ध रूप से निवाई से सम्बन्धित ही है यह प्रश्न। पूरक प्रश्न, प्रहलादजी, करेंगे क्या? यह निवाई से सम्बन्धित है। नाम सबके आ गये, संकेत आ गया। निवाई से सम्बन्धित है, इधर-उधर नहीं। हां, बोलिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे निवाई में बसें बंद की हैं, ऐसी आल ओवर राजस्थान में दूसरी जगह की भी कर दी हैं।

श्री अध्यक्ष: रेलेवेंट नहीं है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): निवाई में बसें बंद की हैं। जो बसें बंद हुई हैं उनको कब तक चालू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: रेलेवेंट नहीं हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): निवाई में और निवाई के आसपास में जो बसें बंद की हैं, उनको कब तक चालू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: निवाई का नाम लेकर आप इस तरह नहीं कर सकते। बैठिये, बैठिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): इस तरह का पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं, निवाई का नाम लेकर। पूरा शुद्ध निवाई का है, वह हो गया। आप निवाई का नाम लेकर सारे राजस्थान का पूछने लगे। दूसरा प्रश्न, श्री फूलसिंह मीणा।

प्रदेश में संचालित टाडा-माडा योजना में क्षेत्रीय विधायकों का मनोनयन

132. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये संचालित योजना टाडा माडा (टीएडीए) के लिए बनायी गयी समिति में कौन-कौन सदस्य होते हैं एवं उनका स्तर क्या होता है?

(2) क्या उक्त संचालित योजना में क्षेत्रीय विधायकों को भी सम्मिलित किया जाता है? यदि हां, तो अब तक किन-किन क्षेत्रीय विधायकों को सम्मिलित किया गया एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना कब से संचालित है एवं वर्षवार इस योजना में कितना-कितना व्यय किया गया? वर्ष 2000 से 2015 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा): (1) केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए संचालित योजना टाडा माडा (टीएडीए) के लिए कोई समिति नहीं बनायी गयी है।

भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्बन्धित राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देने हेतु जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 1980 बने हुए हैं। इस परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं जिनका स्तर निम्नानुसार है:-

1. मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग-अध्यक्ष
2. राज्य मंत्री/उप मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग- उपाध्यक्ष
3. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधान सभा में निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से 14 सदस्यों का इस समिति में सदस्य के तौर पर मनोनयन किया जाता है।
4. गैर सरकारी एवं गैर अनुसूचित जनजाति का 01 सदस्य।

(श्री नन्दलाल मीणा)

5. 03 राज्य सरकार के अधिकारी।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधान सभा के विधायकों में से 14 सदस्यों का इस परिषद में सदस्य के तौर पर मनोनयन किया गया। परिषद के सदस्यगण की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। वर्ष 1978-79 में विभाग के कार्य क्षेत्र का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से माडा क्षेत्र के जनजाति को भी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 2000 से 2015 तक वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, एक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वर्ष 2001 से वर्ष 2015-16 तक की राशि व्यय की वह तो बता दी परन्तु यह नहीं बताया कि किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, जिसके बदले कितनी व्यय की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 में कितनी राशि कुल प्राप्त हुई और जो व्यय की गयी वह कहां-कहां व्यय की गयी? टीएसपी क्षेत्र के जिलेवार किस-किस कार्य पर किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी, कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग का विस्तार 1975 में जनजातियों की आबादी के आधार पर किया गया जिसमें माडा क्षेत्र भी शामिल है। जहां तक माननीय सदस्य ने आबंटित राशि और व्यय के बारे में पूछा है, इसके उत्तर के संलग्न पेज नम्बर 30 पर विस्तृत रूप से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की और व्यय कितना हुआ यह सारा ब्यौरा दिया हुआ है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 से जनवरी, 2016 तक आबंटन हर वर्ष में किया गया, उसका व्यय भी अलग है। आप चाहें तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2000-01 में 4859.52 लाख रुपए आबंटित किये गये थे, 3428.14 लाख व्यय हुआ।

श्री अध्यक्ष: यह आप इनको सूचना दे देना। दूसरा पूरक प्रश्न। आपके पास सूचना आ जाएगी विस्तार से सारी।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति एरिया में बजट का व्यय हो रहा है, हमारे बालिका छात्रावासों में जो बालिकाएं रहती हैं उनकी खुराक में जरा सुपरविजन रहे तो जनजाति की बालिकाएं भोजन पर्याप्त और अच्छा कर सकेंगी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय। वैसे यह आ चुका है परसों बजट में, फिर भी आप जवाब दे दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो उदयपुर ग्रामीण से आते हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि भोजन के बारे में क्या व्यवस्था है। अभी उदयपुर में उदयपुर सम्भाग के जनजाति के बालक और बालिकाओं के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। आप भी सम्माननीय सदस्य थे और प्रति दिन वहां पर उसका अवलोकन करते थे। यहां तक कि जनजाति विकास विभाग के सभी माननीय सदस्य, सभी अधिकारी, मेरे सहित सभी उन बालक-बालिकाओं के साथ भोजन करते थे। उसके बाद मैंने इन सबसे पूछा है कि इसमें कोई कमी खामी हो तो बताएं, परन्तु किसी ने अब तक तो मुझे बताया नहीं है। मैं माननीय सदस्य से पूछ लूंगा, इनकी जानकारी में अगर कोई कमी खामी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। परन्तु एक बात जरूर है कि खेल छात्रावासों में हमने अंडों का प्रावधान अलग से कर रखा है। अंडे मुर्गी के, शाकाहारी अंडे, उसका प्रावधान खेल छात्रावासों के अलावा दूसरी जगह नहीं है, यह जरूर कमी है। और बाकी सब व्यवस्थाएं करा दी गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि टाडा, माडा बजट का वितरण असमानता से होता है, एसटी की जनसंख्या के अनुपात में वितरण का ध्यान नहीं दिया जाता, इसे एसटी की जनसंख्या के अनुपात में बांटने का विचार रखते हैं? करौली जिले में कितना फंड देना चाहते हैं? क्या सरकार द्वारा वित्तीय वितरण हेतु विधायकों की सिफारिश लागू करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य का यह आरोप कि असमान

(श्री नन्दलाल मीणा)
वितरण होता है अर्थ का, ऐसी कोई शिकायत न तो आपके द्वारा आयी है न आपके जिले से आयी और न माडा क्षेत्र के किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार की कोई शिकायत की है। परन्तु यह जरूर है कि विकास माडा क्षेत्र का, टीएसपी एरिया का, माडा क्लस्टर का, माडा बिखरी आबादी का अलग-अलग मापदंड के आधार पर देखा जाता है, क्योंकि माडा कलस्टर के अधिकांश लोग, टीएसपी के लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं बनिस्पत माडा क्षेत्र के।

श्री अध्यक्षः सुशील कटारा। पूरक प्रश्न दो। (व्यवधान) यह नहीं, सुशील कटारा को पूरक प्रश्न के लिए पुकारा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एसटी की जनसंख्या के अनुपात में वितरण होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः नहीं, यह नहीं। एक पूछ चुके।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार संवेदनशील है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, मुख्य मंत्री बेटी योजना भी चला रखी है। माननीय मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूं, टीएसपी क्षेत्र उदयपुर डिवीजन जनजाति बहुल क्षेत्र है और बिखरी हुई आबादी है बच्चियों को दूर-दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, मकान एक-एक पहाड़ी पर दूर-दूर हैं, क्या माननीय मंत्रीजी आगामी बजट में हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बालिका छात्रावास, बच्चों के पास तो बहुत हैं ही सही, पर ग्राम पंचायत स्तर पर या दो-दो ग्राम पंचायतों के बीच में एक बालिका छात्रावास बनाने की कोई योजना रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में एक हाई पावर कमेटी का गठन करके माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया में गये। वहां की गतिविधियों की जानकारी के लिए हम लोग वहां गये थे, उसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत कर दी गयी है। महाराष्ट्र में जो शिक्षा की व्यवस्था लड़कियों के लिए है वैसी अपने राजस्थान में नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह ही राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए, उसके आधार पर छात्रावास खोला जाए। पिछले वर्ष 2015-16 में ट्राइबल सब प्लान एरिया में लगभग 20 कन्या छात्रावास पहली बार राजस्थान में खोले गये हैं। मैं समझता

(श्री नन्दलाल मीणा)

हूं कि यह एक उदाहरण है बालिका शिक्षा के बारे में। परन्तु करौली वाले सदस्य अभी बोल रहे थे, मुझे इनसे शिकायत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माडा क्षेत्र में बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है। जिस पर जोर देना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और इसी वजह से पुरुषों में द्विविवाह की प्रथा प्रारम्भ हो गयी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पैसा ही नहीं दे रहे हैं वहां, पूरा बजट प्रतापगढ़ ले गये। (व्यवधान) गांवों में लोग भीख मांग-मांग पर पेट भर रहे हैं, छात्रावासों की हालत तो यह हो रही है और आप यह कह रहे हैं, आप उनको पैसा ही नहीं दे रहे हैं। आप पूरा बजट आपके क्षेत्र प्रतापगढ़ में ले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो। माननीय विधायक।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): करौली के छात्रावास, नांगल छात्रावास, नांगल पहाड़ी, टोडाभीम छात्रावास में मैंने खुद देखा है, बच्चे गांवों में भीख मांग कर खा रहे हैं। छात्रावासों की जांच करो, एक बार दौरा करके तो देखो, माननीय मंत्रीजी। बच्चों की हालत यह है, मैंने खुद देखा है, मांग-मांग कर खा रहे है बच्चे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको कभी पूरक प्रश्न का अवसर नहीं दूंगा। आपका यह अधिकार हो गया, फिर आप लगातार बोलते रहते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक स्वस्थ परम्परा जनजाति समाज में है कि कोई भिक्षा नहीं मांगता, परन्तु मुझे अफसोस है कि ऐसे जनजाति के लोग करौली जिले में हैं, तो उनका सर्वेक्षण करवा कर कोई भिक्षावृत्ति नहीं हो, उसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस टाडा- माडा में योजना में 2015-16 में केन्द्र सरकार का कितना अंश है और राज्य सरकार का कितना है? और उसमें दिसम्बर, 2015 तक कितना खर्चा हुआ? पूरा खर्चा बहुत कम हुआ है तो पूरा खर्च करने के लिए सरकार क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः विराजिये। लम्बा कर दिया इन्होंने। माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डोटासरा साहब पहली बार चुनाव जीत कर आये हैं, इनकी जानकारी में नहीं है। (व्यवधान) अच्छा, दूसरी बार जीते हैं। भगवान करे आप जीतते रहो, पर ज्ञानवर्द्धन की आवश्यकता है आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसीलिए तो पूछा है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो राशि हमको प्राप्त होती है, वह दिसम्बर, जनवरी तक होती है। उसके कारण 31 मार्च तक पैसा खर्च नहीं हो सकता, कोई भी संस्था अब तक नहीं कर सकी। मैं चार बार इस विभाग का मंत्री रहा हूं 1977 से, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कितनी भी द्रुत गति से इसकी व्यवस्था की जाए, उसके बावजूद भी व्यय नहीं हो सकता है। जो आंकड़े आपने देखे हैं, कृपया उस पर पुनः अवलोकन करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई कार्य योजना बना रहे हो क्या, यही तो पूछा है। पैसा खर्च नहीं होता है तो इसके लिए कोई कार्य योजना है क्या आपके पास, यही तो पूछा है मैंने।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर राजस्थान में आदिवासियों के कल्याण के लिए किस प्रकार पैसा खर्च किया जाए, किस-किस मद में किया जाए, इसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल बनी हुई है। इस कौंसिल की हर तीसरे महीने बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि किस प्रायोरटी के आधार पर किस पर कितनी राशि व्यय की जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। इसके लिए छात्रावास द्रुत गति से हर जगह खोले जा रहे हैं। कोशिश यह की जा रही है कि महाराष्ट्र...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तक कितना हुआ? दिसम्बर तक कितना हुआ?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह सवाल इस प्रश्न से रेलेवेंट नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष: बस, बस, हो गया। आपका जवाब आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यय दिया है न आपने। आपने व्यय दिया है तभी पूछा है मैंने कि 2015-16 में आया है, उसका कितना प्रतिशत खर्च हुआ है?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्रीमती अमृता मेघवाल। (व्यवधान) वह आप उनसे मिल लेना, रिपोर्ट देख लेना।

प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को देय अनुदान

133. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसानों को फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिए सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक कितना-कितना ऋण एवं अनुदान किन-किन किसानों को दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है। विभाग द्वारा कृषकों को ऋण नहीं दिया जाता है।

राज्य में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु किसानों को फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिये मिशन फार इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हार्टिकल्चर उप योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्य योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों पर देय अनुदान के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषकों को फलदार बगीचों की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये अनुदान का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। कृषकों द्वारा फूलदार व औषधीय पौधों की किसी भी योजना में आवेदन नहीं किया गया। अत: इनमें अनुदान नहीं दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री साहब से पूछना चाहूंगी कि लघु कृषक व सीमान्त कृषक को कितना-कितना अनुदान देते हैं? हमारा क्षेत्र जालौर डार्क जोन में आता है, उसके अनुदान की राशि कितनी देते हैं? फलदार पौधों के लिए दवाई छिड़काव के लिए या किसी भी प्रकार की दवाई होती है उसकी कोई अनुदान की योजना है या नहीं है? सैकण्ड क्वेश्चन में इन्होंने मुझे कहा है कि कृषकों द्वारा फूलदार और औषधीय पौधों की किसी भी योजना में आवेदन नहीं किया जाता। आवेदन तभी होगा जब किसानों के बीच में जितनी भी योजनाएं हैं, सही प्रकार से डिसप्ले होगी। जब डिसप्ले ही अच्छी तरह नहीं होगा तो किसानों को किस तरह से पता लगेगा कि कौनसी योजना सरकार की है, कौनसे फूलदार, फलदार हमें बगीचे लगाने चाहिए? मैं मंत्री साहब से पूछना चाहूंगी, इसके लिए आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जालौर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा कि लघु और सीमान्त कृषकों को अनुदान में क्या प्रावधान है। इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उद्यानिकी विभाग में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के माध्यम से तीन प्रकार की फसलों के अनुदान देने के प्रावधान किये हुए हैं। सबसे पहले अधिक मूल्य वाली फसलें, यथा- पपीता आदि। इनके बारे में एक गाइडलाइन के अनुसार 4 हैक्टेयर तक किसी भी वर्ग का कोई भी किसान हो, उसको अनुदान दिये जाने के प्रावधान किये हुए हैं। इसी प्रकार सघन बागवानी फलोद्यान की स्थापना के लिए आम, अनार और अमरूद के पौधों पर भी सेम पैटर्न पर ड्रिप सहित जितने भी, जिनके बारे में खाद और इनपुट की बात कही गयी है, उसमें भी अनुदान देने के प्रावधान हैं। इसी प्रकार सामान्य अन्तराल वाली फसलें-आंवला, बेर, सन्तरा, मौसमी, अमरूद, आम, अनार में भी प्रावधान दिये हुए हैं।

जहां तक आपका प्रश्न है कि अनुदान किस प्रकार दिया जाएगा, तो इकाई लागत का 40 प्रतिशत, कुल 80 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तक अनुदान देने के प्रावधान हैं। इसमें चाहे लघु, सीमान्त, एससी, एसटी या वृहत् किसान हो, सभी को 4 हैक्टेयर तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दूसरा प्रश्न था कि औषधीय क्षेत्र में भी किसानों को जानकारी नहीं है। इसके बारे में एक राष्ट्रीय पादप मिशन बना हुआ है, इसके माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं जिसमें खास तौर से

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मेडिसिनल क्राप्स का उत्पादन है, कृषि का काम है, उसके बारे में भी अनुदान देने का प्रावधान किया हुआ है। इसके बारे में जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर कई प्रकार के ब्रोशर, कई प्रकार की जानकारी दी गयी है। मैं आज आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस योजना को और अधिक आम जनता तक पहुंचाने के लिए किसान के खेत पर स्कूल चलाकर, यानी किसान फील्ड योजना, अभी नई मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसके माध्यम से किसानों के द्वार पर जाकर हम लोग उनको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि इस योजना को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोला, हम अच्छे तरीके से जनता के सामने, किसानों के सामने जो भी योजनाएं हैं, डिसप्ले करेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जालौर क्षेत्र में एक कृषि उद्यानिकी केन्द्र है, वहां पर जब अधिकारी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है तो ये योजनाओं का किस प्रकार से डिसपले करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी नहीं होना एक अलग विषय है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद सृजित करके वहां लगाये हुए हैं। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, सहायक निदेशक हैं, डिप्टी डाइरेक्टर है, सभी पद वहां सृजित किये हुये हैं। जहां तक रिसर्च का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: भरे हुए हैं या नहीं, वे यह पूछ रही हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उस विषय के पदों की ज्यों ही भर्ती करेंगे, उसको भरने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या वर्तमान सरकार ने ग्रीन शेड स्प्रिंकलर, बूंद-बूंद सिंचाई व सोलर पम्प का जो अनुदान प्रतिशत पहले दिया जाता था, उसके अन्दर सामान्य वर्ग व अन्य वर्गों के अनुदान में कमी की है? यदि कमी की है तो कितनी कमी की है और इसको कब तक वापस बढ़ा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में घोषणा की है, ड्रिप इर्रिगेशन पर मिलने वाला अनुदान जो पहले 35 प्रतिशत और 45 प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर अब 70 प्रतिशत लघु, सीमान्त, एससी, एसटी के सभी काश्तकारों को दिये जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसी प्रकार सोलर...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कितनी कमी की है? पहले जो 2013 में था उसमें कितनी कमी की और अभी उसको कितना बढ़ा रहे हैं? सामान्य वर्ग का भी इसमें साथ में दें चारों योजनाओं में।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न का विस्तार कर दिया।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते होंगे, पिछले वर्ष निश्चित रूप से एक फण्डिंग पैटर्न पूरे देश में बदला। बदलाव के चलते भारत सरकार के डाइरेक्शन के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जिन योजनाओं में पैसा अनुदान के रूप में अतिरिक्त दिया जाता था, उसके स्थान पर वहां से दिशानिर्देश ये हुए कि कोई भी नयी योजना, प्रत्येक खेत को पानी मिले, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत राशि का डाइवर्जन हुआ और इसी प्रकार परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि योजना में उसको टेक-अप किया। इस वजह से अनुदान जहां पहले 75 परसेंट मिलता था, वह घटकर 35 और 45 प्रतिशत हुआ था।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 86 परसेंट।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): यह सोलर में था। मैं तो ड्रिप की बात कर रहा हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): चारों बोले हैं मैंने। ग्रीनशेड, स्प्रिंकलर, बूंद-बूंद और सोलर पम्प, चारों।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सोलर में 86 परसेंट अनुदान था।

श्री अध्यक्ष: अब कम हुआ है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उसके स्थान पर तीन स्लैब बना दी गयी हैं। जिन किसानों के पास बिजली है और यदि वे सोलर में लगाना चाहते हैं तो ऐसे किसानों को 30 परसेंट सब्सिडी एमएनआरई के माध्यम से दी जा रही है। इसके अलावा जिन किसानों के पास बिजली नहीं है और वे लगाना चाहते हैं तो उनको 60 परसेंट अनुदान देने के प्रावधान किये हुए हैं। जिन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

किसानों ने बिजली के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन उनका अभी नम्बर नहीं आया है, यदि उसको वे विड्रा करते हैं तो ऐसे किसानों को 75 परसेंट सब्सिडी देने के प्रावधान हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। नहीं, हो गया। आप पूछ लेना। शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि अनुदान कितना कम किया है और उस अनुदान को कब तक बढ़ाएंगे, साहब?

श्री अध्यक्ष: बहुत विस्तार कर लिया आपने। शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बहुत नुकसान हो गया, साहब। किसान रो रहा है राजस्थान का, आपकी कसम, साहब।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, आप रोते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे। आप तो बिल्कुल...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहूंगा कि आपका अनुदान देने का या बागवानी का लक्ष्य कितना था? जालौर जिले का लक्ष्य कितना था और आपके अधिकारियों ने कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? अगर कम किया है तो क्यों किया है? अधिकारी आपको यह जवाब देंगे कि आवेदन नहीं आये, तो आवेदन नहीं आने के पीछे भी क्या कारण थे? आपके कृषि पर्यवेक्षक जो हैं उन्होंने कितने फार्मर्स को बुलाकर मीटिंग की है, कितने में डिसप्ले किया है? यह सारा आनलाइन है क्या या आप करने जाएंगे? इन बातों का आप जवाब दें। नहीं तो क्या होता है कि आज दूसरी खेती से बागवानी में एक किसान चार गुना कमाई कर सकता है। जालौर जिला डार्क जोन होने के कारण से, पानी की कमी होने के कारण से यहां बागवानी की खेती अच्छे तरीके से हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय। बैठो-बैठो। देखो, बीच में नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इन चारों योजनाओं में कितना अनुदान कम किया है, इतना ही बता दो।

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब आ रहा है। जवाब दीजिये, मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जालौर जिले में कुल

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कितने किसानों को लाभान्वित किया गया और कितने लक्ष्य थे। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आओ पहले पाओ, यह प्रिंसिपल एग्रीकल्चर विभाग ने तय किया हुआ है। जो भी किसान आनलाइन आवेदन करेगा, आवेदन करने के पश्चात् प्रायोरिटी के आधार पर ही अनुदान देने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। यदि हम 2013 से 2015 तक का देखें तो लगभग 78 किसानों ने जालौर जिले में फलोद्यान के लिए आवेदन किया था। इनमें से 118.4 हैक्टेयर में वहां पर अब तक दो साल के अन्दर हम लोगों ने प्लांटिंग मैटीरियल सहित, इनपुट सब्सिडी सहित सारे देकर किसानों को लाभान्वित किया है। लगभग 11 करोड़ 60 लाख 525 रुपये का अनुदान वहां के किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, विभिन्न क्लाइमेटिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के 33 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हम उनको ओरचार्ड स्थापित करने के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया करते हैं। शेष 24 जिले जो हैं उनको नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अन्तर्गत कवर करके हम लोग यह प्रयास करते हैं कि आनलाइन जितने भी आवेदन आते हैं उनको अनुदान देकर उनके खेत पर बगीचे लगें, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हो ताकि किसान की आमदनी बढ़े और हर साल ओलावृष्टि में जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मिशन फार इंटिग्रेटेड डवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन में गत दो वर्षों में किन-किन जिलों ने अपने टार्गेट पूरे किये? जिन्होंने टार्गेट पूरे नहीं किये उनको डाइवर्ट किया गया क्या और जो भी अधिकारी/कर्मचारी लापरवाह रहे हैं उनके खिलाफ विभाग ने क्या कोई कार्यवाही की है?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में राजस्थान में लगभग 10653 हैक्टेयर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत नये बगीचे स्थापित करने का हमारा लक्ष्य था। उसके मुकाबले 9237.73 हैक्टेयर में पौधों की स्थापना और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। 2015-16 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक हमारा जो लक्ष्य था, 5120 हैक्टेयर में ओरचार्ड स्थापित करने थे, उसके

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मुकाबले अभी तक मात्र 4400 हैक्टेयर में, लगभग 75 परसेंट लक्ष्य को पूरा किया गया है। ये जनवरी तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है, अभी और आ जाएंगे तो हम समय पर पूरे राजस्थान के जितने भी आवेदन हैं, उनको हमारे लक्ष्य के मुताबिक पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। अगला प्रश्न।

कोटा के रानपुर-रामगंजमण्डी में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

134. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोटा के रानपुर एवं रामगंजमण्डी में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

(2) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि रीको द्वारा कोटा के रानपुर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये स्थापित एग्रो फूड पार्क में क्षमता के अनुरूप इकाइयां नहीं लग पायी हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) कोटा इकाई के अधीन रानपुर में औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (विस्तार) नाम से 228.86 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। रामगंजमण्डी में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु गुण्दी व फतेहपुर की 159.40 हैक्टेयर राजकीय/निजी भूमि चिह्नित की गयी है। 93.21 हैक्टेयर सरकारी भूमि का निगम के पक्ष में आबंटन दिनांक 06.04.2010 को किया जाकर भूमि का भौतिक कब्जा निगम के पक्ष में दिनांक 19.12.2010 को लिया जा चुका है। निजी भूमि 66.19 हैक्टेयर का एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 10.02.2016 को जारी कर दिया गया है। मुआवजा राशि का भुगतान सम्बन्धित नियमानुसार खातेदारों/हितधारियों को किये जाने के पश्चात् उक्त अवाप्त भूमि का कब्जा निगम के पक्ष में लिया जाएगा।

(2) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाएं जिसमें सड़क, पानी, बिजली, नालियां, स्ट्रीट लाइटें सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराती हैं। आवश्यकता होने पर कामन फैसिलिटी

(श्री गजेन्द्रसिंह)

सेंटर भी स्थापित करती है जिसमें बैंक, पोस्ट आफिस, पुलिस चौकी/थाना, टेलीफोन एक्सचेंज इत्यादि के लिए भवन उपलब्ध कराया जाता है। उक्त सुविधाओं के लिए आवश्यकतानुसार पृथक से भूमि भी उपलब्ध करायी जाती है।

(3) जी नहीं। रीको द्वारा कोटा के रानपुर स्थित एग्रो फूड पार्क प्रथम व द्वितीय चरण में क्रमश: 151 व 155 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। एग्रो फूड पार्क प्रथम चरण में 151 भूखण्डों में से 150 भूखण्डों का आबंटन किया जा चुका है जिनमें से 147 भूखण्डों पर औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं एवं 1 भूखण्ड निर्माणाधीन है।

एग्रो फूड पार्क द्वितीय चरण में 155 भूखण्डों में से 152 भूखण्डों का आबंटन किया जा चुका है जिसमें से 42 भूखण्डों पर औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं एवं 6 भूखण्ड निर्माणाधीन हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र के आबंटियों की निर्माण/उत्पादन की समय सीमा शेष है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रानपुर औद्योगिक क्षेत्र कोटा में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अभी तक उद्यमियों को कितने भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं एवं कितने भूखण्ड आबंटित किया जाना अभी शेष हैं? शेष भूखण्डों का भी शीघ्र आबंटन कर क्या राज्य सरकार रानपुर औद्योगिक क्षेत्र में नयी औद्योगिक इकाइयां लगाने का विचार रखती है? क्या राज्य सरकार कोटा में नये उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कोई लैण्ड बैंक बनाने का विचार रखती है? कोटा शहर से सटे आबादी क्षेत्रों में जंगलात की जमीनों में लैण्ड फार लैण्ड के तहत लैण्ड बैंक की कोई योजना सरकार ने बनायी है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न अलग-अलग पूछे हैं जिनका मैं जवाब देता हूं। रानपुर इण्डस्ट्रियल एरिया कुबेर, इसमें 228.86 एकड़ भूमि है, इसके 91 प्लाट्स काटे गये जिसकी 161 एकड़ भूमि है। 20 जो प्लाट हैं, उनके अन्दर 72.66 एकड़ जमीन है, वे पहले आबंटित किये गये थे। इनमें 19 में से 14 यूनिट्स अभी आपरेटिव हैं और एक वर्क इन प्रोग्रेस है। शेष जो 71 प्लाट्स हैं जिनकी भूमि

(श्री गजेन्द्रसिंह)

88.85 एकड़ है, पर्यावरण विभाग के जो नये रूल्स थे उनके तहत इनकी एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पायी, 50 हैक्टेयर से अधिक भूमि के लिए स्पेशल एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस का एक कानून आ गया था। इसके अन्दर लगभग साल भर लग जाता है, इसमें 6 महीने आलरेडी बीत चुके हैं। इन यूनिट्स को जो 71 प्लाट्स हैं इनको केन्द्र सरकार से क्लियरेंस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।

माननीय सदस्य ने दूसरा जो प्रश्न पूछा था, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोटा जिले के अन्दर 14 रीको इण्डस्ट्रियल एरियाज आपरेटिव हैं। एक यह डवलप हो रहा है रानपुर कुबेर का और तीन डवलप होने शेष रहे हैं। सुकेत, नन्ता और लखावा, ये तीन एरियाज हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर जमीन की प्राब्लम आ रही है। वन विभाग से एक्सचेंज करने की बात चल रही है, वह अभी विचाराधीन है। इसकी जो आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं माननीय सदस्य को जल्दी से जल्दी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर पूर्व में औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा है, परन्तु अब धीरे-धीरे उद्योगों का वहां से पलायन हो रहा है। आई.एल. बंद होने के कगार पर खड़ी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार नये उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी सभी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए रिसर्जेन्ट राजस्थान कार्यक्रम के तहत कोटा में नये उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है, कृपया मंत्रीजी बताएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.एल. है कोटा में, वह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की पीएसयू है और उसकी इक्विटी 100 प्रतिशत है। वर्तमान में 800 करोड़ रुपये की इसकी लाइबिलिटी है। जो सरप्लस जमीन थी, उसमें से दो तिहाई सरप्लस जमीन है, राज्य सरकार ने आई.एल. को बोल दिया था कि आप उसको बेच सकते हैं और इससे आपकी जो लाइबिलिटीज हैं और जो आप रैड में चल रहे हैं, इसको दुरुस्त कर सकते हैं। जब यह जमीन बिकी, इसके दो तिहाई फंड आये, इन्होंने सेलेरीज में बांट दिये। अभी जो फाइनेंशल सिचुएशन है आई.एल. की, वह बहुत ही गम्भीर है। केन्द्र सरकार ने हमें पत्र लिखा था, हमें बोला था कि आप इसको टेक-ओवर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कर लें। हमने साफ इन्कार कर दिया कि इतनी हैवी लाइबिलिटीज को हम वहन नहीं कर सकेंगे।

माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न पूछा था कोटा के बारे में, रिसर्जेन्ट राजस्थान के बारे में तो मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कोटा एक बहुत ही फास्ट मूविंग एरिया है। यहां पर पानी, सड़क, रेल, सब सुविधाएं हैं। यहां पर 16 एमओयू साइन हुए थे, अध्यक्ष महोदय, जिनका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। 1,845 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है और 10,470 युवाओं को, कोटा के सिटीजन्स को नौकरी मिलने की पूरी सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। पूरक प्रश्न-एक।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी विधान सभा का प्रश्न है, मुझे भी मौका दीजिए। मैं भी बोलना चाहूंगी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो...

श्री अध्यक्ष: आपने देर से बटन दबाया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ...एक साथ रिलेटेड दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक ही कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दोनों रिलेटेड हैं।

श्री अध्यक्ष: दोनों को जोड़ लीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक तो, माननीय मंत्री महोदय, रानपुर इण्डस्ट्रियल एरिया डार्क जोन है, चम्बल नदी से रा-वाटर वहां पहुंचाने की योजना काफी लम्बे समय से पैंडिंग चल रही है, इमिजिएट उस बारे में क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं?

दूसरा, रानपुर और रामगंजमण्डी के बीच में मण्डाना में मण्डाना रैड एण्ड सैंड स्टोन का कंटेनर एक्सपोर्ट का डिपो है, वहां पर सेज स्थापना की पिछले 15 सालों से मांग चल रही है। इस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानपुर इण्डस्ट्रियल एरिया एक आपरेटिव इण्डस्ट्रियल एरिया है, इसको पानी की सप्लाई मिल रही है। यह जरूर है कि ये जो 71 प्लाट्स हैं, इनको एनवायर्नमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो उसके बाद पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा। जहां तक सेज का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर जमीन का बहुत भारी इश्यु है। जमीन की उपलब्धता एक क्रिटिकल फैक्टर है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा, श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में गजनेर में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक क्षेत्र कब तक चालू कर दिया जाएगा? क्या सरकार बीकानेर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु एग्रो फूड पार्क बनाने का विचार रखती है? क्या सरकार बीकानेर में वर्षों से लम्बित सूखा बंदरगाह की मांग को पूरा करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह अलग ले गये आप। खींच लिया आपने उधर। अब देने दीजिए जो जवाब है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा बंदरगाह के बारे में प्रपोजल चल रहा है, वह अभी सांचौर का चल रहा है क्योंकि सांचौर की भूमि सी लेवल की भूमि है तो उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अभी बीकानेर के बारे में कोई इश्यू विचाराधीन नहीं है।

आपने पूछा कि रीको एरियाज हैं, जो सैंक्शन्ड हैं, मेरे पास जो फीगर्स हैं, गजनेर के औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर विलम्ब केवल एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस की वजह से है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जैसे ही एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस हो जाएगा, गजनेर के औद्योगिक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री रामचन्द्र।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मेरी विधान सभा का प्रश्न है और मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरी विधान सभा का प्रश्न चल रहा है। रामगंजमण्डी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैं दूंगा, इसीलिए तो... आपको जल्दी बटन दबाना

(श्री अध्यक्ष)

चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं मौका दे दूंगा। तीन पूरक प्रश्न की मैंने अनुमति दे दी है।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोटा में जो पुराना औद्योगिक क्षेत्र है डकनिया के पास में, वहां उद्योग लगाने के लिए जमीन अलाट की गयी थी, आज जबकि वहां उद्योग नहीं हैं और वहां पर हास्टल्स और बड़े-बड़े माल्स हैं और उनको वह जमीन हस्तान्तरित कर दी गयी, क्या मंत्री महोदय, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? जमीन अलाट तो उद्योगों के लिए की गयी थी, उसके नये प्रयोजन क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हास्टल्स स्थापित हुए हैं, उनके अन्दर हमारे डिपार्टमेंट ने जाकर बोला, उनसे बात की है, उद्योग विभाग और यूडीएच के जो नार्म्स हैं, सेफ्टी नार्म्स हैं, सैट-बैक है, अगर वे उन नार्म्स को फुलफिल कर देंगे तो हम उनको रैगुलराइज कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। यह विशेष तौर से चौथा पूरक प्रश्न है। तीन हो चुके हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जी, जी। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रही हूं क्योंकि रामगंजमण्डी के सन्दर्भ में ही यह प्रश्न लगा है। रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र का गूंदी-फतेहपुर इण्डस्ट्रियल एरिया है, 2012 में घोषित किया गया है, उसके डवलपमेंट की आज तक की क्या प्रगति है, इसके बारे में मुझे बताया जाए।

दूसरा, धारा 4 और 6 की कार्रवाई किन-किन किसानों पर कितनी-कितनी भूमियों पर की गयी और उन किसानों को मुआवजा कब तक आप दे देंगे? आज तक कितनी-कितनी राशि का मुआवजा उनको देय होगा?

तीसरा, जो 70-80 बीघा भूमि आलरेडी उद्योगों में कन्वर्ट है, उसका आप क्या करेंगे? कितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा?

चौथा, उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में किसानों की कितनी जमीन है, कौन-कौनसी भूमि है, कितनी सिवाय चक है, कितनी चरागाह है, यह भी मुझे बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी में गूंदी और फतेहपुर में 159 हैक्टेयर जमीन ईयरमार्क्ड है। इसमें से 93.21 हैक्टेयर सरकारी जमीन है जो रीको को अलाट हो चुकी है और उसका पजेशन रीको ले चुका है। 66.19 हैक्टेयर जमीन प्राइवेट है। उसका अवार्ड 10.2.2016 को जारी हुआ है। वहां कौन खातेदार हैं, कितनी भूमि है, वह मेरे पास अभी फिगर्स नहीं हैं, माननीय सदस्य को मैं वे फिगर्स शीघ्र भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय रणधीर सिंह भीण्डर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, आई.एल. की चर्चा कर रहे थे माननीय संदीप शर्मा साहब।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। अब आपको दे देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): स्टेट गवर्नमेंट को कुछ निर्णय लेना चाहिए क्योंकि आई.एल. बंद होने के कगार पर है।

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब दे देंगे। श्री रणधीर सिंह।

भीण्डर पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन में शौचालयों के निर्माण की बकाया राशि

135. **म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति भीण्डर में स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृतियों की पालना में शौचालयों का निर्माण करने के उपरान्त भी कितने परिवारों का भुगतान पंचायतों में बकाया है? पंचायतवार परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के अभाव में इस मिशन को जल्दी पूरा करने हेतु उच्च अधिकारियों के मार्फत भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) पंचायत समिति भीण्डर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 211(2) के अनुसार जब कभी चैक पर संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक हों तथा सरपंच, प्रधान, प्रमुख के हस्ताक्षर प्राप्त करना दस दिन तक सम्भव न हो परन्तु भुगतान करना अति आवश्यक हो, तो सरपंच के स्थान पर विकास अधिकारी,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

प्रधान के स्थान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख के स्थान पर जिलाधीश चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है कि पेमेंट हो गया है, हालांकि काफी पेमेंट बाकी है, पर मैं मान लेता हूं कि पेमेंट हो गया है, लेकिन क्या हमें हर पेमेंट के लिए विधान सभा सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि विधान सभा सत्र में जब प्रश्न उठाते हैं तभी वह पेमेंट होता है? आप दस दिन की बात कर रहे हैं, कम से कम छह-छह महीने तक का पेमेंट बाकी है। पेमेंट अभी गुरुवार को किया है मेरे प्रश्न उठाने के बाद में। दूसरा, मंत्री महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि सरकार ने इस योजना को महत्वपूर्ण माना है और इसको मिशन नाम दिया है। 12 हजार में शौचालय बनता नहीं है, उस व्यक्ति को खुद के भी कुछ पैसे उसमें लगाने पड़ते हैं। गरीब व्यक्ति को आप दे रहे हो और उसके बाद वह उसके खुद के पैसे भी लगा रहा है, उसका समय पर अगर पेमेंट नहीं होगा तो इस योजना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लोगों को यह भावना होने लगी है। पेमेंट आने में देरी होती है तो लोग उसको करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए योजना में आप किस तरह से स्फूर्ति लाएंगे? और जो जन प्रतिनिधि ऐसी योजनाओं को अटकाएं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा, इन्होंने कहा कि समय पर भुगतान नहीं होता है, राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो भी टायलेट बन गये हैं उनका समय पर भुगतान हो। आपके भीण्डर में भी भुगतान बकाया था और राजस्थान के अन्य जिलों में भी बकाया था। 60:40 के रेशो के हिसाब केन्द्रीय अंश 60 परसेंट और 40 परसेंट राज्य से होता है, उसके हिसाब से कुछ देरी हुई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि समय पर भुगतान किया जाएगा।

दूसरी बात, मैंने जैसा दूसरे खण्ड के जवाब में दिया है, अगर सरपंच जाइंट हस्ताक्षर में देरी करता है तो उसकी जगह दस दिन के बाद में विकास अधिकारी को अधिकृत कर दिया है हमने, अगर प्रधान देरी करता है तो उसकी जगह सीओ को अधिकृत कर दिया है और अगर प्रमुख देरी करता है जाइंट

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

साइन करने में तो उसकी जगह जिलाधीश को अधिकृत कर दिया है। परन्तु ये सब अधिकार इसलिए दिये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अर्जेंसी हो क्योंकि जन प्रतिनिधियों की व्यवस्था है कि जन प्रतिनिधि साइन करें, परन्तु बाइ-द-वे दस दिन में वह नहीं करे पता नहीं, कोई कारण हो सकता है, तो अर्जेंसी के कारणों को दर्शाते हुए ये अधिकारी करेंगे और उनका समय पर भुगतान करेंगे।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधिगण क्यों नहीं करते, यह तो आपकी जानकारी में है।

श्री अध्यक्षः आप भी दे दीजिए जानकारी।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मेरा कहने का मतलब यह है, यह जानकारी ये जानते हैं। किसी वरिष्ठ नेता की हमारे ऊपर कृपा हुई जब ये प्रधान वहां पर बैठे हैं। उस प्रधान को कंट्रोल हम कैसे करें, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आता। आप कम से कम उस अधिकारी को निर्देशित करें कि वह प्रधान अगर दस्तखत नहीं करे तो वह बीडीओ ही दस्तखत कर दे। सीओ तक फाइल जाती है तो महीने, दो महीने उसी में निकल जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, दस दिन का आपने टाइम दिया है तो दस दिन में उसका पेमेंट हो जाए, इसकी व्यवस्था आप कराएं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 211 (2) में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर प्रधान साइन नहीं करता है तो दस दिन बाद में सीओ को अधिकृत कर रखा है। इसलिए अगर कोई आपको प्राब्लम आएगी तो हमें बताइये, हम निर्देशित भी करेंगे, बाउण्ड भी करेंगे और जल्दी से जल्दी उनका भुगतान भी करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः श्रीमती अनीता, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं, जिन पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया उन पंचायतों में भी अभी बहुत सारे शौचालयों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं, तो उनके पेमेंट्स आप कैसे और कब तक करा देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं, यह जरूर है कि किश्तें बकाया थीं 460 करोड़ 66 लाख रुपये बकाया थे, लेकिन अभी हमारे पास में केन्द्रीय अंश के 509.35 करोड़ रुपये आ गये हैं और राज्य अंश के 339.57 करोड़, ऐसे कुल मिलाकर 848 करोड़ 92 लाख रुपये हमारे पास आवंटित हो गये हैं, जहां पर भी पैसा बकाया है पूरे राजस्थान में, जल्दी से जल्दी उनको भुगतान कर देंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो पंचायतें ओडीएफ हो गयीं, हमने घोषणा कर दी, जिनको प्रमाण पत्र दे दिया, उन पंचायतों में स्पेसिफिकली जो 50 परसेंट से ज्यादा शौचालयों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल करेंगे या जैसे अपन सबको बांटते हैं उसी प्रकार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि पंचायतें ओडीएफ हुई और चाहे ओडीएफ नहीं हों, जिनका पैसा बकाया है, सबका भुगतान समय पर कर दिया जाएगा।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा कहना यह है कि जिसकी अपन ने ओडीएफ की घोषणा ही कर दी, अगर उनको आप पहले कर देंगे तो दूसरी पंचायतों में भी काम्पीटिशन की भावना आएगी और वो भी ओडीएफ के लिए जल्दी काम करेंगे। इसलिए उनको आप पहले करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को निवेदन कर रहा हूं, आप निश्चित रहें, किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं रहेगा। जो ओडीएफ हुई हैं पंचायतें, उनको प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा। ओडीएफ नहीं हुई हैं और जिन्होंने शौचालय बना लिये हैं और उनका पैसा बकाया है, उनका भी समय पर भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: और कुछ रह गया है, श्री अर्जुन जीनगर। इतना व्यापक जवाब दे दिया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कपासन पंचायत समिति के अन्दर 7 हजार ऐसे परिवार हैं जिनको अपने आप ही कम्प्यूटर में बता दिया कि इनके शौचालय बन गये। उनको शौचालय बनाने में दिक्कत आ रही है। जब शौचालय बने ही नहीं हैं....

श्री अध्यक्षः यह भीण्डर से सम्बन्धित सवाल है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): भीण्डर से तो है परन्तु सम्पूर्ण शौचालय की बात है। पूरे राजस्थान का मामला है। कम्प्यूटर की मिस्टेक के कारण यदि इस प्रकार से घोषित कर दिया जाए कि इस परिवार में शौचालय बन गया और वास्तविक स्थिति में शौचालय नहीं बना तो उनका शौचालय बनाने के लिए अनुदान कहां से लाया जाएगा?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शौचालय बने ही नहीं और कम्प्यूटर में बता दिया कि शौचालय बन गया, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले कोई 1200 रुपये में शौचालय बना था, कोई 3200 रुपये में बना, कोई 4600 में। आज से चार-पांच साल पहले रेट यही थी। ऐसे शौचालयों की संख्या 6 लाख 15 हजार है। माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करूं कि उनको नए सिरे से बनाने हेतु स्वच्छ भारत कोष से हम आबंटन के लिए भारत सरकार को लिख देंगे और उनकी भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्षः तीसरा पूरक प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बड़े पैमाने पर हमने शौचालयों का निर्माण कर लिया और ओडीएफ भी घोषित हो गये, एक-एक साल हो गया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा का कब तक भुगतान करा देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए पैसा आ गया है, जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री नरेन्द्र नागर।

जोलपा (खानपुर) की पेयजल समस्या का समाधान

136. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम जोलपा में पेयजल की समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम जोलपा में संचालित जनता जल योजना अन्तर्गत निर्मित दो नलकूपों के सूख जाने के कारण माह जनवरी, 2016 से इस योजना से पेयजल आपूर्ति बंद होने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई।

इसके अतिरिक्त ग्राम में कुल स्थापित 13 हैण्डपम्पों में से 6 हैण्डपम्प वर्तमान में सूखे एवं 2 हैण्डपम्पों में पानी की आवक कम होने के कारण इनसे अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो रही है। ग्राम के शेष 5 हैण्डपम्पों में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर पर सिंगल फेस मोटर डाली हुई है, परन्तु भू-जल स्तर में गिरावट एवं पानी की आवक अत्यन्त ही कम होने के कारण इनसे भी वर्तमान में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

ग्राम की पेयजल समस्या के समाधान के लिए ग्राम से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर सांगोद रोड पर भू-जल उपलब्धता वाले क्षेत्र में एक नलकूप, राइजिंग पाइप लाइन एवं विद्युत सम्बन्ध का प्रावधान लेते हुए योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26.02.2016 को राशि रुपये 25.33 लाख की जारी की गयी है। उक्त योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत माह अप्रैल, 2016 में कार्यादेश दिया जाकर योजना 15 जून, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान के तहत ग्राम में दिनांक 16.01.2016 से 6 टैंकर ट्रिपों के माध्यम से 30,000 लीटर पानी प्रतिदिन परिवहन कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न संख्या एक।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, स्थाई समाधान के लिए जोलपा के अलावा बाकी जो भी गांव खानपुर के हैं, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अकाउ डैम सैंक्शन किया है, जो बाकी गांव खानपुर के बचे हैं, उस डैम के माध्यम से उन गांवों को आप पेयजल से जोड़ने का विचार रखते हैं? यदि रखते हैं तो कब तक और कब स्वीकृत आप कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, जवाब आ जाएगा, समय पूरा हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के पूछे गए प्रश्न पर उनको यह अवगत कराना चाहती हूं, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है यहां पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

2016-17 का, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले के किसानों का, मैं उसी बजट को यहां पर कोट कर रही हूं, वर्षों पुराना परवन सिंचाई योजना का सपना अब सच होगा। परवन का बहुत लम्बे समय से आपका चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने स्वीकृत इसको किया है। इस योजना से झालावाड़, बारां एवं कोटा के जिले के कुल 313 गांवों की 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्षः विराजिये। प्रश्न काल समाप्त। बाकी इन्फोर्मेशन आप इनको दे देना। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से नगरपालिका रायसिंहनगर के अधिशासी अभियंता द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में।

2. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल हेतु डाली जा रही पाइपलाइनों को एनओसी देने के सम्बन्ध में।

3. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ में ऐटा-सिंगरासर माइनर के निर्माण को लेकर 25 गांवों के लोगों द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में सिलिकोसिस की रोकथाम, पहचान और उपचार की समुचित व्यवस्थाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रमेश को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार से जो जवाब आये हैं उनके बारे में।

1. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कुपोषण के कारण हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है कि महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के सम्बन्ध में उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं के माध्यम से इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार प्रयास करने के लिए कटिबद्ध है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है, अगर इस पर आप आधा घंटे की चर्चा रख दें।

श्री अध्यक्ष: वह आप अलग से मूव कीजिये। और आधा घंटे की चर्चा किस विषय पर? प्रश्न पर रखी जाती है, इस पर नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कुपोषण।

श्री अध्यक्ष: वह तो है लेकिन आधा घंटे की चर्चा का जो स्रोत है वह प्रश्न से उत्पन्न होता है जो आपको भी मालूम है। आप और किसी तरह से लिखिये, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

2. श्री मनोज कुमार एवं श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जापानी होण्डा मोटरसाइकिल कंपनी के अलवर टपूकड़ा में स्थित उपक्रम में श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्रम एवं नियोजन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि टपूकड़ा स्थित प्लांट के आस-पास शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है एवं स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि संस्थान में ठेका श्रमिकों की उपस्थिति बढ़ी है।

3. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि मौके पर तहसीलदार उदयपुरवाटी को उक्त खातेदारी भूमि में नियमित चैकिंग कर अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबंद किया गया है। इसके अतिरिक्त खनिज विभाग के सहायक अभियंता तथा सम्बन्धित तकनीकी स्टाफ को भी उक्त क्षेत्र की लगातार निगरानी करने हेतु पाबंद किया गया है।

4. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से करसा राजपूत, खखड़, चंदाना, ऊठड़, परमार, कड़ेचा, तलादरा, दिया गुल, दषाणा समाज के लोगों को अन्य

(श्री अध्यक्ष)

पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के बावजूद प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि सम्पूर्ण राज्य में उक्त जाति के व्यक्तियों के भी नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त जातियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी से यह प्रकट होता है कि उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाई पास क्रासिंग पर अण्डरपास बनवाने के सम्बन्ध में।

2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच को लटकाये रखने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

3. श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

4. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से आयुर्वेद नर्सेज की ग्रेड पे एलोपैथी नर्सेज के समान करने के सम्बन्ध में।

5. श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में विद्युत व्यवस्था ठीक करने व नये जी.एस.एस. निर्माण करने के सम्बन्ध में।

6. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेजों में कार्यरत यूटीबी संविदा नर्सेज को यथावत कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

7. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से मीना/मीणा जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से तहसील कोलायत की उप तहसील बज्जू में नवीन राजस्व तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की क्षतिग्रस्त टोडारायसिंह-बोटूण्डा सड़क को पुन: निर्मित करवाने के सम्बन्ध में।

10. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से बालोतरा उपखण्ड मुख्यालय को जिले का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

12. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी स्थित सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 10 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 56 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, आहोर विधान सभा क्षेत्र के जवाई बांध से सिंचित 22 गांवों को सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामलाल शर्मा, जयपुर से सीकर के मध्य बनी 4-लेन सड़क की त्रुटियों के सम्बन्ध में।

3. श्री कैलाश वर्मा, बगरू विधान सभा क्षेत्र को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री ज्ञानदेव आहूजा, अलवर के मदरसों में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं बच्चों को बेड़ियों से जकड़े जाने के सम्बन्ध में।

श्री रमेश।

सूचना

एटा-सिंगरासर माइनर के किसानों का धरना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय चाहता हूं। ऐटा-सिंगरासर माइनर में सात दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 25 गांवों के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, वहां की कानून स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं कि

(श्री मनोज कुमार)
लम्बे वर्षों से, बीस साल से पांच-दस किलोमीटर के दायरे में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से और सरकार की एक कमेटी भी गठित हुई, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ और किसान सात दिन से वहां आंदोलन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, विराजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर स्थिति है। सरकार इसके लिए उस कमेटी...

श्री अध्यक्ष: केवल आपने ध्यान आकर्षण करने के लिए मांगा। विराजिये आप। नो-नो, अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: रमेशजी, आप बोलिये। नहीं, यों आफ हैंड आप नहीं बोल सकते।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। इन्फार्मेशन मुझे सब मिल गयी आपकी तो। रमेशजी, बोलो। आप मेरी पड़ोस की कांस्टीट्युएन्सी के हैं न, सब इन्फार्मेशन है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष सूचना है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कोई विशेष इन्फार्मेशन दे रहे हैं, दीजिये।

भीलवाड़ा महिला अरबन कोआपरेटिव बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में एक महिला अरबन कोआपरेटिव बैंक के बाहर दो-दो हजार उपभोक्ता रोज उस बैंक से पैसा लेने के लिए लाइन लगा कर खड़े हुए हैं जबकि आरबीआई ने उनकी जो प्रीमैच्योर एफ.डी. थी, उस पर रोक लगा दी है और एफ.डी. पर ऋण देने के लिए भी आरबीआई ने रोक लगा दी है उसके बावजूद उपभोक्ता बहुत ज्यादा परेशान हैं। उपभोक्ताओं का लाखों रुपया बैंक में फंस गया है, इसमें राहत दिलायें।

श्री अध्यक्ष: आ गया। ध्यान आकर्षित कर लिया। माननीय रमेशजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सिलिकोसिस के रोकथाम और उपचार की समुचित व्यवस्थाएं

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए कुशल-अकुशल श्रमिक सिलिकोसिस और एस्वेस्टोसिस बीमारी से पीड़ित हैं और इनकी संख्या राजस्थान में लाखों में है। इस बीमारी से हजारों लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार गम्भीर नहीं है। उनके इलाज न उनकी दवाइयों के प्रति गम्भीर है, न उनकी जांच के प्रति गम्भीर है। इसकी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। पिछली बार भी सरकार ने घोषणा की कि हम इलाज कराएंगे, कैम्प लगाएंगे। सरकार के माध्यम से आदेश भी दिसम्बर, 2014 में निकाले गये, जिलों में न्यूमोकोनोसिस बोर्ड के गठन की बात कही गयी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के चिकित्सा विभाग में न तो कोई प्रशिक्षित स्टाफ है, न डाक्टर्स हैं न इनके पास प्रशिक्षित रेडियोलाजिस्ट हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था सदन में और बाहर भी आदेश निकाले वे असत्य है तो मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री जी से कि इस प्रकार की गम्भीर बीमारी से लोग पीड़ित हैं। सिलिकोसिस है, एस्वेस्टोसिस है, ये दोनों बीमारियां फेफड़ों से सम्बन्धित बीमारी हैं। यह लाइलाज बीमारी है। लोग दिन महीने गिन रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। राजस्थान में 7 मेडिकल कालेज हैं उनमें आपने न्यूमोकोनोसिस बोर्ड का गठन कर रखा है। उसमें महीने में दो बार उनका परीक्षण होता है जिसमें मैक्सिमम 15 से 20 मरीजों का परीक्षण किया जाता है। लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपने कहा कि हम जगह-जगह कैम्प लगवाएंगे। मैं मेरे सम्भाग की बात करूं तो पूरे सम्भाग में रेडियोलोजिस्ट नहीं हैं आपके पास में, डाक्टर्स नहीं हैं जो टीबी से सम्बन्धित बीमारी की पहचान करते हैं, न आपने इनको इस तरह का प्रशिक्षण दिलवाया। यह बीमारी इतनी भयंकर है कि एक अभियान चलाकर सरकार को इस पर विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए, वैज्ञानिक से रिसर्च करवाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए, पांच मिनट ले लिये। वह जवाब दे रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं मात्र एक मिनट लूंगा। आपने मानवाधिकार आयोग का भी ध्यान नहीं रखा और उसकी रिपोर्ट भी समय पर सदन में नहीं

(श्री रमेश)

रख पाये हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो मरीज इस बीमारी से पीड़ित हैं उनका समयबद्ध उपचार हो, समयबद्ध उनको चिह्नित किया जाए, उनको बीपीएल की श्रेणी में जोड़ा जाए, उनको सीएचसी और पीएचसी पर नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवायी जाएं। मैं सरकार से आश्वासन नहीं चाहता हूं, सरकार काम करे तो सच बताए, असत्य न बोले। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्रीजी पहले भी बोल चुके हैं, ऐसे लगता है कि मंत्रीजी की कोई बात चल नहीं रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अब बैठो, रमेशजी। माननीय विधायक, बैठिए, बैठिए। वह जवाब दे रहे हैं। जो लगता है वह रहने दो, आपका जवाब आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सिलिकोसिस बीमारी का यहां जिक्र किया। यह सही है कि सिल्कोंडाई आक्साइड...

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं। माननीय मंत्री महोदय, आपस में चर्चा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फेफड़ों में जमा होने के पश्चात् सिलिकोसिस बीमारी होती है। यह बीमारी व्यवसायजनित बीमारी है। सिलिका फेफड़ों में जमा होने के कारण यह लाइलाज बीमारी है, मैं यह स्वीकार करता हूं। पूरे राजस्थान में सबसे पहले जब हमारा ध्यान आकर्षित किया था माननीय सदस्य ने तो पूरे जिलों में हमने निमोसिस बोर्ड का गठन कर दिया। पहले ये बोर्ड मात्र मेडिकल कालेज के स्तर पर थे, आज हर जिले में निमोसिस बोर्ड गठित हो चुके हैं। 2015 में इसके लिये हमने 10 मोबाइल यूनिट खरीदीं। इन 10 मोबाइल यूनिटों ने राजस्थान में 20 जिले और 34 ब्लाक जो इस सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित हैं, उनमें कैम्पों का आयोजन किया। 2015 में 703 कैम्प और इस फरवरी तक 203 कैम्पों का आयोजन किया गया है। इन कैम्पों के माध्यम से वहीं, उसी जगह पर एक डाक्टर और एक्स-रे टैक्निशियन जाकर प्रारम्भिक जांच करते हैं और उसके बाद इनको निमोसिस बोर्ड के सामने अगर बीमारी के लक्षण पाये जाते हैं तो इनको वहां प्रस्तुत करते हैं। उस बोर्ड में एमडी चैस्ट, एमडी फिजिशियन और रेडियोलोजिस्ट रहते हैं। अब तक 2293 प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इसके लिये अब तक 22 करोड़ 51 लाख रुपये की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहायता भी दी है। हमने सभी जगह पर जहां इस प्रकार का रोग पाया जाता है, माइन्स डिपार्टमेंट को भी यह कहा है कि वह वैट ड्रिलिंग कराए, लोग मुख पर कपड़ा बांधें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एपीडेमिक एक्ट, 1957 है इसमें यह नोटिफाइड डिजीज भी है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। कि हमने पहली बार दिसम्बर में मोबाइल वैन खरीद कर, पहली बार उसी जगह पर जाकर, अलग-अलग जगहों पर कैम्पों का आयोजन किया है।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं। कोई भी निमोकोसिस बोर्ड किसी भी जिले में काम नहीं कर रहा है। मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित जिलों को छोड़ एक भी जिले में काम कर रहा हो तो आप बताएं। मेरे पूरे भरतपुर सम्भाग में बता दें, यहां के विधायक भी बैठे हैं आपके सत्ता पक्ष के। सिलिकोसिस बीमारी से चिह्नित करने का जिला लेवल पर जो बोर्ड का गठन किया गया था, एक भी कार्यरत नहीं है। क्योंकि आपके पास रेडियोलोजिस्ट नहीं हैं, आपके पास डाक्टर नहीं हैं। मेरे करौली जिले में न तो क्षय रोग का चिकित्सा अधिकारी है, न कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है। आप कौनसी बात कर रहे हो? आज बजट की बात कर रहे हो इस बार बजट में पैसा नहीं दिया। पिछला पैसा भी आपने खर्च नहीं किया और 22 करोड़ की बात कर रहे हो। लाखों की संख्या में इस सिलिकोसिस से पीड़ित लोग हैं और आप इनके इलाज के प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं हैं। जो भी आप सदन में बोल रहे हो वह एक तरह से सदन का विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है क्योंकि आप यहां असत्य बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

श्री रमेश (सपोटरा): आप जो आश्वासन दें कि हम कर सकते हैं, वह करें। आपके अधिकारी आपकी बात मानते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में 2015 से लेकर अब तक 20 कैम्प आयोजित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल वैन के द्वारा भी किये गये। मैं निवेदन करूं, इस बीमारी के लक्षण जब पाये जाते हैं तो उसको एक लाख रुपये सरकार सहायता देती है और अगर मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस को तीन लाख रुपये सरकार सहायता देती है। चूंकि यह बीमारी राजस्थान में ज्यादा पायी जाती है, इसीलिए राजस्थान की सरकार ने इसके लिये आवश्यक बजट का प्रबंधन किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट का प्रबंधन नहीं किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2014-15 में 3500 लाख रुपये का इसमें प्रबंधन किया गया और उसका उपयोग भी किया गया। उसके पश्चात् भी यह इस प्रकार की बीमारी है, मैं समझता हूं, लाइलाज बीमारी है, अगर माननीय सदस्यों को कहीं ऐसा लगे कि किसी जगह पर कैम्पों का आयोजन हुआ परन्तु बीमारों को चिह्नित करके उन्हें प्रोपर इलाज नहीं दिया तो आप मुझे सूचित कर दें, मैं विशेष कैम्प लगवा दूंगा। बाकी सरकार बिलकुल गम्भीर है और हमने पहली बार सिलिकोसिस और निमोसिस बोर्ड का गठन किया है। हमने पहली बार वैन खरीद कर अलग-अलग जिलों में कैम्प लगाये हैं। 700 से ज्यादा कैम्प 2014-15 में लगे और 203 कैम्प अभी फरवरी तक लगे हैं। इसमें आप सहयोग करें।

श्री रमेश (सपोटरा): गरीबों का मैटर है, मंत्रीजी भी स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब इनका अंकित नहीं होगा। रमेश जी का अब अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: यह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं इसलिए अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत श्री गिर्राज सिंह (अनुपस्थित) ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो मंत्रीजी जच कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी नजर लग जाएगी। (व्यवधान) नहीं लगे। स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं उनको तो जच के ही आना चाहिए। श्री गिर्राज सिंहजी (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल (अनुपस्थित) श्री नरेन्द्र नागर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खानपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत खानपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, खानपुर विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय खानपुर है। यहां पर उपखण्ड

(श्री नरेन्द्र नागर)

कार्यालय के अलावा तहसील, पंचायत समिति कार्यालय, कृषि उपज मण्डी कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कार्यालय व विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित है। शिक्षा की दृष्टि से वर्तमान में खानपुर तहसील के अन्दर 38 सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हैं। सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में जाना पड़ता है। राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा विद्यार्थी खानपुर क्षेत्र के हैं। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे अपने बच्चे-बच्चियों को पढ़ने के लिये वहां तक नहीं भेज पाते जिसके कारण कक्षा 12वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि खानपुर में कालेज खुलवाया जाए जिससे यहां के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये अन्यत्र नहीं जाना पड़े, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री कंवर लाल (अनुपस्थित) श्री भजन लाल जाटव। (व्यवधान) वह आये देखो, आपकी पार्टी के आये। वह बोल रहे हैं, उनको बोलने दो।

वैर में विद्युत की अव्यवस्था

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन से चार घंटे बिजली आ रही है जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह जल द्वारा सिंचित नहीं हो पायीं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रात को बिजली देने पर जंगली जानवरों द्वारा कई मौतें हो गयी हैं जिससे पहाड़ी क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। साथ ही, किसानों से अवैध तरीके से बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं। जनवरी, फरवरी माह में बिल वसूले जा रहे हैं जबकि 31 मार्च के बाद भी वसूली की जाती थी। बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल फेस बिजली का पूरी तरह से बुरा हाल है। कर्मचारियों को फोन करने पर फोन रिसीव नहीं करते हैं, जिससे फरवरी और मार्च महीने में छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि बिजली की व्यवस्था को तुरन्त प्रभाव से ठीक कराया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र में नए जी.एस.एस. का निर्माण करवाएं, आपकी अति मेहरबानी होगी, जिससे आम जन को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष: आपने लिखित दिया उससे आगे जा रहे है। वो तो आप पढ़ चुके हैं। जो लिखित दिया है प्रक्रिया में, वो तो आप पढ़ चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): ठीक है, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह। एबसेंट। डा. किरोड़ी लाल।

मीना/मीणा जाति प्रमाण पत्र

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में दायर एक याचिका कैप्टन गुरूविन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार (1862/2003) में मीणा/मीना के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में कोर्ट ने मौखिक आदेश दिये थे जिसके आधार पर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिनांक 30.09.2014 एवं दिनांक 23.12.2014 को जिला कलेक्टर्स को जारी पत्रों में कहा गया कि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अत: इस सम्बन्ध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेशों तक जिन व्यक्तियों को मीणा (Meena) जाति का प्रमाण पत्र दिया हुआ है, को मीना (Mina) जाति में परिवर्तित कर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें।

किन्तु उक्त संदर्भित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2016 द्वारा सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। इस निर्णय के तुरन्त बाद मैं तथा समाज के विभिन्न संगठनों के जन प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी से व्यक्तिश: मिलकर राज्य सरकार द्वारा लिखे गए उक्त दोनों संदर्भित पत्रों को वापस लेने का अनुरोध किया। इस पर मंत्रीजी ने दोनों पत्रों को वापस लेने का हमें पूरा आश्वासन दिया, किन्तु अभी तक दोनों पत्रों को वापस नहीं लिया गया है। उक्त सम्बन्ध में समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय महाधिवक्ता श्री एम.एन. लोढा से भी भेंट कर अनुरोध किया कि जो दो पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये, उन्हें वापिस लेने की कानूनी सलाह शीघ्र दें जिससे समस्या का समाधान हो सके। किन्तु महाधिवक्ता का यह कहना है कि इन पत्रों को वापस लेने से न्यायालय की अवमानना बनती है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि संदर्भित याचिका कैप्टन गुरूविन्दर बनाम राजस्थान सरकार

(डा. किरोड़ी लाल)

(1862/2013) के निर्णय दिनांक 4 फरवरी, 2016 को माननीय न्यायालय ने सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। श्रीमान महाधिवक्ता को ऐसा मानना कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है।

उक्त प्रकरण को लेकर धरने, प्रदर्शन के अलावा जयपुर में 2 अक्टूबर, 2015 को एक महा रैली भी आयोजित की गयी। भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधियों को भी राज्य सरकार ने दिनांक 16.09.2015 को लिखित आश्वासन दिया कि पूर्व की भांति मीना एवं मीणा के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 और 23 दिसम्बर, 2014 को वापस लेने के लिए कटिबद्ध है और इस सम्बन्ध में सरकार समस्त वैधानिक कार्यवाही करेगी ताकि जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्व व्यवस्था जारी रहे। किन्तु इसके बावजूद भी सरकार ने दोनों आदेश वापस नहीं लिये। इससे पूर्व एक प्रतिनिधिमंडल को 14.09.2015 को सरकार द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था।

इस समस्या के स्थाई समाधान की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को मीना के साथ मीणा एवं Mina के साथ Meena राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 9 पर जोड़ने की सिफारिश भेजे जाने की सहमति बनी थी, किन्तु राज्य सरकार ने इस आशय का पत्र अभी तक भारत सरकार को नहीं भेजा है। सरकार द्वारा मुझे व मीणा समाज को इस सम्बन्ध में आश्वासन दिए हुए साढ़े चार माह का समय गुजर जाने के बाद भी तथा कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से समाज में भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे के प्रति गम्भीर नहीं है। अत: निवेदन करता हूं कि समस्या की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसका शीघ्र अतिशीघ्र निदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

कोलायत की उप तहसील बज्जू में राजस्व तहसील व उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): श्री कोलायत तहसील की उप तहसील बज्जू में राजस्व तहसील व उपखण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में, राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री भंवरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिला राज्य का सीमान्त जिला है एवं इस सीमान्त जिले की सबसे बड़ी तहसील है श्री कोलायत। इस तहसील का एक छोर जैसलमेर जिले की सीमा पर व एक छोर जोधपुर जिले की सीमा पर है। वर्तमान में श्रीकोलायत तहसील के क्षेत्राधिकार में 245 राजस्व ग्राम आते हैं जबकि जिले की अन्य तहसीलों में बीकानेर तहसील में 125 राजस्व ग्राम हैं, खाजूवाला तहसील में 139 राजस्व ग्राम हैं, लूणकरणसर में 180 राजस्व ग्राम हैं। नोखा तहसील में 145 राजस्व ग्राम हैं व श्रीडूंगरगढ़ तहसील में 98 राजस्व ग्राम हैं। श्रीकोलायत तहसील वर्तमान में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर जिले की सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील का कुल क्षेत्रफल 797174 हैक्टेयर है। इस तहसील के 118 राजस्व ग्राम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में आते हैं। अर्थात् उक्त क्षेत्र में दो फसली रकबा काश्त होता है।

(12.26 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीकोलायत तहसील के अन्तर्गत आने वाले तहसील के अन्तिम ग्रामों की तहसील से दूरी 140 किलोमीटर है। इस प्रकार इतनी लम्बी दूरी वाली राज्य में अन्य कोई तहसील नहीं है। दिनांक 31.08.2015 से पूर्व उक्त तहसील क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग की तीन तहसीलें कार्यरत थीं, परन्तु उक्त दिनांक को उक्त तीनों उपनिवेशन तहसीलों का राजस्व में विलय कर दिया गया। उक्त तीनों तहसीलों का सम्पूर्ण कार्यभार राजस्व तहसील कोलायत के क्षेत्राधिकार में आ गया। उपनिवेशन विभाग की इस क्षेत्र की तहसीलों में 75 पटवारियों व 21 भू-अभिलेख निरीक्षकों व 3 तहसीलदारों, 4 नायब तहसीलदारों व 3 तहसील राजस्व लेखाकारों सहित मंत्रालयिक कार्मिकों व दो आबंटन अधिकारियों के पद स्वीकृत थे जिस कारण क्षेत्र के आमजन का कार्य सुचारु रूप से होता था। परन्तु उपनिवेशन विभाग की इन तीन तहसीलों का राजस्व विभाग में विलय होने के पश्चात् उक्त क्षेत्र में एक तहसीलदार व दो नायब तहसीलदार, एक उपखण्ड अधिकारी का पद, 50 पद पटवारियों, 12 भू-अभिलेख निरीक्षकों, एक त.रा.ले. का स्वीकृत है जिसमें से 2 पद नायब तहसीलदार, 21 पद पटवारी, 2 पद भू-अभिलेख निरीक्षक के रिक्त चल रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्राधिकार वाली राज्य में अन्य कोई तहसील नहीं है, जिसमें तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार 150 X 150 किलोमीटर की परिधि में आता

(श्री भंवरसिंह)

हो। उक्त क्षेत्र जब उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में था तो विभाग में दो आबंटन अधिकारियों के पद स्वीकृत थे व कोलायत में उपखण्ड अधिकारी का पद भी था। इस प्रकार क्षेत्र में उपखण्ड स्तर के तीन प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत थे। परन्तु उपनिवेशन विभाग का राजस्व में विलय होने के बाद क्षेत्र में एक उपखण्ड अधिकारी रह गया और दो पद आबंटन अधिकारी के समाप्त कर दिए जिससे क्षेत्र के आमजन का कार्य सही व सुचारू नहीं हो रहा है। अतः क्षेत्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि क्षेत्र को देखते हुए व क्षेत्र के आमजन की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बज्जू में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का सृजन नितांत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या के हिसाब से यह दो राजस्व तहसीलों के मानदंड (Norms) पूरे करता है।

अगर राज्य सरकार बज्जू स्थित उप तहसील को पूर्ण राजस्व तहसील का दर्जा देती है तो राज्य सरकार को बज्जू में न तो तहसील हेतु भवन बनाने की न ही उपखण्ड कार्यालय हेतु भवन बनाने व न ही तहसील व उपखण्ड कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु आवासीय कालोनी बनाने की आवश्यकता होगी क्योंकि उपनिवेशन विभाग का तहसील भवन, आबंटन अधिकारी कार्यालय व कार्मिकों की आवासीय कालोनी बनी हुई है और आज दिनांक तक सही स्थिति में है।

इस क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1, 2, 3 का राजस्व में विलय करने से पूर्व उक्त क्षेत्र के आमजन के समस्त प्रकार के कार्य राज्य सरकार के आदेशांक 11(3) उप/2006 पार्ट जयपुर दिनांक 08 जुलाई, 2015 से बंद कर दिये गये थे और इसी आदेश के चलते क्षेत्र के आमजन के कार्य आज दिनांक तक सुचारु रूप से शुरू नहीं हो पाये हैं जिससे क्षेत्र के हर किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्य न होने का दूसरा बड़ा कारण कार्मिकों के पद रिक्त होना है व तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक होना है।

अगर राज्य सरकार उक्त क्षेत्र की उप तहसील बज्जू को क्रमोन्नत कर पूर्ण राजस्व तहसील का दर्जा देती है तो भी राज्य सरकार को किसी भी पद पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। आमजन को राहत भी मिल जाएगी।

अतः इस क्षेत्र की महत्ती आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसी बजट सत्र में बज्जू में नवीन राजस्व तहसील व उप खण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा कर क्षेत्र के आमजन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

मालपुरा की क्षतिग्रस्त टोडारायसिंह-बोट्रून्डा सड़क का निर्माण

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह-बोटून्दा पूर्ण क्षतिग्रस्त रोड को पुन: बनाने के क्रम में।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह शहर का टोडारायसिंह-बोटून्दा रोड़ जो राष्ट्रीय राज मार्ग-12 को देवली होकर सीधा जोड़ता है, विगत 10 वर्षों से यह रोड़ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मार्ग पर रोजाना कई हजार बजरी के ट्रक गुजरते हैं। इस मार्ग के क्षतिगस्त होने से यह शहर रोडवेज सेवा में कोटा झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा आदि जिलों से टूट चुका है। लोगों को आने- जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहां तक कि आस-पास गांवों से प्रसव के लिए आने वाली अधिकांश महिलाओं को प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। आस-पास के गांवों से तत्काल चिकित्सा हेतु मरीजों को लाने-ले जाने वाली एम्बुलेंस सेवा भी इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। इस सड़क के टूटने से कृषक अपना सारा माल देवली की कृषि मण्डी में ले जाते हैं जिससे इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और साथ ही टोडारायसिंह कृषि मण्डी में जिंसों की आवक में कमी आ रही है। मण्डी अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पा रही है। इस सड़क के टूटने से टोड़ारायसिंह शहर के व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूर्ण क्षतिग्रस्त टोडारायसिंह बोटून्दा रोड को अतिशीघ्र नया बनवाने की कृपा करावें, जिससे मेरे क्षेत्र की आम जनता व किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह।

बालोतरा उप खण्ड मुख्यालय को जिले का दर्जा

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियम, 1986 के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बालोतरा उप खण्ड मुख्यालय

(श्री हमीरसिंह भायल)

को जिले का दर्जा दिये जाने की वर्षों से मांग चली आ रही है। सभी मापदण्ड पूरे होने के बावजूद अभी तक जिले का दर्जा नहीं मिला है। 15 जिलों से भी बड़ा है बालोतरा। अब क्षेत्र की जनता को उम्मीद जगी है क्योंकि फैक्ट रिपोर्ट राजस्व विभाग ही भेजता है और राजस्व विभाग वर्तमान में बालोतरा के स्थानीय विधायक व राजस्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर जिला बहुत बड़ा है। दूरी के अनुसार आकलन किया जाए तो जिला मुख्यालय सिवाना के अंतिम गांव की दूरी 180 किलोमीटर तक पड़ जाती है। बाड़मेर जिला देश के कई प्रांतो से बड़ा है जिसका क्षेत्रफल 28 लाख 17 हजार 332 हैक्टेयर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक अमला पूरा ध्यान देना चाहे तो भी असम्भव लगता है। राज्य के कई जिलों का क्षेत्रफल बाड़मेर जिले का 20 प्रतिशत भी नहीं है। बालोतरा जनसंख्या, दूरी, उद्योग सहित हर नजरिये से जिला बनने की होड़ में सबसे आगे है। बाड़मेर जिले की जनसंख्या भी 25 लाख के पार हो गयी है। जिले में 17 पंचायत समितियां और 489 ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान राज्य का औसत देखा जाए तो 1 जिले में 8 पंचायत समितियां एवं 300 ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, पर यहां आंकड़ा औसत से बहुत आगे है। बाड़मेर जिले की अन्तरराष्ट्रीय सीमा 225 किलोमीटर है जिसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। इतना बड़ा जिला होने के कारण सामरिक दृष्टि से इस जिले की सुरक्षा आवश्यक है। दो भागों में विभक्त होने पर प्रशासनिक अमले के साथ सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। बालोतरा को जिला बनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा।

बालोतरा में हर सुविधा उपलब्ध है, रेल, बस, बिजली, पानी चिकित्सा, महाविद्यालय, नगर परिषद, अनेक राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं, जिला एवं सैशन कोर्ट, कृषि उपज मण्डी, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के लगभग सभी कार्यालय के साथ-साथ बालोतरा एवं जसोल बहुत बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं। यहां पर प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट, सोडियम, सेलेनाइट, नमक आदि की खानें भी हैं। राज्य सरकार द्वारा जिला मुख्यालय हेतु 50 बीघा भूमि भी आरक्षित कर रखी है।

जानकारी के अनुसार जिला गठन हेतु बनायी गयी कमेटियां भी कई बार बालोतरा को जिला बनाने हेतु सकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी हैं। जिला मुख्यालय से अधिकतम दूरी होने के कारण हर काम में दुविधा रहती है। अधिकारी बैठकों में भाग लेने जाते हैं तो रात्रि विश्राम मुख्यालय पर ही करना

(श्री हमीरसिंह भायल)

पड़ता है जिसके कारण से पीछे कार्यालय में कार्य प्रभावित होता है। जिस तरह से राज्य सरकार ने जनता को पंचायतों का पुनर्गठन करके एक तोहफा दिया, उसी अनुरूप जनता को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि बालोतरा को जिले का दर्जा देकर जनता को राहत प्रदान करेंगे।

अत: राज्य सरकार से मांग की जाती है कि बालोतरा को जिले का दर्जा दिलाया जाए व उसमें सिवाना, बालोतरा, कल्याणपुर, समदड़ी, सिणधरी एवं पाटोदी पंचायत समितियों का समावेश करके एक नया जिला घोषित करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में सरकारी महाविद्यालय

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने के क्रम में निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र एक पहाड़ी, रेतीला और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है एवं यहां गरीब लोग निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि करना है इसलिए गरीब किसान का बच्चा 12वीं पास करके वंचित रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनावों में शिक्षा जरूरी कर दी है लेकिन शिक्षा का द्वार तो खोला जाए।

सरकारी कालेज बानसूर से अलवर में 60 किलोमीटर दूर है जहां छात्र -छात्राएं जाने में संकोच करते हैं। छात्राओं को इतनी दूर कालेज भेजने में माता - पिता असमर्थ हैं। बानसूर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी बड़ा है। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कुल 49 पंचायतें हैं। बानसूर, रामपुर, हाजीपुर, हमीरपुर, गुताशहपुर, हरसोरा, कराना, नारायणपुरा आदि बड़े कस्बे हैं। 80 -90 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है इसलिए उनके बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें।

यदि आप चाहें तो देवनारायण योजना में करोड़ों का बजट आता है, उसमें से खुलवा दें। सरकार ने बड़े-बड़े शिक्षा के वादे किये थे कि गांव ढाणी तक शिक्षा पहुंचाएंगे। पीपीपी माडल चलाया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि किसी भी तरीके से सरकारी महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें। फिर भी कोई मजबूरी हो तो महिला महाविद्यालय खोल देवें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार। (अनुपस्थित) पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आहौर के जवाई बांध से सिंचित 22 गांवों का सुमेरपुर कृषि मण्डी से जुड़ाव

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा आहौर के 22 गांव, जवाई बांध से सिंचित होते हैं। जवाई बांध सुमेरपुर में पाली जिले में है, लेकिन जवाई नदी 300 किलोमीटर जालौर जिले में बहती है। आहौर विधान सभा के 22 गांव जवाई नहर से सिंचित होते हैं, लगभग 13 हजार 445 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है और 5882 किसान लाभान्वित होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इन किसानों का सारा का सारा माल बिकने को सुमेरपुर मण्डी में जाता है। मंडी अधिकृत नहीं होने के कारण से, यह गांव कृषि मण्डी सुमेरपुर से नहीं जुड़े होने के कारण से किसानों का शोषण होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी असुविधा किसानों को होती है कि कृषि मण्डी से जुड़े नहीं होने के कारण से उनको भण्डारण की सुविधा नहीं मिलती है। अगर किसी किसान को माल नहीं बेचना होता है तो वहां भण्डारण की सुविधा नहीं मिलती है और उसे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, उचित मूल्य पर जब सरकार क्रय करती है तो मण्डी से नहीं जुड़े होने के कारण से अनआफिशियली माल तो सारा जाता है लेकिन मण्डी से नहीं जुड़े होने के कारण से किसान का शोषण होता है। जैसे पिछले दो वर्ष पहले चने की खेती जबरदस्त हुई लेकिन वहां बिचौलियों ने इन किसानों का शोषण किया। माल तो गया सुमेरपुर मण्डी में, लेकिन दो नम्बर रास्ते से गया। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इन किसानों की दुविधा को देखकर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से बहुत करबद्ध निवेदन करूंगा, 5882 किसानों का सवाल है, यह गरीब परिवारों का सवाल है। मंत्री महोदय, ये इतनी दुविधा में जीते हैं कि वहां पर उनको रहने की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। वहां पर सौतेला व्यवहार मेरे किसानों के साथ होता है। माल तो जाता है, लेकिन उस मण्डी से जुड़े नहीं होने के कारण से सौतेला व्यवहार होता है। इसलिये मेरे किसानों की ओर से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

कि मेरे इन 22 गांवों को सुमेरपुर मण्डी से जोड़ें ताकि, जो मण्डी टैक्स उनसे लिया जाता है, उसके एवज में उनके विकास कार्य को भी वे प्राप्त कर सकें। इन 22 गांवों की काफी समय से मांग चलती आ रही है, पहले भी आपने बहुत ही पाजिटिव लिया था कि इसके लिये हम जांच कराएंगे। अब जांच हो गयी होगी, यह मैं मानता हूं, इसलिये आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, मेरे किसानों की इस समस्या का निराकरण करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न को इंगित किया है, वास्तव में इसका पूरा परीक्षण कराया है और यह बात सही है कि जवाई कमाण्ड क्षेत्र में आने वाली 12 ग्राम पंचायतें पावटा, डोडियाली, उम्मेदपुर, हरजी, थांवला, चांदराई, पादरली, रोडला, कवरडा, भूती, कवला और सेदरिया है। अभी निश्चित रूप से जालौर कृषि उपज मण्डी के सब-यार्ड आहोर के माध्यम से इन ग्राम पंचायतों का क्रय-विक्रय का काम किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसानों को 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर अपनी जिंस को बेचना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा इसका प्रशासनिक निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 3 की कार्यवाही करके, एक महीने का नोटिफिकेशन करके इसकी आपत्तियां मांगी गयी हैं। वह समय पूरा हो चुका है। मैं आज सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, धारा 3 के बाद अंतिम अधिसूचना धारा 4 और 5 की शीघ्र जारी करके उन किसानों को राहत पहुंचायी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर-सीकर फोर-लेन सड़क पर त्रुटियों की भरमार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं, विषय अत्यन्त ही गम्भीर है। एक तरफ राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग राजस्थान पत्रिका के साथ मिलकर 'आइये जीवन बचाएं' अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से सीकर के मध्य जो फोर-लेन सड़क बनी है, उस फोर-लेन सड़क के अन्दर तकनीकी रूप से इतनी खामियां छोड़ी गयी हैं कि वह फोर-लेन आज मौत का फोर-लेन

(श्री रामलाल शर्मा)

बना हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 बिन्दुओं का मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा।

राधास्वामी बाग़ के ऊपर ओवरब्रिज बनना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं शहर से निकलने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोक कर पहले जयपुर की ओर देखेगा कि कोई साधन तो नहीं आ रहा, फिर डिवाइडर के बीच में खड़ा होगा, फिर सीकर की तरफ देखेगा, कोई साधन तो नहीं आ रहा, फिर उसके बाद वह हाई-वे के ऊपर चढ़ने का काम करता है। एन.एच.ए.आई. ने जहां पर ओवरब्रिज बनने चाहिए, वहां ओवरब्रिज नहीं बनाये। जहां अण्डर-पास बनने चाहिए, वहां अण्डर-पास नहीं बनाये। जहां सर्विस लेन बननी चाहिए, वहां सर्विस लेन नहीं बनायी।

एक तातेड़ा मोड़ है, उस तातेड़ा मोड़ के ऊपर जो डिवाइडर बनाया, तातेड़ा मोड़ से जो सम्पर्क सड़क निकलकर जाती है, सिंगोद और वाया खेजड़ोली होते हुए गुजरती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, कई बार रिलायंस कम्पनी और एन.एच.ए.आई. अधिकारियों को हमने व्यक्तिगत निवेदन किया कि आपने जो डिवाइडर बनाया, वह बहुत ही गलत डिवाइडर है। इस डिवाइडर के ऊपर रात को जो साधन आते हैं, वह डिवाइडर नहीं दिखने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 दुर्घटनाएं हुईं और 19 दुर्घटनाओं के अन्दर 8 लोगों की मौत हुई। जबरदस्ती हमने प्रैशर करके, आर.टी.ओ. के वी.पी. सिंहजी गये, डीवाई.एस.पी. मौके पर गये, एस.डी.एम. मौके पर गये, डी.टी.ओ., चौमूं मौके पर गयीं और जबरदस्ती उस डिवाइडर को हटाया। हमने कहा कि एक बार इस डिवाइडर को हटा कर देखो। बार-बार कहने के बावजूद भी वे यह कहते रहे कि नहीं, हमारे प्लान में यही है। हमारा जो नक्शा एप्रूव होकर आया, वह यही है। हम इस डिवाइडर को छोटा नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छह महीने हो गये उस डिवाइडर को छोटा किये हुए, छह महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई।

इसी तरीके से उदयपुरिया मोड़ के ऊपर भी आपको भी पता है कि खेजड़ोली जाने के बहुत अधिक साधन उस मार्ग से निकलते हैं। खेजड़ोली की तरफ टर्न लेने वाला व्यक्ति पहले सीकर की ओर देखेगा, देखकर वह राइट हैण्ड की तरफ टर्न लेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, आज जैतपुरा के अन्दर ओवरब्रिज नहीं है, राधास्वामी बाग़ के अन्दर ओवरब्रिज नहीं

(श्री रामलाल शर्मा)

है, हाड़ौता के अन्दर ओवरब्रिज नहीं है, उदयपुरिया मोड़ के ऊपर ओवरब्रिज नहीं है। जहां ओवरब्रिज बनने चाहिए, वहां ओवरब्रिज नहीं बनाये। जहां ओवर-ब्रिज की आवश्यकता नहीं थी, उस जगह ओवरब्रिज बनाने का काम एन.एच.ए.आई. ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से यह मांग करुंगा कि यह जो फोर-लेन सड़क बनी है, जो वर्तमान के अन्दर एक मौत का फोर-लेन है, दुबारा तकनीकी दृष्टि से इसका सर्वे कराएं। जहां पर आवश्यकता है, आज गोविन्दगढ़ के बस स्टैण्ड की स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां इन्होंने बस स्टैण्ड ही डवलप नहीं किया। पूरे गोविन्दगढ़ की जनता पुलिया के ऊपर चढ़ कर साधनों का इन्तजार करती है। सीकर की तरफ से जो बस आए, वह पुलिया के ऊपर रुकती है। कभी भी बड़ा हादसा उस स्थान के ऊपर हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि यह जो मौत का फोर-लेन बना है, इस मौत के फोर-लेन की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सरकार जांच कराए। जहां आवश्यकता ओवरब्रिज की है, जहां आवश्यकता सर्विस-लेन की है, जहां आवश्यकता अण्डर-पास की है, वहां उनका निर्माण कराया जाए।

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा। एन.एच.ए.आई. के द्वारा फोर-लेन सड़क बनी है, उसके बाद में जिन किसानों के खेत और मकान हैं, उन खेतों के ऊपर जाने का रास्ता भी ये नहीं देते। ये कहते हैं कि यह तो हमारी जमीन है, इसके अन्दर से आपको रास्ता नहीं देंगे। कई लोगों के कच्चे रास्ते अपने मकान में जाने के रास्ते थे, या अपने खेत में जाने के रास्ते थे, जे.सी.बी. लगाकर उन रास्तों को अवरुद्ध करने का काम एन.एच.ए.आई. के लोग करते हैं। जबरदस्ती चौथ वसूली का काम भी एन.एच.ए.आई. के कर्मचारी करते हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि या तो वे सर्विस लेन बनाएं ताकि किसान अपने खेतों में जा सकें, मकानों में जा सकें। यदि सर्विस लेन नहीं बनती है तो किसान अपने खेत और मकान में जाने का जो कच्चा रास्ता बनाता है, उस रास्ते के अन्दर कोई रुकावट पैदा नहीं करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, आप भी उसी रास्ते से आते हैं, कई बार आपके सामने भी दुर्घटनाएं होती हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस गम्भीर विषय के ऊपर अपना जवाब भी दे और आने वाले समय के अन्दर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इन सारी तकनीकियों को दुरुस्त करने का काम करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस सड़क का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, यह एन.एच.ए.आई. की है। 14.10.2009 को इस सड़क की स्वीकृति जारी हुई थी। 19.02.2010 को एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के अनुसार सड़क का निर्माण हो रहा है। माननीय सदस्य ने जैतपुरा ओवरब्रिज, तातेड़ा मोड़ के डिवाइडर, उदयपुरिया मोड़ के ओवरिब्रज के बारे में जो सवाल खड़े किये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 495 करोड़ की स्वीकृति है और 95 किलोमीटर की सड़क है। फिर भी माननीय मंत्री महोदय मुझे कहकर गये कि मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत करा दूं कि इसके लिये एक उच्चस्तरीय तकनीकी कमेटी बनाकर जहां-जहां कमी-खामी रही है, एन.एच.ए.आई. के लोगों से बात करके उस कमी-खामी को दूर करेंगे। जो एग्रीमेंट हुआ है मूल रूप से, उसका अध्ययन करेंगे। एग्रीमेंट के अनुसार जो-जो सर्विस लेन का, डिवाइडर का निर्माण होना चाहिए, उसको देखेंगे। आपने कहा, कुछ चौथ-वसूली हो रही है टोल रोड के नाम पर, उसके बारे में भी निश्चित तौर पर पूरी जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

बगरू का बीसलपुर पेयजल योजना से जुड़ाव

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में मेरे को बोलने का मौका मिला, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम के सात वार्ड 45 से 51 हैं, एक नगरपालिका बगरू और एक पंचायत समिति सांगानेर की 30 ग्राम पंचायतें विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आती हैं।

2003 से 2008 तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सम्माननीय वसुन्धराजी की सरकार थी। उन्होंने पानी की योजना को अंजाम देते हुए कि पानी की योजना का फायदा बगरू विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को मिले, प्रत्येक ग्राम-ढाणी को मिले, प्रत्येक कस्बे को मिले, उन्होंने इस योजना का, इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रभाव दिखाते हुए, इस विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों को और नगर निगम के एरिये को, पालिका के एरिये को जोड़ने का एलान किया था। मगर पूर्ववर्ती सरकार ने इस एरिये के अन्दर इस विधान सभा क्षेत्र के गांवों को नहीं जोड़ा। पाइप लाइन जिसकी मुख्य धारा डिग्गी रोड, बालाबाला से होती हुई बगरू विधान सभा क्षेत्र

(श्री कैलाश वर्मा)

के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती हुई, गांवों से निकलती है, पालिका से निकलती है और जिसका पानी दूदू, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर तक गया, उस योजना का फायदा विधान सभा क्षेत्र को मिलना था, नहीं मिला।

मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्रीजी से यह विनम्र आग्रह है कि वाकई में योजना का फायदा जिन गांवों को मिलना चाहिए, जिस पालिका को मिलना चाहिए, जिस विधान सभा क्षेत्र को मिलना चाहिए, बीसलपुर की योजना में राजस्व के 144 गांव हैं जिनकी जलाशय की कुल भराव क्षमता 5960 किलोलीटर है। साथ ही शहरी पेयजल योजना में नगरपालिका बगरू के सभी जलाशयों की कुल भराव क्षमता 2890 किलोलीटर है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की कुल भराव क्षमता 11 एम.एल.डी. है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र में 10 एम.एल.डी. पेयजल की आवश्यकता है जो विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान स्रोतों से सम्भव नहीं है। पूरा एरिया फ्लोराइड से युक्त है। सम्माननीय मंत्रीजी का विधान सभा क्षेत्र के कलवाड़ा ग्राम पंचायत के अन्दर दौरा हुआ था, मंत्रीजी गये थे। हमारे प्रभारी मंत्री सम्माननीय कालीचरणजी भी पूरे विधान सभा क्षेत्र का विजिट कर चुके हैं। सरकार की प्रभावशाली योजनाएं यहां हैं, उद्योग से सम्बन्धित जे.सी.पी. है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विश्वविद्यालय मणिपाल यूनिवर्सिटी है, शूटिंग रेंज और स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) इस बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्थित हैं, पर बगरू विधान सभा क्षेत्र को अब तक जो योजना थी, उसके तहत बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया।

मेरा सम्माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया की जब चुनाव की बड़ी सभा बगरू के अन्दर हुई थी, उस सभा के अन्दर सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बगरू विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के 120 ग्राम और बगरू पालिका के गांवों को बीसलपुर से जोड़ने की घोषणा की थी। उसके बाद में मैं सम्माननीय मंत्रीजी से भी मिला हूं और उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है।

आज पर्ची के माध्यम से मेरे को इस विषय में बोलने का मौका मिला, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारी अभी बजट की प्रक्रिया चल रही है, इसी प्रक्रिया के अन्दर इस महत्वाकांक्षी योजना को जोड़कर बगरू विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को इस योजना का फायदा दिलाएं। मेरा निवेदन है कि इस योजना के लिए पूरा स्ट्रक्चर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खड़ा है, पाइप लाइंस जगह-जगह ग्राम पंचायतों के अन्दर डली हुई हैं, टंकियां

(श्री कैलाश वर्मा)

ग्राम पंचायतों के अन्दर बनी हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक हैडक्वार्टर के ऊपर एक बीसलपुर का पाइप दे दें जिससे पानी की टंकियों के अन्दर पानी चला जाए। इसकी एक पाइप लाइन बालाबाला होती हुई मुहाना मंडी से सेज (स्पेशल इकोनोमिक जोन) के अन्दर जा रही है। वह पूरी पाइप लाइन 15 एम.एल.डी. के लिए डिजाइन की हुई है किन्तु उसमें फिलहाल 3 एम.एल.डी. पानी अभी जा रहा है। इसी पाइप लाइन के अनुसार आने वाले समय के अन्दर सेज की जो पापुलेशन होगी, वह 2025 या 2030 तक प्रस्तावित है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस 15 एम.एल.डी. पाइप लाइन से ही पानी की सुचारु व्यवस्था हो सकती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द इस योजना को जोड़कर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा दिलाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से हमारे बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है। यह उनकी जो पीड़ा है, यह बहुत ही मैं मानूंगी कि वाजिब है, इसलिए कि वहां पर क्वालिटी प्राब्लम तो है पानी की। यह क्वालिटी प्राब्लम अभी कुछ समय में ही ज्यादा हुई है, पहले इतनी थी नहीं जब यह योजना बनी थी। बीसलपुर बांध से 16.2 टी.एम.सी. पेयजल के लिए जो आरक्षण किया हुआ है, उसमें से 11.1 टी.एम.सी. जयपुर के लिए पानी आरक्षित किया गया है और वह जो आरक्षित किया हुआ है, उसमें दो योजनाएं हमने स्वीकृत की हैं। उसमें एक जयपुर शहर है और दूसरा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बीसलपुर-दूदू योजना घोषित हुई। योजना में हमने अभी जो तहसीलें ली हुई हैं उसमें दूदू, फागी, चाकसू, बस्सी और फुलेरा, ये तहसीलें सम्मिलित हैं जिनके अन्दर काम भी चल रहा है और काफी कुछ अब तक सारा चल रहा है।

इनका बगरू और सांगानेर, ये दो जो हैं, इनका ग्राउंड वाटर पहले ठीक था, जब यह योजनाएं बनी थीं, तब तो लेने की जरूरत पता नहीं, उस समय क्या महसूस हुई या नहीं हुई, लेकिन तब सिर्फ ये छह ली थीं और अब जो डिमांड आ रही है, वह बगरू की आ रही है, सांगानेर की आ रही है। दोनों जगहों की यह डिमांड आ रही है कि ग्राउंड वाटर दिन-प्रति दिन इतना ज्यादा गिरता जा रहा है, क्वालिटी इतनी खराब हो गयी कि इनको भी बीसलपुर के पानी से जोड़ना चाहिए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सवाल इसका है कि बीसलपुर के अन्दर जो अवेबिलिटी आफ वाटर है, वही कम है। इनको और अभी नया जोड़ना है तो उसके बारे में हम लोगों को फिर से री-प्लान करना होगा कि किस तरीके से हम इसमें जोड़ें। जैसे मेन ट्रांसमिशन लाइन। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर आलरेडी सेज की जो लाइन आयी हुई है, उसी सेज की लाइन से ही हम लोग अपना ले लें, पाइप सब बिछे हुए हैं, गांव के अन्दर। लेकिन यह प्रैक्टिकली इसलिए पांसिबल नहीं है कि बीसलपुर का पानी जो लाना है, उसका अभी जो योजना बनी हुई है, वह जो छह तहसीलों के लिए बनी हुई है, उसी के हिसाब से डिजाइन किये हुए पाइप्स हैं। उसी के हिसाब से ही वह पाइप्स डिजाइन किये हैं, वह कैपेसिटी उसी हिसाब से डिजाइन की है। अब अगर हमें और भी तहसीलों को उसमें जोड़ना है तो री-डिजाइन करना होगा, फिर से मेन-ट्रांसमिशन। उसके लिए पूरा प्रोपर हमने इसका डी.पी.आर. भी बनाना शुरू कर दिया है तो वह डी.पी.आर. बन जाता है क्योंकि, यह जो डिजाइन है वह 2021 तक के लिए ही है। इसलिए हमें अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, उसके अन्दर कुछ भी डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसी से हम नए एरियाज को जोड़ दें। जो नए एरियाज हैं, जो वंचित हैं, बीसलपुर के पानी से जयपुर ग्रामीण के, उनको जोड़ना हमारी भावी योजना में है। उसके लिए डी.पी.आर. हमारे बन रहे हैं। सेज की जो उन्होंने पाइप लाइन ले की है, वह उन्होंने टोटली उनके डिपोजिट वर्क्स से ही ले की है। तो उसमें से हम कुछ पानी ले लें, वह पांसिबल नहीं है कि उस लाइन को हम लोग यूज कर लें, वह टोटली डेडिकेटेड टू सेज ही है इसलिए वह उन्हीं के लिए होगा। जो जयपुर की शेष आठ तहसीलें हैं, उनके लिए हमने बीसलपुर बांध से 6.9 टी.एम.सी. की और मांग की थी पेयजल के लिए आरक्षित करने के लिए हमने उन्हें निवेदन किया था और एक सैद्धांतिक सहमति भी हमें जल संसाधन विभाग के द्वारा 13.01.2015 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अन्दर उन्होंने यह और पानी आरक्षित करने के लिए हमें सहमति दे दी है, जो 6.9 टी.एम.सी. है। अब इसके ऊपर योजना के लिए हमने डी.पी.आर. शुरू कर दी है और डी.पी.आर. जैसे ही बनकर आता है उसके बाद में बजट की अवेबिलिटी के अनुसार हम लोग इसके अन्दर सैंक्शन करेंगे, यह मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर के मदरसों में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक घटना हुई है वहां के एक मदरसे में, वह घटना भयावह है। आई.एस.आई.एस. आतंकवादियों से भी बुरा हाल छोटे बच्चों का है। वहां पर पढ़ने वाले छोटे बच्चों को मदरसे में बेड़ियां बांध कर, जानवरों वाली बेड़ियां और जानवरों वाली बेड़ियां ही नहीं, हथकड़ियां लगाकर बच्चों को बांध कर रखा गया। वे बच्चे, निरीह बच्चे, मासूम बच्चे उस मदरसे से कैसे भी बचकर नमाज के समय निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गये।

(13.00 बजे)

वहां जनता ने इसका कारण पूछा तो बच्चे रोने लग गये। जनता ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाकर उन बच्चों को पुलिस के सुपुर्द किया। मेरे क्षेत्र रामगढ़ थाने में पुलिस ने पूरी इंक्वायरी की, बच्चों का पिता यह कहता है कि खुद मौलवी साहब ने बच्चों को बेडियों से और हथकड़ियों से बांधा और मौलवी साहब कहते हैं कि बच्चों के पिता ने बांधा। अब सच क्या है, वह तो पुलिस की इंक्वायरी होगी। पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे रामगढ़ के एस.एच.ओ. को धन्यवाद दूंगा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने उचित कार्यवाही की और मौलवी साहब को बंद किया। सिर्फ बंद ही नहीं किया, बल्कि जे.सी. भी हो गयी।

ये मदरसों में बेड़ियों से बांधकर रखे गये मासूमों के फोटो हैं-अख़बार के भी फोटो हैं और यह फोटो कापी है। मदरसों में बेड़ियों से बांधकर रखे मासूम, मदरसों में बच्चों को बेड़ियों से जकड़कर रखा था, भागकर पुलिस तक पहुंचे, रामगढ़ की घटना है। यह स्थिति मदरसों की है।

अब मदरसों की पैरवी करने वाले लोग कहते हैं, मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूं और मैं अल्पसंख्यकों के भी खिलाफ नहीं हूं, परन्तु आश्चर्य है कि आज इक्कीसवीं शताब्दी में छोटे, मासूम और निरीह बच्चों को इस ढंग से हथकड़ियों और बेड़ियों से बांधकर रखा जाए, उन बच्चों पर इतना बड़ा अत्याचार किया जाए और बच्चे कैसे भी जान बचाकर वहां से निकले। मैंने पहले निवेदन किया है कि मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूं। वहां तालीम होती हो, शिक्षा होती हो, दीन की हो चाहे हीन की हो, लेकिन होती हो, कोई दिक्कत नहीं है। परन्तु पूरे प्रान्त में और विशेषकर मेवात में, मैं मेवात क्षेत्र का रामगढ़ से विधायक हूं, विशेष रूप से मेवात में अनरजिस्टर्ड मदरसे ज्यादा हैं, रजिस्टर्ड मदरसे कम हैं। 90 प्रतिशत अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान दें। मैं सदन का और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चाहता हूं जो मदरसे बने हैं, वह अवैध रूप से बने हैं, वे मंदिर माफी की जमीनों पर हैं, वे चरागाह की जमीनों पर है, वे सवाई चक जमीनों पर हैं। अब उनको हमारी सरकार वहां पैरा-टीचर्स लगाकर वैध रूप से कम्प्यूटर भी दे रही है और पैरा-टीचर्स का पेमेंट भी दे रही है जो अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके बनाये हुए हैं, मंदिर माफी की जमीन, सवाई चक और चरागाह की जमीन पर बने हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना भी ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं कि वहां एजूकेशन के किताबों की जांच मंत्री महोदय करवाएं। इतना ही नहीं, वहां जो मौलाना हैं, वहां जो मौलवी हैं, वहां जो इमाम हैं, वह ज्यादातर बिहार, यूपी और बंगाल के हैं। वे वहां क्या कर रहे हैं? और पाकिस्तान तक में तो मदरसों पर प्रतिबन्ध लग गया, लेकिन यहां उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं और वहां प्रतिबन्ध लग गया और वहां पता लगाया तो मदरसों के अंडरग्राउण्ड में बहुत सारे हथियार, बहुत बड़ा अंश एम्बूनीशन और वैपन का है। यह पाकिस्तान तक में बैन लग गया तो यहां बैन करने के लिये निवेदन नहीं कर रहा, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि इन मदरसों की जांच की जाए कि वहां तालीम की कौनसी किताबें हैं। वहां का पता किया जाए, वे किस जमीन पर बसे हैं। अगर अनरजिस्टर्ड है और गलत जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है तो वहां से सरकारी पैरा-टीचर्स हटाये जाएं, वहां से कम्प्यूटर हटाए जाएं। सरकार की ओर से उनको कोई मदद नहीं हो। नहीं तो छोटे बच्चों को बेड़ियों में बांधकर और हथकड़ियां लगाकर पढ़ाने के लिये जो कार्यवाही है, अब हालांकि इसकी जांच बिठाई गयी है। अल्पसंख्यक अधिकारी हैं मि. माथुर, वे वहां गये, उन्होंने पता लगाया। उन मदरसों ने कहा कि हमारे पास 226 बच्चे हैं, लेकिन वहां मिले 280 बच्चे। अब क्या हो रहा है यह? हमारी सरकार रहते हुए?

माननीय मंत्री महोदय श्री अरुणजी चतुर्वेदी बहुत जागरूक मंत्री हैं, इस सम्बन्ध में मैंने जो चार-पांच मुद्दे उठाये हैं, मैं संक्षेप में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी पूरी जांच करें। अवैध रूप से बसे हुए, बसाये गये मदरसे हैं, अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। साथ ही बच्चों की संख्या 226 रिकार्ड में है और मिलते हैं वहां 280। तो ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर पूरी कार्यवाही की जाए, कानूनी कार्यवाही की जाए। कानूनी कार्यवाही के लिये मैं सदन से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे और मंत्री महोदय से अपेक्षा रखता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का मुझे भी समय मिल जाए, मेवात क्षेत्र से मैं भी आती हूं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और आज भी मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर में भी नगर, पहाड़ी, कामां के अन्दर बहुत सारे अनरजिस्टर्ड मदरसों के नाम पर अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उसके ऊपर मदरसे बना लेते हैं। उसके बाद उनको कोई कुछ कहने वाला, सुनने वाला नहीं होता है और इस तरीके से कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। उनका यही पता नहीं है। कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन के नाम पर मदरसे तो चला रखे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय जब अपना जवाब दें तो इस बारे में जरूर कहें कि जो अन-रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर सकती है, अगर वह गलत तरीके से मदरसों को चला रहे हैं तो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया है, यह सही है कि 26 तारीख को रामगढ़ में एक मदरसा चलता है, उस मदरसे में दो बच्चे, वहां के मौलवी ने उनको बेड़ियों से बांधकर, उनके पिता ने कहा कि बार-बार भाग जाते हैं तो बेड़ियां बांधकर उनको रखा। वहां बेड़ी तो थी, लेकिन और किसी से बांधा हुआ नहीं था, खिड़की से कूदकर भाग गये लोगों ने उनको पैर में बेड़ी थी, इस कारण पकड़ा और बाद में पुलिस के सुपुर्द किया। गम्भीर घटना है।

जैसे ही अगले दिन 27 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से खबर की जानकारी हुई, तुरन्त ही यहां पर हमारे द्वारा एक कमेटी बनायी गयी। हमारे एडिशनल डायरेक्टर, वहां के एडीएम और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, तीनों की कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है। उन्होंने बाकी सब चीजों के साथ-साथ इस बात को माना है कि वहां पिता के कहने के बाद मौलवी के द्वारा बेड़ियां बांधी गयीं। दोनों में अन्तर है। हमारी जांच रिपोर्ट कहती है कि पिता ने बेड़ी बांधी और पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि मौलवी ने पिता के कहने पर बांधी। इस पर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी एफ.आई.आर. हुई है। गिरफ्तार करने के बाद वह बेल पर रिलीज हुआ है।

ऐसी घटना न हो, इसी तरह की चीजों के बारे में निर्देश जारी करेंगे।

दूसरा, माननीय सदस्य ने सरकारी जमीनों के ऊपर मदरसों की बात की है। हमने जो नई गाइडलाइन निकाली है, उसमें तो टाइटल देना पड़ेगा।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)
पहले शिक्षा विभाग के द्वारा मदरसे चलते थे। उस समय 2010 में गाइड लाइन अलग थी। अब 2013-14 में जो गाइडलाइन निकली है, उसमें उसका टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल के बाद ही रजिस्टर्ड मदरसा बन सकता है। रजिस्टर्ड मदरसा जब तक टाइटल नहीं है, बन ही नहीं सकता।

फिर भी आपने बात कही है कि कुछ अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जे के आधार पर चल रहे हैं। वैसे तो इनके ऊपर कार्यवाही करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, नगरपालिका या पंचायत के द्वारा करने का है, कोई भी कब्जे किसी के हैं। फिर भी मैं एक बार सारी जानकारी मंगवा लेता हूं और आप लोगों के पास भी कोई जानकारी हो तो मुझे दें कि कौन-कौनसी सरकारी जमीनों के ऊपर मदरसे चल रहे हैं। उनको करेक्ट करने के बाद सम्बन्धित एजेन्सीज के पास भेजेंगे, जो यह देखेगी कि वे सरकारी जमीन के ऊपर हैं या किसी और जमीन के ऊपर कब्जा करके मदरसे बने हैं। तो उनके ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित हो, सम्बन्धित विभागों के पास भिजवा देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विषय पुलिस से भी जुड़ गया, क्योंकि पुलिस ने इस पर 115/16 मुकद्मा रामगढ़ में दर्ज किया और इसकी तहकीकात की। यह जो आपका मदरसा है, यह 2013 में आपके यहां मदरसा बोर्ड के द्वारा अधिकृत है और इसमें 11 अध्यापक लगे हुए हैं। यह जो मौलवी है यह 6-7 महीने पहले ही, बाड़मेर का रहने वाला है और यहां इस मदरसे बोर्ड में उर्दू सिखाने के नाम से रह रहा है।

जिस प्रकार से गतिविधियां हैं, यह तो फिर भी आपके मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो मदरसा बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, आप अपने विभाग से भी करें और मैं पुलिस को भी, जितने भी मदरसे हैं, उनकी एक्टिविटिज भी, उनमें पढ़ाने वाले अध्यापक भी और उनके सारे रेफरेंस भी, वे कहां से आये हैं और कहां से पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसमें मैं भी एड कर देता हूं साथ में। निश्चित रूप से जितनी सूचनाएं जैसी आयी हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय ने बतायी हैं, एफ.आई.आर. के बाद आपके वहां ऐसी कोई भी कार्यवाही होगी तो हम निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी मदरसे हैं, जमीनों पर टाइटल की बात देखेंगे- अगर अन-रजिस्टर्ड हैं उसमें भी कौन-कौन हैं, किसके माध्यम से चलते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी आ जाए कि कोई किसी का क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है, जहां से आया है, वहां तो

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

क्रिमिनल रिकार्ड तो नहीं है। इन सब चीजों की जानकारी हम अपने-अपने सोर्स से लेंगे, बाकी हम गृह विभाग से भी अपेक्षा करेंगे कि उनकी जो भी सूचनाएं मिलती हैं, वे मिलें, इससे आगे की कार्यवाही, ऐसे कोई भी मदरसे हैं तो उनको डीरजिस्टर करने की कार्यवाही भी हम करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दोनों मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डोटासराजी, आपका पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। पर इन्फार्मेशन इन्फार्मेशन तक ही सीमित रहे।

सूचना

झालावाड़ में जवाबदेही यात्रा पर हमले को लेकर विधान सभा के बाहर धरना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अक्षरश: पालना होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से कि कुछ दिन पहले झालावाड़ में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे के द्वारा जवाबदेही यात्रा शुरू की गयी थी, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, पेंशन, शिक्षा, राशन, स्वास्थ्य, इनके बारे में थी।

श्री उपाध्यक्ष: आज क्या हुआ, उसका बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज वहां पर जवाबदेही यात्रा पर हमला हुआ था और उसमें हमारे एक विधायक भी शामिल थे, लेकिन उन पर एफ आई आर होने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। आज सामाजिक संगठन, अरुणा राय, निखिल डे और पूरे राजस्थान के लोग यहां पर विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। मैं समझता हूं उनके खिलाफ माननीय मुख्य मंत्रीजी को, आगे बढ़कर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष का विधायक लाठी लेकर

श्री उपाध्यक्ष: आज उनके साथ कुछ हुआ है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज वो धरने पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: The point of information is on happening of today, in the last one hour or two hours, or after the house was adjourned.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, वो ही कर रहा हूं, सर।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वो धरने पर बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है इसलिए मैं इसके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि वो लोग धरने पर बैठे हैं। सरकार से कार्यवाही तो करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं। No. This Government is aware of that.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का प्रथम (वर्ष 2013-14) एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह वार्षिक प्रतिवेदन 2013...

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराज जाएं।

आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर आ रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं वो ही प्रश्न उठा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि 2014-15 का पेश करते, उसकी जगह आपने 2013-14 का पेश किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले एक बार निर्देश जारी कर दिये गये थे। एक बार पूर्व में निर्देश जारी कर दिये गये थे, यह विलम्ब क्यों हुआ है इसमें ...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): और माननीय गृह मंत्रीजी ने भी एक प्रतिवेदन 2013-14 का पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें। He is explaining. Probably instructions have already been given.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन से पूर्व में भी हमें निर्देश दे दिये गये थे। पिछली बार भी जब सदन के अन्दर इस प्रकार के वार्षिक प्रतिवेदन में विलम्ब हुआ तो हमने कारण बताओ नोटिस भी सब को जारी किया था। इस सन्दर्भ में भी, उपाध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी लेकर और उनका एक्सप्लेनेशन लेकर हम आसन को प्रस्तुत कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आउटपुट बजट वर्ष 2014-15 व आउटकम बजट वर्ष 2015-16 राजस्थान नगरीय पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आउटपुट बजट वर्ष 2014-15 एवं आउटकम बजट वर्ष 2015-16, तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरालाल नागर। (अनुपस्थित)। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

याचिका

रामगंजमण्डी की पंचायतों में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों पर भर्ती

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की पंचायतों में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को भरने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबू सिंह। (अनुपस्थित)। श्री सुखराम विश्नोई। (अनुपस्थित)। डा. मंजू बाघमार। (अनुपस्थित)। What's all this! श्री संदीप शर्मा। (अनुपस्थित) श्री ओमप्रकाश। (अनुपस्थित)। श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई में कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

जयपुर के सिद्धार्थ नगर में खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक केन्द्र हेतु भू-आबंटन

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार जयपुर के वार्ड संख्या-45 के सिद्धार्थ नगर-एच ब्लाक में सुविधा क्षेत्र के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि आबंटन करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्पूर्ण सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही का यह एक अभिन्न हिस्सा है। जिन्होंने याचिका उपस्थापन करने का आग्रह आसन को किया और वो सदन में उपस्थित नहीं हैं, आसन इस पर कड़ा रवैया अख्तियार करेगा। यह पहली बार ऐसा अवसर आया है, आसन आपको वार्न करता है। अगली फिर कार्यवाही नियमानुसार होगी।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । श्री रामहेत सिंह यादव।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-17 के बजट पर विचार रखने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे ने सब जन विकास, सब जन उत्थान के मूल मंत्र की परिकल्पना को ध्यान में रखकर राजस्थान की जनता के हित में जो बजट पेश किया है वो गांव के गरीब को समर्पित है, सेना के नौजवान को समर्पित है, बेरोजगार नौजवान को समर्पित है। रिसर्जेंट के माध्यम से राजस्थान ऊंचाई छुएगा, आने वाले समय में सम्पूर्ण वर्ग का ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं हृदय से आभारी हूं।

जिस तरह से पांच साल का कांग्रेस का राज रहा, बजट में जो बातें कहीं, उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। जहां बजट की आवश्यकता थी, उसका ध्यान नहीं कर सारे बजट को वोट आधारित बजट बना दिया गया। बजट में जो प्रोविजन किये, आखिर के बजट में बंदरबांट हुई। पेंशन योजना, दवा योजना, कांग्रेस की राज में बहुत-सी योजनाओं को घोषित किया। उसका परिणाम राजस्थान की जनता ने देखा। उसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिला। यही कारण है कि कांग्रेस के दो दर्जन विधायक भी यहां जीत कर वापस नहीं आये। लोक लुभावनी बात करके जनता को ज्यादा समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता।

माननीय वसुन्धरा राजे ने राजस्थान के नौजवान के हित में बजट रखा है कि राजस्थान में किस तरह से उद्योगपति आए, यहां पर अपना उद्योग स्थापित करे ताकि राजस्थान का नौजवान जो बेरोजगार है उसकी आवश्यकता है, उसको रोजगार मिले। इन सब बातों को ध्यान रखकर बजट में व्यवस्था रखी है।

मैं शिक्षा के मामले में बताना चाहता हूं। हम राजनीति में वर्षों से काम करते हैं, किसी गांव में जाते थे, सबसे पहले कहते थे, साहब, हमारा मिडिल स्कूल है इसमें हैडमास्टर नहीं है। कहते थे, यह मिडिल का भी हैडमास्टर नहीं था, अब यह सैकण्डरी हो गया, इसमें हैडमास्टर नहीं है। सीनियर स्कूल हो जाता था तब तक प्रिंसिपल नहीं लगता था। माननीय वसुन्धराजी को मैं इसके

(श्री रामहेत सिंह यादव)

माध्यम से बधाई देता हूं कि राजस्थान में ग्रामीण जन को भी, झोंपड़ी में बैठे बालक को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था की। यही नहीं, गांव का बालक गांव में अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए एक साथ बजट में पिछली बार 5500 स्कूल खोले। स्कूल ही नहीं खोले, उनमें प्रिंसिपल लगाने की भी जिम्मेदारी ली। उसमें 772 स्कूल ऐसे जिनको आदर्श स्कूल घोषित किया और शिक्षा की सारी व्यवस्था करने का जो सपना था, उसको मूर्त रूप देने का काम किया।

वर्षों से शिक्षा जगत के लोगों में निराशा का भाव था। थर्ड ग्रेड का अध्यापक चाहे वो पीएचडी कर ले, थर्ड ग्रेड से ही रिटायर हो जाता था। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को भी इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं कि जिस काम को वर्षों तक नहीं कर पाये थे, सारी डी.पी.सी. एक साथ करा कर 56 हजार शिक्षा जगत जुड़े हुए शिक्षकों का प्रमोशन करके राजस्थान में नया इतिहास बनाने का काम किया है।

यही देखकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शिक्षा को महत्त्व देते हुए इस बजट में 23177 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो गत वर्ष से 14.47 परसेंट अधिक है। यही नहीं, बालिका शिक्षा के लिए भी 47 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रोविजन किया। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए नवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में 85 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। इसके साथ आठवीं, दसवीं, बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने आदर्श विद्यालय विवेकानन्द माडल स्कूल, शारदे छात्रावास और 770 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वर्चुअल क्लास रूम जैसी अभिनव योजनाओं से शिक्षा को देश के अग्रणी प्रदेश में लाने का प्रयास किया है।

इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष उल्लेख है, वह यह है कि हर विद्यालय में उचित व्यवस्था हो। लैपटाप चले, कम्प्यूटर चले, लाइट की व्यवस्था हो, पंखे लगें, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। 628 विद्यालय जो बिजली के कनेक्शन से महरूम थे, उसके लिए बजट में 13 करोड़ रुपये रखने की जो माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने हरियाणा कुरुक्षेत्र की भूमि से सभी प्रांतों की सरकारों और आम जन का आह्वान किया था, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। साक्षात् रूप से, व्यवस्थित रूप से भ्रूण हत्या रोकने के लिए और बेटी बचाने के लिए बेटियों को पढ़ाने का जो संकल्प इस बजट में लिया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। जिस घर में भी बेटी पैदा होगी, उस दिन उस बेटी के लिए ढाई हजार रुपये की व्यवस्था की है। उसकी पहली वर्षगांठ जब आएगी तो उसको ढाई हजार दुबारा मिलेंगे। जब वह बच्ची पहली क्लास में पढ़ने जाएगी तो 4 हजार रुपये की व्यवस्था की है। जब वह बच्ची छठी क्लास में पढ़ेगी तो 5 हजार रुपये की व्यवस्था की है। जब वह दसवीं पास करेगी तो 11 हजार रुपये और जब वह ट्वैल्थ करके कालेज में जाएगी तो अन्य सुविधाओं के अलावा उसको 25 हजार रुपये देने की जो इस बजट में व्यवस्था की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं।

वास्तव में बेटी बचाने का जो संकल्प लिया है हिन्दुस्तान में पहली सरकार है तो राजस्थान की सरकार है। बेटी को हमारे समाज में बोझ समझा जाता था, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता था। बेटा और बेटी में फर्क की व्यवस्था थी। उसको समाप्त करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। 'मुख्यमंत्री राज श्री योजना' जो राजस्थान में लागू की है, राजस्थान में 1 जून, 2016 के बाद जो बालिका पैदा होगी, उसको इस योजना का फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को लागू करने के लिए इस बजट में जो प्रोविजन किया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऊर्जा की बात है, कांग्रेस के मित्र जब बिजली की बात करते हैं तो बिजली कटौती की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदलने की बात करते हैं। यह स्थिति बनी थी राजस्थान की। हमारे मेनिफेस्टो में मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी पार्टी ने यह तय किया कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज बनता है तो हम किसान को 8 घंटे बिजली देने की बात करेंगे, सिंगल फेस 24 घंटे बिजली देने की बात करेंगे। जो विरासत में हमको 80 हजार करोड़ रुपये कर्ज के रूप में मिला था, उसमें तो 1 घंटा भी बिजली देना राजस्थान सरकार के लिए सम्भव नहीं था। यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री का कुशल नेतृत्व है जिसने अपने कौशल से, अपने प्रशासनिक अनुभव से राजस्थान की जनता को 8 घंटे थ्री फेस और 20-22 घंटे सिंगल फेस बिजली देनी की व्यवस्था की है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

यही नहीं, कांग्रेस के घोटालों के कारण 80 हजार करोड़ का कर्जा बिजली बोर्ड पर हुआ था, उसको 75 परसेंट टेकओवर किया है। इनके राज में जिस तरह घाटा हुआ, उस घाटे में भी पिछले वित्त वर्ष में 3,172 करोड़ रुपये की कमी लाये हैं। यह कुशल प्रशासनिक प्रबंध के कारण हुआ है। पिछली सरकार के समय 15,645 करोड़ का जो वार्षिक घाटा था, उसको कम किया। उस घाटे के बावजूद भी गत 2 वर्ष में 4,283 मेगावाट बिजली उत्पादन करके राजस्थान के किसान को, राजस्थान के आम-अवाम को बिजली देने का राजस्थान सरकार का, माननीय वसुंधराजी का जो संकल्प था, उसको पूरा किया।

हमसे पहले जब कांग्रेस का राज था, ये कहते हैं कि हमने भी बिजली बहुत दी। आपके आंकड़े देखें तो 2,273 मेगावाट बिजली आप अपने कार्यकाल में पैदा कर पाये थे। इतना बड़ा बिजली विभाग का घाटा होते हुए भी माननीय वसुंधराजी चाहती हैं कि आम जन को सुविधापूर्वक बिजली मिले। गत 2 वर्षों में 765 केवीए के 2, 400 केवीए के 1, 220 केवीए के 17, 132 केवीए के 33 तथा 33 केवीए के 643 सब ग्रिड-स्टेशन किये गये हैं। आगामी वर्ष में भी 220 केवीए के 6, 132 केवीए के 16 और 33 केवीए के 200 सब-स्टेशन बनाने का बजट में प्रोविजन किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

यही नहीं, गत 2 वर्ष में 2 लाख 84 हजार घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। आने वाले बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं में हर गांव में, हर झोंपड़ी में बिजली की व्यवस्था हो, इसको ध्यान रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 8 लाख घरेलू कनेक्शन देने का जो प्रोविजन किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं। इसके साथ किसान को इस बजट में, जैसे पहले कनेक्शन दिये गये थे, उसी तरह से 40 हजार नये कृषि कनेक्शन देकर किसानों को फायदा देने की योजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आउट आफ टर्न, बूंद-बूंद योजना से कनेक्शन लेता था तो उसकी टैरिफ और सामान्य किसान की टैरिफ में बहुत ज्यादा अंतर है। ढाई गुणा पेमेंट करना पड़ता था। बूंद-बूंद योजना के कारण बहुत ही भारी-भरकम पेमेंट करना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में प्रोविजन किया है कि अब इस स्कीम पर लगाम लगाएंगे। एक निश्चित

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पीरियड कर दिया कि बूंद-बूंद योजना में अगर कोई कनेक्शन लेता है तो उसको 5 साल होने पर, चाहे उसका प्रायोरिटी में नम्बर आया है या नहीं आया है, सामान्य किसान के नाते जैसे औरों से 90 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लिया जाता है, उसी सामान्य कैटेगिरी में इसको ट्रांसफर करके सामान्य टैरिफ से उससे पैसा लिया जाएगा। इसकी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की है।

कांग्रेस के राज में आखिरी बजट में बगैर बजटीय प्रावधान किये हुए पुल, ब्रिज और सड़कों की घोषणा की गयी थी कि इससे हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान की जनता समझती थी। माननीय वसुंधराजी ने उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्टस को पूरा किया। इसके अलावा शहरों में गौरव पथ बनाने की योजना 2003-2008 की थी, मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गांवों में देखा। गांव की जन भावना थी, विशेषकर महिला वर्ग का कहना था कि गांव में कीचड़ बहुत रहता है, गंदा पानी भरा रहता है। आदमी ठीक से अपना जीवन जी सके, उसके लिए 1,984 पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ बनाने का काम किया। इसके लिए 1,027 करोड़ का पिछले बजट में प्रावधान किया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि इस बजट में भी उन्होंने 2 हजार ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाने की घोषणा की है। 2,182 किलोमीटर लम्बाई व 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की घोषणा इस बजट में की गयी है।

यही नहीं, ग्रामीण सड़कें टूटने की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक निश्चित पीरियड होता है उसके बाद उसका रिन्युअल होना चाहिए। हमारे मंत्रीजी भी बताते हैं। राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने डामरीकरण और पैचवर्क के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है गांव और गरीब की ढाणी को भी सड़कों से जोड़ने के लिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो गांव रह गये थे, उनको भी चिह्नित करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी वित्तीय वर्ष में जोड़ने की बात कही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 67 सालों में राजस्थान की जनता ने, किसान ने झेला है। लगभग 30 सालों से अधिक ऐसे निकले हैं जब ओलावृष्टि के कारण या हिमपात के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। पिछले बजट के दौरान ओलावृष्टि हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के सारे विधायकों को कहा

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कि पार्टी से ऊपर उठकर जनता के बीच में जाएं ताकि जनता का जितना नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन होकर गिरदावरी हो। उसके बाद यहां बैठकर केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी और उस आधार पर एक-एक किसान को राहत देने का काम किया, उसमें राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले 50 परसेंट पर ही खराबा राशि मिलती थी, उसे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने घटाकर 33 परसेंट किया। राजस्थान की सरकार ने, हमारे अकाल राहत मंत्री ने बताया था कि 8322 गांवों में 2924000 प्रभावित किसानों को बैंक खातों में 2427 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित की। उसके बाद उनकी जो भी मुआवजा राशि बनती थी, उसका पेमेंट किया। किसानों के लिए 2016-17 के लिए उनको परेशानी नहीं हो, उनकी फसल के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी भंडारण करने के लिए 39 करोड़ का जो प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के पशुओं में बीमारी हो जाती है, पशुओं को दूर नहीं ले जा सकते, उनको दिक्कत आती थी। पिछले बजट में 600 पशु उप केन्द्र खोले थे, इस बार बजट में किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 हजार ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बधाई देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी इस बजट में बहुत कुछ है। परिवार का मुखिया जिनके आधार पर गृहस्थ जीवन सम्भव होता है, यदि अचानक उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाए तो परिवार गम्भीर आर्थिक संकट में फंस जाता है। ऐसे परिवारों को सम्बल देने के लिए प्रधान मंत्रीजी ने बीमा सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की है, राजस्थान में 50 हजार से अधिक खाते इस योजना में शामिल हुए हैं। इस योजना के साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित भामाशाह योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, नवीन कृषि योजना और नवीन पशु बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा आदि को बढ़ाया गया है, यह अभिनव कदम है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाये जाने वाले छात्रावासों में विद्यार्थियों

(श्री रामहेत सिंह यादव)

को मैस भत्ते का जो 2000 प्रति विद्यार्थी का जो प्रावधान किया है, वह सराहनीय कदम है। यही नहीं, इन विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए, गरम पानी की आवश्यकता होती है बच्चों को सर्दी के समय, उसमें भी 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आईआईटी, आई आई एम, मेडिकल आदि के प्रवेश के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं, गरीब परिवार से हैं, वे भी डाक्टर और इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं, ऐसे एक हजार विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था इस बजट में की है, यह भी सराहनीय कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की हम चर्चा करें, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज को हमने सुदृढ़ नहीं किया तो कहीं न कहीं हमारे विकास की जो गति है, वह पूर्ण नहीं होगी। माननीय वसुन्धरा राजेजी ने पंचायती राज के विकास के लिए 15378 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, इससे हमारे पंचायती राज व्यवस्था को और ग्रामीण क्षेत्र में विकास को विशेष रूप से सम्बल मिलेगा और विकास के काम गांव में होंगे।

हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी का अभाव है। हम कभी हरियाणा से, कभी पंजाब से अपने पानी का हक मांगते रहते हैं लेकिन राजनीतिक विवादों में पड़ने के कारण पंजाब हमें आंख दिखाता है और यमुना के पानी में राजस्थान का जो हिस्सा है वह आज तक राजस्थान को नहीं मिला। इसका अल्टरनेट उपाय क्या हो? तो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की है। हमारे राजस्थान में हिन्दुस्तान का 14 प्रतिशत भू भाग है, 10 प्रतिशत आबादी है लेकिन 1.46 प्रतिशत ही पानी है, तो हम पानी बचाने का उपाय करें। महाराष्ट्र पैटर्न पर राजस्थान में भी जल स्वावलंबन की योजना को शुरू किया, सब जन प्रतिनिधियों को उसमें बुलाया, प्रशिक्षण दिया और आम जन का आंदोलन बनाकर, जन भावना से अभियान चलाया है, मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को। जल स्वावलंबन में राजस्थान के दानदाताओं ने, राजस्थान के पत्रकार बंधुओं ने, राजस्थान की स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिस तरह से बढ़- चढ़कर काम किया तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता में जागरूकता बढ़ेगी। 3118 गांवों में इसको चालू किया और आगामी तीन साल तक लगातार 6-6 हजार गांव जोड़कर कुल 21

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हजार गांवों में यह जल स्वावलंबन योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी के आह्वान पर चालू होगी, इसके परिणाम आने वाले समय में अच्छे मिलेंगे। जिस तरह की राजस्थान की हालत है उसमें निश्चित रूप से जल बचाने का अभ्यास होगा हमारा, जो बहता हुआ पानी है वह रुकेगा, खेत का पानी खेत में रहेगा, गांव का पानी गांव में रहेगा। आम आदमी का इस जल आंदोलन से जुड़ाव है इसी कारण माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन भी है यह। मैं बधाई देता हूं, उसके प्रयोजन के लिए बजट में 440 करोड़ रुपए रखे हैं।

हमारा खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, राजस्थान का खिलाड़ी राजस्थान का गौरव बढ़ाता है, देश का गौरव बढ़ाता है। लेकिन जब वह खेल के बाहर हो जाता है तो वह दर-दर की ठोकरें खाता है और उन मैडल्स को दिखाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का दर्द था कि ऐसे लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसने राजस्थान का गौरव बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, उसका गौरव बढ़ना चाहिए। उसकी व्यवस्था के लिए भी आउट आफ टर्न उनको नौकरी देने का प्रावधान किया है। इसी के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2000 खेल मैदान बनाने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। खिलाडियों को जो आउट आफ टर्न सीधे ही आवेदन करने पर नौकरी की व्यवस्था की है, गृह विभाग, खेल विभाग, शिक्षा, पर्यटन विभाग में, यह सराहनीय कदम है इससे हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे यहां से खेल की भावना से ज्यादा खिलाड़ी और प्रतिभाएं उभरेंगी और राजस्थान का नाम रोशन करेंगी।

कांग्रेस के राज में 26 महीनों का अगर हम कैलकुलेशन करें तो इन्होंने 22 हजार लोगों को नौकरी दी, लेकिन सारी नौकरियां हाई कोर्ट और माननीय न्यायालयों में, कहीं ट्रिब्यूनल में और स्टे के कारण अटकी रही, इन सब पेचीदगियों के बाद भी पिछले 26 महीनों में राजस्थान सरकार ने जो 80 हजार लोगों को नियुक्ति दी है, उससे राजस्थान का नौजवान अपने आपको गौरवान्वति महसूस करता है। 1 लाख से अधिक और वेंकेंसी अभी नियुक्ति की स्थिति में है यह राजस्थान के कुशल नेतृत्व के कारण यह सब हो पाया है कि रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी राजस्थान का नौजवान सरकारी नौकरी के अलावा अपने क्षेत्र में हुनर सीख कर वह नौकरी का स्वयं कौशल पैदा करे, वह स्वयं नौकरी देने की स्थिति में आए ऐसी हालात के लिए, उनको ट्रेनिंग दी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जाए, यही कारण है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए व्यावसायिक शिक्षा का एक सब्जैक्ट जो हर जगह जोड़ने का प्रयास किया है। आने वाले समय में राजस्थान का नौजवान किताबी शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी लेगा। डेढ़ लाख लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया गया है उसमें से 40 हजार लोगों को प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने-अपने संस्थानों में नौकरी दी है। रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से एक बहुत बड़ा इंवैस्टमेंट जो राजस्थान में होने वाला है जिसके लिए एमओयू हुए हैं, आने वाले समय में नौजवान के लिए रोजगार देने का काम करेंगे। राजस्थान का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होकर, अपने हुनर से अच्छा व्यवसाय करके राजस्थान के विकास में अपना योगदान देगा।

इसके अलावा कुछ बातें जो अलवर जिले से सम्बन्धित हैं, कहना चाहता हूं। राजस्थान में चाहे माननीय भैरोंसिंहजी का राज रहा, चाहे माननीय वसुन्धराजी का राज रहा, जब-जब भारतीय जनता पार्टी का राज आता है अलवर जिले को बहुत सारी सौगात दी जाती हैं। अलवर जिला विकास की दृष्टि से राजस्थान के किसी भी जिले से कम नहीं है। अलवर जिला व भरतपुर जिला दो ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में पड़ते हैं। हम राजस्थान के अन्य जिलों से तो बहुत आगे हैं, लेकिन हम एनसीआर में आते हैं। एनसीआर के कारण हम हरियाणा, यूपी, दिल्ली आदि राज्यों के हिसाब से चर्चा करते हैं तो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस का राज था, कोई ऐसी अभिनव योजना एनसीआर से लाकर अलवर व भरतपुर जिले का विकास हो सकता था, उन योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। आज हम एनसीआर की चर्चा करते हैं तो हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो 16 हजार करोड़ से ज्यादा एनसीआर से लोन लेकर अपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर पाया है। सड़कें, रोड, लाइट हमसे ज्यादा वहां अच्छी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन की नेता से आग्रह करना चाहता हूं, हुडको हो, नाबार्ड हो, अन्य संस्था से लोन लेते हैं उसके कंपेरिजन में एनसीआर आधी रेट पर हमको लोंग टर्म के लिए लोन देता है। वहां पानी की आवश्यकता है, हमारे वहां सीवरेज की आवश्यकता है, हमारे वहां यमुना का पानी लाने की आवश्यकता है। इन सब बातों के लिए एनसीआर की बड़ी योजना बनाकर हमारे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कांग्रेस के राज में खैरथल और

(श्री रामहेत सिंह यादव)

किशनगढ़ को शहरी क्षेत्र होते हुए भी पेयजल की योजना से छोड़ दिया गया था। किशनगढ़ से लेकर कोटकासिम बड़ीबोली चौक, उसके बीच में तीन किलोमीटर रास्ता है, उसके लिए तीन करोड़ की आवश्यकता होगी। किशनगढ़ में कालेज की भी आवश्यकता है। हमारे यहां सीवरेज, पाइप लाइन व एनसीआर की सड़कों के लिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट के रिप्लाई में हमारे जिले व विशेष रूप से मेरे क्षेत्र को एक कालेज, खैरथल-किशनगढ़ बाइपास और बेसिक हमारे वहां पानी की कमी है, उसके लिए घोषणा करें। यदि यमुना के फ्लड के पानी को लाने की योजना एनसीआर के माध्यम से बनाएंगे तो निश्चित रूप से अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं जिला तक उसमें कवर होता है। उस योजना से जोड़कर पेयजल की योजना बने।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस आशा और विश्वास के साथ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बजट का रिप्लाई करें तो हमारे जिले को एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में देखकर आर्थिक प्रोविजन इस बजट में करेंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं उस बजट के लिए जो बजट किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, हर वर्ग का ध्यान रखकर बनाया गया है। जिस बजट की सिर्फ राजनैतिक पार्टियों ने ही नहीं, आम जनता ने सराहना की है। राजस्थान के सारे टीवी चैनल, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि वसुन्धराजी ने बहुत बढ़िया बजट दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आता है, हमारी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या शकुन्तलाजी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रही थीं उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरसिंह रावजी, राजीव गांधी और कितनी बातें इन्होंने कीं। यह भी कहा कि हैलिकाप्टर हमने बनाया और पता नहीं दुनिया की कौन-कौनसी चीजों की बातें ये उस दिन कर रही थीं। (व्यवधान) बैलगाड़ी की बात नहीं की इन्होंने। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हैलिकाप्टर कांग्रेस के राज में हमको देखने को मिला। यह बात भी सही है कि कांग्रेस के नेताओं ने हैलिकाप्टर और हवाई जहाज से नीचे उतरने का कभी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

प्रयास नहीं किया, इसलिए सड़कें उन्होंने कभी बनायीं ही नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में जब पहली बार अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर हिन्दुस्तान के गांवों को जोड़ा, क्योंकि गांवों के विकास की शुरुआत सड़कों से होती है। मैं कांग्रेस के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, अटलबिहारी वाजपेयीजी ने सड़कों को जोड़ने की जो योजना बनायी वो योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बना सकते थे, वह योजना श्रीमती इंदिरा गांधी भी बना सकती थीं, वह योजना राजीव गांधी, नरसिंहरावजी, आपके जितने प्रधानमंत्री रहे, वे भी बना सकते थे। (व्यवधान) लेकिन इन्होंने कभी विकास की चिन्ता नहीं की। देवगौड़ाजी तो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन बना सकते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में विकास की अगर शुरुआत हुई तो अटलबिहारी वाजपेयीजी के राज में हुई और राजस्थान में विकास की शुरुआत हुई तो भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के राज में हुई। चाहे कांग्रेस पार्टी का राजस्थान और हिन्दुस्तान में 50-55 साल तक शासन रहा हो, आज हमारे देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में जिस तरह देश और राज्य का विकास किया जा रहा है मैं समझता हूं, निश्चित रूप से आने वाले समय में हिन्दुस्तान विश्व का सबसे ताकतवर और समृद्धशाली मुल्क होगा और राजस्थान हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। ऐसी हमारी भावना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। बजट का जो आंकड़ों का मायाजाल है, मैं उसमें ज्यादा समझता नहीं हूं कि कितने करोड़ स्वीकृत हुए, नहीं हुए। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस बजट की सराहना आम व्यक्ति करे, हमने जिससे भी फोन पर बात की उसने तारीफ की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातें नहीं। आपस में बातें नहीं, नहीं तो फिर आपको बोलने का कभी भी समय नहीं मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपका राज कई साल तक रहा है, लेकिन कभी आपने नदियों को जोड़ने की योजना नहीं सोची, कभी किसान क्रेडिट के बारे में विचार नहीं किया, कभी फसल बीमा योजना बनाने के बारे में विचार नहीं किया। यह तो राजस्थान में भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने तो पहली बार पंचायतों को सड़कों से उन्होंने जोड़ा। पहली बार मिडिल स्कूल भैरोंसिंहजी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

के राज में खुले। पहली बार अंत्योदय योजना बनाकर, काम के बदले अनाज योजना बनाकर राजस्थान का विकास किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।

आज हमें इस बात का गर्व है, अभी आपने देखा, नरेन्द्रजी मोदी की कई योजनाएं राजस्थान में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने लागू की हैं। प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना बनायी, एक दिन में डेढ़ लाख लोगों के, गरीबों के बैंक में खाते खुले। बैंक में लोग जाते हुए डरते थे। पहली बार हिन्दुस्तान का कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा जिसने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। लोग हंसते थे उनके ऊपर। मैंने कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के स्टेटमेंट देखे कि नरेन्द्र मोदीजी क्या स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदीजी की स्वच्छ भारत योजना में शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपया प्रत्येक घर को दिया जा रहा है।

आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद व हमारे जिले के कलक्टर कई गांवों में गये। जब वहां लोगों की भावनाएं सुनीं तो हमारे मन में बड़ी तकलीफ भी हुई। आजादी के 69 साल बाद भी हमारी माताएं व बहनें जब शौच करने के लिए रात को 12 बजे, 2 बजे घर से बाहर निकलती हैं, कई घटनाएं होती हैं। तो विचार आता है इस बात का कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस बात की जिम्मेदार है हिन्दुस्तान में 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने कभी इस बात का विचार नहीं किया कि हिन्दुस्तान की माताओं-बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए।

वह व्यवस्था अगर इस देश में किसी ने की तो उसकी हंसी उड़ायी जा रही है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि माननीय नरेन्द्र मोदीजी की इस योजना के बाद गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो रहा है। चाहे मेक इन इण्डिया की बात हो, स्टार्टअप इण्डिया की बात हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना की बात हो, अटल पेंशन योजना हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जो माननीय मोदीजी ने लागू कीं। विपक्ष के नेताजी, कभी आपने बुलेट ट्रेन देखी है? नहीं देखी होगी। वह मुम्बई से अहमदाबाद चलेगी। (व्यवधान) लेकिन बुलेट ट्रेन आने वाली है। हिन्दुस्तान विकास की उस दौड़ में दौड़ रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर मुल्क होगा।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उसी तरह से हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री लगातार इस बात का प्रयास कर रही हैं कि राजस्थान को हम हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों में लाएं। यह बात ठीक है कि मुख्य मंत्री वसुंधराजी जब पहले मुख्य मंत्री बनी थीं, विकास के कार्य राजस्थान में हुए थे। उसके बाद जब पांच साल तक कांग्रेस पार्टी आयी थी, वो तो हमारी छोटी-मोटी गलतियों की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का राज वापस आया तो पांच साल तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की स्थिति इस राजस्थान की की, उसका नतीजा सामने आया जब चुनाव के परिणाम आये और इनकी सीटें कुल 21 रह गयीं। कल सिंघल साहब कह रहे थे कि ये मैटाडोर में बैठकर आये हैं। जिस तरह का बजट वसुंधराजी ने पेश किया है और आने वाले दो साल में जिस तरह का बजट पेश होगा तो अगली बार आपको इनोवा गाड़ी में आना पड़ेगा, देख लेना, सबको मिलकर। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। क्योंकि आज हर गांव में लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 6 ही बैठे हैं और उसमें 6 ही आते हैं तो ये 6 के 6 ही आ जाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, 7 की जगह है इनोवा में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुंधराजी ने जब राज संभाला था उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, वो आपसे छिपी हुई नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनियों के बारे में बताया गया कि 80 हजार करोड़ रुपये के घाटे में हमारी कम्पनियां थीं, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते हुए मूल्य की वजह से राजस्व में काफी कमी आ गयी, वेतन-पेंशन की वजह से व्यय बढ़ता जा रहा था। इतनी वित्तीय कठिनाइयों के बाद भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दो वर्षों में, इस वर्ष के बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पिछले दो वर्षों में जिस तरह के विकास के काम राजस्थान में किये हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इतने विकास के कार्य कांग्रेस के पूरे पांच साल में हुए होंगे।

यहां रिसर्जेंट राजस्थान की कल मीणाजी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि ये कम्पनियां पुरानी काम कर रही थीं और वापस आ गयीं। नये एमओयू साइन हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि रिसर्जेंट राजस्थान के बाद भी पिछले तीन महीने में 11531 करोड़ के 51 एमओयूज और हुए हैं। बड़ी-बड़ी विश्व स्तर की, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कम्पनियां राजस्थान में आ रही हैं। वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि यहां पर अच्छा वातावरण है, यहां पर औद्योगिक वातावरण

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अच्छा है। हमारी भावना भी है कि हमारे यहां के बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहां का गरीब वर्ग आगे बढ़े, पिछड़े लोगों को हम आगे लाएं। उसके लिए निश्चित रूप से हमको इस तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, इस तरह के एमओयू साइन करने पड़ेंगे।

वसुंधराजी ने भामाशह योजना बनायी। कांग्रेस के राज में एक भी योजना ऐसी आप बता दो जिस योजना में सीधा पैसा जो लाभार्थी है उसके हाथ में जाता हो। कभी कांग्रेस ने इस बात का विचार ही नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा ऐसी योजनाएं बनायीं कि पैसा 10-12 जगह से घूमते-घूमते जाए ताकि थोड़ा कमीशन हमको भी खाने को मिल जाए। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी ने भी इस बात को कहा है कि मैं रुपया भेजता हूं, 85 प्रतिशत रास्ते में खा जाते हैं, 15 प्रतिशत ही पहुंचता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना बनायी और भामाशाह योजना बनाकर, चाहे पेंशन हो, चाहे नरेगा हो, जितनी भी योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ हमारी बहनों को मिले, उनके बैंक में सीधा पैसा जाए, इसकी व्यवस्था की। अभी उन्होंने भामाशाह योजना एक्ट लाने का भी निर्णय लिया है जिसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग का गठन, कौशल राजस्थान की बात हम करते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हो रही है, वसुंधराजी के कौशल की चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है और भारत सरकार ने भी इसकी सराहना की है। हम यहां गोपालन की बात करते हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार यह गोपालन विभाग अलग से बनाया। गोवंश संरक्षण व संवर्द्धन की स्थापना के लिए उन्होंने कई करोड़ों रुपये अभी बजट में दिये हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका लाभ हमको देखने को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार बेरोजगारी की चर्चा होती है। यह बात सही है कि रिसर्जेंट राजस्थान का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उस रिजल्ट को आने में दो-तीन साल लगेंगे लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले 26 माह में 80 हजार नियुक्तियां की हैं। इस वर्ष भी एक लाख नियुक्तियां देने का उन्होंने संकल्प किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और मैं इस बात का विश्वास भी करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने चुनावों में घोषणा पत्र में नौकरियों के लिए जो कहा था, आने वाले तीन वर्षों में वो सारी की सारी नौकरियां लग जाएंगी और राजस्थान बेरोजगारी की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

समस्या से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने चाहे भामाशाह योजना में स्वरोजगार योजना बनायी हो, स्वास्थ्य बीमा योजना बनायी हो, आरोग्य राजस्थान की योजना बनायी हो, चाहे जन आवास योजना बनायी हो, कई योजनाएं ऐसी बनायीं जिनका सीधा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी होती है, उनके पहले के कार्यकाल से अगर हम तुलना करने लगे तो हमको बड़ा गर्व होता है। उस समय बजट का इतना अभाव नहीं था और उस कार्यकाल में वसुंधराजी ने राजस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन पांच साल के कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान को गर्त में पहुंचाया गया, वित्तीय संकट हमारे सामने पैदा किया गया। उससे उबारकर वापस राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वसुंधराजी ने पिछले दो वर्षों से प्रयास किये हैं। आपने देखा भी होगा कि कौशल विकास हो चाहे ई-गवर्नेंस हो, चाहे अक्षय ऊर्जा हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे जल ग्रहण विकास का मामला हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, सब मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजस्थान की सरकार की सराहना की गयी है। उसके लिए हमें बहुत खुशी है और इस बात के लिए मैं वसुंधराजी की तारीफ भी करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वसुंधराजी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम चलाया था, कांग्रेस के लोगों ने उसकी भी बुराई की। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार आएगी। सरकार गयी, हर डिवीजन में सरकार गयी। क्या बोल रहे हो?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हर सरकार चलाती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुख्य मत्री सहित? मुख्य मंत्री, मंत्रिमण्डल, सारे अफसर आज तक किसी सरकार में नहीं गये। गये क्या आज तक?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो इसका फायदा हो गया न?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): फायदा हुआ न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दिख नहीं रहा है क्या सदन में?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या दिख रहा है सदन में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब चले गये, चार ही हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके तो चार भी नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको सुनना ही नहीं चाहते, सब चले गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, मेरे को नहीं सुनना। सब सुन रहे हैं, आप मेरी चिंता मत करो। आप तो सुन रहे हो। विपक्ष अगर मुझे सुन रहा है तो मुझे उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। आपको सुनाना है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको यह विश्वास नहीं है क्या कि आसन भी सुन रहा है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुन नहीं रहा है, सहन कर रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी दलों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की बड़ी मजाक बनायी। अब आप मुझे बताइये, हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला मुख्य मंत्री होगा जो अपनी पूरी सरकार को, सारे आईएएस अधिकारियों को जो जयपुर में बैठते थे, सबको लेकर एक-एक पंचायत में, एक-एक गांव में गया और लोगों की समस्याएं सुनीं। मैं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं, मैं मेरे चित्तौड़गढ़ जिले की बात कर रहा हूं, मैं उदयपुर डिवीजन की बात कर रहा हूं। जितनी समस्याएं हमने बतायीं उन सारी समस्याओं को यहां पर मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में कम्प्यूटराइज कर रखा है और एक-एक समस्या का समाधान हो रहा है। क्योंकि वहां पर समस्याएं व्यक्तिगत आयी थीं। सार्वजनिक बातें अलग हैं। विकास की बात हम कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे है, विकास करा रहे हैं लेकिन 70 प्रतिशत से ज्यादा समस्याओं का समाधान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हो चुका है, आने वाले समय में वो हण्डरेड परसेंट होगा। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी, उसका भगवान ही मालिक है।

न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चला। राजस्व लोक अदालतों के द्वारा 21 लाख मुकदमे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में निपटाये गये। मैं खुद भी कई कैम्पों में गया हूं। उन कैम्पों में जाकर मैं देखता था कि दो भाई पिछले 40-40, 50-50 सालों से आपस में मुकदमों में उलझे हुए थे। उन दोनों भाइयों को चाहे एसडीएम हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे प्रधान हों, चाहे अन्य जन-प्रतिनिधि हों, समझाकर उनमें जब आपस में राजीनामा कराया, जब उन परिवारों को गले

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मिलाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गये। न्याय आपके द्वार में जो फैसला हुआ, उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की थी। उससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, आमजन की समस्याओं के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल बनायी गया हो, चाहे नई सौर ऊर्जा नीति बनायी गयी हो, मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत जो हम सब विधायकों ने चुनी हैं उनके विकास की बात हो, चाहे जीरो परसेंट ब्याज की बात हो, चाहे राजस्थान को शौचालय के मामले में ओडीएफ करने की बात हो, राजस्थान लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक गांव और शहर के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनायी जाए। वो योजनाएं बन गयीं और अब धीरे-धीरे गांवों में विकास शुरू हो रहा है। अध्यापकों की पदोन्नति हो रही है। आपने तो गयी बार शिक्षा के क्षेत्र का सत्यानाश करके रख दिया था।

(14.00 बजे)

आठवीं तक के बच्चों को आप बिना पढ़े ही पास कर रहे थे। आप तो चाहते ही नहीं हो कि राजस्थान का बच्चा पढ़कर आगे जाए। आठवीं क्लास तक अगर बच्चा बिना पढ़े पास होगा तो वह बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसको समाप्त कर दिया, उस निर्णय को वापस ले लिया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज राजस्थान की सभी पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुल गये। सात नये मेडिकल कालेज खुल गये। 767 मिनी बैंक्स की स्थापना हो गयी। किसानों के लिए, खेती पर काम करने वालों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, ऐसी कई योजनाएं हमने चलायीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बार-बार हमारे विपक्ष के सदस्य चर्चा करते हैं- कभी ओलावृष्टि की चर्चा करते हैं, कभी अकाल की चर्चा करते हैं, कभी सूखे की चर्चा कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेताजी भी कल बोल रहे थे कि कांग्रेस के राज में जब सूखा पड़ा था तो हमने अकाल राहत काम चलाये थे। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 69 साल में कांग्रेस की एक सरकार आप बता दो, 50 साल तक इनका राज रहा है, जिसने ओलावृष्टि या अनावृष्टि में एक रुपया भी काश्तकार को दिया हो। किसान को एक रुपया आज तक नहीं दिया। मैं चाहता हूं, सब सदन वाले भी धन्यवाद दें हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को, कि इन्होंने 2015 में ओलावृष्टि में 2,471 करोड़ रुपये राजस्थान के गांवों को और काश्तकारों को दिये। प्रधान मंत्रीजी ने 50

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
प्रतिशत का मापदण्ड था, उसको 33 प्रतिशत कर दिया। इस वजह से राजस्थान के काश्तकार अब आशान्वित हैं क्योंकि हमारे काश्तकार प्रकृति पर डिपेंड हैं। आज हमारे काश्तकार इस बात से आशान्वित हैं, भविष्य में राम हमसे रूठ जाएगा लेकिन राज नहीं रूठेगा, इस बात का विश्वास हमारे काश्तकार को हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर गौरव पथ की चर्चा भी की गयी। डोटासराजी तो बार-बार जब भी भाषण देने खड़े होते हैं, एक ही बात कहते हैं कि गौरव पथ कहीं बना ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने एमएलए साहबान बैठे हैं। 1,984 पंचायतों में गौरव पथ लागत 1,027 करोड़ रुपये जून, 2016 तक पूर्ण हो जाएंगे। हमारे यहां तो काफी पूर्ण हो चुके हैं। यहां पर कहा गया कि जहां गौरव पथ बन गये हैं, वहां नालियां नहीं बनीं। मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन लेना। वहां नालियां भी बन गयी हैं। अब के चुनाव में उन नालियों में ही रगड़ेंगे लोग आपको, देख लेना। जो गौरव पथ की नालियां हैं, वोट मांगने जाना, तब पता लगेगा तुम्हारे को।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): +++ (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): +++ (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहे यूआईटी का चेयरमैन बनूं, चाहे कुछ भी बनूं, राजस्थान में हमारी नेता वसुन्धराजी हैं, वसुन्धराजी ही रहेंगी। उनसे लोकप्रिय राजस्थान में कोई नेता न था, न है, न रहेगा। आप मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। हम उनके साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। यूआईटी का चेयरमैन बनाया, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने चित्तौड़ जिले में...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): +++

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी बात सुनो। आपने पांच सालों में चित्तौड़ जिले से एक मंत्री नहीं बनाया, आप हमें कह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: आसन के बगैर अनुमति के जो-जो बोला है, उसको अपलोपित कर दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं तो आसन की अनुमति से ही बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने आप पर कहां इंगित किया है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय चरण में गौरव पथ में 2,000 पंचायतों में मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण किया है। कई गांव ऐसे हैं मिसिंग लिंक की वजह से जहां दो गांवों के कनेक्शन हैं। हमारे यहां तो दो स्टेट का कनेक्शन है। हम मध्य प्रदेश-राजस्थान की बार्डर पर रहते हैं। यह योजना प्रारम्भ की गयी, निश्चित रूप से उस योजना से काफी लोगों को राहत मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले गांव हैं, चाहे हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाले गांव हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले गांव हैं, चाहे एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने वाले मिसिंग लिंक हैं, ऐसी कई योजनाएं सरकार ने बनायी हैं और उनको लागू किया है और 608 करोड़ रुपये उसमें लगाये गये हैं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस बार मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की भी घोषणा की है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 250 से 350 की आबादी में 4,000 किलोमीटर की सड़कें जिनकी लागत 1,618 करोड़ रुपये है, बनायी जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कांग्रेस के पांच साल में नान-पैचेबल सड़कों की हम बात कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री युनुस खान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल के कांग्रेस के राज में हम देखते थे, सड़क का एक भी गड्ढा ये ठीक नहीं कर पाये। वह हालत देखकर कभी-कभी रोना आता था। आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि इन दो वर्षों में 2,702 किलोमीटर सड़कें तथा 99 पुलियाएं 605 करोड़ रुपये की लागत से बनायी गयी हैं। राजस्थान के लोगों को चाहे वह व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव में रहने वाला मध्यम वर्ग हो, बहुत बड़ी राहत उससे मिली है। वर्ष 2016-17 में भी 2,500 किलोमीटर की 600 करोड़ रुपये की लागत की घोषणा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान में कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिसमें गड्ढा होगा, बिलकुल बढ़िया सड़क बन जाएगी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

250 से 499 की आबादी के 934 गांवों को भी 2071 किलोमीटर सड़क से जोड़ दिया गया है। धार्मिक स्थानों को जोड़ने की बात भी की गयी है। रामदेवरा और कई धार्मिक स्थानों को जोड़ने की बात की गयी है। रेलवे के ओवरब्रिज बनाने की इस बजट में बात की गयी है, 761 करोड़ रुपये के

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

आरओबीज बनाने की बात की गयी है। सबसे बड़ी समस्या तो एनएचएआई, नेशनल हाइवेज के जो रोड बने हुए हैं, उसकी है। कई गांव हमारे राजस्थान में ऐसे हैं जिन रोड्स पर बाई पास नहीं है। नेशनल हाइवे के फोर लेन बने हुए हैं लेकिन कुछ जगह गांव और शहर की आबादी आ जाती है, वहां पर कंजेशन होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे एनएचएआई जहां पर रोड कंजेशन होने की सम्भावना है, 300 करोड़ रुपये से बाइपास वहां पर निकाले जाएंगे।

एनएचएआई के चार नये राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं लेकिन जितना पैसा उन्होंने अभी दिया है, मैं समझता हूं आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया होगा। शायद पहले अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़क बनी थी, उस समय पैसा मिला था या मोदीजी की सरकार में हमको पैसा मिला है। कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी में 5,690 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी मुख्य मंत्रीजी ने रखा है।

मैं ऊर्जा मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सिंगल फेस की 24 घंटे बिजली देंगे और आठ घंटे हम थ्री फेस बिजली देंगे। हालांकि 24 घंटे बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं, यह सही बात है लेकिन फिर भी 20-22 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। कांग्रेस के राज में तो चार घंटे भी नहीं मिलती थी। आज 20-22 घंटे बिजली सिंगल फेस गांवों में मिल रही है। आठ घंटे थ्री फेस बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन छह-सात घंटे बिजली आज थ्री फेस की गांवों में मिल रही है। एग्रीकल्चर बिजली मिल रही है लेकिन आपको तो बुराई ही करनी है। आपने तो विद्युत वितरण कम्पनियों का सत्यानाश किया था। कई हजार करोड़ रुपये का घाटा किया था। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को, सारी आलोचनाओं को सहते हुए, मुख्य मंत्रीजी को पता था कि बजट में व्यवधान आएगा, लेकिन उन्होंने 60,000 करोड़ के विद्युत कम्पनियों के कर्जे के बाद भी टेक-ओवर किया है, 60,000 करोड़ रुपये की उन्होंने मदद की है। राजस्थान के काश्तकारों को सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो बिजली की है-गांवों में बिजली की है, एग्रीकल्चर बिजली की है। आने वाले समय में 420, 220, 132, 33 के नये ग्रिड सब स्टेशन भी बनेंगे। अशोक गहलोत साहब के राज में पांच साल तक एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं हुआ। एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। अभी तक 80,000 कनेक्शन तो हो चुके हैं और इस साल

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

भी बजट में आपने 40,000 कनेक्शन देने की घोषणा की है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह पीएचईडी में कांग्रेस के राज में पांच वर्षों में 3,785 करोड़ रुपये लगे और भारतीय जनता पार्टी के दो वर्षों में 8,500 करोड़ रुपये पीएचईडी में लगाये गये और पीने के पानी की समस्या का समाधान किया गया।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इस बजट में एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं पहले भी विधान सभा का सदस्य रहा हूं, आज से तीस साल पहले जब था, उस समय मैंने भाषण में एक बार कहा था कि सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है चाहे वह स्कूल खोलने की योजना हो, चाहे वह पीएचईडी की योजना हो, चाहे वह एनीकट बनाने की योजना हो, चाहे सड़क बनाने की योजना हो, हर योजना में सरकार जनसंख्या का मापदण्ड रखती है। इस गांव की जनसंख्या ज्यादा होगी, 2,000 की आबादी होगी तो स्कूल खुलेगा। 2,000 की आबादी होगी तो सड़क बनेगी। 1,500 की आबादी होगी तो पीएचईडी की योजना बनेगी। उस समय मैं लोगों को कहता था, एक तरफ तो सरकार परिवार नियोजन की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार आबादी का मापदण्ड रखती है। तो जनता को क्या करना चाहिए? परिवार नियोजन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि आबादी बढ़ानी चाहिए विकास के लिए? सरकार को हमेशा जनता की आशाओं के अनुरूप विकास का काम करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पीएचईडी की योजनाओं के बारे में इस बात की घोषणा की कि हम आबादी का इसमें ध्यान नहीं रखेंगे। इसमें जहां आवश्यकता होगी, वहां पर प्रावधान करके हम पीएचईडी के माध्यम से नल योजना स्वीकृत करके पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे।

सिंचाई की अगर हम बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को। हमारे मंत्री महोदय भी यहां पर बैठे हैं, अभी मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की। कांग्रेस के मित्र अभी बड़ी मजाक बना रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मजाक क्यों बना रहे हो? आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आपको तीस मिनट तो हो गये हैं। नहीं, अब आप पांच मिनट ले ही लो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के लिए कांग्रेस के मित्रों से निवेदन कर रहा था कि इसमें आप थोड़ा हमारा सहयोग करें। यह राजस्थान के विकास की बात है। आप इस योजना के लिए गांवों में मजाक उड़ा रहे हो कि वसुंधराजी और बीजेपी के सारे एमएलए, जन प्रतिनिधि चंदा मांगते फिर रहे हैं लोगों से। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान के गांवों की, राजस्थान की प्रकृति की चर्चा हिन्दुस्तान में होती है। जिस तरह की अकाल की स्थिति राजस्थान में है, आज गांवों का आम व्यक्ति भी यह चाहता है कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना सफल हो। मैं खुद योजना का शिलान्यास करने गया, मैंने लोगों से रिक्वैस्ट की। हज़ारों की तादाद में लोगों ने, किसी ने अपने ट्रैक्टर देने की घोषणा की, निःशुल्क मजदूरी करने की बात कही, किसी ने अपनी गांठ से पैसा देने की बात कही। साढ़े तीन, चार लाख रुपये तो उन लोगों ने इकट्ठा कर दिया। तो यह लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई योजना है। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, इसकी चिंता मत करो। लेकिन अगर गांठ का एक रुपया लगता है तो जनता का उसमें जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव की वजह से मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। चाहे साधु-संतों का आशीर्वाद हो, चाहे जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं वो भी सहयोग करें, हमारे जन प्रतिनिधि भी सहयोग करें, एमपी, एमएलए, प्रधान, प्रमुख सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें। यह योजना अगर सफल हो गयी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान हिन्दुस्तान में सिंचाई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा।

मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मुख्य मंत्रीजी ने काफी पैसा दिया है। आरोग्य राजस्थान के माध्यम से लोगों का सर्वे कराकर लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हर क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा पैसा दिया है।

मैं अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की और चित्तौड़ जिले की कुछ डिमाण्ड्स माननीय मुख्य मंत्रीजी से करना चाहता हूं ताकि रिप्लाई में अगर वो कुछ देंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमको मिलेगा। मेरे निम्बाहेड़ा में कानेड़ा घाटा क्षेत्र है, उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर राम प्रतापजी भी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा उसमें, हमारे यहां हरेण का नाका बांध एक घाटा क्षेत्र है उस बांध को अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से उस घाटा क्षेत्र के लोगों की सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, हमारी मुख्य

(श्रीचन्द कृपलानी)

मंत्रीजी निश्चित रूप से करेंगी। निम्बाहेड़ा की पेयजल योजना, मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट में तो इसका प्रस्ताव ले लिया और भारत सरकार को फाइल गयी है, वह भी टीएसपी क्षेत्र में आप शीघ्र करवाएं। चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कालेज की बात हमेशा हम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कालेज बनाया जाए। नये डाक्टरों की टीम हम खड़ी करना चाहते हैं, राजस्थान में रिक्त पड़े पदों को हम भरना चाहते हैं, निश्चित रूप से जिले की जनता को भी इसका फायदा मिलेगा और मेवाड़ सम्भाग को भी इसका फायदा मिलेगा। उसी तरह रावतभाटा में, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने छोटी सादड़ी में कालेज खोला, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। लेकिन बेगूं में भी महाविद्यालय की आवश्यकता है। उसी तरह औला चौराहे से लेकर शंभूपुरा घटावली रोड जिसकी हमारे विधायक महोदय लगातार लम्बे समय से मांग कर रहे हैं, उस रोड को भी मुख्य मंत्री जब रिप्लाई देंगी निश्चित रूप से स्वीकृत करेगी। बड़ी सादड़ी में जादला बांध, रेलवे ओवरब्रिज भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं उसमें राज्य सरकार सहयोग राशि मिलाकर करेगी तो निश्चित रूप से मैं उनका आभार प्रकट करूंगा।

मैं इस अवसर पर एक बार फिर मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने काफी हद तक इस बजट से राजस्थान की जनता को नयी सौग़ातें दी हैं। मुख्य मंत्री का जो विजन है, वह विजन आने वाले समय में राजस्थान को एक चरम ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्य मंत्री का अच्छा है यह विजन, कांग्रेस का अब नहीं आएगा सीजन। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चाहे हमारे प्रधान मंत्रीजी मोदीजी हों, चाहे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी हों, आने वाले समय में राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक बार फिर मैं अपनी ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस तरह एक विजन आपने इस बजट में दिया है, आने वाले समय में राजस्थान को ऊंचाइयों में लेकर हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री डा. राजकुमार शर्मा, followed by Smt. Anju Dhanka; after him.

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय

(डा. राजकुमार शर्मा)

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, राजस्थान की माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री, किसी ने ताली नहीं बजायी है उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने भी मेज नहीं थपथपाई है। यह दिल की भावना पता चल जाती है। 2016-17 का बजट पेश किया है, इस सरकार का यह तीसरा बजट है और बजट के बाद में बहस का भी आज यह तीसरा ही दिन है। तीसरे दिन मुझे बोलने का मौका आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैंने बीच में टोका, आसन को बुरा लगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि आपकी आज्ञा की अवहेलना करें कभी भी। लेकिन थोड़ी-सी पीड़ा हुई क्योंकि माननीय सांसद रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी अध्यक्ष थे उस समय तो इनको अमिताभ बच्चन कहा जाता था वहां पर। उसके बाद अब ये आ गये विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाद में यूआईटी में चले गये तो इनको क्या खुद की पीड़ा थी जो हम पर डाल दी? लेकिन हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं। यूआईटी के अन्दर, मुझे पता है कि आपने जाइन नहीं किया है, न करेंगे आप। लेकिन वे जो छह पद पड़े हैं उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर एक ही बात कहना चाहता हूं। यशस्वी वाली बात तो इसलिए कही है कि मुख्य मंत्री किसी भी पार्टी के हों, यशस्वी होते हैं। हमारे प्रदेश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं तो यशस्वी होते ही होते हैं, इसमें कोई बात नहीं होती। झुंझुनूं जिले को सबसे ज्यादा निराशा इस बजट से मिली है। मेरे से पहले दो वक्ताओं ने जो बोला, शुरू-शुरू में सबने शुक्रिया अदा किया लेकिन अंतिम समय में जब बातचीत उनकी चल रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे जिले को कुछ नहीं मिला, हमारे विधान सभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब कि जितने भी विधायक बोल रहे हैं वो सब शुरूआत के अन्दर तो खूब शुक्रिया अदा कर रहे हैं लेकिन अंतिम समय में यह बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें यह दे दिया जाए। हम भी उम्मीद करते हैं। जो भी बजट आप कह रहे हो कि जनता बहुत अच्छा बता रही है, विधायक सारे अच्छे बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मैं मेरे जिले की ही बात करना चाहता हूं। झुंझुनूं के अन्दर इस बजट में उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ को जो दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार का करना चाहता हूं। लेकिन उसकी शुरूआत किसने की? आज तो वहां पर सारे समाचार पत्र भरे पड़े हैं, एडवरटाइजमेंट से।

(डा. राजकुमार शर्मा)

वैसे जनता ने कोई धन्यवाद नहीं दिया है, लेकिन नेताओं ने अपनी बड़ी-बड़ी फोटो छाप दी कि पहली बार हम हिमालय का पानी लेकर आये हैं इस सरकार में। मैं कहता हूं कि यह चार साल पुरानी योजना है कुंभाराम लिफ्ट योजना। ये नहर लिफ्ट योजनाएं चार साल पुरानी हैं। खेतड़ी और मंडावा का काम तो लगभग पूरा भी हो चुका है। अब इसके साथ में इन्होंने दो और एड किए हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा, मेरे नवलगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है, उसका नाम पहले शामिल था, अब इसको क्यों वंचित कर दिया गया है? जब मुख्य मंत्री महोदया बजट पर अपनी बात रखें तो उस समय नवलगढ़ को भी जोड़ लें तो कम से कम उन लोगों को फायदा होगा जो पीने के पानी से जूझ रहे हैं।

झुन्झुनूं के साथ में जब से यह सरकार बनी है, शुरू से ही अत्याचार हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब हमारे जिले के प्रभारी हैं। एक भी मंत्री पूरे जिले को नहीं मिला, मंत्रिमण्डल के अन्दर भी हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हुआ। एक मंत्री मिल जाता कम से कम, हम तो राजेन्द्र राठौड़ साहब से काम चला रहे हैं। लेकिन ये चूरू वालों को निपटें कि हम लोगों को निपटें कि सीकर वालों को निपटें? पूरा राजस्थान इनके पीछे पड़ा है, ये किस-किस से निपटें? हमें थोड़ा-सा इनका फायदा मिला है, एक छोटे राठौड़ साहब आ गये तो थोड़ी बहुत इनकी बात वो पूरी कर लेते हैं।

मैं झुन्झुनूं के बारे में बात करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सरकार ने बजट के साथ-साथ एक बात कही, घाटा, घाटा। मेरे मन में एक सवाल उठता है और मैं ही नहीं पूरे राजस्थान के सात करोड़ वासियों के मन में एक सवाल उठता है कि पुरानी सरकार ने घाटा दिया और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एक बिजनसमैन ने दूसरे बिजनसमैन को टेक-ओवर किया है? जनहित के कार्यों के लिए अगर किसी को ऋण लेना पड़े, हर सरकार लेती आयी है और लेती रहेगी, यह घाटा कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जनता के लिए पैसा लिया गया है। किसी ने भी अपने व्यक्तिगत अपने घर बनाने के लिए पैसा नहीं लिया है। पिछली सरकार के समय गहलोत साहब के लिए सब लोग बोलते थे कि गहलोत साहब बोलते हैं, खजाना खाली, खजाना खाली है। कितना मजाक बनाया? इस बजट के अन्दर भी सब लोगों ने एक ही बात कही है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनहित की योजनाओं के लिए अगर ऋण लेकर लोगों के लिए

(डा. राजकुमार शर्मा)

काम किया जाए, गरीबों की योजनाओं पर काम किया जाए तो वह घाटे का काम नहीं हो सकता। बजट के बाद में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रेस कांफ्रेंस में एक बात कही जो सब लोगों ने सुनी कि मैं घाटे का सौदा नहीं करती। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनता ने आपको सम्मान के साथ चुना है, घाटे का कोई मामला नहीं है। आप पर पहले तो गोमाता नाराज थी। अभी कृपलानी साहब चले गये, इन्होंने कहा कि इस बजट में गोमाता के करोड़ों रुपये दिये गये हैं। आपने देवासी साहब को चेयरमेन तो बना दिया लेकिन उसमें बजट कितना दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें।

दूसरी बात, इस बजट में 360 बिन्दु हैं, अगर 360 बिन्दुओं में एक करोड़ रुपया भी गोमाता के कल्याण के लिए दिया हो तो आप स्पष्ट कर दें, हम मान जाएंगे। उलटा गोमाता के कल्याण के लिए पिछली सरकार में पहली बार अनुदान लागू किया गया था, इस सरकार के आने के बाद उस अनुदान पर सबसे पहले कैंची चलायी गयी। आज गायों की स्थिति बहुत खराब है। कल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गाय और मंदिर की चर्चा अगर राजस्थान में नहीं होगी तो क्या बांग्लादेश में होगी। मैं यह कह रहा हूं कि खूब चर्चा करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगें गाय पर और मंदिर पर, लेकिन गाय के लिए इस ढाई साल में क्या एक रुपया भी अनुदान गोशालाओं तक पहुंचा क्या? अगर एक रुपया भी पहुंचा हो तो मैं मेरी सदस्यता छोड़ दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। पिछली बार आपने देखा होगा कि अपना फसल खराबा हुआ था। आदान अनुदान के तहत जो पैसा हमको मिला है, मैं आपको यह कह रहा हूं कि अब तक किसी भी साल में, जो पिछली बार हमने कैटल कैम्प को और गोशालाओं को पैसा दिया है, उसकी तुलना में आप अपना पूरा रिकार्ड निकाल लेना, अगर उससे एक भी साल अधिक निकल जाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय मंत्री महोदय, मैं सिर्फ गोशाला की बात कर रहा हूं, मैं फसल खराबे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ गोशाला के लिए कहा है। मैं सिर्फ गोशाला की बात कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): दोनों को ही जोड़ कर है, कैटल कैम्प भी है और गोशाला भी है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नहीं, मैं आपकी बात का अनादर नहीं करना चाहता, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गोशाला को एक रुपया भी नहीं मिला है। देवासी साहब से हम कई बार मिले हैं, संत लोग धरने पर बैठे हैं। वो संत लोग जो यह कहते थे उस समय हमारे को कि अगर आपकी सरकार में गहलोत ने काम नहीं किया तो हमारी सरकार आएगी तब करा लेंगे। उस समय मैंने एक संत से पूछ लिया झुंझुनूं के अन्दर कि संत साहब, आप कैसे बैठ गये यहां धरने पर। तो उन्होंने ऋग्वेद की ऋचा का श्लोक बोल दिया उस समय। दूसरी बार सुनी है मैंने ऋग्वेद की वह ऋचा जो माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने बतायी है। संस्कृत और हिन्दी का अर्थ तो सबको समझ में आता है, मैं उस लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधा-सीधा सरकार से एक बात कहना चाहता हूं, आपने रिसर्जेंट राजस्थान चलाया, रिसर्जेंट, हिन्दी और संस्कृत में तो अर्थ समझ में आता है, लेकिन मेरी तरह बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, किसान हैं वो पूछते हैं कि रिसर्जेंट राजस्थान क्या होता है। हमें पता है कि जब हमारी सरकार थी उस समय सुराज संकल्प यात्रा माननीय वसुन्धरा राजेजी ने निकाली थी पूरे राजस्थान में, हर भाषण में जय-जय राजस्थान का नारा लगता था। जय-जय राजस्थान का नारा उस समय लगता था तो उसके बाद में रिसर्जेंट करने की आवश्यकता क्या पड़ गयी राजस्थान को? मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान तो सर्जेंट था, है और रहेगा। आप जय-जय राजस्थान बोलते हो, हम भी जय-जय राजस्थान बोलते हैं। अगर रिसर्जेंट करने की किसी चीज की आवश्यकता है तो वह योजनाओं की है और वो योजनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं- स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। इतने सारे इंडिया हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वदेशी जागरण मंच का तो पता ही नहीं है वह कहां खो गया। इन सारी योजनाओं की अगर कांग्रेस सरकार बात करती तो स्वदेशी जागरण मंच नारे लगाते हुए आ जाते। स्वदेशी जागरण मंच को खा गयी है सरकार। उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक मंदिर की बात करने वाले लोग रोजगारेश्वर भगवान का मंदिर वापस नहीं बनाएंगे। जब रोजगारेश्वर महाराज के मंदिर को ही तोड़ दिया तो भर्तियों के ऊपर कोर्ट स्टे ही देगा। महाराज वहां सबकी जिह्वा पर बैठ जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, मैं भर्तियां नहीं होने दूंगा जब तक मेरा मंदिर नहीं बनेगा। इस सरकार के

(डा. राजकुमार शर्मा)

आने के बाद कितने मंदिर तोड़े गये, कितनी गायों की हत्या हुई? आज हिंगोनिया गोशाला शर्मनाक बनी हुई है पूरे प्रदेश के लिए, उस पर कोई नहीं सोच रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है वरिष्ठ लोग बैठे हैं, गोशाला का अनुदान वापस चालू कर दो। गाय माता का आशीर्वाद वापस लो और रोजगारेश्वर महाराज के मंदिर को वापस बनवा दो, ताकि रोजगारेश्वर महाराज सब पर आशीर्वाद रखें और लोगों को रोजगार देना शुरू कर दें। इन्द्र देवता भी नाराज हैं और इस बजट के बाद आम जनता, जनता जनार्दन भी नाराज हो गयी है सरकार से। निराशावादी बजट है यह। कोई यह बात सुनना नहीं चाहता कि घाटे में है सरकार। जो बड़े-बड़े वादे किये थे, अच्छे दिनों के जो वादे किये थे इस सरकार ने, कम से कम वो थोड़ा बहुत तो पूरा करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा विभाग की बात करना चाहता हूं। रिसर्जेंट कर दो मेरे सैटेलाइट अस्पताल को, माननीय मंत्री महोदय। पिछले दो-ढाई साल से मेरा सैटेलाइट अस्पताल, नवलगढ़ का, बंद पड़ा है, आप रिसर्जेंट कर दो उसको। पिलानी में लाखों लोग रहते हैं वहां पर बड़ी आबादी है, आप वहां के प्रभारी मंत्री हो। पीएचसी मैंने खोल दी थी उस समय मेरी सरकार में जब मैं मंत्री था, आप सीएचसी में क्रमोन्नत कर दो। गांव वाले सैकड़ों लोग आये थे, आपसे मिले, आपने उनको जुबान भी दी है। मुझे पता है कि आपने जो जुबान दे दी, आप जुबान से पीछे नहीं हटने वाले। मुझे पूरा पता है, लेकिन पता नहीं यह दुर्भाग्य है कि यह क्या हो गया राजेन्द्रजी राठौड़ को कि सात बार नवलगढ़ के अन्दर सैटेलाइट अस्पताल के लिए कह दिया कि अगले सात दिन में काम चालू करा दूंगा, लेकिन ढाई साल में वह काम चालू नहीं करा पाये। नब्बे परसेंट काम पूरा हो चुका है, दस परसेंट के लिए आज ढाई साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने 31,035 भर्तियां निकाली थीं मेरे समय में। आपने सत्रह हजार समथिंग भर्तियां कर दीं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वे भर्तियां हमारी निकाली हुई थीं आपकी नहीं निकाली हुई हैं। लेकिन आपने उस काम को आगे बढ़ाया उसके लिए आपका शुक्रिया। आप शेखावाटी से आते हैं और शेखावाटी के अन्दर की पीड़ा आपको ज्यादा पता है। लेकिन नौ हजार भर्ती रद्द कर दीं, पांच हजार अभी शेष हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31035 की भर्तियां हों, चाहे वह फार्मासिस्ट की भर्तियां हों, चाहे लैब टैक्निशियन की भर्तियां हो, चाहे रेडियोग्राफर की भर्तियां हों, चाहे सहायक

(डा. राजकुमार शर्मा)

रेडियोग्राफर की भर्तियां हो उन भर्तियों को पूरा कर दीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि अधिकारियों पर मत छोड़िये आप, अधिकारियों पर मत छोड़िये। अधिकारी आपके पीछे पड़ चुके हैं, साफ बता देता हूं आपको। अधिकारी इस सरकार का दिवाला निकालने में लगे हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि और ढाई साल झेलना है। लेकिन हमें भी हंसी आती है कि ये किसी के नहीं होते। ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए होते हैं। नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि खेल के लिए बहुत बड़ा बजट दे दिया। हमारी झुंझुनूं की खेल यूनिवर्सिटी को रिसर्जेंट कर दो, हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा हूं आपसे। खेल यूनिवर्सिटी की हमारी चार साल पुरानी मांग है। पास भी हो गया, सब कुछ हो गया। जमीन भी आबंटित हो गयी। लेकिन उसको रिसर्जेंट कर दो, उसको पुनर्जीवित कर दो, उस काम को आगे बढ़ा दो। उसको वापस खड़ा कर दो जैसे राजस्थान को खड़ा करना चाहते हो। हमारे सैनिक स्कूल को रिसर्जेंट कर दो। झुंझुनूं जिला सैनिकों का सबसे बड़ा जिला है। शहीद होने वालों में अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं से आते हैं तो वह झुंझुनूं जिले से आते हैं। हमें गर्व है हमारी धरती पर। लेकिन उस सैनिक स्कूल को आज तक लटका रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। सैनिकों के लिए तो कम से कम यह सरकार, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर तो धोखा दे चुकी, लेकिन कम से कम झुंझुनूं को सैनिक स्कूल तो दे दो, यह मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं। सैनिक स्कूल, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी, आपने डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है दो हजार ग्राम पंचायतों के लिए, दो हजार पंचायतों में डिवाइड कर दो डेढ़ सौ करोड़ रुपये को। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि डेढ़ सौ करोड़ को दो हजार के अन्दर आप बांटो, मात्र साढ़े सात लाख रुपये एक पंचायत को मिलेंगे एक खेल स्टेडियम के लिए। क्या साढ़े सात लाख रुपये में खेल स्टेडियम की चारदीवारी भी बना लोगे? नहीं बनेगी। उस डेढ़ सौ करोड़ रुपये को डेढ़ हजार करोड़ रुपये अगर यह सरकार करेगी तब जाकर खेल स्टेडियम हर गांव में बनेगा। वर्ना तो अच्छे दिनों की बात की तरह यह बात भी समाप्त हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं,

(डा. राजकुमार शर्मा)

लेकिन, प्रभारी मंत्रीजी, आप हमारे वकील हैं, आपको कहना चाहते हैं। आप हमारी बात आगे रखते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास नब्बे प्रतिशत बन गया था आज से दो साल पहले नवलगढ़ में। दो साल में उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगा पाये हैं। पूरे देश में गायों के नाम पर, मंदिर के नाम पर बात करने वाले कम से कम बाबा साहब का तो ध्यान करो, उस छात्रावास को तो रिसर्जेंट कर दो। उस छात्रावास को तो पूरा करवा दो ताकि गरीब दलितों के बच्चे उसके अन्दर पढ़ें, रहें, सरकार की योजनाओं का फायदा लें और आगे बढ़ें। किसी सर्विस में जाएं और समाज की मुख्य धारा में उस परिवार का बच्चा शामिल हो जाए। लेकिन आज तक, ये जो बातें बता रहा हूं, आपके सामने हैं। आप जांच करवा लें। प्रभारी मंत्रीजी के सब नालेज में है यह। ये चाहते भी हैं कि यह काम हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन सच्चाई यह है कि आप चाहते हो मन से, लेकिन आपकी चलने नहीं दे रहे हैं लोग-बाग़ या चलती नहीं है, पता नहीं है या चलाना नहीं चाहते। यह आप खुद तय करें। हम तो चाहते हैं कि आपकी चले ताकि झुंझुनूं जिले का विकास हो। मैं प्रभारी मंत्री रहा हूं पांच-पांच जिलों में, जितना मेरे से बन पड़ा बिना किसी भेदभाव के काम किया।

मैं बात करना चाहता हूं पानी की। ड्राई के अगेंस्ट ट्यूबवैल मिले चार या पांच। पूरे ढाई साल में नवलगढ़ को एक भी नया ट्यूबवैल नहीं दिया गया। आप चाहे जल स्वावलम्बन की बात कर लो या बड़ी-बड़ी घोषणाओं की बात कर लो। या मुख्य मंत्रीजी के नाम पर जलदाय मंत्रीजी ने झुंझुनूं में जाकर यह कहा था कि यह कुम्भाराम लिफ्ट नहर योजना हम लेकर आये हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप पीने के पानी के लिये ट्यूबवैल नहीं दे सकते और जब मैंने ट्यूबवैल की बात की तो मंत्री महोदया कहती हैं कि पैसा नहीं है, हम ड्राई के अगेंस्ट दे सकते हैं। तो जो नयी बसावट हो गयी, वह पानी कहां से पीएगी?

मैं आपसे ऊर्जा वाले मामले में भी हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि जो गैर आबादी के लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं उस बैरीकेड को हटा दो। राजस्थान का हर व्यक्ति पीड़ित है। आप सब लोग भी इस बात से पीड़ित हैं कि गैर आबादी के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कनेक्शन के लिये लोग दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। सैल्फ फाइनेंस स्कीम के अन्दर वे पैसा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं

(डा. राजकुमार शर्मा)

है। आज घरों को छोड़ कर, गावों को छोड़कर लोग खेतों में बस गये। पड़ौसी से मांग कर अगर वह एक लट्टू जला लेता है तो 15-15 हजार रुपये उसकी वीसीआर भरी जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि बिजली आए या नहीं आए, आप छोड़ दें उस बात को, आप तो सिर्फ गैर आबादी का जो एक बैरीकेड है कि गैर आबादी में जो बसे हुए लोग हैं उनको हम कनेक्शन नहीं देंगे, उन कनेक्शनों को खोल दो। आप कहोगे कि बिजली नहीं है कहां से देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार कहां हैं, क्यों डिग्रियां दे रहे हो। अगर रोजगार के हिसाब से आप डिग्रियां देने लगोगे तो आपको ये कालेजे बंद करने पड़ेंगे। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि कैसे भी करके आप जो गैर आबादी वाला बैरीकेड है, इसको हटा दो।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तब हो सकता है कि आपने बुराई की हो। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्रीजी ने और गुजरात की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान की यह योजना हम लोग गुजरात में भी लागू करेंगे। लेकिन आज उस योजना की स्थिति क्या है? मुझे पता है रात-रात भर आप इंस्पेक्शन करते हो, आप भी जाते हो, लोगों पर छापा मारते हो। हम लोग भी रात-रात भर जगते थे। आपकी भी वही इच्छा है कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता है, उसको इलाज मिले। लेकिन आज उसको भामाशाह से जोड़ कर सबसे बड़ा अहित किया है उस व्यक्ति का। आज प्राइवेट अस्पताल में वेश बदलकर आप चले जाओ, किसी दूसरे को भेज दो, निजी अस्पताल वाले भामाशाह कार्ड के नाम पर उस पेशेंट को दुत्कार कर बाहर भेजते हैं। निजी अस्पतालों को छोड़िए, अगर सरकारी अस्पताल में भी हमारा व्यक्ति जाता है तो जाते ही डाक्टर यह कहते हैं कि पहले राशनकार्ड लेकर आओ। राशनकार्ड इसलिए मांगते हैं कि हमने यह तय कर दिया कि बाहर के प्रदेश से जो भी आएगा, उस व्यक्ति का पैसा लगेगा। उनको लगता है कि कहीं यह बाहर का व्यक्ति नहीं हो, इसलिए राशनकार्ड मांगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, दर्द आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया और वह व्यक्ति अगर सीधा अस्पताल में अपने माता पिता को लेकर चला गया, अपने बेटे को लेकर चला गया तो क्या राशनकार्ड साथ लाना जरूरी है? दो घंटे बाद भी राशनकार्ड आ सकता है। अलवर के अस्पताल की आपने

(डा. राजकुमार शर्मा)

जांच कमेटी बैठायी है, अलवर के अस्पताल का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि राशनकार्ड के नाम पर, भामाशाह कार्ड के नाम पर बाहर कर दिया गया। यह हम सबके लिये कष्ट की बात है, हम सबके लिये शर्म की बात है। आज कोई व्यक्ति इलाज के लिये आए तो उस व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिये।

पिछली सरकार में मेरे गांव परसरामपुरा में दो बड़ी टंकियां स्वीकृत हुई थीं। तीन करोड़ रुपये मात्र का छोटा-सा बजट था, लेकिन इस सरकार ने 6 महीने के रिव्यू के नाम से उसको रद्द कर दिया। प्रभारी मंत्री महोदय, इसको रिसर्जेंट करवा दो। आपने तो पहले ही मेरे से वादा किया था, मेरे को अनशन से उठाया था आपने कि मैं करवा दूंगा। थोड़ा-सा अपना वह महाराणा प्रताप वाला रूप दिखाना पड़ेगा, वर्ना घनश्यामजी भाई साहब की तरह आप भी धीरे-धीरे निराश हो जाओगे। आपको साफ कहता हूं, चारों तरफ से ऋचा के श्लोक याद करोगे। उस ऋचा के श्लोक का अर्थ उन्होंने तो बता दिया, पूरे अर्थ का वाकया बता दिया। वह ऋचा का उपयोग महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये था या फिर जनता के लिये था? क्योंकि अभिभाषण तो जनता का आइना होता है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण को तिलांजलि दी गयी तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जनता के लिये कम से कम यह मत करो क्योंकि जनता तैयार खड़ी है ऋग्वेद की उस ऋचा का उपयोग एक वोट के रूप में करने के लिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीपीपी मोड के लिये भी आपको कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, पीपीपी मोड में आपकी सोच अच्छी हो सकती है लेकिन दिल्ली रोड पर एक अस्पताल है निम्स, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस रास्ते से रोजाना गुजरते हो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आते-जाते एक बार चैक कर लेना, अगर जयपुर में सबसे ज्यादा विश्वासघात मरीजों के साथ में कोई अस्पताल या कोई संस्थान कर रहा है तो वह यह निम्स यूनिवर्सिटी है। पीपीपी मोड के सहारे दिल्ली रोड के 7 अस्पताल उन्होंने ले लिये। अब जब उन्होंने ले लिये तो वहां जो पेशेंट आएगा वह सीधा कहते हैं कि निम्स में जाओ। वह निम्स यूनिवर्सिटी वह है, मुन्ना भाई एमबीबीएस एक पिक्चर आयी थी उसमें एक वाकया दिखाया गया था कि जब एमसीआई का इंस्पैक्शन आएगा तो गांव से 100-100 रुपये में पेशेंट लाकर लिटा दिये जाते हैं, यह वह निम्स यूनिवर्सिटी है। हमारी जनता की उम्मीदें जो पीएचसी, सीएचसी थीं, उसको कैसे मिल गयी, वह इसलिए मिल गयीं कि आपने ट्रांसपेरेंसी रखी कि

(डा. राजकुमार शर्मा)

जो आयेगा और ज्यादा बोली लगाएगा, वह लेगा। 33 लाख रुपये सालाना हम उसको दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय यह कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं निम्स जैसी यूनिवर्सिटी को सरकारी अस्पताल सौंपना, क्या वे रैफरल हास्पिटल नहीं जाएंगे? जो हमारे पेशेंट वहां पर जाएंगे उनको वे सीधे कहेंगे कि इलाज कराना है तो निम्स में जाओ। पीपीपी मोड वाले 90 अस्पताल आपने अभी तक दिये हैं। आपने एक्सपेरीमेंट कर लिया, नतीजा आपके सामने है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस पीपीपी मोडल को खतम करो। सरकारी डाक्टर की कमी है। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, डाक्टर्स की कमी है इसीलिए उस समय 13 मेडिकल कालेज की सोच लेकर आये थे हम लोग, आपने उसको आगे बढ़ाया है। आज आठवीं मांग श्रीचंद कृपलानीजी ने कर दी है चित्तौड़गढ़ के लिये। लेकिन, कृपलानी साहब, मंत्री महोदय भी जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हो कि हमारे जयपुर एसएमएस मेडिकल कालेज के अलावा कोटा का मेडिकल कालेज ले लो, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर का मेडिकल कालेज ले लो, चारो के चारों वेंटीलेटर पर हैं। जब एमसीआई इंस्पैक्शन टीम आती है तो जयपुर के प्रोफेसर्स को वहां पर जबरदस्ती लगाया जाता है। वे हाथ जोड़ते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमको उन कालेजों को बचाना है इसलिए उनको भेजते हैं। क्योंकि हमारे पास डाक्टर्स को पढ़ाने के लिये ट्रेंड स्टाफ नहीं है। पीपीपी माडल में 7 की जो सोच रखी है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप सीकर से चूरू लेकर जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, हम चूरू भी आ जाएंगे इलाज कराने के लिये। लेकिन चालू तो कराओ, रिसर्जेंट तो कराओ। ढाई साल तो बीत गये, अभी एक भी अस्पताल की नींव नहीं रखी गयी। पीडीकोर से सर्वे हम पूरा करा चुके थे, सारा काम हम करा चुके थे। सातों मेडिकल कालेज अगर खुलेंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो कम से कम अगले पांच साल बाद में हमारे पास डाक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी।

मैं आपसे यही बात कहते हुए बिजली के मामले में दो-तीन बातें और कह दूं। मेरे यहां पर तीन जीएसएस तीन साल पुराने बनकर तैयार हैं लेकिन तीन साल से कुछ सामान नहीं मिल रहा। तीन साल में 6 महीने हमारे भी हैं। सामान नहीं मिल रहा इसलिए वे तीनों चालू नहीं हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि वे हमारे जो 95 प्रतिशत बने हुए हैं, 5 प्रतिशत पूरा करके उनको चालू करवा दो। मेरे हिसाब से अजमेर डिस्काम तो घाटे में होना नहीं चाहिये, फिर भी अगर है तो और कर्जा ले लो। कर्जा लेकर जहां-जहां काम बंद पड़े हैं, कम से कम उनको पूरा कर दो।

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रधान मंत्री सड़क योजना में ढाई साल पहले दो सड़कें बनी थीं मीलनगर और गंगासागर ढाणी की, आज तक उनका डामरीकरण नहीं हुआ। कृपलानी साहब, आप बार-बार कह रहे थे कि हमने चार हजार किलोमीटर सड़कों का वादा कर दिया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने नये गांवों को जोड़ा है। ये गांव कौनसे हैं? 7-8 साल पहले वाजपेयीजी के समय से ढाई सौ तक की ढाणियों को जोड़ने का जो प्लान था, वही प्लान है यह, नया किसी का नहीं है। ढाई साल पहले जिन सड़कों पर कांकरे पड़े थे, अर्थ वर्क हुआ था, कम से कम उन पर डामरीकरण तो करवा दो। हम ठेकेदार का घेराव करते हैं, एक्सईएन का घेराव करते हैं तो ठेकेदार यह कहता है कि हमने जो अर्थ वर्क किया, आज तक उसका पैसा भी नहीं मिला। जब उसका पैसा नहीं मिला तो हम क्या उम्मीद रखें? हालांकि उम्मीद पर सब जिंदा हैं। आपकी तरह हम भी हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सड़कें बनाओ, गांव-ढाणियों को जोड़ो। पीने के पानी की व्यवस्था कराओ। गऊ माता का जो अनुदान है उसको वापस चालू करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा निवेदन सुनो, कांग्रेस के पांच साल के राज में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की जो हालत हुई है, इस वजह से यह स्थिति हुई।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गौरव पथ के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत सुन्दर गौरव पथ बने हैं। लेकिन हर गांव की लम्बाई 2 से 3 किलोमीटर है, एक किलोमीटर मिला है, गौरव पथ में। एक मोहल्ले से शुरू करके दूसरे मोहल्ले में पहुंचा दिया तो 7 मोहल्ले नाराज। कृपलानी साहब, जब चुनाव आएंगे तो आपको और हम दोनों को रगड़ेंगे वे लोग। मैं कहता हूं कि जो एक किलोमीटर बनाया, वह बहुत अच्छा बनाया, लेकिन यह तय कर दो कि पूरे ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर को हम सड़क से जोड़ेंगे, इससे कम से कम कोई व्यक्ति नाराज तो नहीं होगा।

यही बात कहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के भाषण पर दो, तीन ऐसी बातें बोली हैं जो पूरे देश के लिये शर्मनाक हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, जे.एन.यू. पर नहीं जा रहा राठौड़ साहब, नहीं जा रहा। माननीय हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, लौहपुरूष-लौहमहिला जिनको किस-किस नाम से पुकारा जाए, इंदिरा गांधीजी के लिए कुछ सदस्यों ने यह कहा कि अपने खुद के कारणों से वो मरी हैं। अगर वे भिंडरावालों से पंगा नहीं लेतीं तो क्यों मरतीं ? मुझे तो संदेह है कि

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय कोई सत्ताधारी सदस्य कल यह नहीं कह दे कि सैनिक जो हमारे झुंझुनूं जिले या पूरे राजस्थान के हिन्दुस्तान की सीमाओं पर बैठे हैं, वो बैठे-बैठे यह कहें कि साहब यह तो नौकरी करने के लिए गया था, अपना परिवार पालने के लिए। किस को कहा था कि पाकिस्तान वालों से जाकर पंगा ले? दु:ख है। इस बात को कार्यवाही से निकलवाना। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह परम्परा नयी शुरुआत हो जाएगी। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए कभी बुराई नहीं की है। हम भी कई बार कहते हैं उनके लिए कि वो कश्मीर हमारा है जहां पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए। आज भी कहते हैं हम लोग। लेकिन इंदिरा गांधीजी के ऊपर अंगुली उठाने वाले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए सदन से। क्योंकि उस लेडी ने, उस महिला ने अगर पंजाब के अन्दर आतंकवाद का खात्मा नहीं किया होता तो पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। आज खालिस्तान बना होता। यही बात मैं कहते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। भारत माता की जय।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आप रोकना या टोकना मत क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। न तो हमें पर्चियों में मौका मिल पा रहा है, इतने सारे लोग पर्ची लगाते हैं, न स्थगन में मिला, न 50-60 क्वेश्चन लगाये उसमें मिला। मुझे लगता है, अगर विपक्ष की दो-तीन दिन लगातार पर्चियां निकलती रहीं तो मंत्री भी न पर्ची लगाने लग जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़े-बड़े दिग्गज, बड़े-बड़े धुरंधर नेता बैठते हैं और सभी का मैं सम्मान करती हूं। आप जैसे, घनश्याम तिवाड़ीजी आदरणीय उनके जैसे, राठौड़ साहब जैसे बहुत धुरंधर नेता हैं ये लोग। बहुत कुछ सीखने की इनसे कोशिश करती रहती हूं- सीखने की, समझने की और जानने की। सुनते-सुनते शायद कुछ सीख जाऊं, आप लोगों को देखते-देखते। न तो मैं किसी राजनीतिक संगठन से कभी ताल्लुक रखती हूं, न कभी किसी संस्था, संगठन या पार्टी का मैं हिस्सा रही हूं। न कोई मुझे अंगुली पकड़ कर राजनीति में लाया है। मैंने जो कुछ पाया है अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, इसलिए कोशिश करती रहती हूं। सिर्फ यहां बैठकर ही अगर मुझे कुछ सीखने को मिले तो मैं प्रयास पूरे करती हूं। पिछले सात सालों में सीखने की कोशिश तो कर रही हूं लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही है, उपाध्यक्ष महोदय। चाहे बजट पर बोलना हो या अभिभाषण पर बोलना हो, सत्ता

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

पक्ष का काम है अपनी सरकार के कामों का, उनकी नीतियों का समर्थन करना, उनकी तारीफ करना। चाहे मन में कितना भी गुस्सा हो अपने क्षेत्र में काम न होने का, लेकिन वो चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी तरह विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, कितनी भी बढ़िया नीति बनाए, उसमें भले ही काम में कमी दिखे या न दिखे, लेकिन पुरज़ोर तरीके से विरोध करना। कहीं कोई कमी न रह जाए विरोध करने में। उसका एक ही अर्थ है और दोनों की वजह एक ही है कि दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब को अपने-अपने बड़े-बड़े वरिष्ठ नेताओं को खुश करना है, आगे भी टिकट चाहिए। आगे टिकट चाहिए तो फिर खुश तो करना ही पड़ेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो बार से निर्दलीय विधायक के रूप में यहां हूं और आगे भी किसी भी पार्टी से टिकट लेने की इच्छा नहीं रखती हूं। मैं जीतूंगी और फिर तीसरी बार जरूर यहां आऊंगी आप लोगों के बीच, यह भी तय है। इसलिए मैं यहां पर जो भी कुछ बोलती हूं या बोल रही हूं, वो निष्पक्ष जनता की आवाज बनकर। इसमें मेरी अपनी आवाज नहीं, जनता की आवाज है क्योंकि इसमें टिकट जैसा कोई लालच नहीं है। पुराने जमाने में एक कहावत होती थी, काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि पिता बहुत अच्छे हों, धनवान हों या कितने भी बड़े रूतबे के हों, अगर उनकी संतान अच्छी न हो तो बिगड़ी हुई संताने उन्हें अर्श से फर्श पर ला पटकती है और अगर संतानें अच्छी निकलें तो जुंआरी, शराबी और गरीब पिता को भी फर्श से अर्श पर ले जा सकती हैं। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।

मैं एक बात बताना चाहती हूं, बार-बार कांग्रेस के लिए आप लोग कहते रहते हो कि पिछले 60-62 सालों से आप राज कर रहे हो। लगातार आप राज किए जा रहे हो। आपने क्या किया। बहुत सारे आरोप आप लगाते रहते हो। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि एक बार तो आपको भी मौका मिला है जब वाजपेयीजी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आपको मौका मिला। हो सकता है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं में कुछ ज्यादा कर्मठ रहे हों, ज्यादा एक्टिव रहे हों। कुछ तो उनमें बात होगी जो वो 62 साल से राज कर रहे हैं, वर्ना ऐसे तो जनता किसी को सत्ता सौंपती नहीं है। यह तो जनादेश है, इस पर बार-बार अंगुली उठाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपके पास है, जैसे बच्चे भूखे रहें और कर्जा हो मां-बाप के ऊपर तो भी मां-बाप कहीं से भी लाकर उसका पेट जरूर भरते हैं। लेकिन आप हर बात पर कह देते हो, हम पर कर्जा है, हम पर कर्जा है। यह कोई बात नहीं है कि कर्जा-कर्जा दिखाकर आप हमेशा यह बात

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कहो। संतान के बारे में मैंने बात कही, अच्छी संतानों के संतान रूपी कार्यकर्ता, इसमें मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को भी एक बार शासन की बागडोर मिली है, अगर आपके कार्यकर्ता अच्छे होते तो शायद उस बागडोर को सम्भाल कर रखते। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद हिन्दुस्तान में वाजपेयी जी जैसा और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, बेजोड़, उनसे कंपेरिजन किसी का हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमने देखा, तेरहवीं विधान सभा में, तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में मैं भी थी। आपके साथ सौभाग्य मिला मुझे। उस वक्त शीर्ष नेतृत्व जो राजस्थान का था, बहुत बढ़िया था। अहंकार से कोसों दूर और जमीन से जुड़े हुए माननीय श्री अशोक गहलोतजी। अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे कि राजस्थान का अच्छा विकास हो, अच्छा बढ़े, आगे बढ़े। परन्तु शायद उनके संतान रूपी कार्यकर्ता या यूं कहें उनके पदाधिकारी, उनका मंत्रिमंडल, वो ऐसे नहीं थे, वो शायद बिगड़ी संतानें थे जिन्होंने उन्हें इस हाल पर ला पटका। अभी जो दो दिन इन्होंने खराब किये हैं, शुरूआत के जो दो दिन खराब हुए हैं, उसके बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी अपने देश से प्यार है। अगर मुझे मौका मिला है तो अपना व्यू जरूर रखना चाहूंगी कि दो दिन इन्होंने खराब किये हैं। यह जो विधान सभा जो चल रही है, जनता के पैसों से चलती है। राजस्थान की आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए और कुछ पाने के लिए चलती है। आपके बड़े नेताओं को सम्मान दिलाने के लिए थोड़े ही न चलती है जो आप उन्हें सम्मान दिलाने के लिए यहां लड़ाई लड़े जा रहे हो कि हमारे नेता को ऐसा क्यूं कहा? जो व्यक्ति देश के टुकड़े करने की बात कहे, मुझे नहीं पता जे.एन.यू. में क्या हुआ लेकिन जो देश के टुकड़े करने की बात कहे या देशद्रोह की बात करे या देशद्रोहियों का साथ दे, उनका समर्थन करे, वो भी शायद उतना ही पाप का भागी है। उसे भी उतनी ही सज़ा होनी चाहिए जितनी कि एक देशद्रोही को होती है। मैं समझती हूं कि जिसे अपने देश से प्यार है, ऐसी बातें सुनने के बाद अगर उसका खून नहीं खौलता है तो उसका खून खून नहीं पानी है। इसलिए आपने उसका विरोध किया वो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन सदन में आने के बाद जो दो दिन खराब हुए, उसमें आपका भी हाथ रहा है। अगर ये लोग अपने नेताओं को सम्मान न दिलाने के बजाए यह सोचते कि इसमें लोगों का पैसा लगा है, हम लोगों का काम करें यहां बैठकर न कि नेताओं को सम्मान दिलाएं। वो तो खुश करना होगा तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, टिकट तो वैसे भी मिल जाएगा।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

दूसरा आपका था कि आपके जो विधायक रहे हैं अगर उनके मुंह से कुछ निकल भी गया था तो वो यह कह सकते थे कि यह हमारी व्यक्तिगत सोच है और अगर हमारे देश के बारे में ऐसा कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसका हमें खेद है। अगर ऐसा कह दें तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटे हो जाते। बल्कि वो और बड़े हो जाते। क्योंकि यह तो जाहिर-सी बात है कि देश के बारे में बुराई सुनने के बाद या टुकड़ों की बात सुनने के बाद गुस्सा आना तो लाजिमी है और जिसको नहीं आता उसे इस देश को छोड़ देना चाहिए। जैसा मैंने बताया, संतान रूपी अभी पूर्व मुख्य मंत्रीजी थे, बहुत अच्छे थे बहुत जमीन से जुड़े हुए थे और बहुत ही कार्यकुशल थे। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके मंत्रिमंडल थे, उनके पदाधिकारी थे, वो ऐसे बेलगाम हुए, ऐसे बेलगाम हुए कि सारे ही चले गये किसी का अता-पता नहीं है, 21 ही रह गये। तो अहंकार तो किसी का भी नहीं रुकता चाहे राजा हो चाहे रंक। अहंकार किसी का नहीं टिका है। और जो अभी-अभी आप एक बात कह रहे थे कि इनोवा में आना पड़ जाएगा आपको, तो यह तो जनता तय करेगी, आप तय करने वाले या मैं तय करने वाली कुछ नहीं होती हूं। अहंकार कभी किसी का टिका नहीं है, आप जैसे वो करते हो।

जन सुनवाई की भी बातें हो रही थीं। जन सुनवाई जो आप करते हो, जैसा मुझे पता चला है, एक बार मैंने भी चाहा कि मैं किसी से मिल लूं। तो मुझे पता चला कि पहले आपको बीजेपी के किसी बड़े पदाधिकारी से लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में चार मंत्री बैठते हैं, आप वहां जाकर मिल सकते हो, अपनी समस्या रखनी हो तो। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप राजस्थान के मंत्री हो कि पार्टी के मंत्री हो? जो बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, वे अपने लिए दूसरे मंत्रियों की व्यवस्था करेंगे क्या? या आप ही सुनेंगे उनकी समस्या? यह थोड़ा-सा आप क्लीयर कर दें। आप अपना दरबार सबके लिए खुला रखिए। आपने जन सुनवाई बीजेपी पार्टी की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बना रखी है। उसको आप सबके लिए खोलिये, सबको आने दीजिए। दिल बड़ा रखिए और सबकी समस्याएं सुनिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप भी बिगड़ी हुई संतानें कहलाएंगी। मैं यह पर्सनली ख्वाहिश रखती हूं ...(व्यवधान) आप बिगड़ी हुई संतानें कहलाएंगे क्योंकि इनके मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी में कोई कमी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह शब्द एक्सपंज कराओ, बिगड़ी हुई संतान। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ यूं इशारा करके इन्होंने कहा बिगड़ी हुई संतान, एक्सपंज कराओ।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी, सुन तो लीजिए। (व्यवधान) मैं कहती हूं कि मैं अपने क्षेत्र की मुखिया हूं और जितने भी मेरे क्षेत्र में....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं यह पूछना चाह रहा हूं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जब सब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती हूं, आप भी सुनिए। (व्यवधान) मैं बजट पर भी आ रही हूं। आप लोग तो जब से इनकी बुराई कर रहे हैं, बजट पर तो आपने बाद में शुरू किया है...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आपने आधा घण्टे बाद बजट पर बोलना शुरू किया है, उससे पहले सिर्फ बुराई करते रहे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सदन में प्रवचन अलाउ है क्या?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं तो तर्क की बात कर रही हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रवचन अलाउ है क्या? यह प्रवचन दे रही हैं या बजट पर बोल रही हैं?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं तो तर्क की बात कर रही हूं, मैं तो सच्चाई कह रही हूं। आप तो सिर्फ बुराई कर रहे थे। मैंने दोनों की बातें की हैं। आपको इतनी क्यों चुभ रही हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्य, एक बार तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आपको बात कहनी है, आप आसन की तरफ मुखातिब होकर अपनी बात कहें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सारी ।

श्री उपाध्यक्ष: और अब बात ऐसी कहें जिससे उत्तेजना न हो। सुपर सेसिटिव 200 पीपल हैं So it is better for you to be careful about it.

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने किसी के बारे में भी गलत नहीं कहा। सिर्फ यह कहा कि....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जब इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की बिगड़ी संतान, तब तो आप टेबल बजा रहे थे। अब कहा कि आप भी बिगड़ी संतान कहलाओगे अगर सही नहीं किया।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने कहा, कहलाओगे, अगर ऐसा नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: किसी की भी संतान बिगड़ी हुई नहीं है, अपनी-अपनी मानसिकता का फर्क है। विराज जाएं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): इतनी सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती, आप लोग जाएं। या ...(व्यवधान) अब आप सुन लीजिए, अब आप खुश होंगे। मैं नहीं चाहती हूं। सुनिए, मेरी पर्सनली यह ख्वाहिश है कि जब तक नरेन्द्र मोदीजी की सांसें चलें, जब तक नरेन्द्र मोदी जी की सांसें चलें, यह देश उनके नेतृत्व में चले। यह मैंने इसलिए कहा कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि वे हमेशा रिपीट होते रहें।

(14.53 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

मैं थोड़ा-सा सैक्युरलिज्म पर भी बोलना चाहूंगी, धर्म निरपेक्षता पर। सैक्युरलिज्म की हर कोई बात करता है, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, हर कोई उसके बारे में बात करता है। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उसके बारे में बातें होने लग जाती हैं कि धर्म निरपेक्ष ऐसे और वैसे। काफी झगड़े भी हो जाते हैं। कई तरह की बातें होती हैं। चुनाव के नजदीक आते ही जब धर्म निरपेक्षता की बातें होती हैं। मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं। मैं कलमा भी पढ़ लेती हूं, शायद पिछले 20-25 साल से पढ़ भी रही हूं, गायत्री मंत्र भी पढ़ती हूं। (व्यवधान) आप सुन तो लीजिए। मैं भी चुपचाप सुनती हूं न आप लोगों को। ला इलाह इल लिलला, मोहम्मद उर रसूल्लाह, यह कलमा है। और गायत्री मंत्र तो हम सभी जानते हैं, ॐ भूर्भुव:स्व:। दोनों ही भाषाओं में हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब चुनावों की बात आती है और धर्म निरपेक्षता की बात को उसके साथ जोड़ते हैं तो हर नेता उसको मद्देनजर रखते हुए इफ्तार पार्टी देता है। क्या आज तक किसी भी नेता ने कन्या पूजन का आयोजन किया है? क्या कभी किसी नेता ने नवरात्रों की डिनर पार्टी रखी है? कभी नहीं रखी। क्या हिन्दु उन्हें वोट नहीं देते हैं? (व्यवधान) एक बात आपके लिए अच्छी है। एक मिनिट, हनुमानजी, आप भी

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सुन लीजिए। मेरी कन्टीन्युटी टूट जाती है इसलिए आप सुन लीजिए। (व्यवधान) एक व्यक्ति आजाद हिन्दुस्तान के 65 सालों में ऐसा हुआ है जिसने ईद पर ईद भी मनायी है और नवरात्रों में कन्या पूजन भी किया है, ऐसा व्यक्ति है प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी। इसे सही मायनों में सैक्युरिलिज्म या धर्म निरपेक्षता कहा जा सकता है। (व्यवधान) वह तो आइकन हैं, उनकी तो सभी करते हैं। सभी धर्मो का मैं सम्मान करती हूं लेकिन मैं यह चाहती हूं कि यह परम्परा आप सब लोग शुरू करें, हम लोग शुरू करें। हम ईद पर ईद मनाएं और नवरात्रों में भी कन्या पूजन आयोजन करें। (व्यवधान) आप सुन क्यों नहीं लेते हो, हो क्या गया आपको? आप मेरी एक बात सुनो, मेरी कन्टीन्युटी टूट जाती है न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलने दो उनको। आप बीच में टोका टाकी नहीं करें, उनको बोलने दें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अब मैं दूसरे विषय पर आने से पहले एक बात चार लाइन में खतम कर दूंगी, कि होने दो घनघोर, जो आप सब गरजते रहते हैं, यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग आपस में भिड़ेंगे नहीं तो फिर विकास इतना अच्छा नहीं निकलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि गरजते रहें यहां पर। तो सुनें। होने दो घनघोर गर्जना, होने दो घनघोर गर्जना, पर राजस्थान को आगे बढ़ने दो, पार्टी की छोड़ो, विकास की करो अर्चना। बाकी सब बातों को जाने दो।

मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। मुझे तो टैक्निकल लैंग्वेज इतनी मालूम नहीं है। मैंने तो जैसा बताया, राजनीति में मैं नौसिखिया हूं, मुझे कुछ आता भी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूं। मुझे टैक्निकली नहीं मालूम कि कितने आंकड़े क्या पेश किये। मुझे तो यह पता है कि जब मैं क्षेत्र में जाती हूं, मेरा आधे से ज्यादा क्षेत्र बस्सी का जेडीए के अंडर में आता है। अभी मंत्रीजी राठौड़ साहब भी जाकर आये थे, पीएचसी का उद्‌घाटन इन्होंने किया था। वहां पर सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। वह स्थिति आपने देखी है। बहुत भयंकर स्थिति है हमारे सांभरिया से कानोता में। आप खुद यह बात देखकर आये हैं।

मैं पानी के बारे में बोलना चाहती हूं। अभी कुछ दिन पहले पूरे राजस्थान में एक बात हो रही थी, सारे लोग परेशान हो रहे थे। जनता जल

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

योजना के थ्रू जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी अचानक से या तो डीपी उतार ली या अचानक से उनके कनेक्शन काट दिये गये थे। दो साल में सिंगल फेस, एक बोर या एक हैण्डपम्प भी विभाग की तरफ से शायद किसी क्षेत्र को नहीं मिला। कम से कम मेरे क्षेत्र को तो नहीं मिला। लोगों में पानी की त्राहि-त्राहि थी, सिर्फ जनता जल योजना का थोड़ा-सा सहारा था, जिसके भी अचानक कनेक्शन काट दिये गये। डीपी उतार ली गयी उसकी वजह से लोग पानी के अभाव में तड़पते-मरते रहे। उनको वजह नहीं बतायी कि आपको क्यों मार रहे हैं हम। बाद में उनको बताया गया कि आपका 13 साल से बिल पैंडिंग है। अगर बिल पैंडिंग 13 साल से है तो आपने 13 साल पहले ही बिल क्यों नहीं पकड़ाया, इकट्ठा 13 साल का बिल क्यों पकड़ाया। 13 साल से बिल पैंडिंग है। अब वह 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपये हो जाएंगे, आम ग्रामीण कहां से भरेगा? जब लोग मरने लगे तब एक निर्णय दिया गया कि 2015 तक सरकार भरेगी और 2016 से पंचायत भरेगी। पंचायत में सरपंच कहते हैं, हमें एसएफसी टीएफसी का ही पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है, हम बिजली का बिल कहां से भरेंगे। घूम फिरकर बात आम जनता पर आ जाती है कि अब आम जनता पानी पिए या मरे। वह क्या करें, यह बात मैं रखना चाहती हूं। इसका निर्णय आप तुरन्त करें कि उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप अपनी बात समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैंने तो बहुत कम बोला है। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं।

श्री सभापति: आपका समय जितना था आप उससे ज्यादा बोल गयीं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सिर्फ दस मिनट, जो मेन....

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप अपनी बात को अब समाप्त करें। जितना समय आपका निर्धारित था, आप उससे ज्यादा बोल गयीं, इसलिए अपनी बात जल्दी समाप्त कर दें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): महोदय, सबने आधा-आधा, एक-एक घंटा बोला है, मैंने तो बोला ही नहीं।

पैरा 39 में एक बात दी हुई है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संस्थागत सुधार पर निरन्तर ध्यान देने का नतीजा रहा है कि हमारी

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 283 मेगावाट की वृद्धि हुई है जबकि गत सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2 हजार 293 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। इतना ही काफी है। महोदय, अगर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है तो फिर बिजली 4 घंटे क्यों आ रही है? फिर 24 घंटे क्यों नहीं आ रही? यहां बैठा एक भी सदस्य कह दे कि उनके क्षेत्र में पर्याप्त बिजली आ रही है। अगर उत्पादन की क्षमता 4 हजार 283 मेगावाट हो गयी और आत्मनिर्भर हो गया तो फिर बिजली 24 घंटे नहीं तो कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे तो मिलनी चाहिए न, एक बात।

(15.00 बजे)

दूसरी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम नम्बर पर आ गया है, ऐसा भाषण में कहा गया है, लेकिन बड़े-बड़े भवनों पर सौर ऊर्जा प्लाण्ट लगाने के लिये कुछ नहीं हो रहा है। जयपुर स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव में कह दिया कि 15 से 50 प्रतिशत बिजली जयपुर में सौर ऊर्जा से बनायी जाएगी, लेकिन निजी भवनों की बात छोड़ दो तो विधान सभा, न्यायालयों में, हाई-कोर्ट में, सचिवालय में, कृषि भवन में, पुलिस मुख्यालय जैसे बड़े-बड़े भवनों में भी सौर ऊर्जा प्लाण्ट लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जयपुर के सारे सरकारी भवनों, बड़े होटलों, बड़े निजी घरों में भी यदि सौर ऊर्जा प्लाण्ट लगा दिया जाए तो अकेले जयपुर की ही लगभग 25 प्रतिशत बिजली बचायी जा सकती है। बल्कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा भवन में सौर ऊर्जा प्लाण्ट लगाने के जो प्रस्ताव अध्यक्ष साहब ने भेजा था, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगी कि जवाब में कम से कम विधान सभा भवन को ईको-फ्रैण्डली बनाने की घोषणा करें ताकि पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाए कि माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान सभा सदस्य सौर ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितने जागरूक हैं। विधान सभा का डेढ़ करोड़ का बिजली का बिल जाता है, अगर सौर ऊर्जा प्लाण्ट लगता है तो उसकी लागत मात्र तीन करोड़ रुपये है, जो बिजली के बिल से तीन या चार साल में कवर कर लेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। श्री धनसिंह रावत। आपकी बात अब अंकित नहीं होगी। आपको जितना समय दिया, उससे ज्यादा बोल लिये। श्री धनसिंह रावत।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापतिजी, हमारी तरफ से तो किसी को बुलाया ही नहीं।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, यह बजट राजस्थान के युवा, महिला, किसान, व्यापारी एवं सभी वर्गों की प्रगति का बजट है। बजट वर्ष 2016-17 का है, इसके लिये मैं हमारी लोकप्रिय नेता को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

बजट में शिक्षा के लिये 23177 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 628 स्कूलों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण करने तथा कालेज एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत ढांचा विकास के लिये 173 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रत्येक जिले में 10 प्रगतिशील किसानों को व्याख्यान के लिये एक हजार रुपये प्रति दिन मानदेय और किसानों को सस्ती बिजली एवं 7205 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा करके सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखलायी है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पेयजल से जूझते हुए राजस्थान को पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2950 करोड़ रुपये की घोषणा की है, उसके लिये सम्पूर्ण राजस्थान की जनता उनका आभार व्यक्त करती है।

शिक्षा व चिकित्सा राजस्थान की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिनको पथ पर लाना हमारा नैतिक दायित्व है। उस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपयों का प्रावधान रखा। राज्य में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए इस बजट में अस्पतालों के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गयी है। यह कदम डाक्टरों की कमी को पूरा करेगा। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मेडिकल कालेजों में 350 सीटों की बढ़ोतरी करने के साथ ही प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में क्रमोन्नति के प्रस्ताव के फलस्वरूप राज्य की जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय सभापति महोदय, गांवों में बालिकाओं और महिलाओं के लिये सबसे निचले स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं साथिनों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गयी है। मुख्य मंत्री

(श्री धनसिंह रावत)

राजश्री योजना के तहत एक जून या बाद में जन्म लेने पर पहली वर्षगांठ पर बालिका को 2500 रुपये देने की घोषणा बालिकाओं का सम्बल बढ़ाने के लिये है।

किसानों को हमेशा खाद की, बुवाई के काम की समस्या आती है। एडवांस में किसानों के लिये 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी. का अग्रिम प्रबन्ध किया है। यह किसानों के लिये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे किसान को कालाबाजारी के अन्दर खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। राज्य में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के अलावा सरकार ने किसानों के लिये और भी योजनाएं लागू की हैं।

हमारी सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की। जो ग्राम पंचायतें थीं गंदी बस्ती थीं, जहां लोग कीचड़ में रहने के लिये मजबूर हुआ करते थे, ऐसे गंदे रास्तों को ठीक करने का काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ओर आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्दर हमारी सरकार ने जो योजना लागू की है, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। जनजाति विकास के लिये बहुत-कुछ किया है, बजट में बहुत-कुछ प्रावधान रखा है। इस वर्ष 2016-17 में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का लक्ष्य जो सौ का रखा गया है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सौ से बढ़ाकर चार सौ इसकी संख्या की जाए। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक बालिका आश्रम छात्रावास, एक-एक बालक आश्रम छात्रावास खोले जाएं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में टी.ए.डी. क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। राजस्थान में टी.ए.डी. क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न लागू है, जहां आश्रम के वार्डन की व्यवस्था है, या और भी कर्मचारी हैं, जहां विभाग का खुद का कैडर होता है, यह पैटर्न राजस्थान में भी लागू किया जाए। टी.ए.डी. क्षेत्र में टी.ए.डी. विभाग का खुद का कैडर हो। आज की तारीख में टी.ए.डी. विभाग के पास जो कर्मचारी हैं, सारे प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान के टी.ए.डी. विभाग के अन्दर खुद का कैडर होना चाहिये जिससे डवलपमेंट के अन्दर सुविधा होगी। साथ ही आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मांग करना चाहूंगा कि टी.ए.डी. का कमिश्नर सैपरेट होना चाहिये,

(श्री धनसिंह रावत)

अभी रेवेन्यू-कम-टी.ए.डी. कमिश्नर है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ट्राइबल क्षेत्र के डवलपमेंट के लिये पृथक से टी.ए.डी. कमिश्नर नियुक्त होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है जिसमें गांव, गरीब और किसान सबका ध्यान रखा गया है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना राजस्थान की एक जबरदस्त योजना है। इस योजना के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में एक नई क्रांति आयी है। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि सरकार दान मांग रही है, भीख मांग रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह दान और भीख नहीं है, यह राजस्थान के स्वाभिमान की बात है। एक जमाना था जब आजादी का आंदोलन चला था, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था, इस देश को आजाद कराने के लिये मुझे आपका सहयोग चाहिये, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। तो लोगों ने खून भी दिया था और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कहने पर लोगों ने अपनी सुहागिनों के जेवर भी दान दिये थे इस देश के लिये। ठीक उसी प्रकार हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी के आह्वान पर राजस्थान की जनता राजस्थान को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये अपना सब कुछ दान करने के लिये तैयार है। बड़े सम्मान के लिये भामाशाह इसमें योगदान दे रहे हैं। राजस्थान में जो भामाशाह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के लिये सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की ओर आना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैं बांसवाड़ा जिले से आता हूं और बांसवाड़ा जिले ने राजस्थान का 3-3 बार नेतृत्व किया है। हमारे हरिदेव जोशी राजस्थान के 3-3 बार मुख्य मंत्री रहे। राजस्थान में माही बांध के अन्दर पर्याप्त पानी है, पर्याप्त पानी होने के बावजूद बांसवाड़ा जिले का जो भाग था गांगड़तिले का क्षेत्र, बागीदौरा का क्षेत्र, दानपुर का क्षेत्र, पीपलखूंट का क्षेत्र, जो असिंचित इलाका है, उसमें आज तक लिफ्ट के द्वारा पानी पहुंचाने की योजना नहीं बनी। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और जल संसाधन मंत्री डाक्टर रामप्रतापजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आजादी के इतिहास में पहली बार लिफ्ट स्कीम अम्बापुरा परियोजना लागू की, इस बजट में प्रावधान किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं बांसवाड़ा की जनता की तरफ से।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा के अन्दर माही बांध से पहले 80

(श्री धनसिंह रावत)

हजार हैक्टेयर के अन्दर सिंचाई होती थी, अब रकबा बढ़ता-बढ़ता एक लाख 25 हजार तक हुआ है। बांसवाड़ा में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, उदयपुर डिवीजन में मात्र 18 हजार हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो रही है और उदयपुर के अन्दर हमारा एडिशनल चीफ इंजीनियर बैठता है। उदयपुर में 18 हजार हैक्टेयर के लिए एडिशनल चीफ इंजीनियर बैठता है तो बांसवाड़ा जिले में तो एक लाख पच्चीस हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है। पहले बांसवाड़ा में चीफ इंजीनियर था, सर्किल का पद था, उसे खतम करके अब एस.ई. के हवाले छोड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सिंचाई मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि क्यों नहीं बांसवाड़ा में एडिशनल चीफ इंजीनियर का पद सृजित करके जो एडिशनल चीफ इंजीनियर उदयपुर के अन्दर बैठता है उसको बांसवाड़ा में बैठने के लिए कहा जाए।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि माही बेसिन, माही की नहरों का 20 टी.एम.सी. पानी सीपेज होकर बेकार जाता है और कडाणा के बैक-वाटर के साथ-साथ बह जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माही व कडाणा का जो पानी नहरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण सीपेज होकर जाता है, उसको रोककर बांसवाड़ा के असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु काम में लाया जाए तो बांसवाड़ा की जनता के लिए बहुत कुछ होगा।

मैं आपसे एक मांग और करना चाहता हूं। बांसवाड़ा में 30 वर्षों से जो नहरें बनी हुई हैं, वे नहरें अब जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि नहरों की बड़े पैमाने पर रेजिंग और सुदृढ़ीकरण कराने के लिए पर्याप्त बजट रखा जाए जिससे बांसवाड़ा की जनता को लाभ होगा। जो अम्बापुरा स्कीम प्रारम्भ की है आपने, उसके लिए धन्यवाद के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम बांसवाड़ा के लिए भी हो, कुशलगढ़ के लिए भी हो। बांसवाड़ा की सभी तहसीलों में इस प्रकार की योजना बनाकर माही का पानी उपलब्ध करवाएंगे तो बांसवाड़ा की जनता आपको कभी भूल नहीं पाएगी। जो शेष पानी बचा हुआ है, उसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी इसमें सम्मिलित किया जाए और डूंगरपुर के किसानों को भी इसका लाभ दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब यही कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, वह वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक काम है। तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहने के बाद भी माननीय

(श्री धनसिंह रावत)

हरिदेवजी जोशी वो काम नहीं कर सके, वह काम वसुन्धराजी ने किया है, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक काम है।

अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि बांसवाड़ा जिले में गुरु गोविंद विश्वविद्यालय की घोषणा करने जा रहे हैं और यह बिल बहुत जल्दी सदन में आने वाला है। एक बार पुनः, माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, 2016-17 के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को शानदार और जानदार बजट पेश करने के लिए आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि इस बजट में उन्होंने राजस्थान के आम-अवाम की मूल भावनाओं को समझा और पूर्ववर्ती सरकार की तरह थोथी घोघणाएं नहीं कीं। यह बजट निश्चित रूप से राजस्थान को आगे ले जाने में सक्षम होगा।

मेरे कुछ मित्र बजट का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वे विरोधी पार्टी में हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोग। विरोध के लिए विरोध करना मेरी राय में उचित नहीं है। मैं मेरे कांग्रेस के साथियों को राजस्थान के पहले वित्त मंत्री श्री नाथूरामजी मिर्धा के पहले बजट भाषण की याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने 7 अप्रैल, 1952 को राजस्थान की विधान सभा में कहा था- 'मुझे यह विश्वास है कि हमें इस सदन में पर्याप्त सहायता और पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता रहेगा। हमारे सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील रूप से प्रकट हो सकेगा।' लेकिन, आज मेरे कांग्रेस के साथी किस प्रकार का व्यवहार इस सदन में और सदन के बाहर कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको नाथूरामजी मिर्धा साहब ने जो आइना दिखाया है, कृपया आप उस पर कायम रहें और जो आपकी अपनी भूमिका यहां पर दिखाई दे रही है, उस पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। बजट की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं और ईमानदारी से इस बजट को

(श्री प्रताप सिंह)

जो पढ़ेगा, समझेगा, निश्चित रूप से इस बजट की तारीफ करे बिना वह नहीं रह सकेगा, इस प्रकार का मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बजट में राजस्थान के विकास का साफ विजन दिखाई देता है। मुख्य मंत्रीजी सुराज के जिस संकल्प के साथ सत्ता में आयी है, उसे जमीन पर उतारने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। साथ ही साथ पिछले पांच वर्ष में राजस्थान के साथ कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार का खेल खेला, उस कलंक को धोने की कोशिश की है। मैं यह कह सकता हूं कि यह राजस्थान के नव-निर्माण का ब्लू-प्रिंट है। यह बजट प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक लोगों के सपनों का धरातल है। वह चाहतीं, माननीय सभापति महोदय, अगर मुख्य मंत्री चाहतीं तो वाहवाही लूटने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं कर सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो घोषणाएं कीं, वे हवा-हवाई नहीं हैं, सभी पूरी होने वाली हैं। मुख्य मंत्रीजी की लीडरशिप में हमारी सरकार सभी घोषणाओं को पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे भी मुख्य मंत्रीजी के बारे में सभी जानते हैं कि वह जो कहती हैं, करती हैं। उन्होंने जो कहा है, उसको पूरा भी किया है। राजस्थान की 7 करोड़ की आबादी, बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपनी जबान से जो बात कही है, उसको निश्चित रूप से पूरा किया है।

माननीय सभापति महोदय, बजट के बारे में राय बनाने के पूर्व मैं हमारे सभी मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में हमको किस प्रकार की व्यवस्था मिली। बिजली कम्पनियों की हालत देखें तो करीब 80 हजार करोड़ रुपये का उनका भार हमारी सरकार को उठाना पडा। पिछली सरकार ने हमारे ऊपर छोड़ा बिजली कम्पनियों का 80 हजार करोड़ रुपये का कर्जा, मैं मुख्य मंत्रीजी को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'उदय' योजना के तहत, (Ujjwal DISCOM Assurance Yojana) उसका 75 प्रतिशत टेकओवर करने का निर्णय लिया। करीब 60 हजार करोड़ रुपया इस प्रकार से हमारी सरकार पर यह भार आया। मैं यह कह सकता हूं कि यह मुख्य मंत्री की दूरगामी सोच का ही नतीजा है। मुख्य मंत्रीजी चाहती हैं कि बिजली के क्षेत्र में राजस्थान के आम-अवाम को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। हमारे किसानों को खेती के लिए बिजली भरपूर मिले, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का यह कदम बहुत ही सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार

(श्री प्रताप सिंह)

में तेल की कीमतें कम हुई हैं। तेल की कीमत कम होने की वजह से राजस्थान के राजस्व में भी करीब 3 हजार करोड़ रुपये की कमी आयी है। कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन का खर्च बढ़ा है। यह सब होते हुए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में राजस्थान की जनता की हर बात को, हर मांग को खुले रूप से पूरी करने की चेष्टा की है और खुलकर सौगातें दी हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए दो-तीन बातों के लिये मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि राजस्थान के आम-अवाम के लिये और राजस्थान के लोगों के हित के लिये वह बहुत ही अच्छी साबित होंगी, बहुत ही कारगर साबित होंगी और राजस्थान में बहबूदी आएगी।

सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा भामाशाह योजना का। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस विधान सभा के सदस्य थे। माननीय मुख्य मंत्री 2008 में इस भामाशाह योजना को राजस्थान में लाना चाहती थीं, पर किन्हीं कारणों से उस समय थोड़ा डिले हो जाने की वजह से और बाद में हमारी सरकार बदल जाने की वजह से वह भामाशाह योजना को अमलीजामा नहीं पहना सकीं। इतनी अच्छी योजना होते हुए भी, महज इसलिये कि यह वसुन्धराजी के द्वारा लायी गयी योजना है, कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं की। हमारी सरकार आते ही मुख्य मंत्रीजी ने फिर भामाशाह योजना की घोषणा की। मुझे बताते हुए खुशी है कि भामाशाह योजना के तहत हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, उनको डवटेल किया जाएगा। बीच में बिचौलिये के कारण कहीं न कहीं पर करप्शन की आवाज आती थी, वह सब खतम होगा और वह सारा का सारा पैसा भामाशाह कार्ड के माध्यम से, उस नम्बर के माध्यम से बैंक के खातों में जमा होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भामाशाह योजना के तहत न केवल भ्रष्टाचार रूकेगा, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होगा। इसके साथ-साथ हमारा बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत होगा और छोटे-छोटे गांवों में, पंचायत मुख्यालय पर माइक्रो ए.टी.एम. भी खोले जाएंगे। हमारा बैंक से सम्बन्ध रहेगा और हमें यह भी पता रहेगा कि कहां पर यह माइक्रो मशीन काम कर रही है, उसमें कितना लेनदेन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर भामाशाह योजना राजस्थान के लोगों के लिये, राजस्थान की महिलाओं के लिये निश्चित रूप से अच्छी और बहुत ही बेहतरीन साबित होगी और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में भी इसका योगदान रहेगा।

(श्री प्रताप सिंह)

जिन महिलाओं का भामाशाह योजना का कार्ड बना है, प्रत्येक महिला के खाते में करीब दो-दो हजार रुपये जमा होंगे। मुझे बताते हुए खुशी है... (व्यवधान) मैं एक के बाद एक फीगर बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं। साथ ही साथ ...(व्यवधान) बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: समाप्त कर दो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्यों कर दो समाप्त। रैस्ट मिल गया साहब, बीमार आदमी हूं।

मुख्य मंत्रीजी का दूसरा कार्यक्रम जल स्वावलम्बन है, मैं समझता हूं, इस कार्यक्रम में राजनीति नहीं होनी चाहिये। यह खाली सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह राजस्थान की पूरी जनता का कार्यक्रम है। सभी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिये। मैं इतना कह सकता हूं कि जल स्वावलम्बन के तहत गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रहेगा। राजस्थान लगातार अकाल से जूझता रहता है, निश्चित रूप से पीने के पानी की कमी है, हमारे यहां खेती के पानी की कमी है, उसमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लोग कहते हैं कि आने वाला विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिये होगा। इसलिये मैं कह सकता हूं जिस प्रकार की यह जल स्वावलम्बन योजना बनी है, निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। राजस्थान की जिस प्रकार से स्थिति है, यहां पर पीने के पानी की कमी, यहां पर खेती के पानी की कमी, हमारा ग्राउण्ड वाटर लगातार नीचे जाता जा रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जल स्वावलम्बन योजना चलायी है। इसमें सभी विधायकों ने, सभी एम.पी. साहिबान ने, राजस्थान की जनता ने सभी ने भरपूर सहयोग दिया है, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सहयोग दिया है। मैं मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की बहबूदी के लिये इस महती योजना की आप सब लोगों ने मदद की। भविष्य में भी जल स्वावलम्बन अभियान में आप सब मदद करेंगे, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा, उनकी मात्र दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं एक भामाशाह योजना और दूसरी जल स्वावलम्बन, तीसरी है कौशल विकास। कौशल विकास के काम को लोग समझ नहीं रहे हैं। राजस्थान में विशेषकर गांवों में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कोई-सा भी गांव राजस्थान में ऐसा नहीं देखोगे जहां पांच-दस लड़के बी.ए. या एम.ए. पास नहीं मिलें। वे लोग खेती के काम के तो रहे नहीं, ज्यादा पढ़ने के बाद खेती

(श्री प्रताप सिंह)

कर नहीं सकते। रोजगार की उनके सामने समस्या है। उनको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, प्राइवेट नौकरी मिल नहीं सकती। इसे ध्यान में रखते हुए कौशल विकास की जो योजना हाथ में ली है, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का बच्चा कुछ ट्रेनिंग लेकर अपने पांव पर खड़ा होकर अपने रोजगार से अपने परिवार को पाल सकेगा तो निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। मैं खुद देखता हूं, मेरा स्वयं का अनुभव है। सभापति महोदय, मुझे 30 साल का राजनीतिक अनुभव है। सन् 1985 में सबसे पहले मैं पहली बार विधायक बना, तब से लगातार देख रहा हूं। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं यह कह सकता हूं कि अगर समय रहते इस प्रकार की योजना को मूल रूप में जमीन पर नहीं उतारा तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी नक्सलवाद पनप सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज इस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कौशल विकास का काम हाथ में लिया, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरी मांग को, मेरी गुजारिश को मानते हुए छबड़ा के कालेज को सरकारी कालेज का दर्जा दिया। उसके लिये मैं छबड़ा की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही, छीपाबड़ौद का एक और स्ववित्त-पोषित कालेज है, उसकी भी 2006 में स्थापना हुई थी। वह बीच में सरकारी कालेज भी बन गया था, पर किन्हीं कारणों से वापस उसको प्राइवेट कालेज घोषित कर दिया गया। आपने उस क्षेत्र को देखा है, वहां के लोगों की गरीबी को देखा है, उस नाते मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने छबड़ा के प्राइवेट कालेज को सरकारी कालेज का दर्जा दिया है, उसी प्रकार से छीपाबड़ौद के कालेज को भी सरकारी कालेज का दर्जा दें।

मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि लासी डैम बनकर तैयार हो गया, जून में उसका पानी भर जाएगा। निश्चित रूप से यह हमारे क्षेत्र के लोगों के लिये खुशी की बात है कि डैम बनकर पूरा हो जाएगा। पर नहरों के अभी तक न तो टेण्डर हुए हैं, न ही और किसी प्रकार का काम चला है। मैं समझता हूं कि जब तक नहरें नहीं बनेंगी उस डैम का कोई यूज नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो जन हित में वहां के क्षेत्र की गरीबी को देखते हुए नहरों के टेण्डर हों, जल्दी

(श्री प्रताप सिंह)

से जल्दी नहरों का काम पूरा हो ताकि हमारे किसानों को, किसानों के खेतों को पानी मिल सके।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में छबड़ा थर्मल लगा हुआ है, थर्मल प्रोजैक्ट लगा हुआ है, वह आगे चलकर सुपर क्रिटिकल थर्मल बनने जा रहा है। उसमें बाहर के, अन्य प्रदेशों के लोग ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। या कुछ कम्पनी के लोग जान-बूझकर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार दें। आशा है, माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र की भावनाओं को समझेंगी और इन पर इस प्रकार की कार्यवाही करेंगी।

यहां पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी नहीं हैं पर मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा। 2003 से लेकर 2008 के बीच में पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन छबड़ा में लिमिटेड टेण्डरों के मामले में घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। जमीन पर काम नहीं हुआ, बिल बनाकर सब उठा लिया गया। इसकी ए.सी.बी. से जांच करवायी जाए और जो दोषी हैं, उनको निश्चित रूप से दंड दिया जाए।

इतना ही निवेदन करते हुए एक बात प्रमुख रूप से हमारे क्षेत्र की है, सोयाबीन की फसल। माननीय सभापति महोदय, पिछले समय में हमारे सोयाबीन की फसल न-केवल छबड़ा और छीपाबड़ौद क्षेत्र में बल्कि बारां जिले सहित पूरे हाड़ौती में अतिवृष्टि की वजह से और बाद में बरसात नहीं होने की वजह से करीब-करीब समाप्त-सी हो गयी थी। किसी के पांच किलो बीघा के हिसाब से सोयाबीन निकली, किसी के दस किलो बीघा के हिसाब से सोयाबीन निकली। लगातार दो-तीन साल से फसल खराब होने की वजह से हमारे किसानों की माली हालत चरमरा गयी है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसका किसानों को निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाए।

पिछली जो फसलें खराब हुई हैं, उनमें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया गया है। कृषि मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने किसान के दु:ख और पीड़ा को समझा और खाद के भण्डारण की व्यवस्था करवायी। तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया, बीस हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. और 50 हजार मैट्रिक टन

(श्री प्रताप सिंह)

जिप्सम का भण्डारण होगा। हमारी मां-बहनों को लम्बी-लम्बी लाइनों में लगना पड़ता था, कांग्रेस की हुकूमत के समय हमारी मां-बहनों के ऊपर पुलिस डंडे चलाया करती थी, उससे निजात मिलेगी। किसानों को दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, ऊंची कीमत नहीं देनी पड़ेगी और जरूरत के हिसाब से उनको खाद मिलेगी। किसानों के हित में इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता था इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये चंद मोटी-मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसके साथ-साथ एक-दो बातें और मेरे क्षेत्र की निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा।

हमारे यहां छीपाबड़ौद कस्बे में लासी नदी पर एक पुल बनना आवश्यक है। बरसात के दिनों में छीपाबड़ौद के दो हिस्से हो जाते हैं। बरसात के दिनों आदमी इधर का उधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता। इस प्रकार की स्थिति कई दिनों तक बनी रहती है इसलिए एक पुल का निर्माण करवाया जाए। नेशनल हाइ-वे नम्बर 90 पर परवन नदी पर एक हाई लेवल ब्रिज बनवाया जाए। साथ ही साथ, एक दो-ढाई किलोमीटर छबड़ा-छीपाबड़ौद रोड का काम बाकी रह गया है, वो बजट के अभाव की वजह से बाकी रह गया है, उसको भी पूरा कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक और महत्वपूर्ण सड़क है जो मध्य प्रदेश को जोड़ती है और आगे चलकर नेशनल हाइ-वे नम्बर 3 आगरा-मुम्बई रोड से जुड़ती है छबड़ा से कुम्भराज सड़क। यहां पर बसों का संचालन होता था, यहां पर जीप-कारों का, ट्रकों का संचालन होता था। पर रोड़ जाम हो जाने की वजह से, रोड खराब हो जाने की वजह से पिछले पांच वर्षों में वहां पर किसी प्रकार का संचालन नहीं हुआ, 35-40 किलोमीटर की सड़क बंद पड़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, युनुस साहब को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने थोड़ी बहुत रिपेयर करके उस पर यातायात प्रारम्भ करवा दिया। पर फिर भी आज हम यह कह सकते हैं कि वो मोटरेबल स्थिति में नहीं है, वो यातायात चलने के काबिल नहीं है। यह इन्टर-स्टेट रोड है, नेशनल हाइ-वे को जोड़ती है इसलिए इसको प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए।

ये चंद बातें मैंने आपके सामने निवेदन करने की कोशिश की है, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए और गौरव पथ ...

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): धन्यवाद, साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, बजट 2016-17 पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी और आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत कम समय में अपनी बात को रखकर मैं खुद ही अपने स्थान पर बैठ जाऊंगी, मुझे आप थोड़ा-सा समय देने का प्रयास करें।

मैं चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी क्योंकि हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जिन बारीकियों को छूते हुए इस प्रदेश का बजट जनता के सामने रखने का प्रयास किया, वो वास्तव में अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखता है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, 'धुंधले आइनों को एक दिन फेंक दिया जाता है। गुण हो तो पत्थर अपनी पहचान बना लेते हैं। वारिस हैं हम मानवता के प्रहरी उन मूल्यों के जो दुश्मन को भी अपना मेहमान बना लेते हैं। जिनके दिल में प्यार-मोहब्बत का जज्बा होता है, दीवारों में खिड़की-रोशनदान बना लेते हैं।

कितनी प्यारी लगने लगती है यह सारी दुनिया जब हम अपने फर्जों को ईमान बना लेते हैं।'

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा लगातार इस बजट की आलोचना की जा रही थी, मैं बैठी-बैठी सुन रही थी। मेरे से पूर्व अभी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनके द्वारा दिये गये उद्‌बोधन में मैं सुन रही थी कि अधिकारी इस राजस्थान का दिवाला निकाल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: नवलगढ़ से आने वाले ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नवलगढ़ से।

मैं उनसे कहना चाहती हूं अगर दिवाला किसी ने निकाला है तो वो कांग्रेस की सरकार ने निकाला है। 80 हजार करोड़ रुपये का बिजली का जो कर्जा आप लोग छोड़ कर गये, उसको चुकाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर यह दिवाला निकाला तो मात्र आप लोगों ने निकाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आती हूं, अगर मैं वहां के एक-एक काम को गिनाना चाहूं तो मुझे लगता है कि कितना भी बोलूं, धन्यवाद समाप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार ने 50 साल राजस्थान पर राज किया और हमने भी। भारतीय जनता पार्टी के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भैरोंसिंहजी और सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी के शासन काल को देखते हुए हम लोग कहना चाहें तो 17 साल हमने राज किया है। अगर दोनों के कार्यों का पलड़ा हम लोग देखना चाहें तो मैं मेरी विधान सभा में उनको बता सकती हूं। आपका राज था उन 50 वर्ष के राज में रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में मात्र पांच या छह जी.एस.एस. हुआ करते थे, लेकिन आज मैं बड़े विश्वास और बड़ी खुशी के साथ बोल सकती हूं कि मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में बारह-बारह, तेरह-तेरह और आने वाले समय में 15 जी.एस.एस. बनाकर हम जनता को देने वाले हैं। यह बहुत उपलब्धि है हमारी।

सभापति महोदय, कांग्रेस राज के विगत 5 वर्षों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने बिजली के लिए धरना नहीं दिया हो, जब हमने पानी के लिए धरना नहीं दिया हो, जब हमने शिक्षा और चिकित्सा के लिए धरना नहीं दिया हो। जब कोटा से झालावाड़ तक नेशनल हाइ-वे 12 की जर्जर हालत के लिए हमारे हाड़ौती के सभी विधायकों ने जमीन पर बैठकर, सड़क पर बैठकर धरना नहीं दिया हो। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब एक-एक बात के लिए हमें संघर्षरत न रहना पड़ा हो।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं, आज भी वह समय याद आता है जब थानों में भी कांस्टेबल सुरक्षित नहीं थे- चाहे मेरे चेचट का माया हत्याकांड देखें, चाहे कोटा, गोविन्द नगर चौकी का नन्दलाल हत्याकांड देखें। वह समय हम लोगों ने देखा है।

हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने हर गरीब को छुआ, हर बेरोजगार भाई को छुआ, प्रत्येक महिला को छुआ और इस तरह से गरीब को छूते हुए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बंधु का ध्यान रखते हुए उन्होंने बजट घोषित किया, उसके बावजूद भी आलोचना की जा रही है। मैं मानती हूं कि यह इनका धर्म है, ये धर्म निभाने के लिए कर रहे हैं। बाकी मेरा कहना है कि इनको भी इस बजट के लिए धन्यवाद हमारी मुख्य मंत्री महोदया वसुंधराजी को देना चाहिए।

सभापति महोदय, गौरव पथ के लिए हम सभी चर्चा कर रहे थे। हमारी पंचायतों में एक-एक किलोमीटर गौरव पथ का निर्माण किया गया है, जैसे ही हम लोग गांवों में जाते हैं, हमारे लिए पलक-पांवड़े बिछाकर लोग बैठे हुए तैयार मिलते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कोटा से झालावाड़ तक की सड़क के लिए। कोटा से दरा तो हमारा सैंक्शन हो ही गया। दरा से झालावाड़ के लिए जो रोड

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सैकिण्ड फेज बनना है, उसके लिए भी जितने प्रयास हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे मंत्री महोदय ने किये, यह सबको मालूम है कि किस तरह से प्रयास उस रोड के लिए चल रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ बोल सकती हूं कि आने वाले 3 साल के अन्दर हमारी सरकार उस रोड को भी 4 लेन बनाकर जनता को सुपुर्द करेगी।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने हमें क्या दिया, वह भी मैं आपको बताना चाहती हूं। मेरे रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जब कांग्रेस की सरकार जाने लगी तब उन्होंने एक अंडरपास हम लोगों को दिया। आप देखिये, अंडरपास की ओनली स्वीकृति जारी की, उसके लिए किसी तरह का कोई बजट नहीं था। सरकार चली गयी। मैं धन्यवाद देती हूं हमारी सी.एम. को, आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया को और जो भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनको कि उन्होंने प्रयास किया। राजस्थान की सारी सैंक्शंस डी-सैंक्शन में डाल दी गयी, लेकिन रामगंजमंडी का एक मात्र अंडरपास दिया साढ़े 5 करोड़, 6 करोड़ का। उस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, रामगंजमंडी की धरती के एक-एक गांव में चम्बल का पानी आता है। आज मैं मानती हूं कि यह सौभाग्य हम लोगों को मिला तो यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। पिछली बार मुख्य मंत्री जब सम्माननीय वसुंधराजी थीं तो उन्होंने एक-एक गांव में चम्बल का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया। न केवल संकल्प लिया बल्कि उस संकल्प को उन्होंने पूरा भी किया। आज हम बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं कि चम्बल का पानी हमारे रामगंजमंडी के लोग पी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ताकली सिंचाई परियोजना का शुभारम्भ भी हमारी सम्माननीय सी.एम. ने पिछली बार किया लेकिन पूरे 5 साल बजट के लिए डिमांड करते-करते यहां तक आ पहुंचे। बड़े दु:ख के साथ बोल रही हूं कि आज भी न तो किसानों को पता है कि कहां पर गांवों को विस्थापित करना है, न क्या। कुछ महीनों से हम लोग लगे, सम्माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि एक-दो गांवों के लिए आपने जगह भी देखी है, गांव को विस्थापित करने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हमने इस योजना के लिए पैसा नहीं दिया तो मैं मानती हूं कि यह योजना मात्र एक योजना बनकर पड़ी रह जाएगी। यह योजना हम जल्दी से जल्दी पूरी करके अगर किसानों को देना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

चाहते हैं तो हमें इसका बजट देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सम्माननीय सी.एम. से मांग करती हूं कि हमें इसका भी बजट दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो ओवरब्रिज दिया, वह भी रामगंजमंडी के अन्दर हमारी सरकार के समय में ही दिया गया। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस अंडरब्रिज की मैं मांग कर रही हूं मोडक के अन्दर, वह भी हमें सम्माननीय मंत्रीजी द्वारा और मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिया जाएगा।

अभी कुछ दिनों पूर्व ही सम्माननीय मंत्रीजी किरण दीदी ने प्रयास किये, रामगंजमंडी में पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं थी, इन सारे कामों के लिए प्रयास उन्होंने किये और सम्माननीय सी.एम. जी के कहने से उन्होंने हमें राशि दी है। उस राशि के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। हम 16 लाख रुपयों में रामगंजमंडी के अन्दर पाइप लाइन बिछाएंगे और यह काम भी जो अधूरा था, उसको भी हम लोग पूरा करके दिखाएंगे।

अभी सम्माननीय राजकुमारजी बोल रहे थे, माननीय सदस्य शायद यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आपके पास भी मेडिकल विभाग रहा था। मैं इस सरकार की सराहना करना चाहूंगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसने नये-नये कीर्तिमान मेडिकल में स्थापित किये हैं। उसका जीता-जागता उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एसएमएस हास्पिटल में आर्गन ट्रांसप्लांट का काम शुरू हुआ है। इस बात के लिए पूरा राजस्थान हमारी सरकार को धन्यवाद दे रहा है। गरीब लोग कहीं बाहर प्राइवेट हास्पिटलों में जाकर अपनी किडनी चेंज नहीं करवा सकते थे, वह सारा काम हमारे एसएमएस हास्पिटल में शुरू हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी देन है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित हमारी सरकार के समय में होंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट 2016-17 में प्रावधान रखा मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निवासियों के स्वैच्छिक पुनर्वास का जो आपने कहा है, इस योजना का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं यह स्वागत योग्य है। अपने श्रम से, स्नेह से पल्लवित घर, खेत, खलिहान से भावना से हमारा जुड़ाव हो जाता है, यह हमारा सहज मानव स्वभाव भी है। इसके बाद अगर हम किसी को बोल दें कि आपको यहां से विस्थापित होना है, तो बहुत मुश्किल होती है। इस योजना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

के क्रियान्वयन से मुख्य मंत्रीजी ने आत्मिक स्नेह प्रकट किया है, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

टाइगर रिजर्व के जो हमारे निवासी हैं, उन लोगों के लिए नवीन कुकिंग गैस पर अनुदान जो 50 प्रतिशत था, उसको आपने 100 प्रतिशत किया, इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। यह बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया है।

मेरे किसान भाइयों को खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए घंटों तक लाइनों में लगना पड़ता था, इसके लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अग्रिम भंडारण का प्रावधान रखा है, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहना चाहूंगी कि किसानों को जो देरी से खाद मिलता था उससे भी छुटकारा मिलेगा और जो कालाबाजारी होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा।

किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए बिजली प्रदाता कम्पनियों को 7,205 करोड़ रुपये का अनुदान सकारात्मक प्रयत्न है, मैं इस बात के लिए भी तहे दिल से और मन से उनको धन्यवाद देती हूं। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने शुरू की, हमारे किसान कृषि मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, यह योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। कम प्रीमियम की राशि में जितना उनका खराबा है, जो वास्तविक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वे लोग कर पाएंगे। यह बहुत ही अच्छा काम उन किसानों के लिए होगा।

'भामाशाह पशु बीमा योजना' बीपीएल, एससी, एसटी वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम राशि में 70 प्रतिशत और अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान आपने देने के लिए कहा है, मैं मानती हूं कि यह भी बहुत स्वागतयोग्य है। खनन क्षेत्र में पर्यावरण खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए एवं अन्य विकास के लिए जो आपने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वह खनन क्षेत्र है। राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विधान सभा क्षेत्र है रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद भी विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे माइनिंग एरिया में जितनी भी सड़कें हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और दुबारा फिर कहना चाहूंगी, हम नया कुछ नहीं मांग रहे, जो कुछ हम रायल्टी के रूप में देते हैं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उतना ही अगर हमें दे दिया जाए तो वहां की सड़कें जो टूटी-फूटी हैं, उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राशि हम लोगों को मिलेगी जो हमारा हक है और उसके बाद हमारी सड़कें अच्छी स्थिति में आएंगी।

'किस्मत' स्कीम हमारी सरकार ने लागू की है, Knowledge, Integrated Skill Modules for Agriculture, Horticulture, Animal Husbandary Training (KISMAT), मैं मानती हूं कि कृषि, बागवानी और पशुपालकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के मद्देनजर साढ़े चौदह करोड़ रुपए जो इसकी लागत आएगी और इसको आप हर जिले में बना रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

तकनीकी का जमाना है और मैं मानती हूं कि गरीब किसान-मजदूर है, अगर गांवों में पूछें और जाकर देखें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईटीआई के पीछे दौड़ते हैं और वह करते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वे करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसा नहीं है। इसके लिए सम्माननीय वसुन्धरा राजे सिंधियाजी, हमारी सीएम साहिबा ने 50 करोड़ रुपए का आगामी तीन वर्षों में जो प्रावधान रखा, मैं उस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देती हूं।

आईटीआई के भवन निर्माण हेतु जो 155 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत का आपने प्रावधान रखा, वह भी बहुत स्वागतयोग्य है। आईटीआई के राजकीय संस्थानों में उपकरणों हेतु जो 31 करोड़ 50 लाख रुपये आप देंगे, मैं मानती हूं, सीएम साहिबा को गांव के गरीब का बेटा भूलने वाला नहीं है, यह काम बहुत ही अच्छा आपका रहेगा सरकार का।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना भी हम लोगों के लिए वरदान साबित होगी। मैं कहना चाहती हूं हमारी मुख्य मंत्री महोदया के लिए कि महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी-ऐसी योजनाएं उन्होंने इस राजस्थान की धरती पर लागू की हैं जिनसे वास्तव में गांव की गरीब महिला का सीधा जुड़ाव है, गांव के बंधु का सीधा जुड़ाव है। चाहे हम भामाशाह योजना को लें, चाहे हम किसी दूसरी योजना को लें, ये सारी योजनाएं गांव के गरीब के लिए वरदान साबित होगी, यह मैं दुबारा कहना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के लिए भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। वैसे मैं धन्यवाद देती हूं कि किसी ने मुझे टोका नहीं विपक्ष से। मैं कहना चाहती हूं :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमें पत्थरों से उलझना ही होगा,
अगर आइनों की इबादत करेंगे।
क्योंकि अंधेरों से जब हम बगावत करेंगे,
तो उजाले हमारी हिफाजत करेंगे।
इन्हें टोकने की जरूरत नहीं,
आदतें इनकी हैं, कुछ तो शरारत करेंगे।
क्योंकि हकीकत पर जिनको भरोसा नहीं,
ख्वाबों, ख्यालों की बस हिमायत करेंगे, हिमायत करेंगे।

हमारा राजस्थान आन, बान और शान के साथ चहुंमुखी विकास के पथ पर निरन्तर बढ़ता रहे, ऐसे प्रावधान बजट में सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा किये गये हैं। चाहे हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देखें, चाहे हम किसी और को देखें जो कुशल श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक हैं, उनके अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से हर जिले में फैसिलिएशन एंड इन्फार्मेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जो आगामी दो वर्षों में ही सरकार करके देगी। मैं मानती हूं, यह भी बहुत बड़ा काम होगा। श्रमिकों को समय पर वेतन मिलेगा, पूरे वेतन सहित बोनस मिलेगा, जो ओवरटाइम है या अन्य लाभ हैं-चाहे वे पीएफ के हों, चाहे ईएसआई के हों, इन सभी की जानकारी व समय पर भुगतान बिलकुल सम्भव हो सकेगा। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां पर श्रमिक बंधु हैं और लगातार इन बातों के लिए वे लोग संषर्घ करते रहते हैं। यह बहुत बड़ा काम हमारी सीएम साहिबा ने किया है, इस बात के लिए दुबारा से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी मुख्य मंत्री महोदया को कि इस बजट में कम से कम 9 बिन्दु ऐसे रखे हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो काम वास्तव में कभी हुए ही नहीं, एकदम नये हैं। मुख्य मंत्री राजश्री योजना को देखें आप, यह योजना महिलाओं के लिए अच्छी साबित होगी। हम गरिमा बालिका संरक्षण योजना को देखें, कामकाजी महिलाओं के लिए राजकीय छात्रावास बनाएंगे, उस योजना को हम लोग देखें, चाहे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए संचालित पालनहार योजना के लिए जो 131 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है बजट में, उसको देखें। मैं मानती हूं, सबसे ज्यादा पुण्य अगर सम्माननीय हमारी सीएम साहिबा ने कमाया तो वह यह है कि विधवा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

महिला के पुनर्विवाह हेतु राशि 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए की है। यह बहुत अच्छा काम हमारी सीएम साहिबा ने किया है। राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का मैस-भत्ता बढ़ाकर जो 2000 रुपये प्रति माह हम लोगों ने किया है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की रहेगी।

पशुपालकों के बालक-बालिकाओं के लिए और जेतेसर धाम, सिणधरी, जिला बाड़मेर में आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु 12 करोड़ 91 लाख का जो प्रावधान किया, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, हां, लेटेस्ट। बिलकुल वही बोल रही हूं, लेटेस्ट किया है, उसी में ले रही हूं। (व्यवधान) जैतेश्वर ही बोला है, जैतेश्वर। वह गलत सुन लिया जेतेसर।

बाड़मेर जिले में दो आवासीय विद्यालय-एक एससी के बालकों के लिए और एक सभी वर्गो की बालिकाओं के लिए, मैं मानती हूं, यह भी बहुत सराहनीय कदम हमारी सरकार का है। इनका संचालन 2016-17 से किये जाने से स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग के ही नहीं अपितु हर जिले को भी ध्यान में रखकर बजट में प्रावधान किया है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई के साथ-साथ खेल का मैदान भी उनको मिले। तो यह बहुत अच्छा काम हमारा होगा।

मैं कहना चाहूंगी, एक योजना की सब लोग बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे विपक्ष वाले कि भीख मांग रहे हैं, जल स्वावलम्बन योजना। मैं मेरे विपक्ष के भाइयों से कहना चाहती हूं कि अगर आपको काम देखना है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आइए, आप मेरे साथ चलिये। आप हमारे निमाणा के काम को देखिये आप हमारे सरावधा के काम को देखिये, आप हमारे खीमच के काम को देखिये आप हमारे रीझी के काम को देखिये। अगर आपको देखना है तो आप मेरी हीरे खेड़ी में जाकर देखिये कि मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत कितने काम पूरे हो गये और कितने चल रहे हैं जिनको हम आपको पूरा करके जल्दी से जल्दी देने वाले हैं। मैं कहना चाहती हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी तो कह रही हैं आओ हमारे साथ चलो, आप कह रही हैं आओ, हमारे साथ चलो, बता तो दो कि किसके साथ चलें?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप सभी के साथ चलिये, इसी में सर्वांगीण विकास है।

मैं इस बात के लिए कहना चाहती हूं कि हमने किसी भी तरह से कोई ज्यादा राशि की किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जिनके पास ट्रैक्टर थे, चाहे वह गरीब था उस गरीब ने ट्रैक्टर दिया, जिसके पास जेसीबी मशीन थी उसने खुदाई के लिए जेसीबी मशीन दी। जब हमने इस योजना का हमारे विधान सभा क्षेत्र में शुभारम्भ किया तो ऐसी-ऐसी महिलाएं, ऐसे-ऐसे बच्चे जिन्होंने एक-एक रुपए का दान उस कलश में डाल दिया। यह कितना बड़ा काम हुआ। डार्क जोन का धब्बा हमारे रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र पर लगा हुआ था, इसकी वजह से हमारे किसान लोन नहीं ले पाते थे, किसानों को बड़ी परेशानी आती थी। आज हम देख रहे हैं कि इतने अच्छे काम हमारे हो रहे हैं, लोग इतने खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि फरवरी के महीने में जो हैण्डपम्प हवा फेंकने लगता है, कम से कम उससे छुटकारा तो मिलेगा। यह बहुत अच्छा काम हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। इसके अलावा भी मैं धन्यवाद देती हूं जो उन्होंने किया। कोटा के अन्दर सिविल सर्विसेज प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर का करने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, उस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

(16.00 बजे)

सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में पहली बार, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं, पहली बार संशोधन एवं विकेन्द्रीकरण से पारदर्शिता, रिफण्ड और राइट-आफ के कार्यों में बेहद सुधार होगा। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्यस्तरीय वार्षिक खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, खेल प्रतिभा खोज योजना, कबड्डी, हाकी को बढ़ावा, मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना, मुख्य मंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना, ये सारी योजनाएं। कोटा के अन्दर दो पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। मामूली से विवादों में लोगों के घर उजड़ते रहते थे, जो आपसी मनमुटाव थे, कहीं न कहीं उन सबका जल्दी से जल्दी निस्तारण होगा। इस बात के लिए मैं सम्माननीय सीएम साहिबाजी को धन्यवाद देना चाहती हूं, यह बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं सुझाव देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के लिए। राजकोष में जो राशि जाती है, जो हम बच्चों से लिया करते हैं, यह राशि सीधे विद्यालय कोष में जाएगी तो मुझे लगता है, इससे और भी अच्छा काम

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

करवा पाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि राज्य कर्मचारियों की सुविधा के विस्तार हेतु एसआई, पीएफ एवं पे-मैनेजर के सम्पूर्ण एकीकरण से 7 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। 2004 के बाद से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन अंशदान 505 करोड़ और समूह दुर्घटना राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करना, यह भी बहुत बड़ा काम सरकार का है।

मैं मेरे क्षेत्र की कुछ छोटी-छोटी बातें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय कृषि मंत्री महोदयजी भी यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि मेरी बात को सुनें। कांग्रेस की सरकार ने द्वेषतावश हमारे यहां कृषि कार्यालय रामगंजमण्डी था, उसको विगत समय सांगोद में स्थापित कर दिया। हमारे जो किसान हैं वे बड़े परेशान हैं, उनको बार-बार सांगोद चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, सीएम साहिबा से निवेदन करूंगी कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कृषि कार्यालय रामगंजमण्डी की धरती पर खोलेंगे तो बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिलेगा।

दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि पहले हमारी चेचट उप तहसील तहसील हुआ करती थी। उसे अगर पूर्ण तहसील का दर्जा दुबारा देंगे तो मुझे लगता है, वहां की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि चेचट से रामगंजमण्डी बहुत दूर पड़ता है।

हमारा हाइवे पर डेली बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जिस तरह से मैं मेरी बात को बोल रही हूं, बिलकुल मेन रोड पर इस तरह का कोई हास्पिटल नहीं है। आने वाले समय में अगर हमने ट्रोमा हास्पिटल यहां पर स्थापित किया तो दुर्घटनाग्रस्त बंधुओं को तुरन्त प्रभाव से चिकित्सा मिलेगी। अगर यह काम भी हमने किया तो अच्छा होगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, विश्वविख्यात है। हमारे व्यापारी बंधु इतने परेशान हैं कि जो वेस्ट मैटीरियल है, कोटा स्टोन की स्लरी निकलती है उसको कभी सड़कों पर फेंकेंगे, कभी कहां फेंकेंगे। मैं विगत सात वर्ष से मांग कर रही हूं कि डंपिंग यार्ड हेतु जमीन आबंटित की जाए। मुझे पूरा विश्वास है सम्माननीय सीएम साहिबा के ऊपर कि वे आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हमारे व्यापारियों को डंपिंग यार्ड हेतु व्यवस्था करके देंगे। बहुत बड़ा काम होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट में मेरी बात को समाप्त कर रही हूं।

मैं कहना चाह रही हूं कि जो हमारा सुकेत से रामगंजमण्डी का रोड

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

है, इसको अगर डिवाइडरयुक्त डबल लेन नहीं बनाया तो बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका है, और हो भी रही हैं। यह हमारे लिए हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हमारे सातलखेड़ी और सुकेत है, इसकी नई पेयजल स्कीम हम लोगों ने बनाकर दी है क्योंकि पिछली बार जो स्कीम बनी उसमें हमारे कुछ गांव छूट गये थे। इनको अगर हम शुद्ध जल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो जो लास्ट स्टेज पर स्कीम चल रही है, इसको भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

एक हमारे रामगंजमण्डी में जबर्दस्त आवश्यकता है कि बाइपास हम लोग बनाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय से लेकर निमाना रोड तक बाइपास बना देंगे तो मैं मानती हूं कि जो हमारा अन्दर का सिटी है, उसमें कहीं न कहीं वाहनों की संख्या कम जाएगी और आये दिन जाम लगा रहता है इससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। हमारी विश्वविख्यात धनिये की मण्डी है, इसके लिए भी हम चाहते हैं कि ट्रैफिक से रोज-रोज परेशान न हों। हमारे किसान जब भी सीजन आता है। धनिया लाते हैं, गेहूं लाते हैं, आये दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है इस जाम से भी हमें छुटकारा मिलेगा अगर नयी जगह हम इस मण्डी को स्थापित कर देंगे। उसके लिए हमें कम से कम 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अगर यह काम भी हमने कर दिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी बहुत-सी स्कीम हैं उनके बारे में तो हमने धन्यवाद दिया है। उनको पूरा भी नहीं कर पा रही हूं क्योंकि समय का अभाव है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारी वन विभाग की कालोनियां हैं, सरकार एक ऐसा अभियान चलाए, जिस तरह से हमने प्रशासन गांवों के संग चलाया या आनलाइन पोर्टल स्कीम हमारी चल रही है, ताकि जनता की समस्याओं का तुरन्त निस्तारण हो। हम ऐसा अभियान भी चलाएं कि हमारे जितने भी गांव हैं जो 100-150 वर्षों से वन विभाग में बसे हुए हैं, वन विभाग की भूमि का भू-रूपान्तरण करवाकर उन गांवों की, शहरों की कालोनियों को पट्टा देने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

मैं एक छोटी-सी बात और रखना चाहती हूं। चेचट और सुकेत में राजकीय चिकित्सालय की भूमि की प्राब्लम है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी साल्व करेंगे और इनकी बिल्डिंग बनाकर देंगे तो यह बहुत अच्छा काम हो सकता है।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतनी-सी बात कहना चाहूंगी कि वास्तव

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

में मुख्य मंत्री महोदया ने जिस तरह से बजट पेश किया, उसी दिन लग रहा था, मैं तो कहूंगी कि इतिहास बना है। लगातार तीन घण्टे तक बिना पानी पीये हमारी सीएम साहिबा ने बजट को प्रस्तुत किया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में उसी मन से उनका काम करने का मन है, जनता को सुविधा मिलेगी, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं सरकार देना चाहती है वे सब कुछ हम लोग देंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं बजट पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पिछले तीन बजट सरकार के आ गये- पहले बजट में, दूसरे बजट में और तीसरे बजट में, तीनों में प्रिएम्बल में यह कहा गया कि पिछली सरकार सब कुछ आर्थिक तंत्र तहस-नहस कर गयी, कुछ छोड़ा नहीं, खजाना खाली है। यह सच्चाई है तो आपके बजट की साइज क्यों नहीं घटी? आपकी प्लान की साइज क्यों नहीं घटी? आपने कौनसा जादू कर दिया दो साल में जो आपने इतने संसाधन जुटा लिये? यह प्राब्लम आपको पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों से नहीं है, प्रॉब्लम आपको भारत सरकार से है। 70 स्कीम्स थीं जिनको भारत सरकार फण्ड करती थी, उनको घटाकर मात्र दो दर्जन पर ले आये। उसमें भी उन्होंने आपका हिस्सा कर दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में कहा कि हमें सेंटर से कम मिला। आप कृपा करके या तो यह बताएं कि यह आर्थिक दुराचार कर दिया या यह आर्थिक गलत काम कर दिया जिससे राज्य की इकोनोमी पर खराब असर पड़ा है। बोलचाल की भाषा में यह कह दें कि पिछली सरकार ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया आर्थिक रूप से, तो यह चलने वाला नहीं है। आप बजट में स्पेसिफिक कहते कि ये-ये गलत काम उस सरकार ने किये जिनकी वजह से यह स्थिति हुई। फिर आपने दो साल में कौनसे नये संसाधन जुटा लिये? जो हमारा बजट था या हमारा जो प्लान साइज था, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ा आर्थिक नीतियों का फर्क होता तो फिर उसको आप कैसे मेंटेन कर पाते? आपको प्राब्लम दिल्ली में जो एनडीए की सरकार है, उससे है। यूपीए की सरकार आपको खूब सहायता देती थी, अब आपको पता नहीं क्यों दिल्ली से सहायता नहीं मिलती। दिल्ली में हर मिनिस्ट्री का बजट कम कर दिया और उसका असर आप पर ही नहीं, सब राज्यों पर पड़ा है। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री को ले लें, चाहे रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री को ले लें, चाहे

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आप दूसरी और मिनिस्ट्री को ले लें। और तो और, अब रेलवे में भी यह कर दिया कि आधा हिस्सा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा अगर आप कहीं नयी रेल लाइन बिछवाना चाहते हैं या कहीं गेज कन्वर्जन कराना चाहते हैं। तो पिछले दो साल में जो भारत सरकार के लेवल पर आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आया है, उसका असर आपको यहां देखने को मिल रहा है न कि पिछली सरकार का।

आपके पहले बजट में एक बात थी कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कों को स्टेट हाइवे, एमडीआर, ओडीआर, इनको विश्वस्तरीय बनाएंगे और पीपीपी मोड पर बनाएंगे। उसके लिए आपने एक आईएएस अधिकारी को भी एम्प्लाय किया एडवाइजर के रूप में और उसको दिल्ली में बिठाया। आप भारत सरकार के पास गये। आप उसमें 20 परसेंट पैसा लेना चाहते थे, 20 परसेंट आप देना चाहते थे, 60 परसेंट संवेदक उस पर खर्च करता। क्या हश्र हुआ उसका? पहले साल में एक किलोमीटर सड़क बना नहीं पाये। उसके बाद आपने दुबारा 2015-16 के बजट में भी उस बात को रिपीट किया कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कों को पीपीपी मोड पर बनाएंगे। फिर आप उसमें एक किलोमीटर सड़क नहीं बना पाये। वह आपका पैट प्रोजैक्ट था। इस बजट में उस पर कोई चर्चा नहीं है, एक अक्षर भी नहीं लिखा कि हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी या इसमें हमने इतने एमओयू साइन कर लिये या इतने वर्क कांट्रेक्ट दे दिये, कोई एक शब्द आपने उस पर नहीं कहा। दो साल तक आप उसमें बोलते रहे। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य प्रधान मंत्री सड़क की बहुत चर्चा कर रहे थे। प्रधान मंत्री सड़क का नाम पहले एमएनपी था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, उसके तहत वो सड़कें बनती थीं। वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट आयी तो दस महीने तक उस स्कीम का नाम बदलने के लिए उस स्कीम को ठण्डे बस्ते में डाले रखा। प्रद्युम्न सिंहजी साहब विराजे हुए हैं, एमएनपी में पैसे आते थे या नहीं? आप में भी कोई वरिष्ठ सदस्य होंगे, आते थे। वाजपेयीजी के जन्म दिन पर उसको शुरू करने के लिए, योजना अच्छी थी, उसमें कुछ चेंजेज किये। पर आप जो यह कह रहे थे कि वो योजना थी ही नहीं, तो वो पहले मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत चलती थी। उसमें अब क्या कर दिया, उसमें अब क्या कर दिया....(व्यवधान) मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय, नहीं तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। आप मुझे संरक्षण दें।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप तो आराम से बोलें।

श्री सभापतिः आप आसन की ओर देखकर बोलें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): प्रधान मंत्री सड़क योजना में हमारी सरकार जब अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में थी 1998 से लेकर 2003 तक, तो उसमें काफी काम हुआ। बाड़मेर जिले में तो 18-18 किलोमीटर सड़क एक-एक गांव को जोड़ने के लिए बनी। उसके बाद आपकी सरकार आयी, उसमें भी काम हुआ। फिर हमारी सरकार आयी। आपकी सरकार ने तो यह प्रमाण पत्र दे दिया था कि सब गांव जुड़ गये। हम फिर भारत सरकार के पास गये और हमने कहा कि उसमें हैबिटेशन शब्द है। उस हैबिटेशन का, कुछ ढाणियों का पेयजल के लिए सर्वे हुआ था उसको हम भारत सरकार के पास लेकर गये और उस हैबिटेशन के लिए हमने काफी प्रोजैक्ट मंजूर करवाये जिसका जिक्र इस बजट में भी है कि दो साल में 250 से लेकर 350 के हेबिटेशन जुड़ जाएंगे। इस पूरे पीरियड में हण्डरेड परसेंट वह सेंट्रली फण्डेड स्कीम थी। अब हुआ क्या है कि उसमें भी 60 परसेंट तो देगी भारत सरकार और 40 परसेंट आपको देना पड़ेगा। यह आप पर एक बर्डन आ गया। यह हमारी आर्थिक नीतियों से नहीं आया है।

सड़कों के मामले में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें की गयीं। यह भी कहा गया कि राजस्थान एक तरह से सड़कों का स्वर्ग बन गया है। मैं जिस जिले से आता हूं उसमें दो नेशनल हाइवे यूपीए सरकार ने मंजूर किये थे- एक 709 जो हरियाणा सीमा से पिलानी होते हुए राजगढ़ तक जाएगा। नेशनल हाइवे का यह सिस्टम है, माननीय सभापति जी, कि वो एक पाइंट के नेशनल हाइवे को दूसरे पाइंट से जोड़ता है। दूसरा नेशनल हाइवे यूपीए सरकार ने मंजूर किया रेवाड़ी-नारनौल-झुन्झुनूं-फतेहपुर, वो फतेहपुर में नेशनल हाइवे से मिल जाएगा। ढ़ाई-तीन साल हो गये इन दोनों नेशनल हाइवे को डिक्लेयर किये हुए, पर एक पैसा इन पर न तो भारत सरकार ने आबंटित किया है और न राज्य सरकार ने आबंटित किया है। राज्य सरकार इसके लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह तो आपकी सड़कों की स्थिति है।

आपने ग्रामीण गौरव पथ की बात की। पहले घोषणा इसी सदन में की गयी थी कि हम उन पंचायतों को जो एक पंचायत समिति में सबसे बड़ी है, पंचायत समिति मुख्यालय से जोडेंगे। डबल रोड करके, बीच में डिवाइडर बनाकर उसमें लाइट लगाएंगे। वो आपने कर दी? सब पंचायतों में बनाएंगे और इस साल एक तिहाई पंचायतों में बनाएंगे। उस एक तिहाई में आप बनाते तो 3 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में वो बनतीं। 9 हजार से अधिक ग्राम

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पंचायतें हमारे राजस्थान में हैं, उस प्रकार आपको 3 हजार ग्राम पंचायतों में बनानी थीं जबकि आप 2 हजार के आसपास ही बना पाये हैं। इसी तरह से स्टेट हाइवे, जो एमडीआर थीं, उनके लिए आपने कहा कि हम इन सबको स्टेट हाइवे घोषित कर देंगे। स्टेट हाइवे सिर्फ घोषित करने से क्या हो, उस पर आपने एक पैसा लगाया नहीं। जयपुर-दिल्ली जो राजस्थान के लिए, राजधानी के लिए और आगे के सारे इलाकों के लिए लाइफलाइन है, उसका क्या हाल है? डेट बढ़ाते जा रहे हैं। गड़करी जी भी यहां आये, एमओएस हैं वो भी आये, हमारे उस इलाके से जीते हुए सांसद भी एमओएस हैं, वो भी कई बार घोषणा करके चले गये, पर वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो आपने और सड़कों के लिए कहा कि नान पैचेबल सड़कों को हम री-कारपेट करेंगे, पर वो लक्ष्य भी आप प्राप्त नहीं कर पाये। यह तो आपकी सड़कों की स्थिति है। वो जो 20 हजार वाली पीपीपी मोड पर बनने वाली थीं, उसमें तो जिस व्यक्ति को आपने एडवाइजर बनाया था, गजेन्द्र हल्दिया जी थे जिनको दिल्ली में बिठाया था, वो भी इस्तीफा देकर चले गये कि कोई काम ही इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं। यह तो आपकी सड़कों की स्थिति है।

इसके बाद आपने पहले बजट में हमारी गत सरकार को दोष दिया कि इन्होंने इतनी सारी पेयजल योजनाएं मंजूर कर दीं बिना किसी बजटीय प्रावधान के। हमारी सरकार ने एक-एक योजना पर बजट का प्रोविजन किया था। खैर, आपने उसमें 13 योजनाओं के लिए कहा कि हम इनको इसी साल पूरा कर देंगे। पर आपसे वो भी एक पूरी नहीं हुई। फिर आप 2015 में आये और फिर आपने कुछ वृहत् पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की, वो भी पूरी नहीं हुई। फिर आपने यह घोषणा की कि हम सारी जो जनता जल पेयजल योजनाएं हैं, उनको ठीक-ठाक कराकर इस स्थिति में ला देंगे कि जनता को पानी मिले। वो भी आप नहीं कर पाये। हमारी सरकार ने झुन्झुनूं जिले के लिए इंदिरा गांधी नहर की कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पेयजल आधारित योजना बनाकर उसके लिए 956 करोड़ रुपये का बजट दिया था। वो कार्य आरम्भ हो गया, कार्यादेश जारी हो गये, दो साल काम चलते हुए हो गया पर उसकी गति इतनी धीमी है कि अभी तक भी उस पर 300 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए हैं, जो बजट हमारा दिया हुआ था। नया बजट तो दिया ही नहीं पर वो भी खर्च नहीं हुए हैं। इस बार आपने हमारे जिले की दो और योजनाओं की घोषणा की है। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पर या तो

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

मेरे साथी लोग उसको समझ नहीं पाये हैं या पढ़ा नहीं है, उसमें यह है कि हम इण्टरनेशनल फण्डिंग एजेन्सियों से उसके लिए धन लेंगे। कब धन मिलेगा, कब उनका काम शुरू होगा? यह पेयजल की आपकी योजनाओं की स्थिति है।

आपने विद्युत के लिए यह कहा कि हमने 4283 मेगावाट की नयी क्षमता बिजली में जोड़ी। आप बता दें कि इन दो साल में कौनसी यूनिट आपने बनाकर तैयार कर दी? यह जो क्षमता आपने जोड़ी है, यह हमारी सरकार द्वारा जो काम शुरू किया गया था, वह यूनिट अब कमीशन हो गयी, उससे जुडी है यह क्षमता। आपने एक नयी यूनिट इसमें नहीं लगायी। दो साल में कोई एक भी यूनिट लगाकर प्रोडक्शन में आ गयी हो तो आप बता दें, हम आपसे और सदन से माफी मांग लेंगे। यह आपकी स्थिति है।

फिर आपने पहले बजट में कहा था कि राजस्थान में 3.11 लाख कृषक 31 दिसम्बर, 2013 को वेटिंग लिस्ट में हैं और हम इस पूरी लिस्ट को खत्म कर देंगे। इन सबको कनेक्शन दे देंगे। उसके लिए आपने 2014-15 में 40,000 कनेक्शन का लक्ष्य रखा। वह आप पूरा नहीं कर पाये। फिर 2015-16 में 40,000 कनेक्शन का लक्ष्य रखा, फिर अब 2016-17 में 40,000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इस हिसाब से तो आप अपने इस पूरे कार्यकाल में उस लिस्ट के पूरे कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। इस बीच में जो नये और आवेदक आ गये, वे अलग हैं।

यही नहीं, आपने कहा है कि यह 4283 मेगावाट की क्षमता जुड़ने के बाद हम विद्युत के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गये हैं। आपने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि हम 24 X 7 बिजली देने की ओर बढ़ रहे हैं और यह हम देंगे। आपने यह घोषणा की थी कि गांवों में तो 24 घंटे लाइट के लिए दे देंगे और किसानों को आठ घंटे बिजली दे देंगे। क्या आप दे पा रहे हैं आठ घंटे बिजली? क्या आपने 24 घंटे बिजली दे दी है? अभी हमारे उधर के सम्माननीय सदस्य पहले तो बड़ाई करते हैं और फिर इस बात पर आते हैं कि मेरे यहां यह कमी है, मेरे यह कमी है। हमारी सरकार गयी तब 72,000 करोड़ रुपये का घाटा था और आपने दो साल में उसको बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये का कर दिया। यह आपने उसका ''उदय'' कर दिया। घाटे का उदय कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि हम इन-इन कम्पनियों को... (व्यवधान) पांच साल में हमारी सरकार ने एक पैसा बढ़ाया नहीं और जो भार कम्पनियों पर पड़ा, वे बजट के प्रोविजन से उसकी पूर्ति की। अब आप कह रहे हैं कि हम

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

20,000 करोड़ रुपये एक साल देंगे, 20,000 करोड़ रुपये एक साल देंगे। वह तो आप लाइबिलिटी कमिट करके आये हैं दिल्ली में। ऊर्जा क्षेत्र का जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम हुआ है उसके लिए। वह सरकार है, वह निरन्तर चलने वाली संस्था है। यह नहीं है कि इसके टाइम में यह हुआ है तो हम यह नहीं करेंगे। इस तरह की व्यवस्था आपने की है।

उसके बाद आप आइये उद्योग पर। रिसर्जेन्ट राजस्थान नवम्बर, 2015 में आयोजित किया, 3.21 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए। बहुत सारे उद्योगपति आये। खैर, खातिर-तवज्जोह करना, मेहमानबाजी तो राजस्थान की परम्परा है। उनकी खातिर की, मेहमानबाजी की, अच्छा किया। परन्तु आपको देकर क्या गये? आज चार महीने होने को आ गये, एक भी कोई प्रोजैक्ट धरातल पर आया क्या? किसी को जमीन आबंटित हुई है क्या? किसी ने बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई किया है क्या? किसी ने एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस के लिए एप्लाई किया क्या? किसी ने और तरह की बात के लिए आपको सम्पर्क किया है क्या? वे आये और यहां खातिरदारी करवाकर चले गये। एक उद्योगपति राजस्थान के ही हैं, राजस्थान मूल के हैं। राजस्थान में तो वह नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा था कि उद्योग भावना से नहीं लगते हैं, उद्योग हम तब लगा सकते हैं जब हमको भी दो पैसे की कमाई हो। उन्होंने कहा कि आपके यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके यहां उद्योग फ्रैंडली वातावरण होना चाहिए। आपके यहां बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके यहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके यहां कुशल श्रमिक होने चाहिए। तब कोई उद्योग लगाता है। उद्योग में आपने रिसर्जेन्ट राजस्थान में कांफ्रेंस कर ली, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर उनकी खातिरदारी भी कर दी परन्तु एक भी निवेश अभी तक तो आया नहीं है। शायद वह कागज पर ही है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आ जाएगा, आ जाएगा। थोड़े दिन में आ जाएगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आ जाएगा तो हम आपको धन्यवाद कर देंगे।

यही नहीं, आपने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी या यह कहें कि अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि पर आपने एलोकेशन किया है 5.02 प्रतिशत, जिसमें कृषि भी शामिल है, वन विभाग भी शामिल है और सहकारिता भी शामिल है। एक तरफ तो हम अपने आपको कृषि प्रधान राज्य कहते हैं और दूसरी तरफ उसका एलोकेशन घटता आ रहा

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

है। आपने उद्योग पर तो इतना जोर लगा दिया, कभी आपने कृषि के बारे में भी सोचा है? कभी किसान के बारे में भी सोचा है? जो प्रदेश कृषि प्रधान है, पशुपालन में देश में अग्रणी है, उसके पशुपालकों की क्या स्थिति है? उसके किसानों की क्या स्थिति है? रिसर्जेन्ट राजस्थान पर जितना ध्यान आपने दिया, उसका 10 प्रतिशत भी अगर आप किसानों की ओर दे देते तो बहुत बड़ा कल्याण किसान का हो जाता। हमारे मंत्रीजी भी किसान हैं, पर क्या, वह तो वही काम कर सकते हैं जो उनको बजट एलोकेशन हो। बजट में भी जो प्रोविजन किये हैं, 5.02 कृषि के लिए है। हमारे टाइम में जो था, उससे भी कम आ गया है। मैं यह नहीं कहता कि यह आपके टाइम में ही घटा है। कृषि की बजाए धीरे-धीरे हम उद्योग की तरफ ध्यान देने लग गये। कृषि की तरफ ध्यान दिया नहीं। कृषि में बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि में बहुत परिवार के परिवार लगे रहते हैं। उसके अलावा आप अनाज को लेबोरेटरी में नहीं पैदा कर सकते। हमको और आपको खाने के लिए अनाज चाहिए। उद्योग के लिए भी कच्चा माल कृषि से आता है। कृषि को अगर आप नैग्लेक्ट करेंगे तो यह प्रदेश ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, उद्योग भी आने चाहिए, वर्तमान वातावरण में औद्योगीकरण भी जरूरी है परन्तु उसके लिए हम हमारे पुराने, पुरातत्व संसाधन हैं, कृषि है, दूसरे हैं, उनको नहीं भूल सकते।

राजस्थान में हस्तशिल्प भी बहुत है। यहां छोटे उद्योगों के लिए भी बहुत स्कोप है। आप जिस कांस्टीट्युएंसी से आते हैं, वहां तो स्माल स्केल इण्डस्ट्री हैं। लोगों के पास कौशल है। माइक्रो बेस पर भी हम जा सकते हैं।

यहां खादी के लिए बात आयी, कभी सदन के किसी सदस्य ने सोचा है कि जो खादी भण्डार में वर्कर काम करते हैं उनकी क्या स्थिति है? उनको क्या वेतन मिलता होगा? हम सब बहुत चमकदार खादी पहनते हैं परन्तु, सभापति महोदय, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। खादी के लिए कह रहे हैं कि हम नये स्टोर खोलेंगे। पर खादी में जो वर्कर हैं, उनके लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए।

आपने कहा खेल और युवा मामलों के बारे में। आपने कहा कि 2,000 पंचायत मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाएंगे। हम पीपीपी पर अकादमियां खुलवाएंगे। हम राज्यस्तरीय टूर्नामेंट आयोजित कराएंगे। पिछली सरकार ने, सभापति महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

एक क्रांतिकारी कदम था। देश में पहली खेल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। दूसरी यूनिवर्सिटी जिसको पहले पीपीपी मोड पर देने की बात थी पर फिर कोई प्लेयर नहीं आया तो सरकार ने अपने क्षेत्र में उस यूनिवर्सिटी को खोला, गवर्नमेंट के क्षेत्र में खेल यूनिवर्सिटी को झुंझुनूं में खोला। उसका वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया। ओएसडी नियुक्त कर दिया, रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया। पर आपने उसमें एक नये पैसे का बजट दिया नहीं। आप जानते हैं कि राजस्थान में प्रतिभाएं हैं खेल की। वे प्रतिभाएं तभी निखर सकती हैं जब यहां खेल के लिए हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन हो। आज हम पंजाब की चर्चा करते हैं। पंजाब में हाकी में भी प्लेयर हैं, एथलेटिक्स में हैं, कबड्डी में भी हैं, और क्षेत्रों में भी हैं। वे क्यों हैं? उसका कारण, सभापति महोदय, यह है कि पंजाब में बहुत समय पहले से नेशनल स्पोर्टस इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। उसकी वजह से पंजाब के लोगों को खेल में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली। उससे उनको बहुत बढ़ावा मिला और पंजाब आज हमसे आगे है। आप इस बात पर नहीं सोचें कि किस सरकार ने यह यूनिवर्सिटी खोली थी। आप उससे मिलने वाले लाभों की ओर ध्यान दें और कृपा करके उस यूनिवर्सिटी को चालू करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जितना सीमित कर सकें, आप सीमित कर लें। आपका समय अब समाप्त हो गया है, जितना सीमित कर सकें, आप कर लें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति जी, चालीस-चालीस मिनट बोले हैं यहां लोग, मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सभापति: कोशिश नहीं, अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति जी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक एमओयू साइन हुआ झुंझुनूं के दोरासर गांव में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए। वह दो सरकारों के मध्य हुआ था। कोई दो पार्टियों के मध्य नहीं हुआ था। यह ठीक है कि उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां यूपीए की सरकार थी, पर सरकार तो सरकार ही होती है। जो समझौता उन दोनों सरकारों के बीच में हुआ उसका आपको आनर करना चाहिए। झुंझुनूं जिला सबसे ज्यादा सैनिक देता है। आपके केन्द्रीय मंत्री तो वहां आये और बोले, झुंझुनूं में पानी नहीं है, ये भूखे हैं इसलिए सेना में चले गये। आप इस बात को मानते हैं क्या? यह उन सैनिकों का अपमान किया गया है। हरियाणा जो हम से छोटा प्रांत है, उसमें दो सैनिक स्कूल हैं। आप

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

बड़ा दिल रखते हुए झुंझुंनूं जिले में जो दोनों सरकारों के मध्य समझौता हुआ है उसका आनर करें और सैनिक स्कूल की स्थापना करने की मेहरबानी करें।

आपने पहले बजट में यह कहा था कि हम राज्य की विकास दर को 12 परसेंट पर ले जाएंगे और राज्य के निवासियों की 10 परसेंट आय प्रति वर्ष बढ़ाएंगे। आप ले गये विकास दर को 12 परसेंट पर और आपने बढ़ा दी 10 परसेंट? कुछ वास्तविकताएं भी होनी चाहिए। मैंने तीनों साल के बजट पढ़े हैं, 30 परसेंट बातें तो इनमें रिपीट हैं, पैराग्राफ बदलकर दूसरी लिख दीं। 35 परसेंट आपके बजट की घोषणाएं चाहे वह 2014-15 का हो या चाहे 2015-16 का हो, उनकी क्रियान्विति ही नहीं हुई। अब इस बजट में क्या घोषणाएं होंगी, क्या नहीं होंगी? राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग अकाल से ग्रस्त है। बहुत बड़ी जनसंख्या अकाल से प्रभावित है, पशुधन भी अकाल से प्रभावित है उसके लिए बजट भाषण में एक शब्द नहीं है। यही नहीं, आप गो-पालन की और गो-संवर्द्धन की बात करते हैं, एक पैसा उसमें दिया नहीं अलबत्ता सेस लगाया है रजिस्ट्रियों पर कि उससे गो-संवर्द्धन करेंगे। इस सरकार का उसको मैं फ्लैगशिप प्रोग्राम कहूंगा, स्टार्टअप जैसे मोदी जी का है न, मेक इन इंडिया, उसके लिए आपने मात्र 10 करोड़ रुपये का आबंटन किया है और प्रचार उसका इतना किया है। रोजगार के बारे में इस पूरे बजट भाषण में कहीं पर भी यह नहीं है कि हमने इतने व्यक्तियों को रोजगार लगा दिया या इतने व्यक्तियों को अगले साल लगा देंगे। आपने कहा है आईआईटीज हैं, आईटीआई हैं, उनको निजी क्षेत्र से जैसे एल एण्ड टी है, और है, उनसे लिंक करेंगे और वो उनको रोजगार देंगे। वो तो रोजगार, माननीय सभापति जी, उन्हीं लोगों को देंगे जो उनके कारखाने में फिट बैठते हों, जो उनका काम करते हों। आपने मुझे समय दिया, सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल आत्मा से बोलेंगे। जब आपने कह दिया है तो कुछ विषय अब चेंज कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के हमारे एमएलए साहब ने कहा है कि आत्मा से बोलें। आत्मा की आवाज और दिल की आवाज तो कहती है कि मुख्य मंत्री महोदय ने सम्भाग स्तर पर जाकर और जन प्रतिनिधियों के साथ में, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बात का आकलन करने के बाद यह बजट दिया है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मुझे लगता है, इस बजट को देने के बाद में तो बानसूर से आने वाली विधायिका को तो बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। आप पहले बहुत ज्यादा बोली थीं। माननीय सभापति महोदय, बजट में व्यापकता है। जहां तक विचारों की बात है, यह देश एक ईश्वरीय देश है। जब-जब भी इस देश में कोई विकट समय आया है चाहे सरकारों के माध्यम से हो, चाहे कुछ विदेशी देशों के माध्यम से हो, तो यहां पर ईश्वर ने किसी न किसी को जन्म देकर भेजा है। माननीय सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष को यह विचार करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी यह दशा हो रही है। इसमें कहीं न कहीं प्रश्नचिह्न तो लगता है। जब प्रारम्भ करें बात को तो इनकी पार्टी में मिनिस्टर रहे हुए, केन्द्रीय मंत्री रहे हुए डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा देकर एक देशभक्त विचारवान पार्टी की स्थापना करते हैं, यह पहला प्रश्नचिह्न इनके ऊपर लगता है। उसके बाद देश में एक विचारधारा पनपती है और उसके बाद कश्मीर के विषय को लेकर इतना दर्द हुआ। अभी प्रतिपक्ष के बंधु इस बात को बहुत पाजिटिव कह रहे थे कि परिवार के मोह के अन्दर आज भी शेख फारुख अब्दुल्ला और जवाहर लाल नेहरू खानदान के ऊपर एक प्रश्नचिह्न लगता है, सम्बन्धों के ऊपर कि कश्मीर का कहां सौदा किया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत पर प्रश्नचिह्न लगता है, संजय गांधी की मौत पर प्रश्नचिह्न लगता है, शास्त्री जी की मौत पर प्रश्नचिह्न लगता है और यहां तक कि माधव राव सिंधिया जी की मौत पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। प्रतिपक्ष को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आपकी विचारधारा की यह दशा हुई है यह प्रश्नचिह्न क्यों लगा है। मैं यह कभी नहीं कहूंगा, यह कहते समय, कि आज की दशा के अन्दर यह कहना ठीक नहीं है कि सोनिया गांधीजी विदेशी हैं। मैं यह भी कभी नहीं कहूंगा कि इटली के एक खुफिया अफसर की वह बेटी हैं, यह भी मैं कभी नहीं कहूंगा कि सोनिया जी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की श्रीमती जी हैं इसलिए हम उनका आदर करते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह जो दशा हुई है, इनके नेताओं को आज इस देश की स्थिति और इस देश की परिस्थिति में यह ज्ञान नहीं है कि लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में फर्क क्या होता है। ऐसे नेताओं को तो आगे रखकर इनकी पार्टी चलती है तो इनकी पार्टी पर प्रश्नचिह्न नहीं तो क्या लगेगा? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन इन्होंने कहा दिल से बोलो तो मेरा दिल तो यह कह रहा है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, इस बार जो बजट दिया है, उद्योगपतियों को इकट्ठा करके राजस्थान की परिस्थिति को सामने लाकर राजस्थान की सरकार आपके लिए तत्पर है, आपके लिए तैयार है। एक सरप्राइज है 295 एमओयूज के बाद में। 3 लाख 21 हजार करोड़ के एमओयू होते हैं। वह अच्छा हुआ है, सही हुआ है, लेकिन तीन माह के बाद में लगभग 51 एमओयूज और होते हैं। यह आखिर कहीं न कहीं अच्छी चीज आई है। इंतजार करें, इसमें कहीं न कहीं राजस्थान का बहुत बड़ा भला होने वाला है। उसके बाद उद्योग में निवेश, आर्थिक वृद्धि, रीको लैंड बैंक के द्वारा एक बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि राज्य के अन्दर उद्योग स्थापित करने में एक बहुत बड़ी दिशा देगी। माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है, इनको तो कभी ध्यान में नहीं आया। पाली, बालोतरा और वहां के आजू-बाजू के किसान मर रहे थे। केमिकल इण्डस्ट्रीज के कारण से वहां की जमीनें खराब हो गयी थीं, किसान बेघर हो गये थे। पहली बार हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्पेशल पैकेज देकर पाली और बालोतरा की इण्डस्ट्रीज पर तो एहसान किया ही किया है, वहां के किसानों पर भी एहसान किया है। यह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? यह हमने किया है जो अच्छा किया है।

उसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना की बात चली। मैं यह कहता हूं कि इस देश में नरेन्द्र भाई मोदी सरदार पटेल के मूर्त रूप की छाया प्रति हैं। जैसा पटेल ने इस देश में चमत्कार किया था न, वैसा ही चमत्कार नरेन्द्र भाई मोदी भी करने वाले हैं। दूसरा एक विचाराधारा को बहुत-बड़ा श्रेय देने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधियाजी की छाया प्रति रूप में हम राजस्थान की मुख्य मंत्री को देखते हैं जिन्होंने एक प्रकार से भैरोंसिंह जी की अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाया। मतलब यह है कि आज दिन तक कांग्रेस ने सिर्फ एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने का काम किया है। अभी अम्बेडकरजी वाली बात चली, अम्बेडकरजी के नाम पर कई बार कांग्रेस के लोग भाषण देते हैं कि ये तो सामंतशाही और वो है, वो है। यह क्या कह रहे हो आप? अम्बेडकरजी को शिक्षा-दीक्षा देने वाला कौन परिवार था? बड़ौदा घराने के गायकवाड़ परिवार थे उन्होंने उस हीरे को तराशा और विदेशों में पढ़ने भेजा। कांग्रेस ने क्या किया? अम्बेडकरजी अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद इस देश की छाया अलग होती, इस देश का विकास अलग होता। कांग्रेस ने उनको संसद में नहीं पहुंचने देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया और

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

उनको संसद में नहीं जाने दिया। यह किया कांग्रेस ने और आज उनके नाम पर राजनीति करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, भैरोंसिहजी की कल्पना थी कि गांव के गरीब का अंत्योदय कैसे हो। परिवार की एक महिला इतनी सम्बल हो जाए कि वह अपने परिवार को, अपने को स्वाभिमानी तरीके से स्थापित करे। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने भामाशाह योजना में विभिन्न योजनाओं को जोड़ा, स्वास्थ्य बीमा योजना हो या मुख्यमंत्री जन आवास योजना हो या अन्नपूर्णा भण्डार हो।

राजस्व लोक अदालत, यह कांग्रेस के दिमाग में कभी विचार क्यों नहीं आया? लोक अदालत के माध्यम से इक्कीस लाख प्रकरणों को निपटाया। यह एक आश्चर्य है हिन्दुस्तान के इतिहास में। छोटे-मोटे राजस्व के बंटवारे वगैरह के मामले वर्षों से लटकते आ रहे थे न्यायालयों के चक्कर में, लोग वकीलों के पीछे घूमते फिर रहे थे। उन केसों का निपटारा किया। 21 लाख केसों को निपटाया है। यह क्या है? यह चमत्कार नहीं तो क्या है? यह हमारी सरकार का चमत्कार है। गोविन्द सिंहजी, आप लेट आये हो, वास्तव में आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके सारे माननीय सदस्य रिपीट कर रहे हैं, आप भी रिपीट कर दें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आज यदि अपन इस बात को कहें तो यह पहली बार हुआ है। सड़क का प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह पहली बार हुआ है कि सड़क के मामले में हमारी मुख्य मंत्री ने लगभग 22 प्रतिशत बजट को बढ़ावा देकर उसका प्रावधान किया है। गौरवपथ की कल्पना आपके दिमाग में कभी क्यों नहीं आयी? कीचड़ और गन्दगी में गांव रहता था, ऐसी भावना क्यों नहीं आयी? आपका दिल साक्षी दे रहा होगा कि ऐसे गौरवपथ शायद हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं बने हैं। पंचायतों के माध्यम से गांवों में ऐसा विकास होगा क्या? स्वच्छता के लिए स्पेशल पैकेज जो दिया है मुख्य मंत्री महोदय ने, ऐसी भावना आपके दिमाग में क्यों नहीं आयी?

माननीय सभापति महोदय, लगभग दो हजार गौरवपथ और देने का जो पैकेज दिया है और लगभग 1027 करोड़ की लागत से 1955 किलोमीटर जो दिया है, वह वास्तव में सराहने योग्य है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या दिया है, 1955 ? पहले का बताया है, पिछली साल का।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बताता हूं। आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान का भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए आता था, तो ऐसा आपके दिमाग में कभी क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है। आपकी कल्पना ही नहीं है। मुझे लगता है कि कृष्ण को जानते हैं या नहीं, यह भी प्रश्नचिह्न लगेगा आपके ऊपर।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नाम ही नाम है, गोविन्द कुछ नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): भरतपुर गोवर्धन की 84 कोस की परिक्रमा के लिए 103 करोड़ रुपये दिये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नाम ही नाम है लेकिन हम नकली नाम नहीं लगाते हैं असली नाम लगाते हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): और ये इतने सारे आरओबी दिये हैं। मैं कह रहा हूं कि 337 करोड़ में दस आरओबी और 761 करोड़ में 19 आरओबी वास्तव में सराहने योग्य बात है। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरी कांस्टीट्युएंसी में भी बागड़ा-जालौर आरओबी दिया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत अभिवादन करता हूं।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): मेरे तरफ से कर दीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपकी तरफ से भी? चलो, भीनमाल एमएलए साहब की तरफ से भी अभिवादन करता हूं।

पेयजल के लिए भी योजनाओं का विस्तारीकरण किया है। आप लोगों ने तो क्या किया कि फटाफट अंत में जैसा चाहिए वैसा कराके पत्थर लगाओ। मतलब योजनाएं तो बना दीं, लेकिन उनके लिए फंड ही नहीं दिया। पेयजल में मैं मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा। नर्मदा के नीर को जालौर की धरती पर लाने के लिए 2007 में जो तय किया था लक्ष्य, आपकी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राजस्थान की जनता, जालौर की जनता का आपने लगभग पांच सौ करोड़ का नुकसान किया है। वह योजना पांच सौ करोड़ और महंगी हो गयी। हमने उसको पिछले बजट में दिया है और अब बहुत द्रुत गति से नर्मदा का पानी पहुंचेगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय से और पेयजल मंत्री से एक निवेदन करूंगा कि जो नर्मदा का विषय चल रहा है, थोड़ी-सी स्पीड धीमी है। इस

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

स्पीड को तेज करने के लिए और बजट आबंटित करना पड़ेगा। प्रोजैक्ट में मेरी कांस्टीट्युएंसी के 26 गांव अभी तक छूट रहे हैं, उनको भी पूरा पानी दिया जाए। जमीन का वाटर लेवल बहुत नीचे है इसलिए हैंडपंप से काम चलाया है। लगभग 40 करोड़ रुपये हैंडपंप के लिए भी दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा वाला विषय है, यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला विषय नहीं है। सब लोग कह रहे हैं, सभी ने सुना है। पूरा राजस्थान सुनता है कि आपने तो इस बिजली के विषय को बिलकुल गर्त में डाल दिया था। कोई चिन्ता नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रबंधन कर इसके वितीय भार को सैट असाइड किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 75 प्रतिशत तो उस विभाग को वापस खड़ा कर दिया है। लगभग साठ हजार करोड़ रुपये उसके लिए तैयार कर दिये हैं। यह एक सोच है। आपने क्या किया? गर्त में डाल दिया था। आज सौर ऊर्जा के मामले में पूरा देश अगर राजस्थान को प्रथम स्थान देता है तो कुछ न कुछ तो किया है न। यह कल्पना आपके दिमाग में क्यों नहीं आयी? क्योंकि आपकी सोच ही नहीं थी। आपको तो आनन-फानन में खजाना लुटाना था, ये करो, वो करो लेकिन कोई उसका प्रोविजन नहीं किया था।

माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रथम दो वर्षों में 4282 मेगावाट और पूर्ववर्ती सरकार ने किया 2293, मतलब आधे भी नहीं पहुंचे। कैसे आप कुछ कहोगे? कहने के लिए कोई लिमिट बची नहीं है। यह बजट पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। छीजत बचाने के लिए 220 केवी के 6, 132 केवी के लगभग 16, 33 केवी के 200 । छीजत कैसे कम हो, इस बात की चिन्ता की है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि बिजली की चोरी रोकने के लिए आज जो गांव के गरीब और गांव के किसान को मारा जा रहा है, उसकी कहीं न कहीं रोकथाम करनी पड़ेगी। आज एक गरीब बीपीएल परिवार को 11 हजार का बिल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आधा बिल भर दो, आधा बिल बाद में देंगे। आधा क्यों भरे, कैसे भरे वो बीपीएल परिवार?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट रुकें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय इस बात की थोडी-सी चिंता करें, अधिकारियों की लापरवाही से जीएसएस पर मीटर लगा दिये, उनका एडजेस्टमेंट करने के लिये कहीं बिल गड़बड़ हो रहा है। उसको हमें चैक करना चाहिये। देखिए, जो बात है उसको स्वीकार करेंगे, आप चिंता मत करो।

देवस्थान- 12 देवस्थानों को लगभग 33 करोड रुपये, यह कभी इनके दिमाग में ही नहीं आया। पर्यटन इस राजस्थान की आत्मा बन सकता है। है भी, था भी और उसको और डवलप किया जा सकता है। इसके प्रचार-प्रसार हेतु 62 करोड 33 लाख दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन के मामले में कहना चाहूंगा कि हमारी पर्यटन की जो विरासत है इस विरासत के बारे में वास्तव में चिंता करें, इसके प्राइवेटाइजेशन का नहीं सोचें। दक्षिण भारत से यहां पर्यटक आते हैं, उत्तर भारत में कैसी स्थिति है? आज राजस्थान में इतना जबरदस्त पर्यटक आ रहा है, मेरा सिर्फ एक निवेदन है, जिस प्रकार से हमने 2003 में किया था, मुम्बई के जितने भी कैटर्स एसोसिएशन हैं, पर्यटन विभाग की तरफ से एक डिसप्ले करके उनको आमंत्रित किया था। उसके बाद मुम्बई का पर्यटक आ रहा है। वे जैसी व्यवस्था चाहते हैं वैसी व्यवस्था हमने यहां पर की तो हमारा पर्यटन का बिजनेस 2003 से 2008 में अच्छा हो गया था, बढ़ गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और यह वापस गर्त में चला गया। इस चीज को वापस उबारना चाहिये। पर्यटन वास्तव में राजस्थान की आत्मा है, पर्यटन पर हम बहुत ध्यान दे सकते हैं।

खनन में भी विकास कार्य के लिये लगभग 150 करोड़ दिये हैं।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, खनन के बारे में खनन नीति वगैरह सारा चल रहा है। पिछली सरकार के समय आनन-फानन में पहले पट्टे दिये और फिर पट्टे कैंसिल किये। घोटाला किया। आप लोग घोटाले के दोषी हो, इसके कारण आज खनन पर एक प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। उस जमाने के आपके अफसर, मैं आज आपको कह रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखना, श्रवण जी। माननीय सभापति महोदय, सीबीआई का दुरुपयोग करके प्रतिपक्ष ने क्या किया? हमारे शेर जैसे अफसरों को जेल में डाल दिया था, दिनेश एनएम जैसे को। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस शेर जैसे अफसर को बाहर निकालकर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा। यह हमने किया है, आपने संरक्षण दिया था।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग में भी हमने काफी प्रावधान किये हैं। गत वर्ष में लगभग 600 पशु चिकित्सा केन्द्र दिये थे, इस वर्ष लगभग हजार दिये हैं, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है। आपदा के मामले में अभी बात चल रही थी, हकीकत में किसानों की चिंता करके आपदा राहत कोष में जो अनुदान दिया है, वह शायद इतने वर्षों में कभी नहीं दिया गया था। यह पहली बार हुआ था। बीच में ओलावृष्टि वाला विषय हुआ था तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सभी अपने-अपने फील्ड में जाएं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। 50 से 33 परसेंट पर उसको लाये। आप लोग नहीं कर रहे हो, यह करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई वाले विषय में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंचाई मंत्रीजी को। यह पहली बार हुआ है। प्रतिपक्ष हमेशा ....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह पहली बार के चक्कर में हम 21 आ गये, इस पहली बार को तो छोड़ो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह पहली बार हुआ इसलिए कि आप 50 साल से पाकिस्तान बार्डर पर कच्ची नहर के माध्यम से पाकिस्तान में पानी चोरी करवा रहे थे। यह आप पर सीधा आरोप है। हमारे मंत्री महोदय ने यह पहली बार किया है कि उस कच्ची नहर को पक्की करवाया। सभापति महोदय, सौ-सौ किलोमीटर अन्दर से पाकिस्तान में पाइप लाइन दी हुई थी और वह पानी चोरी जा रहा था। यह पहली बार हुआ है कि उस नहर को पक्की करके उस सारी चोरी को बंद कर दिया गया। ये फोटोग्राफ हैं, आप देख सकते हो। इतने वर्षों तक आपने चलाया, हमने पहली बार किया है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रखरखाव के लिये 370 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। नदियों से नदियां जोड़ना, यह कल्पना आपके दिमाग में क्यों नहीं आयी? अटलजी की कल्पना को साकार करने का काम हमारे नरेन्द्र भाई मोदी और वसुंधराजी ने हाथ में लिया है, राजस्थान स्वर्ग बनेगा, राजस्थान में भी कश्मीर की तरह केसर की क्यारियां होंगी, यह राजस्थान की कल्पना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध, जवाई बांध के पुनर्भरण के लिये आपने जो डीपीआर की मंजूरी दी है, उसके लिये मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ में आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जंवई बांध जिस जवाई नदी पर बना है वह जवाई नदी 300 किलोमीटर जालौर जिले में चलती है। पूरा जालौर जिला जवाई नदी के किनारे हैं और जवाई नदी डार्क जोन में आ गयी है, उस नदी को जीवित करने के लिये भी आप कुछ सोचें, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से मेरा एक और निवेदन है। मेरे 22 गांव जो जवाई से सिंचित होते हैं, उसमें 700 किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में से नहर जा रही है। सैटलमेंट के समय और कांग्रेस के राज के समय कुछ मजबूत लोगों के कारण उनको नहर से बाहर कर दिया था। इस बार, मंत्री महोदय, आपके आदेश से 136 की कार्यवाही के बाद सारे केस पूरे तैयार हो चुके हैं। आपका विभाग वाले देखभाल कर चुके हैं। सुमेरपुर के कुछ ऐसे हजार केस हैं। हजार बीघा सुमेरपुर की है और लगभग 4 से 5 हजार बीघा मेरे आहोर की है, उनको आप नहरी करें। वे मेरे गरीब किसान हैं, एक भी किसान 20-25 बीघा से बड़ा किसान नहीं है। आपको बहुत बड़ी दुआ लगेगी। मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है, यह वास्तव में बहुत ही मार्मिक काम है, इस विषय को भावनात्मक रूप से जोड़ें और करें तो गरीबों का बहुत बड़ा भला होगा और आपको दुआ लगेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे कुछ विषय हैं। एक तो सूखडी डाइवर्जन, सूखडी नदी थी उसको किसी जमाने में, कांग्रेस के शासन में बंद कर दिया था। उसको हमने वापस खोल दिया है। उसको पक्का करने के लिये, चैनल बनाने के लिये लगभग 2 करोड रुपये की डीपीआर बनी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, बजट में मेरी यही मांग थी, मंत्री महोदय मेरी इस मांग को

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पूरा करेंगे तो मेरे लगभग 28 गांव, वह सूखडी नदी जवाई से निकलकर वापस जवाई में गिरती है, 28 गांवों के बीच में से होती हुई जाती है, उससे वह 28 गांव बहुत लाभान्वित होंगे। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का भी यह एक पार्ट है। हमारे हिन्दुस्तान में तो ऐसी संस्कृति थी कि अमावस्या और पूर्णिमा को ओडी लेकर दो-दो तगारी तालाब से लेकर रेती बाहर डालते थे। इस धार्मिक काम को वास्तविकता में जोड़ा है इसके लिये मुख्य मंत्री महोदया को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। लगभग सारे गांवों में यह विषय हो जाएगा। प्रवासियों को जोड़ कर, सारे जन प्रतिनिधियों को जोड़ कर। कण दे या मण दे, जो भी दे, उसका स्वागत है। गांव के हर व्यक्ति में यह मेरा काम है, यह मेरी योजना है, ऐसा अपनत्व तैयार किया। मुख्य मंत्री महोदया ने जो ऐसा किया, उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास में मेरा एक निवेदन है। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, सिरोही, जालौर और पाली के मीणा ट्रायबल हैं, चौकीदार मीणा है, एकदम गरीब। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं यह भील और मीणा एक दम चौकीदार मीणा हैं। रिजर्वेशन का सारा फायदा? मैं बडे भाई कहूं, और बडे भाई को छोटे भाई के प्रति उपकार करना चाहिये, सवाई माधोपुर, टोंक में निश्चित रूप से उनकी लिटरेसी ज्यादा है, पढ़ाई-लिखाई ज्यादा है इसलिए सारा भाग वहां जाता है, मेरे पाली, जालौर और सिरोही के मीणा समाज, भील समाज को बिलकुल नहीं मिलता है। जनजाति मंत्री महोदय को मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरे जालौर जिले में 20 प्रतिशत मीणा और भील समाज है, जालौर, सिरोही और पाली तीन जिलों के सेंटर में मुझे या तो एक आवासीय विद्यालय दें या आवासीय छात्रावास दें। मेरे यहां बच्चियों की संख्या भी खूब है, आप बालिका छात्रावास भी दें तो भी स्वागत है, लेकिन दीजिए, इससे जनजाति समाज आगे बढेगा।

(17.00 बजे)

आज दिन तक हमारे यहां पर दो या चार-पांच कर्मचारी हैं, उसके अलावा कोई सरकारी अफसर नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। कैसी अंधाधुंध दुनिया है ये? माननीय सभापति महोदय, कहीं तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। एक साइड में तो एक परिवार में पांच-पांच, छह-छह आई.ए.एस. अफसर और एक साइड में पूरे गांव के अन्दर एक पिऑन भी नहीं है। यह बैलेंस हमने नहीं संभाला, संभालना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है ।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर एक अभूतपूर्व चेंज किया है। सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी हमारे चप्पल फट जाते थे, लेकिन एक ही आदेश के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने पांच हजार चार सौ सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी किया। इसके बाद शिक्षा में लगभग–लगभग चौदह-पंद्रह परसेंट बजट भी बढ़ाया। इसके लिए भी बहुत-बहुत उनका अभिनंदन है। एकीकरण वाला यह काम भी शिक्षा जगत को बहुत बड़ी दिशा देगा।

खेल और युवा मामले में हाकी और कबड्डी की विशेष कोंचिंग के लिए जो किया है, वह भी बहुत अच्छा निर्णय किया है। माननीय गेम्स मिनिस्टर यहां पर हैं, आहोर में मुझे एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता है। अगर आप देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा।

माडल स्कूल और बालिका छात्रावास, इसमें भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए भी हमने बहुत अच्छा पैकेज दिया है 58 करोड़ 65 लाख रुपए का और अन्य कार्यों के लिए 1750 करोड़ का।

उच्च शिक्षा के अन्दर बहुत अच्छा प्रावधान, मुझे आहोर में कालेज दिया। सरकारी कालेज पिछले बजट में दिया, इसके लिए स्वागत है। बस अब वहां पर साइंस और कामर्स सब्जेक्ट दे दीजिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना ही मेरा निवेदन है।

चिकित्सा के अन्दर, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, वास्तव में आपने तो बहुत बड़ा कमाल किया है। जोरदार कमाल किया है। गरीब व्यक्ति जो बड़े हास्पिटल में जा नहीं सकते थे, बीमारी के कारण उनको मरना पड़ता था। आपने वहां पर उनका हक दिलवा दिया है। यह बहुत बड़ा उपकार किया है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, लगभग 8742 करोड़ का प्रावधान किया, यह भी अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और इसके अलावा काफी सारे पैकेज दिये हैं।

चिकित्सा मंत्री महोदय, आपकी कृपा हमेशा रही है हमारे ऊपर, एक छोटा-सा निवेदन मेरी आहोर की जनता के लिए। आहोर की सी.एच.सी. का ओ.पी.डी. पूरे जालौर जिले में प्रथम है। मतलब इतनी बढ़िया सेवा होती है। मैंने वहां एन.जी.ओ. को भी कुछ जोड़ा हुआ है। वहां सफाई व्यवस्था आप देख लो, जोधपुर डिवीजन में ऐसा हास्पिटल आपको नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

इतना कर दीजिये। 50 शय्या से 75 शय्या कर दीजिए। और मुझे एक या दो पी.एच.सी., जितनी मेरे हिस्से में आए उतनी आप दे सकते हो तो दे देना।

आरोग्य राजस्थान में एक करोड़ पांच लाख परिवारों जो हैल्थ सर्वे करके हैल्थ कार्ड बनेगा, वह निर्णय भी बहुत अनुकरणीय है।

आयुर्वेद में, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मुझे आयुर्वेद हास्पिटल ऊण में चाहिए, ऊण में। वो भी आप मुझे देंगे।

कौशल विकास मतलब गांव का व्यक्ति चाहे वो लाइनमैन है या कंपाउंडर है या और कोई इस्तरी का काम करता है, उसका कौशल विकास। उसके अन्दर जो हुनर है उसका विकास कैसे हो, इस बात की चिंता हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने जो की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आकोली में मोगलड़ा बांध है जो अधूरा पड़ा है। वो आपके किसी टैक्निकल काम से अधूरा पड़ा है। उसको वापस प्रारम्भ कर दिया जाए। आपका विभाग भी उस बारे में चिंतित है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बजट स्वर्णिम बजट है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। किसान ओरिएंटेड भी है, लेबर ओरिएंटेड भी है, रूरल ओरिएंटेड भी है और सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी है। सारे विभागों को छुआ है मुख्य मंत्री ने।

फिर से माननीय सभापति महोदय, एक ही बात कहकर विपक्ष कहीं न कहीं एक छोटा-सा उदाहरण। एक यमुना नदी में एक पति-पत्नी यमुना नदी को पार करना था और पति दिन कहता था और पत्नी रात कहती थी तो बीच में मटकों में पहले मटकों में बैठकर नदी पार कर रहे थे बीचोंबीच जाकर उस पति ने कहा कि अब तू एकदम बराबर पकड़कर बैठना तो कहा कि नहीं बैठूंगी। अरे बराबर पकड़कर बैठना तो नहीं बैठूंगी और वह पत्नी डूब गयी। वैसे ही मेरे प्रतिपक्ष के लोगों आप लोग पाजीटिव सोचो तो सही रहोगे। नहीं तो वो ही उस पत्नी की हालत हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 8 तारीख को बजट पेश किया उस पर चर्चा में

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

भाग ले रहा हूं। महोदय, जब भी हम बजट पर बोलने के बारे में सोचते हैं तो एक बात जो सबके दिमाग में आती है वो यह आती है कि वो बजट पेश कौन कर रहा है? उसका विजन क्या है? क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है Leadership is the capacity to translate vision into reality. अगर विजन अच्छा होगा तो हकीकत भी अच्छी होगी और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस सदन को ऐसा नेता मिला है। जिसका न कि केवल विजन अच्छा है, बल्कि उसको हकीकत में बदलने की क्षमता हम 2003 से 2008 में भी देख चुके हैं और अभी भी हम लोग देख रहे हैं। सभापति महोदय, अमरीका के प्रसिद्ध राजनयिक हैनरी किसंजर ने कहा है The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. यानी कि लीडर का टास्क यह है कि लोगों को जिस जगह पर वो हैं वहां से ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर वो कभी गए नहीं हो और मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम राजस्थान को उसी प्रगतिशील पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं बजट का विश्लेषक नहीं हूं पर यह जरूर जानता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जिन बेसिक थ्रस्ट की हमको जरूरत है। इस बजट में उन सब बातों पर विशेष ध्यान हमारी सदन की नेता ने दिया है। महोदय, बालिका उत्थान, बालिका-महिला उत्थान सबसे बड़ा आज का सवाल है और उस पर बहुत कुछ बजट मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे राजस्थान में अंडर डवलप्ड है, उसके ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने खूब घोषणाएं की हैं। गौरव पथ भी दिये हैं, रोडों का निर्माण भी किया है, पुलों का भी दिया है। कृषि विभाग को भी बहुत कुछ दिया है तो चिकित्सा विभाग को भी बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा जो हौसला मुख्य मंत्रीजी ने किया वो ये कि बिजली का घाटा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 75 परसेंट बिजली का घाटा बजट में समायोजित करके उस घाटे को सदा के लिए समाप्त कर रहे हैं। बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस राज में बिजली आती थी चार से पांच घंटे, हम बिजली दे रहे हैं छह से सात घंटे। कांग्रेस राज में कनेक्शन नहीं दिये किसानों को। फाइलें लम्बित पड़ी थीं। हमने पिछले साल चालीस हजार दिये, इस साल भी चालीस हजार कनेक्शन की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

सभापतिजी, मैं बजट की बातों को दोहराना नहीं चाहता, काफी लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की चर्चा ज्यादा करूंगा। मेरे क्षेत्र

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। जब-जब जलदाय मंत्री के पास मैं गया, उन्होंने सहयोग दिया। हैंडपंप दिये, ट्यूबवैल दिये, सब कुछ दिया। लेकिन आज की तारीख में ग्राउंड वाटर ही उपलब्ध नहीं है। मेरे यहां पर सरफेस वाटर को टैप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने सरफेस वाटर की स्कीम बनाना शुरू किया। महोदय, उदयपुर सम्भाग की देवास योजना बहुत बड़ी योजना है, हमने सोचा था कि जिस तरह से उदयपुर में पानी आ रहा है, उदयपुर के अलावा सम्पूर्ण उदयपुर जिले में पीने के पानी की समस्या से हम निजात पा जाएंगे। लेकिन, महोदय, देवास योजना का पानी पिछोला को भरने में, स्वरूप सागर को भरने में, फतेह सागर को भरने में और उदयपुर शहर को पानी पिलाने में पूरा हो रहा है। महोदय, यह बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है जब उदयपुर की सब झीलें भरी हुई रहती हैं। हमको भी अच्छा लगता है जब ट्यूरिस्ट आकर कहता है कि उदयपुर कितना खूबसूरत है। लेकिन उससे हमारे पीने के पानी की जो समस्या है उसका क्या? सरकार ने इस ओर कब ध्यान दिया ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, देवास योजना जब शुरू हुई थी तब भैरोसिंहजी के टाइम पर नाबार्ड के पास लोन लेने के लिए गये थे। नाबार्ड ने यह पूछा था कि इस पानी को लाकर आप क्या करोगे। तो जवाब था कि हम पानी पिलाएंगे। उन्होंने पूछा, पानी किसको पिलाओगे। तो कहा, उदयपुर शहर को पिलाएंगे। तो नाबार्ड ने कहा कि हम तो रूरल बैंक हैं, शहर के पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, आप किसी अन्य बैंक के पास जाओ। तब यह लिखकर दिया गया कि वल्लभनगर और मावली को पीने के पानी की व्यवस्था हम इस देवास योजना से करेंगे। सभापति महोदय, वह योजना ग्रामीण क्षेत्र के पीने के पानी के लिए बनी थी लेकिन आज शहरी क्षेत्र को पानी पिला रहा है। उदयपुर को पानी पिलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उदयपुर को आरएसएमएम से पानी ले जाकर पिला रहे हो, उदयपुर को जयसमंद से भी पानी ले जाकर पिला रहे हो, उदयपुर को मानसी वाकल से भी पानी पिला रहे हो, उदयपुर को उनकी झीलों से भी पानी पिला रहे हो और जिले के अन्य क्षेत्र ऐसे के ऐसे पड़े रहें यह किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। योजनाएं बनें तो पूरे जिले के लिए बननी चाहिए न कि एक मात्र शहर के लिए।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

(समय 17.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वल्लभनगर के लिए हमने खूब प्रयास किया लेकिन मानसी वाकल योजना उदयपुर शहर की बनकर रह गयी। अब सुन रहे हैं कि यह पानी तो राजसमंद जा रहा है देवासरी में। तो फिर हम तो रह ही गये। सुरेन्द्र सिंह जी बहुत मुस्करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें 500 एमसीएफटी पानी ही ज्यादा आने वाला है। आपकी राजसमंद की झील है 3700 एमसीएफटी की, उसमें कुछ पानी पहुंचेगा ही नहीं। फिर भी आप ले जा रहे हो, लेकिन हमको पानी पिलाकर ले जाओ। उदयपुर जिले के वल्लभनगर और मावली प्यासे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मार, हिन्दुस्तान जिंक हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है। रात को वह अपशिष्ट छोड़ता है। 12 पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। मैंने यहां विधान सभा में बात उठायी, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड वालों ने कहा, वह पानी तो बहुत अच्छा है, उसको सब पी सकते हैं। मेरा उनके अधिकारियों से निवेदन है, मेरे साथ चलें, उस पानी को खुद चखकर देखें कि वह पानी पीने योग्य है या नहीं है। 12 पंचायतें पूरी तरह से पानी के प्रदूषण से ग्रस्त हैं। पीने का पानी रहा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हिन्दुस्तान जिंक को आपने डैडीकेटेड पाइप लाइन निकालकर दे रखी है देवास योजना से, वह ठेठ दरीबा तक जा रही है। सरकार न करे लेकिन हिन्दुस्तान जिंक को तो बाध्य करें कि 12 पंचायतें जो इनके कारण खराब हुई हैं, उनमें पानी की व्यवस्था हिन्दुस्तान जिंक करे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने वल्लभनगर की समस्या के लिए कसोटिया बांध की योजना बनायी मेरे विधान सभा क्षेत्र के 162 गांवों को पानी पहुंचाने के लिए। वह सरकार के पास है, मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पूरा बजट न सही लेकिन बांध बनाने के पैसे तो इस वर्ष जरूर दिये जाएं ताकि हमारे क्षेत्र को पीने के पानी की समस्या से सदा के लिए निजात मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं एमएलए लैड से पिछले दो वर्ष से 60 से 70 प्रतिशत पेयजल पर ही खर्च कर रहा हूं परन्तु यह पैसा नाकाफी है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 68 पंचायतें हैं और दो नगरपालिकाएं हैं। मेरा बजट भी 2 करोड़ है और उनका बजट भी दो करोड़ है जिनके यहां 25 पंचायतें ही

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

है। यह विसंगति है। आप जानते हैं कि शहर के विधायक तो खर्च करने के लिए जगह ढूढते हैं कि हम कहां खर्च करें। गेट लगवा रहे हैं, फाटक लगवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। मेरा यह निवेदन है कि शहर के विधायकों का बजट थोड़ा कम करके ऐसी विधान सभाओं को दिया जाए जिसमें कि पंचायतें अधिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय से यह कहा जाता रहा है कि विधायक का प्रोटोकोल चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर है, लेकिन होता क्या है? 15 अगस्त को एक आरएएस हमारे सामने झण्ड़ा फहराता है और हम बैठे-बैठे देखते हैं। यह मामला केन्द्र सरकार का जरूर है लेकिन इसको हमारी सरकार लिखकर भेजे कि यह विधायकों का अपमान है। हमको कहते हो कि चीफ सैक्रेटरी से ऊपर हमारा प्रोटोकोल है और आरएएस अफसर हमारे सामने झण्ड़ा फहराए और हम बैठ-बैठे देखें, यह तो उचित नहीं है। हमारे क्षेत्रों में झण्ड़ारोहण का अधिकार विधायकों को दिया जाए।

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि मेरी तहसील बहुत बड़ी है। सदियों से उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि भीण्डर में और कालोड में नयी तहसील खुले। हमने खूब प्रयास किया, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट घोषणा करते-करते रूक गयी। वह पूरी योजना यहां पर है। परमेश चन्द्रजी की कमेटी है उसमें भी उस बात की जानकारी है। भीण्डर-कानोड़ को तहसील की घोषणा की जाए। कांग्रेस ने तो जहां एलआर सर्कल थे वहां पर भी तहसील की घोषणा कर दी, लेकिन यह सरकार जहां जरूरत है, न्यायोचित है वहां पर जरूर घोषणा करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति में 52 पंचायतें हैं। अभी नयी पंचायत समितियां खूब बनीं और ऐसी बन गयीं जिनमें 20-20,25-25 पंचायतें ही हैं। जानबूझकर व्यक्तिगत द्वेष भावना रखते हुए पूर्व पंचायत मंत्रीजी ने मेरी पंचायत समिति को दो टुकड़ों में विभाजित नहीं होने दिया। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरी पंचायत समिति जो बहुत बड़ी है, उसके भी दो टुकड़े किए जाएं। पंचायती राज मंत्रीजी, आप भी सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि 52 पंचायतें हैं, सबसे बड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है।

इसी तरह से मेरा जो सीओ सर्कल है डीवाई एसपी बैठता है उस पर 8 थाने लगते हैं। यह भी उदयपुर सम्भाग का सबसे बड़ा सीओ सर्कल है। इसको भी तोड़कर दो बनाने की जरूरत है। भीण्डर में एक नया डीवाई एसपी कार्यालय खुले, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा। गृह मंत्रीजी

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

यहां नहीं हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से बजट बहुत अच्छा है। हम सब यह अपेक्षा करें कि हमारी-हमारी ही तहसीलों में सब कुछ हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जनरल बातें सब विधान सभा की, जैसे गौरव पथ है, चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय है, ऐसी चीजों का मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है और सबको दी हैं। कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही अच्छा रहा, परन्तु एक कहावत कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। Teamwork makes the dreams work, but a vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team. मुझे ध्यान है कि मुख्य मंत्रीजी इस बात को ध्यान में रखेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: इसको आप हिन्दी में अनुवाद करके दें, यह Big dream and bad team वाला क्या मामला है ।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष जी, आपका निर्देश है तो मैं इसको हिन्दी में कर देता हूं-Teamwork makes the dreams work, अगर टीम अच्छी है तो जो सपना हमने संजोया है वह अच्छा चलेगा। But a vision becomes a nightmare लेकिन किसी का विजन है वह सपना बनकर रह जाएगा अगर टीम बहुत बेकार हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी तो सारी बात मानते हैं आपकी।

श्री उपाध्यक्ष: अब प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको कौनसी गलतफहमी हो गयी इससे?

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है, हमारी सदन की नेता इन बातों का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों में अच्छा विकास कर रही है और छोटी-मोटी समस्याएं जो मैंने उठायीं हैं, उन पर भी ध्यान रखेगी।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसीराम।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा 8 मार्च को चौदहवीं राजस्थान विधान सभा कासमग्र विकास की भावना से प्रस्तुत बजट राज्य के कोने-कोने में सराहा जा रहा है। चाहे अर्थशास्त्री हों, समाजशास्त्री हों, सीनियर लेजिस्लेस्टर हों, ब्यूरोक्रेटस हों

(श्री जगसी राम)

या समाज के किसी तबके के नागरिक बंधु हों, यहां तक की टीवी, मीडिया, समाचार पत्रों के बीच श्रीमती वसुंधरा राजे जी के बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है।

बजट में सिरोही जिले की पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, जल वितरण, वन एवं गैर वन क्षेत्र, जल संग्रह की मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस हेतु मैं सिरोही जिले की आम जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। नगर पालिका क्षेत्र को जल वितरण, सीवरेज और ड्रेनेज के लिए राज्य के 37 शहरों के लिए कुल 4200 करोड़ की योजना शामिल की गयी है। सिरोही जिले को वन क्षेत्र एवं गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रह क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 जिलों के लिए बनायी गयी 157 करोड़ 61 लाख की योजना में शामिल किया गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सिरोही जिले की अहम और बड़ी पेयजल समस्या के समाधान की मंशा से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर 213 करोड़ की विशाल पेयजल योजना का प्रावधान कर सिरोही जिले की कायापलट करने का तोहफा दिया है। जल ही जीवन है, इस हेतु सिरोही की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोटि-कोटि सादर धन्यवाद देता हूं।

कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में मुझे रहने का मौका मिला था, उस समय में जो घोषणाएं की गयीं थीं, आज तक अमल में नहीं आयीं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 8 तारीख को पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र को छुआ है। छोटे से छोटे काश्तकार तक की भी बात उसमें सम्मिलित की है, हमारी मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा।

किसी भी क्षेत्र का सड़क विकास वहां की समृद्धि का द्योतक माना जाता है। राज्य के आधारभूत विकास के तहत मुख्य मंत्रीजी ने राज्य की छोटी-बड़ी सड़कों के समग्र विकास के लिये पर्याप्त प्रावधान इस बजट में कर चार चांद लगा दिये हैं। ग्रामीण गौरव पथ जैसी प्रभावी सड़क योजना की उपयोगिता एवं गांवों से मिल रहे बहुत ही अच्छे रेस्पांस के चलते इस योजनान्तर्गत 1955 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के लिये 1027 करोड़ का बजट प्रावधान जो किया है, प्रदेश की जनता इससे बहुत खुश है। राज्य की 1009 मिसिंग लिंक व 2182 किलोमीटर लम्बी सड़कों के लिये रुपये 608 करोड़ का प्रावधान काबिल-ए-तारीफ होने के साथ-साथ राज्य के आधारभूत

(श्री जगसी राम)

ढांचा विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 250 से 350 की आबादी की सड़कविहीन 1468 बसावटों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने हेतु 4303 किलोमीटर लम्बाई के लिये 618 करोड़ 64 लाख का प्रावधान इन ग्रामीण बसावटों का कायापलट कर देगा।

हमारी मुख्य मंत्रीजी की ईश्वर में अगाध आस्था से हम ही नहीं अपितु राज्य के चप्पे-चप्पे की आम जनता वाकिफ है। पूर्वी राजस्थान की श्रीगोवर्धन एवं ब्रज परिक्रमा का मार्ग तथा पश्चिमी राजस्थान में श्रीरामदेवरा पदयात्रा मार्ग के श्रद्धालुओं की पीड़ा को देखते हुए इन फलदायी आस्था केन्द्रों के मार्गों के नव-निर्माण एवं सुधार के लिये करोड़ों के प्रावधान प्रशंसनीय हैं। गोवर्धन एवं ब्रज परिक्रमा क्षेत्र के लिये 103 करोड़ 94 लाख का प्रावधान किया जाना बहुत सराहनीय है। 14 करोड़ 64 लाख रुपये का प्रावधान रामदेवरा के लिये है। 10 आर.ओ.बी. और 19 अन्य आर.ओ.बी., 2 आर.यू.बी. ब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिये 300 करोड़, नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा कर सड़क की आधारभूत सुविधा से राज्य को सराबोर करने पर मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने अपनी ओर से प्रीमियम पेटे पहले से जमा करायी जा रही राशि में बढ़ोतरी कर किसानों को विशेष राहत दी है, इससे प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल होगा।

किसानों को आये दिन निजी खाद विक्रेताओं से महंगी दर पर यूरिया और डी.ए.पी. खरीद को बाध्य होना पड़ता था। किसानों के दर्द को समझते हुए मुख्य मंत्रीजी ने तीन लाख मीट्रिक टन यूरिया, 20 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. खाद के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान जो किया है, किसानों के लिये बड़ी राहत का विषय है।

डिजिटल इंडिया के माननीय प्रधान मंत्रीजी के सपने को साकार करने की मंशा से मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में ई-मंडी की स्थापना सराहनीय कदम है। किसान अपने खेत, खलिहान और घर में बैठे-बैठे ही आनलाइन अपने कृषि उत्पादन को बेच सकेगा। कृषि विपणन क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता के साथ गुणवत्ता पर भी हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने विशेष ध्यान दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में फ्लोराइड व अन्य प्रकार के जल प्रदूषण को देखते हुए

(श्री जगसी राम)

आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही आवश्यक समझकर यह प्रावधान किया है। सिरोही जिले के लिये 213 करोड़ रुपये की योजना से बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर पेयजल सप्लाई की घोषणा की है। सिरोही जिले की जनता की ओर से, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनन्दन करना चाहूंगा। राज्य में बंद पड़ी पेयजल योजनाओं के लिये 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 13 लम्बित पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिये 831 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में 40 करोड़ की लागत से 4 हजार नये हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान किया गया है। विस्तारित जयपुर हेतु बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में कार्य के लिये 1945 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गयी है। पेयजल पीड़ित लगभग प्रत्येक जिले को राहत दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने बिजली कम्पनियों को घाटे में धकेल दिया था। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की सूझबूझ एवं बिग विजन से तीनों डिस्काम में बिजली की छीजत और लागत कमी से घाटे से भी थोड़ा-बहुत बाहर निकले हैं। दूसरी ओर किसानों एवं हर एक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यकतानुसार सुचारू विद्युत सप्लाई दी जा रही है। आवश्यकतानुसार 220 के.वी. के 6, 132 के.वी. के 16 ग्रिड सब-स्टेशन, 33 के.वी. के 200 नये सब-स्टेशन का प्रावधान सराहनीय है। ऊर्जा विभाग के 80530 करोड़ के कम्पनियों के कर्जभार को हमारी साहसी मुख्य मंत्रीजी ने अपने ऊपर लेकर 40 हजार करोड़ का घाटा 2015-16 में एवं 20 हजार करोड़ का घाटा 2016-17 में टेक-ओवर करने का बहादुरीपूर्ण कदम उठाया है। विद्युत महकमे को घाटे में धकेलने वाली कांग्रेस सरकार ने घाटे को टेक-ओवर करने की हिम्मत कभी नहीं दिखायी। ऊर्जा के क्षेत्र में जनजाति, उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिये बहुत अनूठा कदम उठाते हुए किसानों को आन डिमाण्ड कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान जो किया है, बहुत सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के लिये साइकिल और स्कूटी वितरण का जो प्रावधान रखा है, इससे ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। इससे छात्राएं पढ़कर अपने प्रदेश के लिये कुछ कर पाएंगी। मुख्य मंत्रीजी ने विवेकानन्द माडल विद्यालय खोले हैं, प्रदेश में इसका काफी अच्छा रेस्पांस मिल रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री जगसी राम)

देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अन्दर यह बहुत सराहनीय कदम उठाया है। अनुसूचित जनजाति के लिये नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना में वाहन पर जो टैक्स में छूट दी गयी है, यह प्रदेश की अनुसूचित जाति के लिये बहुत सराहनीय है।

चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी ने गरीब तबके के लोगों के लिये कदम उठाये हैं। हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने आबू रोड के अन्दर कुछ ही दिनों पहले 3 करोड़ की लागत से नये हास्पिटल का शिलान्यास किया है। आने वाले समय के अन्दर हमारे क्षेत्र की जनता आपका आभार व्यक्त करेगी। इस सुविधा से वहां लाभ मिलेगा। यही नहीं, बी.पी.एल. परिवार की महिला को भामाशाह योजना में सम्मिलित किया है और उनके बैंक खातों में दो हजार रुपये किश्तों में हस्तांतरित करेंगे। भामाशाह योजना से जोड़ते हुए प्रदेश के किसानों को फसल ऋण से सम्बन्धित ब्याज, अनुदान, फसल बीमा एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की राशि शीघ्र पारदर्शिता से प्रदान की है, इससे प्रदेश का किसान उन्नति की ओर बढ़ेगा और खुशहाली मनाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रदेश में लागू है। हमारा सिरोही जिला डार्क जोन घोषित किया है और आए दिन वहां पर पानी नहीं मिलने से खेती आधी-अधूरी रह जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में गुजरात से सटता हुआ जो एरिया है, वहां पर टमाटर और मूंगफली की बहुत अच्छी खेती हो रही थी। पानी कम होने की वजह से अभी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना जो लागू की है, एम.आई. टैंक के माध्यम से, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर हमारे सिरोही जिले का सारा किसान खुशहाली मनाएगा। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 11 जगह एम.आई. टैंक बांधे जा रहे हैं, 70 परसेंट पूर्ण हो चुके हैं। यह बहुत सराहनीय कदम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उठाया है। वर्तमान में यह जो श्रमदान वाली योजना जो लागू की है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह पर अपने स्तर पर लोगों ने जे.सी.बी., ट्रैक्टर और खुद की मेहनत से तालाब और नाड़ी खुदाई के कार्य किये हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर इससे काफी फायदा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जो मुख्य मांगें हैं, मैं हमारी

(श्री जगसी राम)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा। रेवदर मुख्यालय से आबू रोड और सिरोही का लगभग 80 किलोमीटर का दायरा है, लम्बे समय से उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के लिए मुख्य मंत्रीजी से मांग की है, रेवदर उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि रेवदर की जनता को राहत देने के लिए उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय और रेवदर-मंडर बाई पास निकाला जाए तो क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहेगी।

यह 8 तारीख वाला बजट पूरे प्रदेश के कोने-कोने को छू कर हर वर्ग को देखते हुए बहुत सराहनीय है। मैं इस बजट की भूरि-भूरि तारीफ करना चाहता हूं। मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने राजस्थान का जो वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया है, यह बजट राजस्थान की हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छत्तीसों जात की आम जनता का बजट है। इसमें गरीब लोगों के उत्थान की जो योजना बनायी गयी है, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

रामदेवरा के पैदल श्रद्धालुओं के लिए जोधपुर से रामदेवरा तक सड़क की योजना है, उस सड़क के चौड़ाइकरण करने का काम किया है, उसमें 14 करोड़ 64 लाख रुपये और भरतपुर के गोवर्धन व ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग पक्का करने के लिए 103 करोड़ 94 लाख रुपये का बजट दिया है, इसकी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। पैदल यात्रा करना बड़ा कठिन है। भगवान का भक्त ही इस कठिनाई को पहचान सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धरती पर जब-जब भी पापों का वज़न बढ़ा है, तब श्रीकृष्ण भगवान जैसे अवतारियों ने अवतार लिया है। इसी प्रकार राजस्थान की धरती पर पापों का जब भार बढ़ा है, राजस्थान की देवी मां के रूप में माता वसुन्धराजी ने अवतार लिया है। इसी प्रकार...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वाह-वाह। शंकर सिंहजी, आप वैल में मत आना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): और बजाओ, बजाओ ताली।

(श्री शंकर सिंह)

इसी प्रकार भारत देश में भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने अवतार लिया है। पहले के प्रधान मंत्री की तुलना हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी से आप करेंगे तो पहले आपके प्रधान मंत्रीजी जब भी कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो उनके सलाहकार उनको सलाह देते थे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हो तो काश्तकारों की बातों को थोड़ा ज्यादा उठाना। काश्तकारों को उन्होंने देख लिया, यह बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद काश्तकारों को वह पूछते कि आप यह हरी मिर्च क्यों बोते हो। आपको अगर उत्थान करना है तो लाल मिर्च क्यों नहीं बोते हो। यह बहुत महंगी जाती है। ऐसी-ऐसी सलाह प्रधान मंत्रीजी को देते थे। लेकिन अभी के प्रधान मंत्री में और उनके अन्दर रात-दिन का अंतर है क्योंकि उन्होंने काश्तकार को नजदीक से नहीं देखा और वर्तमान प्रधान मंत्रीजी ने बहुत नजदीक से देखा है।

इन्होंने सबसे पहले गरीब के प्रति सोचा। जिन्होंने कभी बीमा नहीं करवाया, जिस गरीब ने कभी बैंक में खाता नहीं खुलवाया, उसकी तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। केन्द्र और राजस्थान की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब और किसान का उत्थान करने का प्रयास किया है। चाहे भामाशाह योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना हो, काश्तकार की फसलों के 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत खराबे पर भी मुआवजा देने की जो योजना है, यह भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धराजी के कार्यकाल में बनी है।

किसानों के हितैषी बनने वाले हमारे विपक्ष के बंधु कह रहे थे कि हम भी किसानों के हितैषी हैं। आपने कभी किसानों के ऊपर अगर सोचा भी होता तो आज यह दशा नहीं होती। आज भामाशाह पशु बीमा योजना, मुख्य मंत्री जन आवास योजना कि हर गरीब को मकान मिले, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना और ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों और 27 गांवों में 847.46 लाख का बजट अलग-अलग विभागों में देकर आम जन के सहयोग से भामाशाहों के द्वारा कार्य करवाये जा रहे हैं। काफी काम उसके अन्दर पूरे हो चुके हैं, अभी भी कार्य चालू हैं। इस योजना के लिए हम जितनी भी तारीफ करें माननीय मुख्य मंत्री महोदया की, वह कम है।

श्रमिक कार्ड योजना गरीब के लिए बनायी गयी है। मजदूर मजदूरी करने जाता है, उसकी अकस्मात् मृत्यु होने पर राजस्थान सरकार ने 10 लाख

(श्री शंकर सिंह)

रुपये बीमा के रूप में क्लेम देने की योजना बनायी है। कार्डधारी श्रमिक की लड़की की शादी के लिए भी 55 हजार रुपये की जो योजना बनायी है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, यह मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे की देन है। विपक्ष में बैठने वाले बंधु कान खोलकर सुनें कि वसुन्धराजी ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, योजना बनायी है। गरीबी कैसे बढ़े, सिर्फ वह काम आप लोगों ने किया है। गरीब कभी बीमार होने पर भी अपना इलाज नहीं करा पाता था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि गरीब को इलाज कराने के लिये तीन लाख रुपये तक की भामाशाह योजना बनी है और इलाज हो रहा है। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ में सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गरीबों के बच्चों के लिए 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया। उसमें उनको पढ़ाई करने का जो अवसर मिल रहा है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। शिक्षा के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक टीचर तो स्कूलों में बहुत कम ही थे संख्या में। मैं सदन में पिछले कार्यकाल में भी था, उस समय शिक्षा की इतनी बुरी दशा हो रही थी कि गरीब का बच्चा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक तो सरकार की मेहरबानी से पढ़ जाएगा, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा देने के लिये कौन जाएंगे, इसकी चिन्ता उनको नहीं थी। अभी हमारी सरकार आने के बाद, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सबसे पहले उस योजना को बदला जो पहली कक्षा से आठवीं तक अनिवार्य पास करने की योजना थी। सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जो वादा किया था, उसी के अनुरूप आज हर गरीब का बच्चा मेहनत करने का काम भी सीख गया है और उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए उनको चिन्ता होने लगी है।

राजस्थान के इतिहास में शिक्षा के अन्दर जितनी पदोन्नतियां हुईं, ये पदोन्नतियां हमारी सरकार ने की हैं। साथ ही पांच हजार स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम किया है, यह बहुत सराहनीय कदम है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में सब जगह खुल गये हैं, लेकिन ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो ग्राम पंचायतें ऐसी बची हुई हैं जो कहीं न कहीं भूलवश रह गयी हैं। उनमें भी खोलने की निश्चित तौर पर आप कृपा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। राजकीय माध्यमिक

(श्री शंकर सिंह)

विद्यालय ब्यावर खास को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दधालिया को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये और राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोडमाल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनाकर, राजियावास को भी क्रमोन्नत करने के लिये हम आपसे निवेदन करते हैं।

विकास के लिये शुभलक्ष्मी योजना, माडल विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द विद्यालय, शारदे बालिका छात्रावास, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का जो हमारी सरकार ने काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों के लिये मेरा निवेदन है कि काश्तकारों का सिर्फ नाम लेकर ये गलती से सरकार के अन्दर आकर बैठ गये थे। अब सारे काश्तकार लोगों ने समझ लिया है कि हमें झूठ-मूठ का पेट भरने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इनसे दूरी बना ली, इसलिये यहां पर भी दूरी से ही बैठे हैं। मेरा इस सम्बन्ध में एक निवेदन है, माननीय कृषि मंत्री महोदय विराजमान हैं। खेत में किस प्रकार से मेहनत करके काश्तकार फसल को पैदा करता है, उस मेहनत को वह काश्तकार ही पहचान पाता है। लेकिन पकी-पकाई फसल कभी रोजड़े खराब कर देते हैं। इससे भी ज्यादा नुकसान काश्तकारों को अंग्रेजी बबूल के द्वारा हो रहा है। अंग्रेजी बबूल जहां है उसकी छाया में, माननीय मंत्री महोदय, कोई फसल तो पैदा होना बहुत दूर, उसके अन्दर घास भी पैदा नहीं होती है। यह काश्तकारों की एक बहुत बड़ी समस्या है। फसल को इंजन चलाकर बिजली खर्च करके पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन यह अंग्रेजी बबूल, इसको तो पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। 200 फीट नीचे से भी जड़ों के द्वारा कुएं में से पानी सोखकर, बिना इंजन और बिना लाइट के ये पानी पी लेते हैं। काश्तकारों के ऊपर यह जो एक बहुत बड़ा संकट है, कोई योजना बनाकर, चाहे नरेगा के अन्दर बनाएं, या और कोई योजना के तहत, अनिवार्य करते हुए काश्तकारों को इस समस्या से निजात दिलाने की आप कृपा करेंगे। मेरा तो इसमें सुझाव है कि किसी निश्चित योजना का पैसा लगाकर अंग्रेजी बबूल रहित राजस्थान बनाने के लिये आप कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसा आप कर सकते हैं क्या, कृषि मंत्री महोदय?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हमारा सरकार से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वैसे तो सदन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेजी बबूल उगाने के लिए तो यहां से एक्ट पास किया हुआ है

(श्री उपाध्यक्ष)

कि अंग्रेजी बबूल की जो खेती करेगा, उस पर तो सीलिंग का एक्ट भी लागू नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह भी स्मरण होगा कि एक्ट पास करने वाले अब उधर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसीलिये मैंने आपको यह याद दिलाया है कि आप वह साल और सम्वत् भी बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 के अन्दर पास हुआ था और उसके साथ पत्ती तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माने वाला मामला भी पास हुआ था और वह जन-जन में चर्चा का विषय रहा।

श्री रमेश (सपोटरा): फिलहाल तो जिले...(व्यवधान) चाहिए, यह तो बाद में मांग लेना।

श्री उपाध्यक्ष: फिलहाल तो हम अंग्रेजी बबूल में अटके हुए हैं, आप कहां जिले तक ले गये उनको?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बिलकुल धीरे-धीरे सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सारी बात आएगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि गौ-माता पिछली सरकार में तो बहुत ज्यादा दु:खी थी, आपने बहुत अच्छा कार्य मंत्री बनने के बाद में संभाला है। मेरी इस सम्बन्ध में एक छोटी-सी गुजारिश है, विधायक कोष के अन्दर भी ऐसी कोई योजना बनाएं कि गायों को गौशाला में चारा डालने के लिये उसका बजट अलाट किया जा सके। निश्चित तौर पर यह एक धर्म का काम है।

स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि अमृत कौर अस्पताल, ब्यावर के अन्दर चार जिलों के मरीज हमेशा इलाज कराने के लिये आपको भर्ती मिलेंगे। कभी भी, एनी टाइम आप चैक करोगे तो वहां आपको मिलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि स्टाफ की कमी रहती है, एक मेडिकल कालेज ब्यावर में अगर और देने की कृपा करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा और गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सड़क के मामले में हमारी सरकार ने 250 से 499 की आबादी तक को सड़कों से जोड़ने का जो कार्य किया है, उसमें 2071 किलोमीटर लम्बी

(श्री शंकर सिंह)

सड़कों से 934 गांवों को जोड़ा जा चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन साल से चरणबद्ध रूप से एक किलोमीटर गौरव पथ बनाने का काम माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्री युनूस खान के द्वारा किया गया है। ब्यावर क्षेत्र में जो गौरव पथ बनाये गये हैं, उनकी गुणवत्ता विभाग द्वारा जांच के अन्दर पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी आंकी गयी है। उन बनाने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि गांव वालों को भी ऐसी सड़कें मिली हैं। मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत ब्यावर शहर के लिए अजमेर रोड बाई पास से पाली रोड बाई पास और चांगेड़ से उदयपुर रोड बाई पास तक सिक्स लेन रोड के लिए बजट की मेरी मांग है, निश्चित ही उसमें भी सुधार करेंगे। जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर तक तीन मीटर से सात मीटर तक चौड़ाई करने का जो कार्य है, वह भी नितान्त आवश्यक है। कोटड़ा से देवाता चौराहा अपूर्ण सड़क को भी तीन मीटर से सात मीटर चौड़ा करने के काम को आप निश्चित स्वीकृत करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

अब आप समाप्त करें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पांच मिनट में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। थोड़ी ठंडी नजर रहे आपकी, बस इतना ही आपसे आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीस मिनट तो बोल चुके हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): खाद्य सामग्री के मामले में मेरा निवेदन है कि वर्ष 2012 में जब राजस्थान में और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस गांधीवादी सरकार ने पूरे प्रदेश में राशन कार्ड बनाने की योजना बनायी। राशन कार्ड बनाने को राजस्थान में कोई ईमानदार आदमी नहीं मिला, उनको गुजरात में जाकर अहमदाबाद में एक ईमानदार आदमी मिला। उसको 200 करोड़ में पूरे राजस्थान के राशन कार्ड बनाने का ठेका दिया गया था।

एक माननीय सदस्य: बहुत ईमानदार था वो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बहुत ईमानदार था जिसने बाप की उम्र 18 साल और बेटे की उम्र 60 साल कर दी, सासू की उम्र 20 साल और बहू की उम्र 60 साल कर दी। ऐसे पूरे प्रदेश में है...(व्यवधान) आप गुस्सा मत करो, आपकी तरफ में भी शायद ऐसा हुआ होगा। आप बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं बोल देता हूं।

ऐसे फर्जीवाड़ा से वोट लेने के लिए कई राशन कार्ड फर्जी बना दिये जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने उसमें सुधार करने के लिए पी.ओ.एस. मशीन के द्वारा राशन वितरण व्यवस्था का कदम उठाया है जो स्वागत योग्य है। इससे फर्जी राशन कार्ड से भी मुक्ति मिलेगी और सही व्यक्ति तक राशन पहुंच पाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पी.ओ.एस. मशीन के द्वारा तकनीकी कारणों से राशन वितरण व्यवस्था में बहुत बड़ा व्यवधान हो रहा है। लोगों को समय पर राशन नहीं मिलने के कारण विपक्षियों द्वारा सरकार पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस नाम पर ब्यावर में कांग्रेस के लोगों द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए एक दस दिन का धरना लगाया गया। सरकार के द्वारा पूरा राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पी.ओ.एस. मशीन के द्वारा फ्रिंगर प्रिंट नहीं मिलने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें सुधार करने के लिए जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा राशन डीलरों को पाबंद किया जाए। व्यक्ति को पहचानने के बाद में उसको राशन मिल जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आपसे निवेदन है।

समय का अभाव है। विद्युत व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। सुराज संकल्प यात्रा में वादे किये गये थे कि हमारी सरकार के टाइम में हम 24 घंटे सिंगल फेस की बिजली देंगे, वो आज सब जगह पर मिल रही है।

जलदाय विभाग की जितनी तारीफ की जाए, कम है। हमारे ब्यावर

(श्री शंकर सिंह)

क्षेत्र की जनता को पीने के पानी के लिए बड़ी भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा था, खारा पानी पीते-पीते काफी वर्ष हो गये थे। 199 गांवों को बीसलपुर का मीठा पानी पिलाने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी और जलदाय विभाग की मंत्री महोदया को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ढाई सौ करोड़ की योजना को पास किया। ब्यावर क्षेत्र के गांवों को पानी पिलाने के लिए योजना बनायी और कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कल तो लड़ाई कर रहे थे आप मंत्री महोदय से।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं लड़ाई इस बात के लिए लड़ रहा था, माननीय सदस्य, कि वहां के ठेकेदार और अधिकारियों ने लापरवाही करते हुए उस काम को छह महीने से बंद कर रखा है। कभी कह रहे हैं कि हमारे पास में बजट नहीं पहुंचा, कभी और कोई दूसरी बात बता रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि उनको पाबंद कर उनकी समय सीमा तय की जाए। यह कितने वर्ष की योजना है, उसके अन्दर जल्दी कार्य पूरा करवाने के लिए उनको पाबंद किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

पंचायत समिति जवाजा के लिए देवाता फीडर की योजना आदरणीय जलदाय मंत्री महोदय रामप्रतापजी ने बनाकर जो कार्य चालू करवाया है, माननीय जलदाय मंत्रीजी का बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसमें छोटी-छोटी योजनाएं जो एक-एक करोड़, दो-दो करोड़ की भी नहीं हैं, माननीय जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि उन दो-दो करोड़ की योजनाओं की भी स्वीकृति जारी करावें ताकि अधूरा काम पूरा हो सके और उस क्षेत्र के अन्दर खुशहाली आ सके।

एक माननीय सदस्य: जल संसाधन हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जल संसाधन मंत्री महोदय, यही बोला न मैं।

पिछली गांधीवादी सरकार की उपलब्धियां बताऊं उससे पहले मैं अपनी बात और कह दूं। ब्यावर शहर में एक मेडिकल कालेज, ब्यावर में कन्या महाविद्यालय, टाडगढ़ उपखण्ड में बड़ा खेड़ा में महाविद्यालय और जवाजा को तहसील के साथ सारोट फीडर, चूलियादे फीडर, सुरेगा का फीडर इन तीन के लिए छोटा-छोटा बजट है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको आप पूरा करवाएं।

(श्री शंकर सिंह)

सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर किये हुए वादे हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सारे पूरे किये हैं। एक छोटा-सा और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ब्यावर को जिला बनाने का कार्य निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि इसी कार्यकाल में पूरा होगा।

पिछली गांधीवादी सरकार की उपलब्धियां मैं गिनाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, अपराधियों ने तो अपराध किया ही है लेकिन तत्कालीन सरकार के हमारे मंत्री भी पीछे नहीं रहे जो आज भी जेल में हैं, जिनकी आज तक जमानत नहीं हुई है।

हमारी केन्द्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई आरोप नहीं लगा पाये। हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो या और किसी प्रकार का आरोप हो, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा पाये।

हमारी सरकार की जितनी तारीफ की जाए, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान की सरकार का जो बजट पेश किया है, छत्तीस जात को साथ में लेकर, आओ साथ चलें, उस नारे को चरितार्थ करते हुए जो उन्होंने बजट पेश किया है उसकी मैं बहुत-बहुत तारीफ करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

जिस दिन बजट पेश हो रहा था तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं। सदन में लगे हुए बोर्ड को भी पढ़कर उच्चारण किया गया था तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा बजट पेश होगा क्योंकि दो तो मुख्य सचेतक और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री और मंत्रीजी, ये तो नहीं लेकिन सदन के बाकी सारे विधायक यह देख रहे थे। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हम याचक बनकर और जनता को दाता मानकर बजट पेश करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे बजट पढ़ा गया, सारे माननीय सदस्य महोदय निराश-से दिख रहे थे। बजट पेश होने के बाद ऐसा लगा कि दाता ने बजट पेश किया और राजस्थान की जनता याचक बन गयी।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सबसे पहले हर बात पर जिक्र आता है रिसर्जेंट राजस्थान का, लेकिन जब बजट को पढ़ा गया, सारी चीजों की घोषणाएं पढ़ी गयीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि यह पिछड़जेंट राजस्थान बना दिया गया है। जो घोषणाएं की गयीं, वो या तो पूर्ववर्ती सरकार की घोषणाओं के परिवर्तित नाम थे। अभी हाल ही में 'शुभ लक्ष्मी योजना' का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' कर दिया जिसका बहुत ढिंढ़ोरा पीट रहे हैं। 'निर्मल भारत' जो हमारी योजना थी, उसको 'स्वच्छ भारत' में परिवर्तित कर दिया, वो उसी का पर्यायवाची है। जो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाएं थीं, चाहे विधवा पेंशन की योजना हो, पालनहार योजना हो, बुजुर्गों की हो, जितनी भी योजनाएं बनायी गयीं उनका इम्प्लीमेंट कर लें वो ही बहुत है।

बात की गयी, कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। लेकिन जिस समय बजट का उच्चारण हो रहा था तो महिलाओं के लिए या महिला सुरक्षा का कहीं पर जिक्र नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर बार-बार चर्चा आ रही थी कि इस तरह से घाटा हुआ, इस तरह से घाटा हुआ। लेकिन राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित करने के कानून के विपरीत यह 9.99 प्रतिशत पहुंचेगा। डिस्काम का घाटा पूरा करने को उदय, उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना, कच्चे तेल के कारण राजस्व में कमी से घटते राजस्व इश्यु का जिक्र, जनता से जुड़ी हुई योजनाओं पर कंजूसी दिखायी। सभी वर्गों का जिक्र तो किया, लेकिन सुप्रबंधन का जिक्र नहीं हुआ, कुप्रबंधन का जिक्र हुआ।

हमारे माननीय अलवर से आने वाले विधायक बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे। कह रहे थे, हम 9-9 हैं, 9 शकुंतलाजी। मैंने कहा, 9 काम तो ले लेते आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जोर से बोलो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 9 विधायक होने के नाते 9 काम तो ले लेते आप। उसके अन्दर जो घोषणाएं हैं अलवर की- बम्बोरा की की गयी, नीमराणा की, भिवाड़ी में जिसका उद्‌घाटन मुख्य मंत्रीजी पहले ही कर चुकी हैं, उसका इसके अन्दर जिक्र किया गया है। राजगढ़ में सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, वह भी पहले से चल रहा है। आरओबी का है, जो सेन्टर गवर्नमेंट की योजना थी, वह पहले ही घोषणा हो चुकी थी। गोविन्दगढ़ में तो सब्जैक्ट मांग रहे थे लेकिन बिल्डिंग दे दी।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

देवस्थान का सब जगह का जिक्र किया। विधायक महोदय देख रहे थे। जिस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया महाराजा भर्तृहरि जी के नाम से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देवता का नहीं किया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन सदन में हमारे विधायक महोदय ने खूब रखा तो जिसके नाम से यूनिवर्सिटी बदली महाराजा भर्तृहरि, उनका कहीं जिक्र तक नहीं किया गया बजट के अन्दर। ऐसी-ऐसी जगहें हैं, धाम हैं- पांडुपोल है, तालवृक्ष है जहां दो धाराएं गर्म और ठंडे पानी की निकलती हैं, ऐसी प्राकृतिक चीजों का, देवस्थानों का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया।

क्या दिया गया, वह व्यथा मैं सुन रही हूं। जितने भी विधायक महोदय बोल रहे थे, बहुत जोर से बोले। किसी का भी जिक्र किया कि यह योजना चलायी, वह योजना चलायी। लेकिन लास्ट में आकर, लेकिन, परन्तु, प्लीज, हमारे ये काम कर देना। हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। यह कैसी विडम्बना है। यह सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? याचक ही हो क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले सभी ने रखी है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक-आधा छूट गया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक-आधा नहीं छूटा है। इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप मजबूती से गिना सको। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको ठोस तरीके से आप कह सको। माननीय सदस्य, अभी तो हाथ जोड़कर कह रहे थे, विनती कर रहे थे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी 500 करोड़ का काम चल रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अगर सरकार में आपकी हिस्सेदारी होती तो कोई काम तो गिना देते आप अपना। आत्मा से यह मत पूछो कि क्या दिया। सब कह रहे थे कि आपको धन्यवाद देना चाहिए। बिलकुल हम धन्यवाद देते, महंगाई को दूर करने की बात करते, कुपोषण को दूर करने की बात करते। गरीबी कैसे दूर हो? भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? किसान का बिल कैसे कम होगा? गांव तक शिक्षा कैसे पहुंचेगी? अतिवृष्टि का जो पिछला मुआवजा था, वह तक नहीं मिला है। आप अपने-अपने क्षेत्र की उठाकर देख लेना, कितनी पंचायतें और कितने गांव बच गये हैं आपके। (व्यवधान) आप बैठ जाइये, आप क्या गिनाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बानसूर की लिस्ट दे दो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बानसूर की लिस्ट दे दीजिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको मिल गया होगा।...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी सीट से बोलें। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गिरुडी को नहीं मिला, लेखड़ी को नहीं मिला, चतरपुरा को नहीं मिला, ज्ञानपुरा को नहीं मिला। कितने गिनाना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सदस्य, आप टेबल करिये अपनी लिस्ट को। आप सदन में असत्य बोल रही हैं...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने टेबल भी किया है...(व्यवधान) और सुनो, रामहेतजी, कलक्टर को भी दिया है मिलकर। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी सफाई पेश कर रहे हैं। पैरवी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): टेबल करिये, अगर आपके पास सूची है तो। (व्यवधान) नहीं, आप टेबल करिये न, कौनसी सूची है जिसको मुआवजा नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): टेबल तो किया है। टेबल किया है, रामहेत जी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): उपाध्यक्ष महोदय, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको मुआवजा नहीं मिला हो। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कलक्टर को ज्ञापन दिया है। एसडीएम को ज्ञापन दिया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको मुआवजा नहीं मिला हो। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लिस्ट आप चैलेंज करो यहां पर, मैं लाकर दूं। अगर आप दिलाओ तो पेश करूं, असत्य क्यों पेश करूं? (व्यवधान) मुझे आपको सच्चाई बताने के लिए कोई पैरवी नहीं करवानी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर दिलवाएं तो मैं यहां लिस्ट पेश करूं। अगर दिलवाएं सदन के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपने एक बात कही है यहां सदन में कि एक भी विधायक बता दे कि ओलावृष्टि का पैसा बाकी है ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सदन के माध्यम से अगर आप, मुआवजा दिलवाएं तो मैं कल की तारीख में लिस्ट पेश कर सकती हूं... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इतना मुआवजा आज तक किसी ने नहीं दिया। सरकार ने जो पैसा दिया ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यहां असत्य पैरवी कर रहे हो ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): असत्य पैरवी नहीं है ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जाकर पूछ लो आपके मुण्डावर में।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साढ़े 8 करोड़ रुपया मेरे विधान सभा में मिला है ...(व्यवधान) बानसूर में पूछो। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, इतने गांव शेष रह गये जिसमें मेरे साथ एसडीएम गयीं, तहसीलदार मेरे साथ में गयीं। जो खुद-खुद के थे ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साढ़े 8 करोड़ मुण्डावर के अन्दर मुआवजा दिया है ...(व्यवधान) असत्य बात कहलवा रहे हो वहां बैठे-बैठे। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पटवारी ने मनमर्जी से आधे लोगों को, कुछ लोगों को, थोड़ा-थोड़ा मुआवजा देकर बाकी सारे छोड़ दिये। उस आदमी से जाकर पूछो जिसका बिजली का कनेक्शन कट गया। जो फीस नहीं भर सका। जिसके पास घर का खर्चा चलाने को पैसा नहीं है, उससे पूछो। आप क्या जानो। आपके उप सचेतक महोदय कह रहे थे कि मुआवजा मैंने लिया है। उप सचेतक महोदय, कालूलालजी गुर्जर कह रहे थे, मिनिट्स के अन्दर दर्ज है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपने अभी क्या बोला?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नहीं चला रहे हो व्यवस्था। आप बैठ जाओ, आपका काम नहीं है ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं उप मुख्य सचेतक ही। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, आप बंद करो इनको ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपको पता तो है नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसको पता नहीं है? किसको नहीं है पता?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने तो बोला ही नहीं है। मैं तो यहां बैठा हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मिनिट्स निकालो ...(व्यवधान) मिनिट्स निकालो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमें सब पता है। हमारी माननीय सदस्या बोल रही हैं, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इन्होंने मुझे पुकारा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं पुकारा। आपको कैसे पुकारेंगे। पुकारने वालों को ही पुकारा जाता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह देखो मिनिट्स के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुकारने वालों को ही पुकारा जाता है। इन राठौड़ साहब को पुकारा और आप जबरदस्ती ही खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मिनिट्स में देखो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो राठौड़ लगाते ही हो, राठौड़ तो यह हैं, देखो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप थोड़ा कान ठीक करा कर आओ ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बहुत अच्छा काम किया जिससे आपका एक विधायक जीता...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इन्होंने उप सचेतक कहा था ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने मुझे पुकारा है क्या? (व्यवधान) आपने मुझे पुकारा है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सदस्या, आपने राजस्थान के किसानों की लिस्ट उठाकर देखी है क्या, कितना मुआवजा इस वर्तमान सरकार ने दिया है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने पुकारा... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम चैलेंज के साथ आपको कहते हैं कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया होगा। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं भी चैलेंज के साथ कह रही हूं ...(व्यवधान) मैं भी चैलेंज से कह रही हूं कि अगर सदन मुआवजा दिलवाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन पांवों पर है। आप दोनों सचेतकों को क्या हो गया?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पुकारा था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैंने कहा मुख्य सचेतक, आपका नाम नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पुकारा। इन्होंने पुकारा और हम चले आए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किसने किसको क्यों पुकारा, यह सदन का विषय आज नहीं है। यह आप सदन के बाहर तय करना कि किसने, किसको, क्यों और किसलिए पुकारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: इतनी लम्बी सूची है, इस सूची की सूचना जनता तक पहुंच जाए, आसन भी प्रयत्न कर रहा है और सदन भी चाहता है। अब एक सदस्या अगर कोई बात अभिव्यक्त कर रही हैं तो सहनशक्ति आप भी दिखाइये। अगर कहीं वहां धीरज है तो धैर्य यहां भी है। बाकी लोगों को बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य: धीरज भाग गया है।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों तरफ से सक्षम सदस्य हैं जो अपनी बात कहकर उसको मंजिल तक पहुंचा देंगे। अब अगर किसी और की लाइट जली तो उसको बिलकुल बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक मिनट विराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कोई भी बात मुआवजे की जहां आयी है उस असत्य बात को यहां रिकार्ड करवाना, आज मुण्डावर के बारे में कोई भी एमएलए यह बता दे कि उसके क्षेत्र में मुआवजा बाकी हो, मैं यह कहता हूं चैलेंज के साथ में। मेरे क्षेत्र के बारे में यह कह देना? साढ़े आठ करोड़ रुपये मुआवजा पूरा उस क्षेत्र में बंटा है। पिछली सरकार से दुगना मुआवजा दिया। पिछली सरकार ने छह-छह महीने तक मुआवजा नहीं दिया था इस सरकार ने और मोदी जी ने सीधा किसान के खाते में पैसा भेजा है। नहीं तो पहले पटवारी के चक्कर काट-काटकर किसान मर जाता था। अपनी बात तो कहें, आपको कोई बानसूर में तकलीफ है, कहें। मुण्डावर के बारे में चैलेंज क्यों करें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात रिकार्ड पर आ गयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, एक बार तय कर लें कि सारे ही अलवर जिले वाले बोलना चाहते हैं तो फिर इनको एक-एक करके बुलवा दिया जाए। (व्यवधान) अब हो गया। जो बात सम्माननीय सदस्य ने कही है, उन सबसे सत्ता पक्ष तो सहमत है न? विपक्ष हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? सदस्य, आप शुरू करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र की बात कर रही हूं। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने यह कहा, मुख्य सचेतक महोदय, यह मिनिट्स में है, कि हमने मुआवजा लिया है, उन्होंने कहा है। तो यह पता नहीं क्यों, मैं यही सोच रही थी कि इतनी देर से कोई उठ क्यों नहीं रहा है। लेकिन ये रह नहीं सकते। मैं यही बोलने वाली थी कि उठो एक-एक करके, लेकिन काफी देर बाद उठे।

मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रही थी, बानसूर में जो मुआवजा दिया गया उसमें से मेरे गांव जो रह गये। आप अगर चैलेंज करते हैं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप परमीशन दें तो कल की तारीख में, बचे हुए गांवों की लिस्ट लाकर दे दूं। अगर ये दिला दें तो इनकी मेहरबानी मानेंगे- मैं सदन के माध्यम से इनको धन्यवाद दूंगी। जो पंचायतें मैंने गिनायी हैं, नीमूचाना की आधी रह गयी है, होलावास, घिरूड़ी, चतरपुरा, ज्ञानपुरा, रामपुर, हाजीपुर, और इधर चलें-सामोता, मुंडावरा, नारायणपुर। जो शेष बची हुई सूची है, हमने एसडीएम को दी है, कलक्टर को दी है, डेलीगेशन के रूप में भेजी गयी है और आप चैलेंज करते हैं तो मैं कल की तारीख में लिस्ट यहां लेकर आपको दे दूं अगर आप मुआवजा दिलवाने में सक्षम हों तो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप मुण्डावर की बात कर रहे हैं, बानसूर की करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): फिर आपके मुण्डावर की बात किसने की थी, आप उठे क्यों बीच में? (व्यवधान) आप बिना बात ही उठ जाते हैं बीच-बीच में? (व्यवधान) मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रही हूं। (व्यवधान) मैं मेरे बानसूर की बात कर रही हूं। (व्यवधान) आपको पता ही नहीं क्यों तकलीफ होती है? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बधाई देते। देखिये, सस्ता क्या-क्या सामान हुआ है। टीवी, बायोमास, माइक्रोफोन, फोटो कॉपियर, मार्बल के सामान, गाड़ियां, ये सारी चीजें। लेकिन 70-80 परसेंट गांव की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जिक्र होता कि रसोई का कोई सामान सस्ता किया होता। रसोई का कोई सामान सस्ता किया होता, प्याज सस्ती की हुई होती, दाल सस्ती की हुई होती, सब्जी की हुई होती, जिससे कि एक गांव में कच्चे घर में बैठे आदमी को बेनिफिट मिलता और वह दुआ देता। किसान की बिजली की दरें कम की होतीं तो हम धन्यवाद देते। गिनाओ तो सही हमें। केसीसी का लोन माफ किया होता, बिजली का बिल माफ किया होता। उस दिन कह रहे थे मुख्य सचेतक महोदय कि बिजली का माफ हुआ था। अतिवृष्टि के टाइम पर, मेरे बानसूर में तो माफ नहीं हुआ। मुझे तो लगता नहीं है बिजली का बिल माफ हुआ था कहीं। उस दिन खड़े होकर कह रहे थे कि हमारा बिल माफ हुआ है। बड़े शर्म की बात है, अगर आपने बिल माफ करवाया तो। जनता का बिल माफ नहीं हुआ।

इसमें जिक्र किया गया कि तनख्वाह बढ़ायी गयी आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनियों की। नाम मात्र के लिए। एक मजदूर भी ज्यादा कमा लाता है, इतनी महीने की वृद्धि की गयी है उनकी। उनको खुश करने के लिए सिर्फ दिखावा है। रोजगार के नाम पर प्रशिक्षण ले लो, आईटीआई खोल लो लेकिन काम नहीं मिलेगा। आपने क्या-क्या एमओयू साइन कर लिये? भिवाड़ी, टपूकड़ा, खुशकेड़ा में, नीमराना में बड़ी-बड़ी कम्पनियां लगाने के बड़े-बड़े वायदे कर लिये, यह कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, गिनती कर दी कि इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां का स्थानीय जो आदमी है, युवा लड़का है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा अन्याय है, यह कैसा एमओयू है, ये कैसी कम्पनियां हैं? उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब वह अपना बायोडेटा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लेकर वहां जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप स्थानीय हो, आपको यहां नौकरी नहीं दी जाएगी। युवाओं को फटकार कर वहां से भगा दिया जाता है। जिस कम्पनी के लिए कह रहे थे हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, अपने अधिकारों की मांग रखने का अधिकार है, वह अपनी मांग रख सकता है। होंडा कम्पनी में भी उन्होंने अपने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यूनियन का एक कागज रखा, जिसके लिए उनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। उन्होंने बात ही नहीं रखी, उन्होंने मांग ही नहीं रखी उससे पहले ही मारपीट शुरू कर दी। यह कैसा अन्याय है गरीब युवाओं के साथ? जो बहरोड़ में जमीन वाला मैटर है उसमें देखिये। एक किसान के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक तरफ की जमीन तो जा रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपये में और दूसरी तरफ की जा रही है ग्यारह लाख रुपये में। यह कैसा अन्याय है। ऐसा किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी खेती की जमीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में....(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस थोड़ी देर और लूंगी। सारे इस तरह के ढिंढोरे घोषणाओं के ढिंढोरे पीट रहे हैं। मेरे लिए यह कह गया, हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदय कि आपने भामाशाह का बोला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान की, वह सिर्फ इनकी मुख्य मंत्री नहीं हैं, यह बार-बार बोलते हैं, उन्होंने यह कहा...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने समय निर्धारित किया था।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरा समय आपने ले लिया बहस के अन्दर।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनके माननीय सदस्य इस तरह से बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष कैसे बोलेंगे, साहब, फिर नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैंने जमीन का उठाया था, वह भामाशाह का नहीं था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वह आज भी है कि अपनी जमीन के लिए एक सैनिक की पत्नी कागज लेकर चक्कर लगा रही है। उसको जमीन स्वीकृत कर दी गयी थी, अलाट कर दी गयी थी। उसको फोरेस्ट में जमीन दे रहे हैं और उससे दस लाख का मुआवजा मांग रहे हैं कैसा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अन्याय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहती हूं, कहना चाहती हूं और दो वर्ष के अन्दर अधिकतर जगह 80 परसेंट को किसी को मिला हो तो मुझे ज्ञान नहीं लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में शौचालय का पैसा या बीपीएल आवास का पैसा दो वर्ष के अन्दर मिला है। कहीं नहीं है। कई जगह ऐसा कह दिया कि गांव में पूर्ण रूप से शौचालय बन चुके और वहां पर नहीं बना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीपीएल में जो नरेगा में काम कर रहे हैं उनको भी नहीं मिला है। ऐसे नाम काट दिये, खाद्य सुरक्षा में से गरीब लोगों के, उनको दुबारा से जुड़वाएं। पानी के लिए, आये दिन पानी की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जल स्वावलम्बन योजना के तहत जो एनीकट और बांध बनाये जा रहे हैं, जो पहले से बने हुए हैं उनकी फोटो खींच कर पेश की जा रही है, कई जगह ऐसा हुआ है। भू-जल में पानी की जो पाइप लाइन है उसकी और स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं जिससे दिक्कत होती है गांव वालों को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी ...(व्यवधान) असत्य नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) जो हमने कालेज का मुद्दा उठाया उस पर भी नहीं दिया था सर्व शिक्षा में। सर्व शिक्षा में कोई भी काम नहीं दिया। सर्व शिक्षा में दो वर्ष में किसी स्कूल में, किसी आफिस में काम नहीं किया है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रही हैं मैं असत्य नहीं सत्य बोल रही हूं। जबकि मैं तो मेरे चैम्बर में था और यह कह रही थीं बार-बार कि चीफ व्हिप ने, चीफ व्हिप ने किया, जबकि मैं तो यहां आया ही नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं की, मुझे समझ ही नहीं आया। इनको यह ही मालूम नहीं है कि चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप में क्या अंतर है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान) कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं किया है। बिजली के लिए घोषणाएं कर दीं, फाइल लगाकर चक्कर काट रहे हैं। किसानों की दो-दो लाख की वीसीआर काटी जा रही हैं। बिलों में अनियमितता हो रही है। बिल वितरित नहीं किये जा रहे हैं। (व्यवधान) पैनल्टी लगायी जा रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको बंद करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप गलत नहीं हो, आपका नाम नहीं लेना चाहिए था, इनसे गलती हुई है। आप तो सो रहे थे उस वक्त, आपका नाम लिया ही क्यों? (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो लाइन कहना चाहूंगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं सो रहा हूं चाहे जग रहा हूं लेकिन मेरा नाम बार-बार, मैं चैम्बर में बैठा हुआ देख रहा था, बार-बार माननीय सदस्या बोल रही थीं कि चीफ व्हिप ने यह किया, चीफ व्हिप ने यह किया। मैंने कहा, मैं तो यहां था ही नहीं, मेरा नाम कैसे आया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कनक्लूड करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): थोड़ी देर। ये कहना चाह रहे हैं बिलों में जो अनियमितता है, विद्युत मंत्री यहां हों तो गांव के आदमी को पैनल्टी लग जाती है, बिल देने नहीं आते हैं और मोटी पैनल्टी लगा देते हैं, वीसीआर भर देते हैं और चैक करने के बाद भी कई बार द्वेषता निकालते हैं। सड़क के नाम पर तो मेरी समझ में नहीं आता क्या कहें। स्वास्थ्य विभाग के बारे में बार-बार अवगत कराते हैं कि महिला चिकित्सक लगायी जाए। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। मंत्रीजी को मैं बार-बार अवगत कराती हूं। चाहे विद्यार्थी मित्र हों, कम्प्यूटर शिक्षक हों, जिनको रोजगार से हटाया गया बिलकुल गलत है। कानून-व्यवस्था में मेरे यहां रात-दिन हत्याएं हो रही हैं।

दो लाइन और कहूंगी, देवनारायण योजना में बानसूर में कोई काम नहीं हो रहा है जबकि उसके अन्दर पूरा लग रहा है, बानसूर और थानागाजी। (व्यवधान) इतनी जल्दी-जल्दी मचा दी। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग मेरा टाइम ले लेते हैं, यह मेरे साथ अन्याय है। एक उदाहरण देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आसन ने तो आपके साथ बहुत उदारता का बर्ताव किया है। आपकी पार्टी के पास तो शून्य समय था उसके उपरान्त भी आपको दे दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह एक उदाहरण है पूरे राजस्थान के लिए। तहसील में जनसुनवाई के लिए एक-एक प्रोफार्मा भरवाया गया था कि 5 समस्याओं का समाधान सरकार करेगी, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। दो लाइन इसलिए कहना चाहूंगी, जो बजट पेश हुआ उसका सार मेरे शब्दों में पेश करना चाहती हूं। ''तीन पहर रो तावड़ो, यानी तीसरे पहर रो तावड़ो जातो-जातो ही दिखे। तीन घंटा में पढ़ेड़ो बजट, मन्ने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रीतो ही रीतो दिखै। राजस्थान का युवा बेरोजगार, व्यापारी, किसान मन्ने दुःखी होता ही होता दिखै। राम-राम सा।''

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने वर्ष 2016-17 का अत्यन्त ही शानदार बजट पेश किया, इसके लिए मुख्य मंत्री जी को खूब-खूब बधाई और आभार देना चाहता हूं। यह बजट राजस्थान के इतिहास में हमेशा-हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

यह बजट राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता की आकांक्षाओं, आशाओं और भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। प्रस्तुत बजट में गांव के विकास से लेकर शहर के विकास की बात के साथ-साथ आमजन की बातों का भी ध्यान रखा गया है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। सरकार ने पिछले दो साल में कई जन-कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं। इसमें से मुख्य भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, मुख्यमंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा भण्डार जैसी कई योजनाओं को सरकार ने लागू किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया- न्याय आपके द्वार। राजस्थान में 30-30, 35-35 सालों तक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता था, इस कार्यक्रम के तहत पूरे राजस्थान के अन्दर 21 लाख 43 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, वित्तीय वर्ष 2008 में कुल भार 77138 करोड़ था जो मार्च, 2014 तक 33502 करोड़ बढ़कर 130640 करोड़ हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच आप देखिए। हमारे गांवों की मुख्य सड़क पानी के बहाव के कारण, नालियों के कारण बहुत टूटी हुई थी, इसके लिए गौरव पथ का निर्णय लिया। गौरव पथ के साथ-साथ नालियां बनेंगी, उस गौरव पथ पर सौर ऊर्जा लगेगी और उसी गौरव पथ के साइड में वृक्षारोपण होगा। गौरव पथ का मुख्य मंत्रीजी ने एक विजन देखा है। फर्स्ट फेज में 1984 ग्राम मुख्यालयों पर 1027 करोड़ की लागत से 1955 किलोमीटर गौरव पथ का

(श्री नारायण सिंह देवल)

निर्माण करा लिया गया है। दूसरे चरण में 608 करोड़ की लागत से 2182 किलोमीटर गौरव पथों का निर्माण होगा। मिसिंग लिंक में 1900 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा। नान-पैचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए 2500 किलोमीटर सड़कों पर 600 करोड़ रुपयों का व्यय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधान किया है, पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 21.90 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में 29 आरओबी और 2 आरयूबी की घोषणा की गयी है, इनके ऊपर 1098 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक आरओबी स्वीकृत हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से लगाकर 350 आबादी तक 1468 सड़कें बनेंगी। इसमें 1618 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है। इस योजना से जो राजस्थान का अंतिम तबके का गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति ने कभी बड़े हास्पिटल या बड़े निजी चिकित्सालय नहीं देखे होंगे, इस योजना के माध्यम से उनको निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लगभग एक करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें सारी कैशलैस सुविधा होगी। 30 हजार से लगाकर 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर इस भामाशाह बीमा योजना में दिया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 दिन तक के शिशुओं को नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जाती थी जिसका दायरा बढ़ाकर इस बजट में एक वर्ष तक कर दिया गया है।

ऊर्जा विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में किसान बिजली कब आएगी इसके लिए इंतजार करता था, परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज 6 से 7 घण्टे किसानों को एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी जाती है और घरों में 20 से 22 घण्टे बिजली दी जाती है। गत सरकार के आधारभूत संरचनाओं की उपेक्षा की, वित्तीय पुनर्गठन योजना, 2012 को ईमानदारी से लागू नहीं किया, कंपनियों के घाटे को उबारने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस कारण से 2008 से 2009 तक बिजली कंपनियों का जो घाटा 15 हजार करोड़ के लगभग था, पूर्ववर्ती सरकार के समय 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस तरह से 5

(श्री नारायण सिंह देवल)

वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये का बिजली पर घाटा बढ़ गया। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप 2014-15 में इन कंपनियों का घाटा 3172 करोड़ रुपया कम हुआ है। इस वर्ष भी 3500 करोड़ का घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली कंपनियों का ऋण 80530 करोड़ होने के कारण 8 हजार करोड़ का ब्याज भुगतना आज के समय में बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री ने उदय योजना के तहत अवशेष ऋण 80530 करोड़ का 75 परसेंट टेकओवर करने का निर्णय लेते हुए 40 हजार करोड़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में और 20 हजार करोड़ वित्तीय वर्ष 2016-17 में टेकओवर किया है। सरकार ने प्रथम दो वर्ष में उत्पादन क्षमता में 4283 मेगावाट की वृद्धि की है जबकि पूर्ववर्ती सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2293 मेगावाट की वृद्धि हुई थी। इससे प्रदेश विद्युत उत्पादन में आज के समय में आत्मनिर्भर हो गया है। पिछले दो साल में किसानों को 40-40 हजार कृषि कनेक्शन दिये गये हैं और इस बजट में भी किसानों को 40 हजार कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे। ऐसे गांव और ढाणी जहां बिजली नहीं है, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से इस बजट में 24 करोड़ 97 लाख रुपये से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 8 लाख ग्रामीण आबादी में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से भी विद्युतीकरण किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस समय तक किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला। 2014-15 में खरीफ फसल में हुए नुकसान के लिए किसानों को 605 करोड़ का लोन दिया गया था और 2015-16 में रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को 2471 करोड़ का बजट आबंटन किया गया। पूरे राजस्थान में 29 लाख 24 हजार किसानों को यह लोन दिया गया। मेरे जालौर जिले में भी इसके तहत 47 करोड़ रुपये के लगभग किसानों को यह मुआवजा दिया गया जो राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में किसान की फसल का अगर कोई नुकसान हुआ तो 50 प्रतिशत से अधिक खराब होने पर मुआवजा दिया जाता था, परन्तु आज केन्द्र में और राजस्थान में हमारी सरकार है तो इन नार्म्स में संशोधन कर 33 प्रतिशत अगर किसान की फसल का खराबा होता है तो मुआवजा दिया जाता है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

कृषि मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्ष 600 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये थे और इस बजट में 1 हजार नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे। 6 लाख 28 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार में हमेशा यूरिया और डीएपी की किल्लत रहती थी और कालाबाजारी हमेशा होती थी। अब 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी का स्टाक रहेगा जिससे किसानों को खाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए किसान अपनी फसल आनलाइन बेच सकता है, यह भी बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने गांवों का भी ध्यान इसमें रखा है। 15378 करोड़ रुपये से पंचायती राज और ग्रामीण विकास के कार्य होंगे।

इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की गयी हैं जिनमें मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास योजना, मुक्तिधाम विकास योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण सहित कई योजनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों में फायर ब्रिगेड के वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इस बजट में 23 हजार 177 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है जो 2015-16 के संशोधित अनुमान से 14.47 प्रतिशत अधिक है। केन्द्र स्तर की शिक्षा के लिए 61 नये स्वामी विवेकानन्द स्कूल के साथ-साथ 770 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना करने का भी प्रावधान रखा गया है। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 380 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 445 विद्यालयों में 180 करोड़ रुपये की लागत से 1667 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पढ़ रहे हो तो टेबल कर दो, सब माना जाएगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आप अपना काम करो न। आप नींद ले लो। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ठीक है न? आप कैसे बोलते हो वो भी मुझे ध्यान है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर ठीक है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 445 विद्यालयों में 180 करोड़ रुपये की लागत से कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, प्रयोगशाला और पेयजल की व्यवस्था और शौचालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आठवीं, दसवीं और बारहवीं में जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनको 80 करोड़ की लागत से लैपटाप का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा 85 करोड़ रुपये की लागत से बच्चियों को साइकिल वितरण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बच्चियों को स्कूल जाने के लिए ट्रांजिट कैम्प की भी व्यवस्था की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। वर्ष 2016-17 में 2 हजार हैबिटेशन, ढाणियों के लिए 18 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जनता जल योजना जो आपकी सरकार के समय में बन्द हो गयी थी, उस योजना को 100 करोड़ रुपये देकर पुनः चालू करने का सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। 40 करोड़ रुपये की लागत से 4 हजार हैण्डपम्प का इस बजट में प्रावधान किया गया है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में जो नर्मदा की योजना थी, उसके लिए 2007 में राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की थी, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल तक इन लोगों ने उसके ऊपर टाइम पास किया। इन दो सालों के अन्दर नर्मदा का पानी हमारे जालौर और आहोर में पहुंच चुका है।

इसी तरह से मुख्य मंत्रीजी ने जो मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत की है, यह योजना हमारे राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा वरदान साबित होगी क्योंकि राजस्थान के अन्दर मात्र 1.16 प्रतिशत सतही पानी है। इस पानी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र में सतारा और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर वर्षा का पानी कम बरसता है उसी को ध्यान में रखते हुए यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरूआत की है, आने वाले समय में इस काम से हमारा वाटर लेवल निश्चित तौर से ऊपर उठेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की आपके माध्यम से कुछ मांग करना चाहता हूं। मेरे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एससी व एसटी की जनसंख्या 29.30 प्रतिशत है। जालौर जिला साक्षरता में सबसे अंतिम पायदान पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज नहीं होने के कारण विद्यार्थी अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। उच्च शिक्षा के संसाधन नहीं होने से इस क्षेत्र

(श्री नारायण सिंह देवल)

में शिक्षा का स्तर दिनों-दिन कम हो रहा है। महिला साक्षरता में भी जालौर जिला अंतिम पायदान पर है। तो मैं आपके माध्यम से रानीवाड़ा में एक महाविद्यालय स्वीकृत करने की मांग करता हूं। अगर वो स्वीकृत होता है तो निश्चित तौर पर उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए भामाशाह तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारे जालौर जिले और रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़कें जर्जर हालत में विरासत में मिली हैं। और अभी सड़कों की स्थिति सुधर रही है। फिर भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में करीब 18 से 20 सड़कें जो करीब 80 किलोमीटर की हैं, वे बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन सड़कों का भी काम स्वीकृत किया जाए।

आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में सिंचाई विभाग के माध्यम से एनीकट और बांध बने हुए थे लेकिन अभी सिंचाई विभाग ने इनको पंचायती राज को हैण्डओवर कर दिया है। पंचायती राज विभाग के पास में कोई टैक्निकल टीम नहीं होने के कारण अतिवृष्टि में वे सारे बांध टूटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर कोई निर्णय करके हमारे यहां राजीकावास, बामनवाड़ा और पांचला में बांधों को स्वीकृत किया जाए।

इसके अलावा रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जसवंतपुरा सीएचसी है वहां पर अन्त:रोगी शय्या 30 से बढ़ाकर 50 करने की मैं मांग करता हूं।

अंत में रानीवाड़ा में एक एसटी व एससी छात्रावास की भी मैं मांग करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं:-

''है समय नदी की बाढ़, जिसमें सब कुछ बह जाया करता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं।''

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ तारीख को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया, वह महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए

(श्री अशोक डोगरा)

समर्पित बजट था। पूरे राजस्थान में चाहे तो अख़बार के माध्यम से, चाहे टेलीविजन के माध्यम से चाहे पब्लिक ने, हर वर्ग ने उसकी खूब सराहना की है और उसको बहुत अच्छा बताया है। दो साल का हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो कार्यकाल है, उसमें बहुत विकास हुआ है। कई काम तो ऐसे हुए हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं थी। हमारे लेबर मिनिस्टर टीटी साहब बैठे हैं इन्होंने एक योजना निकाली मजदूर के लिए। पहले मजदूर का रजिस्ट्रेशन कराने में ही जोर आता था। इन्होंने यह कर दिया कि जो कोई महिला या पुरुष नरेगा में 90 दिन काम कर लेगा, उसका पंचायत के सचिव स्तर पर, बीडीओ स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी या इर्रिगेशन या पीएचईडी में लेबर के रूप में तीन महीने ही काम कर लेगा, उसके एईएन को आथोराइज कर दिया कि वह उसका रजिस्ट्रेशन करे। मात्र 85 रुपये खर्च करके पाँच साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके फायदे कितने हैं। भगवान नहीं करे, किसी की दुर्घटना में मौत हो जाये तो 9.75 लाख रुपये। कांग्रेस वालों ने कभी ऐसी कल्पना ही नहीं की होगी। साधारण मृत्यु पर 3.25 लाख रुपये। वह विकलांग हो जाए तो 6.50 लाख रुपये। उसको खुद का मकान बनाना है तो 1.50 लाख रुपये सरकार की तरफ से। उसकी बच्ची मात्र 18 साल की हो जाती है, चाहे उसकी शादी हो, या नहीं हो और वह मजदूर सर्टिफिकेट पेश कर देता है कि मेरी बच्ची 18 साल की हो गयी तो उसके खाते में 55,000 रुपये चले जाते हैं। वह बच्चों को शिक्षा दिलाता है, छठी क्लास में उसका बच्चा या बच्ची आएगी तो उसको पैसे अलग मिलेंगे। इस तरह की योजनाएं राजस्थान सरकार ने बहुत सारी बनायीं। ''सबजन विकास, सब जन उत्थान'' की तर्ज पर इस बजट को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया।

रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से 3,21,295 एमओयू साइन हुए और उसके तीन महीने बाद भी 11,531 करोड़ के एमओयू साइन हुए। भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान। आरोग्य राजस्थान में मैं खुद गया हूं, हर गांव में, हर पंचायत में जाकर डाक्टर्स का कैम्प लगता है। उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो पीड़ित हैं, उनको सरकार के खर्चे पर आगे रैफर किया जाता है और उनका इलाज कराकर वापस घर छोड़ा जाता है। ऐसी बहुत सारी अनूठी योजनाएं सरकार ने लागू कीं।

राजस्व अदालतें लगीं, मैं खुद कई गांवों में गया, हर पंचायत मुख्यालय पर लगीं। लोगों के 20-20 साल के जो रेवेन्यू के मुकदमे चल रहे

(श्री अशोक डोगरा)

थे, ऐसे 21 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण हुआ। कौशल विकास, ई-गवर्नेस, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, जल संग्रहण विकास एवं सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिले।

ग्रामीण गौरव पथ की बहुत सारे लोग बात करते हैं। गांवों में 65-70 साल की आजादी के बाद भी कीचड़ जैसी हालत थी, बुरी हालत थी। माननीया हमारी मुख्य मंत्रीजी का यह सोच ग्रामीण गौरव पथ के बारे में आया और लोगों ने उसको सराहा। मुझे याद है, मैं मेरे एक गांव में गया वहां मुझे एक सरदार मिला। उसने कहा कि आजकल हमारे गांव में चण्डीगढ़ स्टाइल की सड़कें बन रही हैं। मैंने कहा, वाह। मतलब वह आदमी कितना प्रसन्न हुआ। आज एक किलोमीटर की सड़क नाली सहित बन रही है। उसमें प्रथम चरण में 1,984 पंचायत मुख्यालयों पर 1,027 करोड़ रुपये की लागत से 1,955 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें जून, 2016 तक पूरी हो जायेगी और 608 करोड़ रुपये की लागत से 2,182 किलोमीटर लम्बाई की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएंगा। दूसरे चरण में 2,000 और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक की सड़कें बनेंगी। इससे गांव में जो रहता है, उसकी इच्छा हो गयी कि मैं अब शहर जाकर नहीं बसूं, गांव में ही रहूं। इतनी बढ़िया सड़कें हैं। हर चीज की व्यवस्था हो रही है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी 250 से 300-350 की आबादी की 1,468 बसावटों को 1,618 करोड़ 64 लाख रुपयों की लागत से 4,303 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी की भगवान में बहुत आस्था है, धार्मिक हैं। इस वजह से उन्होंने जो गोवर्द्धन की यात्रा पर जाते हैं, भरतपुर में गोवर्द्धन व ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा का मार्ग सुगम बनाने एवं यात्रियों को विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 103.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसी तरह से रामदेवरा में पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए भी 14.64 करोड़ रुपयों की लागत से चार मीटर चौड़ाई का कच्चा मार्ग निर्माण की बात हुई। 761 करोड़ रुपयों की लागत से 19 आरओबी बनाये जाएंगे। मेरे जिले में भी दो आरओबी मिले हैं- मुख्य जिला सड़क जिला बूंदी में एलसी नम्बर-136 और कोटा-मथुरा सड़क जिला बूंदी एलसी नम्बर-116, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बूंदी जिले में दो आरओबी दिये।

पेयजल के लिए भी 2016-17 में 2,950 करोड़ रुपये का प्रावधान

(श्री अशोक डोगरा)

किया गया है। इसमें मेरे यहां चम्बल से बूंदी को पानी आना है, उसको कम्प्लीट कराने की भी योजना बजट में बतायी गयी है। 4,000 नये हैण्डपम्प 40 करोड़ रुपयों की लागत से लगेंगे।

बिजली की बात है, बिजली कम्पनियों में क्या स्थिति थी? जब पुरानी सरकार थी तब भी मैं विधायक था, गांवों में सिंगल फेस चार घंटे, पांच घंटे से ज्यादा कभी नहीं आती थी। जब भी हम गांव जाते थे तो गांव वाले माथे आते थे कि थ्री फेस बिजली नहीं आ रही है। आज यह स्थिति है कि मेरे करीब-करीब गांवों में, 90 परसेंट गांवों में तो 24 घंटे सिंगल फेस बिजली है। कहीं नहीं होगी तो 22 घंटे बिजली होगी। 22 घंटे से कम तो कहीं नहीं आती। हर गांव में बिजली मिल रही है। थ्री फेस बिजली की जहां तक बात है, छह से सात घंटे बिजली थ्री फेस की मिलती है। ऐसी बढ़िया व्यवस्था करा दी कि किसान बिलकुल खुश है। यदि कहीं कोई फाल्ट आ जाता है तो अगले दिन उस बिजली को बढ़ा दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है।

पुरानी सरकार के टाइम पर जो 77,000 करोड़ रुपये का कर्जा था, उसको हमारी सरकार ने 2014-15 में 3,172 करोड़ रुपये कम किया और इस वर्ष 3,500 करोड़ रुपये का घाटा कम करने का लक्ष्य है। उसके बावजूद भी हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने "उदय" योजना के तहत 80,530 करोड़ रुपये के कर्जे का 75 प्रतिशत टेकआवर करने का निर्णय लिया है। यह बहुत साहसिक फैसला है जिससे 60,000 करोड़ रुपये टेकआवर हो जाएंगे। इससे बिजली कम्पनियों को बहुत राहत मिलेगी।

हमारी सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन की क्षमता में 4,283 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जबकि इनके दो सालों में 2,293 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हुआ था।

हमारी सरकार ने दो वर्षों में 765 केवी के दो, 400 केवी का एक, 220 केवी के 17, 132 केवी के 33 ग्रिड सब-स्टेशन लगाये हैं। इसमें मुझे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना है कि मेरे बूंदी जिले में भी 132 केवी के दो सब ग्रिड सैंक्शन हुए हैं। जमीन भी अलाट हो गयी है और अब उसका निर्माण शुरू हो रहा है। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 40-40 हजार कनेक्शन दो सालों में दिये और 40 हजार कनेक्शन अभी और दिए जा रहे हैं, इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार।

ओलावृष्टि की मुआवज़े की बात थी। अभी हमारी बानसूर से आने

(श्री अशोक डोगरा)

वाली माननीय विधायक महोदया ने कहा कि मुआवजा नहीं मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे बूंदी जिले में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पहुंचीं और उसके दूसरे ही दिन केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी माननीय अरुण जेटली जी वहां आये और वो सर्वे करके गये। उसके दो दिन बाद केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी खुद वहां आये, उन्होंने सर्वे किया और उसके बाद अरुण जेटलीजी ने हफ्ते भर के बाद एक टीम भेजी। उस टीम ने पूरा मुआयना किया, सर्वे किया और उसके बाद ही ये नई रेट और यह सब तय हुई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे बूंदी जिले में एक भी काश्तकार ऐसा नहीं है जिसको मुआवजा नहीं मिला। 300 करोड़ से ज्यादा मुआवजा अकेले बूंदी जिले में लोगों के खाते में गया है। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। ऐसा मुआवजा आज तक कभी मिला ही नहीं। जिनको मुआवजा मिला किसानों को, वो कहते हैं कि हमने इतने मुआवजे की कभी कल्पना ही नहीं की थी। राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी जिसमें किसानों को कम प्रीमियम दर पर वास्तविक नुकसान की समय पर भरपाई होगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली प्रीमियम राशि 676 करोड़ 37 लाख रुपये निर्धारित है। हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने यह फसल बीमा योजना लागू की है, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मण्डी आनलाइन को आगे बढ़ाते हुए ई-मण्डी की स्थापना की जाएगी, जहां किसान अपनी उपज को आनलाइन बेच सकेंगे। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहां भी नई मण्डी का निर्माण हो रहा है और यह तीन-चार महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, इसको भी आप ई-मण्डी का दर्जा दिलवाएं ताकि किसानों को सुविधा रहे।

पशुपालकों के जानवर मर जाते थे उसके लिए भामाशाह पशु बीमा योजना की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। इसमें बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को पशु बीमे की प्रीमियम की राशि का 70 परसेंट तक अनुदान और अन्य वर्गों को 50 परसेंट के अनुदान का प्रावधान है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। कृषि एवं उद्यानिकी सम्बद्ध सेवाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 में 4 हजार 850 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि पिछले साल से करीब 48 परसेंट ज्यादा है।

(श्री अशोक डोगरा)

परिवार का कोई मुखिया मर जाता है, उसकी अचानक मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों पर आर्थिक कठिनाई आ जाती है। ऐसे परिवारों को सम्बल प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गयी है। प्रदेश के 50 लाख से भी अधिक बैंक खातेदार इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। इन योजनाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही फ्लैगशिप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और नवीन प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना, नवीन पशु बीमा योजना की क्रियान्विति से राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का रास्ता खुलेगा।

राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 400 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 300 रुपये प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय 250 रुपये प्रति माह बढ़ाया, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार।

हमारे प्रधान मंत्रीजी का एक नारा है कि बालिका बचाओ और बालिका पढ़ाओ। प्रधान मंत्रीजी के उस नारे के अनुरूप हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्य मंत्री राजश्री योजना लागू की। इस योजना के तहत 1 जून, 2016 के बाद जो बच्ची पैदा होगी उसको 2 हजार 500 रुपये और जब वह कक्षा प्रथम में आएगी तो 4 हजार रुपये, जब वह छठी और दसवीं में जाएगी तो क्रमश: 5 और 11 हजार रुपये और जब वह 12वीं पास करेगी तो उसको 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, भ्रूण हत्या भी कम होगी और यह बालिकाओं के लिए बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार।

कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए शिशु पालना गृह संचालित करने की भी योजना है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहले 10 हजार रुपए दिए जाते थे और 2 हजार 500 रुपये उस संस्था को मिलते थे। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए किये और 2 हजार 500 से 3 हजार रुपए किये संस्था को। इसकी भी जितनी सराहना की जाए, कम है। मदरसों के लिए भी 66 करोड़ 30 लाख रुपये दिये हैं। स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल्स, शारदे छात्रावास,

(श्री अशोक डोगरा)

शाला दर्पण, लैपटाप वितरण, साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित की गयी हैं स्कूली शिक्षा के लिए इस बार 23 हजार 177 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। विद्यालयों में नवीं में बालिका को साइकिल मिलती है उसमें 2 लाख 77 हजार बालिकाओं को साइकिल दी गयी और इस वर्ष 2016-17 में 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बालिका गांव से जब आती है तो छोटी बहिन को पीछे बैठा कर लाती है, एक बच्ची और पढ़ने के लिए आ जाती है।

चिकित्सा सुविधा में भी इस साल 8 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रावधान है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी योजना है जिसमें प्राइवेट हास्पिटल हो या सरकारी हो, 30 हजार से 3 लाख रुपये तक का लाभ उस आदमी को मिलेगा। इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। प्रदेश के 67 परसेंट परिवार इससे जुड़ गए और इतने कम समय में 43 हजार परिवारों को इसका लाभ मिला। मेरे विधान सभा क्षेत्र खटकड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मुख्य मंत्रीजी ने क्रमोन्नत किया, उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारी सरकार ने आरएसएलडीसी के माध्यम से 1 लाख 11 हजार से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही आईटीआई, पोलीटैक्निक, राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगभग 40 हजार युवाओं के कैम्पस प्लेसमेंट किए गये। 26 माह में 4 लाख 74 हजार 514 नवीन ईपीएफ अकाउंट, मतलब इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। जबकि पिछली सरकार के टाइम पर ये 2 लाख 18 हजार 718 ही थे। इसमें डबल की वृद्धि हुई है। नए आईटीआईज के निर्माण के लिए 155 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ काम हैं। हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र को बहुत कुछ मिला है और बूंदी जिले में सात बड़े काम हुए हैं। फिर भी कुछ काम रह गये हैं। मेरे यहां बूंदी-नैनवां जाने के लिए कोई बाइपास नहीं है। बूंदी से जो नैनवां जाते हैं वो सिटी में से होकर जाते हैं। बूंदी से नैनवां, खटकड़, लाखेरी, इन्द्रगढ़, टोंक, सवाई माधोपुर जाने का वहीं रास्ता है। जिसमें इतना ट्रैफिक निकलता है। एसीसी की सीमेंट फैक्ट्रियां हैं लाखेरी में, पूरा ट्रैफिक सिटी में से जाता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं।

(श्री अशोक डोगरा)

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि बूंदी-नैनवां पर एक बाइपास का निर्माण किया जाए। शायद उनको ध्यान नहीं रहा इसका। 15 अक्टूबर को माननीय मुख्य मंत्रीजी जब कोटा पधारी थीं तब माननीय केन्द्रीय सड़क मंत्रीजी गडकरी साहब के साथ एक कार्यक्रम था। उसमें इन्होंने इसकी घोषणा भी की थी लेकिन किसी वजह से रह गया। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसको इसमें जोड़ लें।

पेयजल के लिए मेरा माननीय पेयजल मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के चार ऐसे गांव हैं जो 5 हजार की आबादी से ऊपर हैं- खटकड़, माटून्दा, सिलोर और तीर्थ। इनको पाइप योजना से घर-घर नल लगाने की सुविधा प्रदान कराएंगे, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। बूंदी शहर में नैनवां रोड पर आईटीआई से लेकर रंजीत टाकीज तक बूंदी की 30 परसेंट आबादी इसी सड़क पर रहती है और यह भीड़भाड़ वाला इलाका है। इस रोड को डबल करके डिवाइडर लगा दिए जाएं ताकि दुर्घटनाएं नहीं हों। बूंदी से बिजौलिया मेगा हाइवे बने पर्यटन की दृष्टि से। जो लोग सवाई माधोपुर से बूंदी होते हुए उदयपुर जाते हैं वो कोटा होकर निकल जाते हैं। सीएडी की जो बायीं मुख्य नहर है उसमें पानी वेस्ट होता है। इसके लिए उसको पक्का कराना है, उसका बजट भी आया हुआ है। मेरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि एलएमसी जो मेरे यहां से निकलती है सीएडी की, उसको पक्का कराएं।

(19.00 बजे)

बूंदी में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। टूरिज्म के लिए एक पैकेज मिल जाए तो वहां यह कुटीर उद्योग बन सकता है। मेरे दो नये स्टेट हाइवे डिक्लेयर हुए हैं, उनमें से कम से कम बूंदी-बिजौलिया वाला जरूर बन जाए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा सत्र 2016-17 हेतु बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर बोलने हेतु आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह सब जन विकास, सब जन उत्थान के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया है। 'चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी-भी अंधेरा है।' इस युक्ति

(श्री रामपाल)

को चरितार्थ करते हुए बच्चों, युवाओं, वृद्धों, मातृ शक्ति, गरीब हित, कस्बे-ढाणी, ग्रामों व शहरों सभी का उत्थान ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की अनूठी पहल अनुकरणीय है जैसे भामाशाह कार्ड योजना से 16 लाख 48 हजार महिलाओं को जोड़ना, रिसर्जेंट राजस्थान हेतु 3 लाख 21 हजार करोड़ के 295 एमओयू करना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, गौरव पथ योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना से 43 हजार परिवारों को जोड़ना। अन्नपूर्णा भण्डार, राजस्व लोक अदालतों से 21 लाख प्रकरणों का निस्तारण करना। सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान प्रदेश का होना। यह चरितार्थ करता है- 'कोई चलता पदचिह्नों पर, कोई पदचिह्न बनाता है, वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है।' ऐसी अनूठी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रदेश के लिए दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के चहुमुखी विकास में अच्छी एवं सुदृढ़ सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में प्रदेश में 2500 किलोमीटर लम्बाई से भी अधिक अन्य नान पैचेबल के नवीनीकरण का कार्य 600 करोड़ की लागत से करवाया जाना पूरे प्रदेश में आम जन द्वारा सराहा गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ योजना की पूरे प्रदेश में सराहना हुई है। इस योजना में प्रथम चरण में 1984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1027 करोड़ रुपये की लागत से 1955 किलोमीटर लम्बी गुणवत्तापूर्ण सीसी सड़क का निर्माण किया गया है। इस योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी यह कार्य किया गया है जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र में हुई है।

साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र अटरू से बड़ोरा-झालावाड़ सड़क की ऐसी दुर्दशा थी कि उस पर अनेकों घटनाएं घटित होती रहती थी। कांग्रेस शासन में कितनी ही बार जनता ने आग्रह किया, परन्तु कोई सुध नहीं ली गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस सड़क के लिए 53 करोड़ रुपये दिये। आज वह कार्य प्रगति पर है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही मिसिंग लिंक में आटोन से बेंसड़ा, मोटपुर से नयागांव, रहलाई से रामनिवास, मेरमाचाह से महेशपुरा, मवासा से अमृतखेड़ी, बारां से लक्ष्मीपुरा और बारां शहर में सात करोड़ की पांच सीसी सड़कें देकर क्षेत्र के लोगों को विशेष राहत प्रदान की है।

(श्री रामपाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 250 से 499 की आबादी के 934 गांवों में 2071 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है जो सराहनीय कदम है। शेष 37 गांवों में नवीन तकनीकी सड़कों के निर्माण हेतु 142 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक गांव ऐसा है जिसकी जनसंख्या 1200 के लगभग है, कांग्रेस शासन में भी काफी ध्यान दिलाया उसके बावजूद भी उस गांव को सड़क से नहीं जोड़ा। यह गांव चारपुरा गांव है, इसको भी इस योजना में जोड़ने का निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां विकट हैं। यहां देश का दस प्रतिशत भू-भाग है उसके लिए केवल एक प्रतिशत पानी उपलब्ध है। इस विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन योजना का श्रीगणेश किया है, जल संचय करने का जनजागरण अभियान शुरू किया है। उसमें राजस्थान के हर नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी, समाजसेवी, संत-महात्मा, मातृ शक्ति सभी ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। इसी योजना में मेरे क्षेत्र की आठ ग्राम पंचायतों के 18 गांवों में 13.52 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें सब लोगों का उत्साह है और सब लोग जनसहभागिता का परिश्रम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2016-17 में वृहत् परियोजनाओं के लिए में 2950 करोड़ रुपये की लागत का बजट प्रस्तुत किया है जिसमें 13 लम्बित परियाजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से पेयजल की समस्या से मेरा क्षेत्र अटरू कस्बा जो 35 हजार की आबादी का है त्रस्त रहा है। हर बार आंदोलन, हर बार लोगों की डिमाण्ड। अभी भी टैंकरों की सुविधा वहां की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी इस बजट में 80 करोड़ रुपये देकर वहां की जनता के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

ऊर्जा के क्षेत्र में गत कांग्रेस सरकार ने 2013-14 के अन्त तक 72722 करोड़ रुपये का घाटे का बोझ इस सरकार को दिया है जो अब वार्षिक घाटा 15645 करोड़ रुपये हो गया है। उसके बदले में लाइट मिली 3 से 4 घंटे थी

(श्री रामपाल)

फेस और 7-8 घंटे सिंगल फेस। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल प्रबंध क्षमता के उदाहरण को फेस करते हुए इस प्रकार के कर्ज का बोझ होते हुए भी प्रदेश में आज साढ़े 6 घंटे से 7 घंटे थ्री फेस और बीस घंटे से बाइस घंटे सिंगल फेस की जो व्यवस्था हो रही है, यह सराहनीय कदम है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। दो वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4283 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 1273 मेगावाट की सौर ऊर्जा की परियोजना स्थापित कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 33 केवी के सब स्टेशन फेरवालिया हाथी, दिलोद, बराना और देंगणी डींगपुर में सब स्टेशन बन जाते हैं तो मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल भराव क्षमता बढ़ाने एवं नहरों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 4047 करोड़ 41 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिससे राजस्थान के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ व अतिवृष्टि का पानी बेकार बह जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इसे ध्यान में रख कर व्यास, सतलज, घग्घर नदियों के बाढ़ के रूप में बहने वाले पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का रीस्ट्रक्चरिंग कर राजस्थान वाटर रीस्ट्रक्चरिंग फोर डिसेंट एरिया चलाया जाएगा। प्रदेश के किसानों के हितों के लिए यह सराहनीय कदम है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में परवन वृहत् परियोजना तीन जिलों के लाभ की योजना है- झालावाड़, कोटा और बारां, यह योजना वर्षों से लम्बित थी। किसान इस अन्नदायिनी, प्राणदायिनी योजना के लिये हर समय मांग करते रहे, अधिकांश समय कांग्रेस शासन का रहा, परन्तु उस क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली गयी इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परवन वृहत् परियोजना की शुरूआत करके क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी खुशियों की सौगात दी है। जैसे ही बजट में यह घोषणा हुई है, दीपावली की तरह गांव-गांव ने आतिशबाजी चलाकर उत्साहवर्धन किया है। माननीय, इस योजना से बारां, झालावाड़, कोटा के कुल 313 गांवों की 1 लाख...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय पांच मिनट, 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी एवं 820 गांव पेयजल से लाभान्वित होंगे।

(श्री रामपाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र बारां शहर में वर्षों से हल्की-सी भी बरसात होती थी तो पूरा बारां शहर बाढ़ से पीड़ित होता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 60 दिन की कार्य योजना में 56 करोड़ 15 लाख रुपये की डायवर्जन चैनल की घोषणा करके आज उसका कार्य चल रहा है और इस साल वहां की जनता को बाढ़ का मुंह देखने को नहीं मिला। बारां शहर के बीच में से झालावाड़-बारां रोड पर जो बिना रेलवे मार्ग गुजरता है, उस पर आरओबी की घोषणा करके पूरे शहर को एक हर्ष की सौगात दी है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मेरे क्षेत्र की थोड़ी-सी समस्या है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारां कालेज को वाई फाई की सुविधा दी इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता ही हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र में अटरू उपखण्ड मुख्यालय जिसकी आबादी 35 हजार है, उसके आस पास 55 सीनियर स्कूल हैं, वहां के बालकों को कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस स्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर डिग्री कालेज की घोषणा हो जाती है तो वहां की जनता के लिये बहुत ही सराहनीय कदम रहेगा।

मैं जिस उप खण्ड अटरू की बात कर रहा हूं, यह 35 हजार की आबादी वाला कस्बा है और 3 ग्राम पंचायतें इस कस्बे में स्थित हैं। गलियों की लम्बाई एक किलोमीटर से दो किलोमीटर तक की है। इसका पर्याप्त विकास पंचायतों से नहीं हो पाता। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अटरू उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन नगर पालिका की घोषणा हो जाती है तो वहां के लोगों को विकास के सुअवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री बच्चू सिंहजी।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चिकित्सा मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बयाना में 75 बैड के हास्पिटल को 100 बैड का करने पर चिकित्सा मंत्रीजी एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस हास्पिटल को 100 बैड का तो कर दिया है लेकिन हमें एक सोनोग्राफी मशीन की भी जरूरत है। हमें तीन डाक्टर्स की बयाना में जरूरत है। रूपवास

(श्री बच्चूसिंह)

तहसील हास्पिटल में 6 पद खाली हैं, उन सभी 6 पदों को भरा जाए। फाडपुर सीएचसी है, मैं पिछले एक साल से मंत्री महोदय से बजट मांग रहा हूं, वह बजट हो जाए तो वहां डाक्टरों के रहने की सुविधा हो जाए। अगर वहां डाक्टर रुक जाये तो लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। मंत्री महोदय से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस बजट में हमारी सीएचसी को भी बजट दे दें ताकि वहां डाक्टर रुक सके और इससे उस क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिल सके। हमारे यहां फाडपुर हास्पिटल में तीन डाक्टर्स की कमी है, डाक्टर्स वहां लग जाये।

मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एवं साथ ही माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद ना चाहूंगा हमारे यहां तीन इतने बड़े-बड़े रोड दिये हैं भरतपुर से बयाना होते हुए हिण्डौन, 375 करोड़ का रोड और वह चालू भी हो गया है। इसके अलावा बयाना से बाड़ी बसेड़ी होते हुए धौलपुर का काम वन विभाग की वजह से बंद पड़ा था, वह काम भी चालू हो चुका है। भरतपुर से ऊंचे नगला से होते हुए रूपवास तहसील से धौलपुर के लिये निकलते हुए 300 करोड़ का रोड है। इस तरह से हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे मेगा हाई वे तैयार होने वाले हैं और जल्दी ही हो जाएंगे। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद। गोरधन परिक्रमा जो कि 84 कोस की है, भरतपुर जिले की ही है, उसके लिये 104 करोड़ अभी इस बजट में दिया हैं, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद। छोटे-मोटे और भी रोड हैं जो कि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को बताएंगे। एक 6 किलोमीटर का रोड है फाडपुर पंचायत से सिंगनिया पंचायत, उस पंचायत से लगते हुए हम 40-50 किलोमीटर की दूरी सफर करके आते हैं और 6 किलोमीटर की दूरी है, उस रोड की भी मांग करते हैं।

मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गौरव पथ की हर जगह सराहना हो रही है। हमारे गौरव पथ का काम बहुत अच्छा हुआ है, पूरे क्षेत्र में वाहवाही हो रही है। इसके साथ-साथ नाली के निर्माण की कमी चल रही है, नाली का काम हो जाए। काम तो गौरव पथ का अच्छा हुआ है, नाली का भी अच्छा हुआ है परन्तु सफाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पंचायती राज मंत्रीजी से एक निवेदन करूंगा कि हर पंचायत में दो-दो, तीन-तीन सफाई कर्मचारी लगाये जाएं। इसके लिये मैं मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग गुणगान कर रहे हैं, मैं भी आपके बजट में आपका आभार प्रकट करते हुए शुरू करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वीरों की धरती पर आपने सैनिक विश्राम गृह की घोषणा की, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। इस धन्यवाद के साथ कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज यह पुलिंदा आप पेश कर रहे हैं, पिछले जो दो बजट पेश किये उसी तरीके से अगर करेंगे तो मैं आपको पिछले बजटों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पिछले दो वर्ष के बजट में किसानों के लिये, विद्यार्थियों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये आपने जो घोषणाएं कीं, आज किसान भी त्रस्त हैं, विद्यार्थी भी आज त्रस्त हैं, बेरोजगार भी आज त्रस्त हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय विराजमान हैं, पिछले बजटों में जिला स्तर पर डायलिसिस सुविधा कराने की घोषणा हुई थी लेकिन आज तक जिला स्तर पर इसकी किसी भी प्रकार से पालना नहीं हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना को पिछले बजट में भी आप लोगों ने समाहित किया। उससे पहले बजट में भी समाहित किया और आज भी उसी योजना को आप समाहित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने पिछले तीन बजट पेश करने के बाद भी अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में एक भी घर को अगर विद्युतीकरण से जोड़ने का काम किया हो। एक ही योजना को आप लगातार तीन साल तक बजट में घोषित करते हो लेकिन आज तक आपने एक भी विद्युतीकरण नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें लिखने से नहीं धरती पर, धरातल पर जाकर काम करना पड़ेगा। सहकारी बैंकों में किसानों को शून्य ब्याज पर कर्ज देने की बात थी, आज भी किसानों से तीन प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है। आज दिन तक किसान को एक को भी शून्य ब्याज पर कर्ज नहीं दिया गया। सी.एम. आवास योजना आप लोगों ने शुरू की, मुख्य मंत्री के नाम से आप योजना शुरू कर रहे हैं, उसकी विफलता। आज दिन तक मुख्य मंत्री आवास योजना में एक भी आवास, प्राइवेट पार्टनरशिप से आप जोड़ना चाह रहे थे, आप नहीं दे पाये। मुख्य मंत्री के नाम से पिछले बजट में आदर्श ग्राम पंचायत योजना आपने शुरू की, उस योजना में आज दिन तक एक पैसा आप लोगों ने खर्च करने का काम नहीं किया। इस बजट में आपने चार योजनाओं को मुख्यमंत्री के नाम शुरू किया-मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, मुख्य मंत्री जन

(श्री मनोज कुमार)

सहभागिता विद्यालय विकास योजना, मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास योजना और मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना। मैं कहना चाहता हूं, आप इस तरीके के नाम लिखो, लेकिन उसकी पालना धरातल पर जा कर करें नहीं तो जो हालत मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत की हुई। कि इस बजट में आपने उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा। आप दो बजट उसकी घोषणा कर चुके थे और एक पैसा इस राजस्थान की जनता को आपने नहीं दिया। आपने समाज कल्याण विभाग के छात्रों को ई-ट्यूशन योजना की पिछले बजट में घोषणा की, लेकिन आज तक आपने समाज कल्याण विभाग द्वारा ई-ट्यूशन किसी भी छात्र को देने का काम नहीं किया गया। इसी तरह आपने प्रदेश में आर्ट वर्क, एनिमेशन ग्राफिक को डैडिकेटेड आई.टी.आई. और विज्ञान मानविक शोध संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक आपने उसको शुरू नहीं किया। जयपुर में एक बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय जो पांच बत्ती चौराहे पर है, उसको बाहर ले जाकर आपने विकसित करने की बात कही लेकिन आज दिन तक उसी स्थान पर पांच बत्ती पर चल रहा है। यह योजना आपने घोषित की थी लेकिन आपने चर्चा नहीं की। जयपुर में अत्याधुनिक वाहन फिटनैस, ड्राइविंग ट्रेक की अब तक सुविधा नहीं, शुरू नहीं किया गया है लेकिन आप लोग इस बजट के पुलिंदे में शामिल करते हो। द्रव्यवती नदी से सटे किशनबाग में बाटेनिकल पार्क बनाना कागजों तक सीमित है, आज तक आप नहीं बना पाये। किसानों के बच्चों को शिक्षा के मद्देनजर रखते हुए आपने कहा था, एग्रीकल्चर किसान के पास घरेलू कनेक्शन है, उसको हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, लेकिन आज तक आप उनके कनेक्शन नहीं कर पाये। आपने यह घोषणा की थी। विद्यार्थी मित्रों की दो बजटों में आपने घोषणा की लेकिन अब की बार विद्यार्थी मित्रों का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की वेतन– विसंगतियां आपने दूर करने का काम नहीं किया।

अब की बार इस बजट में रिंग रोड़ जो आठ साल से जयपुर में चल रही है, ने आठ महीने से मंद गति से, अभी तक कोई काम नहीं किया। दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कारिडोर का आपने इस बजट में नाम नहीं लिया। मैट्रो के सैकेंड फेज का आपने नाम नहीं लिया। रिफाइनरी का आपने इस बजट में नाम नहीं लिया। ये सारी की सारी घोषणाएं आपके पहले वाले बजटों में शामिल थीं लेकिन आप लोगों ने इस कार्य के बारे में एक शब्द नहीं लिखा।

(श्री मनोज कुमार)

आपने एक लाख लोगों को नौकरी देने की इस बजट में घोषणा की है लेकिन किस आधार पर कैसे देंगे, किसको देंगे, आपने इसमें शामिल नहीं किया। कार खरीदना आपने वन टाइम टैक्स लगाकर बढ़ा दिया। सबसे गम्भीर आपके इस बजट की बात, महिला दिवस के दिन महिला मुख्य मंत्री होने के नाम से आपने उनके जन्मदिन पर बजट पेश किया और महिलाओं को 2015-16 में 1790 करोड़ रुपए का बजट आबंटित था, इस बजट में 1756.78 करोड़ जो कि महिलाओं के नाम से आप बार-बार चर्चा कर रहे हैं, आपने उस बजट को घटाने का काम किया है। एस.सी.-एस.टी. के नाम से बार-बार आप नाम ले रहे हैं एस.सी.-एस.टी. का। अनुसूचित जनजाति का 2015-16 में बजट 517 करोड़ रूपए था और इसको घटाकर आपने अबकी बार 502 करोड़ किया है। आप किस तरीके से विकास की बात करना चाह रहे हैं? किस तरीके से आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? बजट में आपने 300 करोड़ रूपए के नए टैक्स लगाए हैं और 325 करोड़ रुपए की आपने राहत देने की बात की, लेकिन आपने बजट से चंद दिनों पहले वैट शिड्यूल में 0.5 का टैक्स लगाकर 300 करोड़ रुपए की और आय प्राप्त करके जनता से 600 करोड़ रूपए का टैक्स वसूल करने का काम किया है।

इससे भी गम्भीर बात आपके सामने पेश करना चाहूंगा, किसानो की बात आप बार-बार कर रहे हैं, खेती की बहाली की बात कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूं, 2012-13 और 2013-14 के बीच कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास दर 10.38 परसेंट थी, जो 2013-14 से 2014-15 के बीच घटकर 8.43 प्रतिशत रह गयी। दो साल में 11 लाख टन घटा खाद्यान्न उत्पादन।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस का शासन था। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपका दो साल में 11 लाख टन घटा खाद्यान्न उत्पादन। इस देश का नागरिक अन्न खाने से जिएगा। आपके रिसर्जेंट राजस्थान से नहीं। सबसे पहले इसका रिसर्जेंट करिए, खाद्यान्न का उत्पादन अगर कम हो रहा है तो आप लोग चल नहीं पाओगे, मुद्दे आपके चल नहीं पाएंगे। इसलिए कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर राजस्थान की जनता खाने के लिए अन्न का उत्पादन बढ़ाने का काम करें। किसानों के ऊपर ग्वार का टैक्स लगाया जो कि टैक्स फ्री था। आप लोगों ने अब की बार उस पर टैक्स लगाया।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में मैं आपको कुछ बातें और कहना चाहूंगा।

(श्री मनोज कुमार)

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण की आपने चर्चा की, इस चतुर्थ चरण में मेरा राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 59193 है, एक लाख के बीच में शामिल होना चाहिए था, जो कि पहले जब भी हाइपावर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें मेरा राजगढ़ शहर शामिल था लेकिन इस बजट में उसका नाम काट दिया गया। वो काटने का कारण मात्र एक ही है हमारे साथ राजनैतिक द्वेषता। हमारे क्षेत्रीय सांसद के दबाव में राजगढ़ का नाम काटने का काम किया है। माननीय पंचायती राजमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति में भी आपने इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कहने से काटने का काम किया- मेरी पंचायत समिति में 56 ग्राम पंचायतें हैं और ढाई लाख से अधिक आबादी है, उसके बाद भी हमारी दूसरी पंचायत समिति नहीं बनाना। सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण हमें इन दो चीजों से आपने वंचित करने का काम किया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ग्राम पंचायत की आज पापुलेशन जहां 15 हजार से अधिक है, वहां अग्निशमन यंत्र वाहन की बात की। मैं कहना चाहता हूं, मेरा नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ शहर है, वहां आज भी अग्निशमन वाहन नहीं है। गुजारिश करता हूं कि अग्निशमन वाहन की व्यवस्था कर मेरे राजगढ़ शहर को जहां की पापुलेशन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 60 हजार है, एक वाहन उपलब्ध करा दें तो कि पूरी तहसील में एक अग्निशमन वाहन हो जाए।

माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, हमारे सिद्धमुख नहर का बार-बार नाम लिया जा रहा है। 31 मार्च, 2015 तक आपने कहा था कि वहां खाले निर्माण कर दिए जाएंगे। 2808 हैक्टेयर भूमि में खाले नाले निर्माण होने हैं, आज तक नहीं हुए। बीस साल से हम उसका इंतजार कर रहे हैं। एन.एच. 65 में ग्राम सदासुख लुटाणा में और रड़वासे रास्ते में अंडरब्रिज निर्माण-मूल रास्ता है, गांव के लिए उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की सड़क बन चुकी है। लेकिन उसके बाद भी वहां अंडरब्रिज नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यह अंडरब्रिज तुरन्त पास करे और मेरे राजगढ़ की जनता को लाभ दें। इसी के साथ ही साथ चूरू रोड से हिसार रोड हमारे एन.एच. 65 से जो जुडी हुई है, बाइपास जा रही है। उसमें हमारी पांच रोड जुड़ रही हैं- तारानगर रोड, गुलपुरा रोड, सिद्धमुख रोड, ढंडाल रोड, हिसार रोड, पंद्रह किलोमीटर

(श्री मनोज कुमार)

रोड़ अगर और जोड़ दी जाए, अगर मुख्य मंत्री महोदय दया कर दें तो पूरे राजगढ़ की रिंग रोड बन जाएगी। आपका आभार जीवन भर मेरी राजगढ़ की जनता नहीं भूलेगी। उसमें मात्र तीन रोड चूरू रोड़ से झुंझुनू रोड, पिलानी रोड और बहल रोड जाएगी तो रिंग रोड बन जाएगी। इसी के साथ-साथ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पानी पहुंचाया है उधर (व्यवधान)।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अभी बताऊंगा, पहुंचाया नहीं है। वो ही बताऊंगा मैं। अभी दो मिनट का समय और ले रहा हूं। राजगढ़ में 2006 से बुंगी जलदाय प्रदाय योजना चल रही है, 11 साल हो गये माननीय मंत्री महोदय। आज तक राजगढ़ की जनता को उसका पानी नहीं मिला। आपने सदन में 31 जुलाई को यह कहा था कि मैं राजगढ़ शहर को पानी पिला दूंगी। उसके बाद कहा था कि नवम्बर तक हम पानी पिला देंगे। आज मार्च आ गया, अब भी आपकी मंशा मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि आप महीने दो महीने और पिला पाएंगे। आपका आभार उस दिन करेंगे जिस दिन आप राजगढ़ में पानी पहुंचा देंगे। शहर में नहीं आया, अभी तक, नहीं माननीय मंत्री महोदय, नहीं आया। मैं आज भी यह कह रहा हूं, आपके अधिकारी फिर आपको असत्य बोल रहे हैं।

इसी तरह कालेज भूमि स्वीकृत कराकर भवन निर्माण की मांग करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि महिला महाविद्यालय भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है, उसका निर्माण किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे दो जीएसएस जो चल रहे हैं, उनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है इसलिए निगरानी करके तुरन्त प्रभाव से उनको शुरू कराने का काम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सिद्धमुख पीएचसी लम्बे समय से है, अधिक पापुलेशन है, उप तहसील है उसको सीएचसी घोषित करने का इसी बजट में, इसी समय, आपकी डिमांड पर आप हमें आश्वासन दें।

माननीय गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारा हरियाणा सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, रात-दिन वहां क्राइम हो रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे वहां एक थाने की और व्यवस्था की जाए

(श्री मनोज कुमार)

जिससे राजगढ़ व हरियाणा सीमा को चैक कर नफरी बढ़ाकर राजगढ़ की जनता को राहत दी जाए।

माननीय देवस्थान विभाग मंत्री बैठे हैं, हमारी चूहों के नाम से प्रसिद्ध करणी माता का राजगढ परिसर में एक मंदिर है, जिसमें आजादी से लेकर आज दिन तक देवस्थान विभाग का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने आपको चिट्ठी लिखी, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसका जीर्णोद्धार करा दिया जाए, हमारी भी शान उस गढ़ में माताजी के मंदिर के जीर्णोद्धार से हो जाए।

साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अपील, बीपीएल अपील और इंदिरा आवास सूची, इनमें जो लोग हैं उनकी अपील में एसडीएम के निस्तारण करने का कोई समय निर्धारित नहीं है इसलिए उनको पाबंद किया जाए, अपील का समय निर्धारित किया जाए जिससे जनता को तुरन्त इसका लाभ मिले। इसके साथ एक और कहना चाहूंगा कि अभी एन्टासिंगरासर माइनर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, 25 गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। संकल्प पत्र में शामिल था माननीय मुख्य मंत्री महोदय के, और 2006 में कमेटी गठित की थी आपकी ही सरकार ने। 2006 से लेकर 2016 तक किसान आज भी वैसे ही प्रताड़ित है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें इसको शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ, साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह जी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, अनुमति दी, इसके लिए आपका और सदन का आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण 2016-17 प्रस्तुत किया गया, मैं मानता हूं कि यह राजस्थान के प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा और विकासशील बजट दिया गया है। जिस राजस्थान प्रदेश को गत सरकार ने विकास अवरूद्ध कर भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया था, उस प्रदेश को एक सम्पूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बजट साबित होगा।

प्रदेश में गिरता भूजल स्तर गम्भीर समस्या है इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान उसी दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। 3318 गांवों में जल संरक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

आगामी वर्ष के लिए 440 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे और पेयजल की समस्या का समाधान होगा।

प्रदेश में वर्तमान में सबजन उत्थान और सबजन विकास का नारा दिया गया, उसको यथार्थ रूप में लाने के लिए सभी महत्वपूर्ण विभागों कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा में हमें देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगी ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष उल्लेखनीय बात है वह है 628 विद्यालयों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, विद्यार्थी अब तक गरमी में बेहाल रहते थे, राशि 13 करोड़ रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमारी सरकार ने कार्य किया है उतना कांग्रेस पिछले 60-62 वर्षों में नहीं कर पायी। गत वर्ष 5500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। 56 हजार शिक्षकों की डीपीसी कर उनको पदोन्नति दी गयी है, यह ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया है। माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि बालिका शिक्षा के लिए भी 47 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बालिका को कक्षा नवीं से साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आठवीं, दसवीं व बारहवीं में बोर्ड की मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आदर्श विद्यालय स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल, छात्रावास, 770 राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम जैसी योजनाएं शुरू की गयी हैं। उच्च शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सभी को दृष्टिगोचर कर जनता को पूर्ण रूप से लाभान्वित करने का विचार किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 400 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 300 रुपये प्रति माह, आंगनबाडी सहायिका को साथिन, आशा सहयोगिनी को मानदेय के 250 रुपये प्रतिमाह बढ़ाए जाने की घोषणा की गयी है जिसके तहत लगभग 1 लाख 50 हजार मानदेय कर्मी लाभान्वित हुए हैं। साथ ही वर्क परफोरमेंस के आधार पर प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाने का निर्णय लिया गया है।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को चयनित विभागों में उपयुक्त स्तर पर आउट आफ टर्न सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नीति लाने की घोषणा की गयी है जिससे प्रदेश के खिलाडियों को काफी प्रोत्साहन मिला है। इसके चलते प्रदेश की खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी। साथ ही प्रदेश की हाकी व कबड्डी टीमों को बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इनकी राज्य स्तरीय टीमों को रीको और आरएसएमएम लि. द्वारा स्पांसर किए जाने की घोषणा की गयी है। माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और खेल मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का मानदेय काफी कम है, आज महंगाई के हिसाब से टीए और डीए भी काफी कम है। ओपन हो या स्कूल, जो भी खिलाड़ी स्टेट में खेलने जाता है या जिला स्तरीय खेलने जाता है उसका टीए-डीए काफी कम है। आज के महंगाई के दिनों में बच्चा पर्याप्त भोजन नहीं कर पाता है। इसके लिए उनको प्रोत्साहन के रूप में टीए-डीए और जो भी मानदेय है, वह बढ़ाया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्टार्टअप नीति, 2015 के तहत उत्पादों का निर्माण करने सहित पर्यावरण हितैषी उद्योगों की स्थापना के लिए महिला उद्यमियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य किया गया है। साथ ही मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से वायु एवं जल प्रदूषण नगण्य होने की दशा में जल व वायु अधिनियम के तहत कन्सेंट प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। राजस्थान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विषय को प्रोत्साहन करने का कार्य है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्टार्टअप पालिसी, 2015 के तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है जिसके लिए 2016-17 में 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

साथ ही इलैक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको के माध्यम से करौली, भिवाड़ी क्षेत्रों में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र में ग्रीन फील्ड इलैक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

गर्मी दस्तक दे चुकी है और हमारा पूरा प्रदेश वर्षों से भंयकर गर्मी

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

की मार झेलता आया है, ऐसे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 हजार नये हैण्डपम्प लगाने की घोषणा की है, वह निश्चित ही जनहित में और प्रशंसनीय है, जिससे प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या से राहत मिलेगी। लेकिन मेरा विचार है हमें प्रदेश के स्थाई पेयजल समाधान की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ जहां पर नदियां, बांध उपलब्ध हैं, वहां की आम जनता के लिए स्थाई पेयजल का समाधान किया जाना चाहिए। चित्तौडगढ़ के गोसुंदा बांध से पेयजल के लिए बढेसर व चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की डीपीआर बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और पेयजल मंत्री जी किरण जी माहेश्वरी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उक्त कार्यों हेतु इसी बजट सत्र में योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट राशि की जाती है तो चित्तौड़गढ़ की आम जनता के लिए बहुत लाभदायी होगा। मैं मानता हूं, मंत्री महोदय का ससुराल भी चित्तौड़गढ़ विधान सभा में ही है इसलिए इसी सत्र में इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही यदि गोसुंदा के ओवरफ्लो पानी को गोसुंदा तालाब में डाल दिया जाए तो मेरे क्षेत्र की 11 पंचायतों के 65 गांवों को पेयजल एवं पशुओं के लिए पानी उपलब्ध होगा।

जल संसाधन विभाग- सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई एवं मिनि स्प्रिंकलर संयंत्र पर अनुदान बढ़ाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में की गयी जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त भार से निश्चित ही राहत मिलेगी। इसके लिए प्रदेश का हर किसान माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट कर रहा है।

इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घाटा क्षेत्र की 11 पंचायतों को पेयजल और सिंचाई हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर घाटा क्षेत्र है, जगह पर पानी नहीं रोका जा सकता है। इसके लिये मेरा जल संसाधन मंत्रीजी को निवेदन है, क्योंकि इसकी डी.पी.आर. भी बन चुकी है, पूरा काम कमप्लीट है, माननीय जल संसाधन मंत्रीजी, अगर साकेड़ा बांध की घोषणा कर दें तो 11 पंचायतों की पानी की जो समस्या है, वह साल्व हो जाएगी। नहरों का निर्माण भी किया जाए, इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में घाटा क्षेत्र की आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। इसी क्रम में, जितनी भी नहरें हैं उनकी वर्तमान स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनमें आधी नहरें कच्ची हैं, आधी नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

में हैं। इसलिये चित्तौड़गढ़ के लिये एनिकट और नहरों के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से विशेष मांग करता हूं। मंत्री महोदय को इसी बजट में घोषणा करने की विनती करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण एवं विद्युत कनेक्शन के लिये अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है जो सराहनीय है। इसमें प्रदेश की जीर्ण-शीर्ण शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ शहर में संचालित पी.जी. कालेज में एक बालिका कालेज में नवीन विषय खोलने की मांग लम्बे समय से चल रही है लेकिन शायद कम्प्यूटर में टाइपिंग की गलती से नवीन विषय खोलने की सूची में चित्तौड़गढ़ के उक्त महाविद्यालय का नाम छपने से रह गया। लेकिन, चित्तौड़गढ़ के प्रति माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सकारात्मक भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री कालीचरणजी इसकी घोषणा कराएंगे। इसी शिक्षा सत्र में उक्त महाविद्यालय के नवीन विषयों को खोला जाए जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्यत्र न भटकना पड़े। साथ में मैं मांग करता हूं कि चित्तौड़गढ़ राजकीय कन्या महाविद्यालय को नवीन विषय के साथ पी.जी. में क्रमोन्नत करने की कोशिश करें, क्योंकि जहां चित्तौड़गढ़ का पी.जी. कालेज है, 6 हजार के आसपास स्टूडेंट हैं। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि पाँच हजार से ऊपर एक कालेज और खोलेंगे। तो जो कन्या महाविद्यालय है, उसको क्रमोन्नत कर पी.जी. करने की कोशिश करें। भजेसर, जो चित्तौड़गढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण उपखण्ड है, जहां से पूरे चित्तौड़गढ़ के 80 प्रतिशत जन-प्रतिनिधि सम्बन्धित हैं, वहां मैं माननीय मुख्य मंत्री की मंशानुसार शीघ्र ही नवीन महाविद्यालय खोलने की मांग रखता हूं। उपखण्ड भी है और सभी वहां से बिलोंग करते हैं और हैडक्वार्टर से 35 किलोमीटर दूर है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि राज्य में आमूलचूल परिवर्तन किया है। सभी पंचायतों को 12वीं तक किया है। सभी जगह प्रिंसिपल और पी.टी.आई. और सभी शिक्षकों की पूर्ति की है।

चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय व माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के असीम प्रयास रंग ला रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रदेश के गरीब परिवारों के बीमार व्यक्तियों के इलाज में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, 2015 प्रारम्भ की गयी

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

गयी है जिसके तहत 432 राजकीय चिकित्सालय तथा 423 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। करीब 43 हजार परिवारों द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया गया है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। साथ में लम्बे समय से अटकी जी.एन.एम., ए.एन.एम. की भर्ती प्रकिया पूरी कर प्रदेश में लगभग 11 हजार जी.एन.एम., ए.एन.एम. की भर्ती करना, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की ही करामात है। वे कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो निश्चित ही सराहनीय है। चित्तौड़गढ़ में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय की मांग काफी लम्बे समय से चल रही है। इस विषय में मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ में पुराना महिला एवं बाल चिकित्सालय भवन है चूंकि उक्त चिकित्सालय अब नवीन भवन में शिफ्ट हो चुका है इसलिये पुराने भवन में जो अभी रिक्त है, नवीन सैटेलाइट चिकित्सा केन्द्र इसी बजट में स्वीकृत कर दिया जाए तो क्षेत्र की जनता काफी लाभान्वित होगी। माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल चिकित्सालय का उद्‌घाटन करने पधारे थे, उस टाइम घोषणा भी की थी। मेरे को आशा है, मंत्रीजी इसी सत्र में घोषणा करके सैटेलाइट हास्पिटल वहां करेंगे। साथ ही मंत्रीजी ने एक और घोषणा वहां की थी। जिला चिकित्सालय की, वर्तमान में 300 बैड की क्षमता है, उसे 500 बैड में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है, पूरे जिले का एक मात्र बड़ा हास्पिटल है, जिसके लिये मैं सरकार से मांग करता हूं।

एक विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र से नहीं, अपितु सम्पूर्ण जिले के लिये है औरी महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़ जिले का नवीन मेडिकल कालेज। मैं चित्तौड़गढ़ के सभी विधायकों, एम.पी. साहब को साथ लेकर चित्तौड़गढ़ नवीन मेडिकल कालेज करने की मांग करता हूं। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने थोथी घोषणा वहां कर दी थी किन्तु न तो कोई बजट का प्रावधान किया, न कोई दूसरा प्रावधान किया। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं, वहां मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रदेश में 2016-17 में 2500 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की एवं अन्य पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण का कार्य 600 करोड़ रुपये की लागत से करवाने का प्रावधान किया गया है। माननीय पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी को मैं कहना चाहता हूं कि मेरा होड़ा चौराहे से शम्भुपुरा नाहरगढ़ जो रोड है...

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सर। होड़ा चौराहा, नाहरगढ़, शम्भूपुरा, घटयालवी होते हुए चित्तौड़गढ़ जो रोड है, वहां बहुत टूट-फूट है। वहां एक आदित्य फैक्ट्री भी है उसके कारण काफी समस्या है। आज की तारीख में वहां डामर नाम की कोई चीज नहीं बची है। शीघ्र इस रोड को बनवाने की आप घोषणा करें।

चित्तौड़ी खेड़ा से ओसली पुलिया का निर्माण चित्तौड़ी खेड़ा से ओसली जोड़ने के लिये एक पुलिया की आवश्यकता है। उसकी भी आप घोषणा करें। चित्तौड़गढ़ सिटी की मेन समस्या है, कपासन चौराहे से मानपुरा रोड। चित्तौड़गढ़ सिटी में ओवरलोड गाड़ियां आती हैं, एक्सीडेंट काफी होते हैं, इसलिये बाई-पास के लिये कपासन चौराहे से मानपुरा रोड की भारी मांग है। इसमें भी आप घोषणा करें।

मैं मुख्य मंत्रीजी के बजट की पूरी प्रशंसा करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटूसिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2016-2017 का जो बजट पेश किया गया, यह बजट आम अवाम, मजदूर, किसान, महिला, व्यापारी, यहां तक कि सड़क चलते हुए आम आदमी को पैनी नजर से देखकर उनकी मूल भावनाओं को...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मान्यवर, उनकी मूल भावनाओं को समझ कर उनके सर्वांगीण विकास का बजट बनाया गया है। बजट सबका विकास, सबका साथ लेकर बनाया गया है। प्रदेश में वर्ष-प्रतिवर्ष आपदाएं, ओलावृष्टि, कभी सूखा तो कभी किसानों के खेतों में पाला आता रहता है, फिर भी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस बजट में भामाशाह योजना, स्वरोजगार सृजन योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान योजना, मुख्य मंत्री जन आवास योजना, अन्नपूर्णा भण्डार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालांकि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार हजारों करोड़ का कर्ज वर्तमान सरकार को दे गयी, फिर भी, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अति सम्माननीय हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बड़ी कुशलता से प्रबन्ध करते हुए कई फैसले लिये जो कि दूरगामी साबित होंगे। मान्यवर, राजस्थान प्रदेश की चुनी हुई सरकार ने आम गरीब के द्वार पर जाकर उसकी कुशल क्षेम पूछकर समस्या की जानकारी पहली बार ली है। तकरीबन 21 लाख से भी अधिक प्रकरणों, का निस्तारण हाथों-हाथ किया। मान्यवर, ऐसे कई मामले शिकायती थे, 7 लाख मामले, तकरीबन 89 प्रतिशत का निस्तारण 2016 तक हुआ। आमजन के सपने सच्चे हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैरा नम्बर 7 में विद्युत कम्पनियों के कुप्रबन्ध से प्रदेश पर 80 हजार करोड़ का विशाल ऋण, फिर भी आमजन की झोंपड़ी में कैसे उजाला हो, गरीब किसान के खेत में कैसे कृषि कनेक्शन हो, इन सबका ध्यान रखते हुए प्रदेश की 7 करोड़ जनता की आस्था से, आकांक्षाओं से, भावनाओं से बजट प्रतिबिम्बित है। बजट इसके साथ ही सरल और पारदर्शी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 2 में रिसर्जेण्ट राजस्थान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। स्वदेशी ही नहीं, विदेशी कम्पनियों को भी आमंत्रित किया। 3 लाख 21 हजार करोड़ के एम.ओ.यूज. माननीय मुख्य मंत्री के विश्वास से इस प्रदेश में किये गये। इससे उद्योगों का विकास होगा। रोजगार में, अर्थव्यवस्था में और सुदृढ़ता आएगी।

मान्यवर, पैरा नम्बर-8 में है सड़क निधि- सड़क एक ऐसी चीज होती है कि सही हो तो विकास की दर बहुत अच्छी होती है। आवागमन के लिए

(श्री छोटू सिंह)

आम जनता को सुख मिले, महंगाई कम हो, इसके लिए जरूरी है, सड़क मार्ग। प्रदेश में मिसिंग लिंक, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 250 से 300 की आबादी के गांवों को जोड़ने का भी, गांव में सुदृढ़ और नवीनीकरण सड़क की सोच को रखते हुए स्वागत योग्य कदम इस बजट भाषण में लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ-साथ ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ बनाये गये हैं, मैं मान रहा हूं कि गौरव पथ रोड पूरे राजस्थान में कहीं-कहीं दलदल थीं तो कहीं कीचड़खाना था, लेकिन, मेरे जैसलमेर में मान्यवर, ऐसी ड्यूंस थीं कि बस स्टेंड से कोई भी गाड़ी घर तक नहीं जा सकती थी। आज गौरव पथ एक वरदान साबित हुआ है। गौरव पथ रोड बनने से घर तक आम महिला चाहे वह डिलीवरी केस में हो, चाहे वह बीमार हो, चाहे कहीं वृद्ध हो, वह पहुंचती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गौरव पथ से आम जन को, आम गांव को बहुत बड़ा लाभ मिला है।

आदरणीय, हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री धार्मिक विचारों की हैं, पूजा-प्रतिष्ठा में विश्वास रखती हैं। 84 कोस की जो गोवर्धन परिक्रमा है, उसको सुगम बनाने के लिए आपने अति स्वागतयोग्य बजट भाषण किया और पैदल जो लोग चलते थे, उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया। इसके साथ ही, रामदेवरा के लिए प्रदेश से ही नहीं पूरे राष्ट्र से लोग पैदल आते हैं। जोधपुर से रामदेवरा के लिए बहुत लम्बा रास्ता है, आए दिन सड़क व्यवधान के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी चार मीटर का एक सही और सुलभ कच्चा रूट यात्रियों के लिए बनाने का प्रस्ताव लिया, वह भी बहुत स्वागत योग्य है। हम जैसलमेर- वासी ही नहीं पूरे प्रदेश के वासी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

आदरणीय, राज-मार्ग के अन्दर भी नए-नए बाई-पास बनाना, उसके लिए 337 करोड़ का प्रावधान, किया गया राष्ट्रीय राज मार्ग के नजदीक में जो गांव आता है, राष्ट्रीय राज मार्ग पर आम यात्री को छोड़ा जाता है लेकिन अब जिस हिसाब से बजट में करोड़ों का प्रावधान किया है, इससे राष्ट्रीय राज मार्ग से गांव वह सड़क से जुड़ेंगे। इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

जनता जल योजना पूर्व में बंद थी। चार साल तक इसका किसी ने नाम नहीं लिया। फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उक्त योजना के अन्दर चाहे हैंडपम्प हों, बड़े-बड़े जी.एल.आर. हों, उनका वापस उत्थान और नवीनीकरण

(श्री छोटू सिंह)

करने का प्रावधान किया। इसके साथ में मेरे जैसलमेर के अन्दर जो डीजल सैट से कई ट्यूबवैल्स चलते थे, आए दिन खराब भी होते थे, पेयजल की समस्या होती थी। इस वर्ष 3.29 करोड़ रुपये का बजट लिया और सौर ऊर्जा से उन ट्यूबवैल्स को जोड़ने का जो प्रावधान किया है, वह भी स्वागत योग्य है। जैसलमेर की जनता बहुत-बहुत दुहाइयों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद देती है।

जल स्वावलंबन योजना-मान्यवर, हिन्दुस्तान आजाद होने के पूर्व ट्यूबवैल्स नहीं थे, पेयजल परमात्मा पर निर्भर था। इन्द्रदेव की जब मेहरबानी होती थी तो वह जो पानी के रूप में प्रसाद आता था, उसका कलेक्शन किया जाता था। दूरगामी सोच माननीया मुख्य मंत्री ने, पूरे सदन ने और मंत्रियों ने रखी, उस सोच से आज जल स्वावलंबन योजना बनी। हम चाहे एनीकट्स कहें, चाहे बेरियर्स कहें, रेंगते हुए पानी को रोकना, उसको इकट्ठा करना और उस बरसाती पानी को पीने के लिए उपयोग में लेना, यह बहुत बड़ी सोच है और आने वाले समय में यह बहुत ही अच्छी साबित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत वितरण के लिए 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। वार्षिक घाटा 15 हजार करोड़ हो गया था। दो वर्ष के बाद माननीया मुख्य मंत्रीजी और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के अथक प्रयास से यह घाटा 3500 करोड़ कम हुआ। यह व्यवस्था दूरगामी है, सोच अच्छी है। इस संस्थागत सुधार का नतीजा यह रहा कि प्रदेश में 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन हुए। मेरा जिला विशेषकर इसके लिए उत्सुक था क्योंकि हमारे जिले में ट्यूबवैल व्यवस्था नहीं थी। आज यह व्यवस्था आयी है। किसी भी प्रकार से, फव्वारा पद्धति से भी खेती होती है, हम चाहते हैं कि 40 हजार में जैसलमेर के किसानों का भी नम्बर आएगा। हम चाहेंगे कि पूर्व में जिले को जो डार्क जोन घोषित किया गया है, उसको बंद करके इस प्रकार की योजना पुनः शुरू करें और ये कनेक्शन दिये जाएं जिससे खाद्यान्न की जो कमी आ रही है उसका निराकरण हो सके।

साथ में जनजाति के लिए आन डिमांड कृषि कनेक्शन का जो प्रावधान 2018 तक पूर्ण करने का इस बजट के अन्दर लिया है, वह भी स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंद-बूंद, डिग्गी सिंचाई हमारे यहां पर है। जहां पर नहरी क्षेत्र है, वहां के लोग चाहते हैं कि डिग्गी से और बूंद-बूंद से हम खेती कर सकें, फलदार पौधे लगा सकें। माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने उक्त

(श्री छोटू सिंह)

बजट के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की है। साथ ही कैम्प लगाकर अलग-अलग घरेलू कनेक्शन का भी इरादा जता दिया है। इसके अलावा डिग्गी कनेक्शन लगातार पांच साल से रखा है, उसको सामान्य में परिवर्तन करना, हर वर्ग के लिए यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार के बजट की हमेशा प्रशंसा होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण, यह विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां के लोग वनों में रहते हैं और क्षेत्र आधे से ज्यादा वन में हैं। चाहे वन में गार्ड का काम हो, चाहे फोरेस्ट का काम हो या कोई लेबर का काम हो, इसके अन्दर नियम में संशोधन करके आदरणीय हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने बजट में लिया है कि जो वहां के रहवासी हैं, उनको नौकरी के लिए विशेष वरीयता दी जाएगी, इसके लिए भी माननीय मंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्योग में युवा उद्यामियों को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। इस हेतु 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया है, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है।

खनन क्षेत्र के अन्दर श्रमिकों के स्वास्थ्य और क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव के लिए जो 150 करोड़ रुपये दिये गये हैं, मैं माननीय, निवेदन करना चाहता हूं कि खनन क्षेत्र में हमेशा सड़कें टूटी-फूटी रहती हैं, वहां मजदूरों के आवागमन में बहुत तकलीफ रहती है। मजदूरों को अच्छी तरह से वहां पर सुख-सुविधाएं नहीं मिलती हैं, पानी नहीं पहुंचता है। खनन क्षेत्र हमारे प्रदेश को अच्छी इनकम देता है, उसके लिए 150 करोड़ रुपये के विकास के काम लिये हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन एक धंधा है विशेषकर जैसलमेर में। प्रधान मंत्रीजी ने खुद सोचा था कि बड़े पशुओं का किसी भी प्रकार से बीमा होना चाहिए। उसमें कुछ विसंगतियां थीं उन सबको दूर करते हुए पशुओं में चाहे वह बड़ा हो, चाहे दूध देने वाला हो, बीमा योजना लागू की, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय, पूर्व में फसल बीमा में बहुत सारी विसंगतियां थीं। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, इसमें सरकार को दी जाने वाले प्रीमियम राशि को बढ़ाकर 676 करोड़ 37 लाख प्रस्तावित किया है, इससे किसानों को पुनर्भरण होगा। किसानों को पर्याप्त उर्वरक और यूरिया लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके साथ ही माननीय

(श्री छोटू सिंह)

मुख्य मंत्री साहिबा ने यूरिया, डी.ए.पी. और जिप्सम के बड़े अग्रिम भंडार की घोषणा की है, उससे आम किसान को भटकना नहीं पड़ेगा और लेने के लिए सुगमता होगी।

आदरणीय, सिंचाई में बूंद-बूंद स्प्रिंकलर के लिए अनुदान की व्यवस्था में लघु और सीमांत कृषक के लिए 70 परसेंट की मांग रखी गयी है। अन्य के लिये 50 परसेंट अनुदान प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव भी अनुकरणीय है। जनजाति क्षेत्र और विशेषकर जैसलमेर का क्षेत्र, यहां खरीफ में हमेशा देखते हैं कि इंगलिश खाद डालते हैं। इस बजट के अन्दर खेती को बढ़ावा देने के लिये विशेष योजना बनाकर पायलट बेसिस पर कार्य प्रारम्भ करने का सोच किया है, वह भी स्वागत योग्य है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में दूध देने वाले पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें बी पी एल, एस सी और एस टी के लिये 75 प्रतिशत अनुदान और अन्य के लिये 50 प्रतिशत अनुदान की जो घोषणा की है, वह भी स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देता हूं आपदा मंत्री को। आज से एक साल पूर्व बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ओलावृष्टि भी हुई थी। गांव की बात करते हैं तो दो लाख गाएं उस समय बचीं। आज चारों तरफ जैसलमेर में हरियाली है, खूब सारा घास है। लेकिन उस समय नहीं था। राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने पूरे प्रयत्न के साथ दो लाख गायों को बचाया। दूसरी बार बरसात इतनी तेज हुई कि ओलावृष्टि हुई, उसमें भी काफी लोगों का नुकसान हुआ। उसके लिए आपदा राहत मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 123 करोड़ रुपये की घोषणा की और रुपये घर-घर दिलवाये, हर खाते में दिलवाये, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचित क्षेत्र से भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिये भी योजना बनायी है कि बच्ची जन्मते ही बारहवीं कक्षा तक पहुंचेगी तब तक उसको 50 हजार का विशेष लाभ मिलेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

चिकित्सा के अन्दर भी भामाशाह योजना बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना है। कोई भी गृहिणी पहले रवाना होती थी तो सोचती थी कि पाकेट में पैसा है या नहीं है। लेकिन आज एक कार्ड लेकर चलती है। हास्पिटल जाने के लिये

(श्री छोटू सिंह)

अब किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। ये जो सुविधाएं दी हैं, इनके लिये मैं माननीय मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही, जैसलमेर के अन्दर जो स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं-सुल्ताना, चेलापुर और भैंसड़ा, इनके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि दुर्गम स्थल, सीमावर्ती क्षेत्र में आपने इस प्रकार से पी एच सी की घोषणा की। इसके लिये जैसलमेर की जनता की ओर से, हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

साथ ही जो 700 एम बी बी एस सीटें थीं, साढ़े 300 और बढ़ाईं। इससे जो डाक्टर की समस्या प्रदेश के अन्दर है, वह भी मिटेगी। इसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

बहुत कुछ बोलना है, लेकिन फिर भी रह गया, घंटी आपकी बज गयी। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की कुछ विशेष समस्याएं हैं। सड़क के मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क आप दौसा जिले को भी देते हो जिसका क्षेत्रफल इतना-सा है और एक जैसलमेर जिले को देते हो जो कि एक प्रदेश के बराबर है। मैं चाहता हूं कि जो भी दुर्गम, सीमावर्ती क्षेत्र है, उसका बजट दायरा क्षेत्रफल से बढ़ाया जाए। जोधपुर से, जैसलमेर से या पूरे राजस्थान से कोई तनोट माता के दर्शन करना चाहता है और पर्यटक के हिसाब से तनोट से वह पुन: सम जाना चाहता है तो तनोट से सम जाने वालों को वापस जैसलमेर आना पड़ता है, जबकि जैसलमेर न आकर रामगढ़ से सीधा मार्ग है जिसकी दूरी केवल 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर के लिये 100 किलोमीटर का फासला तय न करना पड़े, इसके लिए यदि रोड बना दी जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दर्शनार्थियों को भी लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि यह रोड ली जाए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श ग्राम पंचायत के लिये मैंने एम एल ए कोटे से एक बडोड़ा गांव लिया है। जैसलमेर में सबसे बड़ा गांव है, शहीदों का गांव है। बहुत सारे पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक भी हैं, मैंने भी उस हिसाब से लिया है। लेकिन यह इतना बड़ा गांव, जैसलमेर जिले में सबसे बड़ा है, लेकिन वहां भाग्य ऐसा है कि केवल तीन मीटर की रोड है, वह भी बाबा आदम के जमाने की। मैं चाहता हूं, वह 15 नम्बर हाइवे से निकलती है, वह कम से कम छह मीटर की बनायी जाए। ऐसा कोई ज्यादा फासला नहीं है, सात किलोमीटर की रोड बन जाए तो बड़ोडा-मेरा आदर्श गांव और जैसलमेर का सबसे बड़ा गांव रोड से जुड़ता है।

(श्री छोटू सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय, पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी आये नहीं हैं, मैं आदरणीय राठौड़ साहब से ही निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री होने के नाते आप इन दो चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें तो जैसलमेर की जनता की ओर से बहुत-बहुत दुआएं मिलेंगी।

श्री उपाध्यक्षः आदरणीय सदस्य, एक बार आसन से भी निवेदन करके देखो।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। पेयजल के मामले में जैसलमेर एक अनूठा जिला है जहां से नागौर पानी जाता है, जहां से बाड़मेर पानी जाता है, जहां से जोधपुर जाता है, लेकिन जैसलमेर की जनता, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पी रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारी योजनाओं में मिला है, नहर की एस एम जी 105 आर.डी. से न्यारवाल बार्डर पर पानी पहुंच सकता है, लेकिन कोई बड़ी पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं है। 60 गांवों को पेयजल का पानी मिल सकता है। सर्वे भी चल रहा है। इसकी वित्तीय स्वीकृति, आदरणीय, इस आने वाले सप्लीमेंट्री बजट में यदि ली जाए तो, आदरणीय, यह हो सकता है।

बहुत कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आपकी घंटी बार-बार बज रही है। मौके पर और बोलेंगे। सम्पूर्ण बजट में जनता पर कम से कम भार पड़े एवं नई-नई परिसम्पत्तियों का प्रभावी तरीके से निर्माण हो, इस हेतु सरकार द्वारा दूरगामी एवं नीतिगत फैसले लिये गये हैं जिसके लिए सरकार एवं उनके मुखिया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः श्री समारामजी।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को जो बजट भाषण है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को चर्चा करने के लिये रूम दिये हुए हैं। पांच-पांच मंत्री एक साथ चर्चा कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छा नहीं लग रहा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: वह आसन की अनुमति से कुछ चर्चा कर रहे हैं।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू और पूरे जिले भर के लिये मैं 2003-04 से प्रयासरत था, यह सपना था कि बत्तीसा नाला बन जाए तो पूरे जिले में पानी की समस्या मिट जाए। आम किसान, आम जनता और पूरे जिले के लिये जो बत्तीसा नाले की घोषणा की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया जी को, सिंचाई मंत्री डा. रामप्रताप जी को, इरिगेशन मंत्री और किरण माहेश्वरी जी को कि उन्होंने इस बात को सोचा। प्रतिपक्ष वाले कहते हैं कि मंत्रियों के सामने वह मनमानी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर मांगते हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं था। 213 करोड़ की लागत से यह घोषणा हुई, मैं पूरे जिले की जनता और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं कहना चाहूंगा, प्रतिपक्ष वाले कहते हैं कि क्या दिया, वास्तव में समीक्षा करें। सबके पास में बजट की किताब आती है, पहले भी आयी थी। मैं देखता हूं कि पूर्व में हमारी सरकार 2003-04 में जब थी, उस समय के भी अगर आंकड़े देखे जाएं तो कई गुणा अधिक है। पूरे पांच साल पूर्व सरकार ने यहां पर केवल टेबिल बजायी है, इसके सिवाय कुछ नहीं दिया है। मैं बधाई दूंगा यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को। मैं 2003 में भी विधान सभा का सदस्य रहा था, हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री उस समय में राजेन्द्र जी राठौड़ थे, वे आबू रोड पधारे थे। मैं उनको याद दिलाता हूं, आपको याद दिलाता हूं। रजवाड़ा ब्रिज था आबू रोड के अन्दर, कई वर्षों से इधर भी पुलिस रहती थी, उधर भी पुलिस रहती थी, वह रजवाड़ा ब्रिज इतना सकड़ा था कि उस पर आवागमन में दिक्कत थी। इन्होंने हमारी आवाज को सुना और रजवाड़ा ब्रिज पांच करोड़ का स्वीकृत किया, बिना टोल लिये उसको पूरा बनाया। मैंने मंत्रीजी को कहा कि हमारे बत्तीसा नाला पर इतने पुल हैं, वहां एक घोषणा की जाए तो अति-उत्तम रहेगा। हमारी आदिवासी महिलाएं डिलीवरी में मरती हैं। तो मंत्रीजी ने उस समय फटाक से एक घोषणा की और पांच पुल बन गये। बत्तीसा नाला जिसको कहते हैं, बत्तीस बार जो नदी कटे, उसको बत्तीसा नाला कहते हैं। बिना वहां देखे, बिना सर्वे किये हुए इन्होंने उसकी घोषणा की। फिर कांग्रेस सरकार आयी। एक अध्यापक था उसकी पांच दिन नदी में लाश गिरी, नहीं मिली। मेरी बिरादरी की एस.टी. की कांग्रेस की सदस्य थी उसने, हमारे सारे आदिवासियों ने धरना दिया, उन्होंने एक पुल की घोषणा करने का बोला लेकिन एक पत्थर भी नहीं रख सके। एक पुल तो क्या एक पत्थर भी

(श्री समाराम गरासिया)

नहीं रख सके, ऐसी सरकार, और कहते हैं गरीबों की सरकार। ये हमेशा चुनाव में भाषणों में वादा देते हैं, झूठे वादे करते हैं। जैसे कहते हैं कि हाथ हमेशा गरीब के साथ, लेकिन फिर भूल जाते हैं। हाथ हमेशा गरीब के साथ कहने वाले चुनावों के बाद में जीत जाते हैं तो फिर बाद में कभी कहते हैं, हाथ हमेशा अमीर के साथ। यह सपना होता है। हाथ हमेशा भ्रष्टाचार के साथ में रहता है, हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ में रहता है। यह इनका सपना है। मैं 2003-04 में भी देख रहा हूं, पूर्व में भी मैंने बैठे देखा, मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी, इस प्रकार का ऐतिहासिक काम हुआ।

हमारे गृह मंत्री गुलाबचन्द जी कटारिया जी हैं, इनको मैं बहुत-बहुत बधाई दूंगा। हमारे पिछले महीने एक घटना हुई थी, गोली लगी थी असामाजिक तत्व और पुलिस वालों की भिड़ंत में। असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे गरासिया को गोली लगी थी। उस समय मैंने सात बजे मंत्री महोदय को फोन किया कि, मंत्री महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गरीब को गोली लगी है असामाजिक तत्व और पुलिस की मुठभेड़ में। तो उन्होंने दस मिनट के अन्दर मुझे जवाब दिया कि साढ़े सात लाख रुपये गरीब को सहायता दी जाएगी। मैं बधाई देता हूं, पहली बार सिरोही जिले में इस प्रकार की सहायता राशि मिली, धन्यवाद देता हूं। वास्तव में ऐसा लोग भी कहते हैं कि आपकी सरकार में हमने कभी ऐसा देखा नहीं।

विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, हमारे विद्युत लाइन से दो मौतें हुई थीं, उसमें भी तुरन्त प्रभाव से पांच-पांच लाख रुपये। बाकी कांग्रेस सरकार में हमने देखा है, कागजों में रह जाता है, बेचारा गरीब भटकता रहता है। उसकी कोई किसी को पड़ी नहीं, सिर्फ लालीपाप देकर अपना चुनाव कैसे भी करके ले लेते हैं।

मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को। इन्होंने और सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने गौरव पथ देकर हर पंचायतों का इस प्रकार का काम दिया है। मैं समझता हूं, इस बात से लोगों को यह लगता है कि वास्तव में कोई सरकार आयी है। नहीं तो पूर्व सरकार में क्या था? 2003-04 की फोर लेन को देखो और 2009 और 13 के बीच की सरकार का देखो। हाई-वे जयपुर से हमारे सिरोही की ओर जाता है, इसको देखो। पालड़ी एम पर कई प्रकार के धरने हुए हैं, सुरंग को देखो सिरोही वाली को। न तो कोई फर्म बनाये हैं न कोई किये हैं। और यह उदयपुर वाली दो सुरंग हैं गोगुंदा साइड की, उस सुरंग को जाकर देखो। यह सत्यता आपको साबित होगी कि वास्तव में सुरंग किस सरकार के समय में बनी। इसमें भ्रष्टाचार सामने दिखाई देता है कि किस सरकार ने भ्रष्टाचार किया।

(श्री समाराम गरासिया)

टोल नाके बंद किये। वास्तव में रोड पर कई एक्सीडेंट होते हैं। वो टोल लेते हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, टूटी-फूटी सड़कें। 2004-05 के अन्दर बनी हुई सड़क देखो और यह सड़क जो गयी है इस सड़क की तुलना करो। वास्तव में भ्रष्टाचार कहां हुआ, यह जीता जागता उदाहरण आपके सामने है।

शिक्षा विभाग में देखो। अपन शिक्षा विभाग में देखें तो पहले आठवीं पास पढ़ाये। अपनी सरकार आयी, मैं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदय जी को धन्यवाद दूंगा कि यह क्वालिटी है स्कूल में कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, किस प्रकार की गुणवत्ता दी जाए। अब सरकारी स्कूल में संख्या की बढ़ोतरी हुई है। नयी सरकार वसुन्धरा राजे जी ने बनायी है इसमें गुणवत्ता आयी है। लोग कहते हैं कि वास्तव में प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा।

मेरी एक ही मांग है, सारी मांगें हमारी सरकार में पूरी हुई हैं, लेकिन अगर एक सरकारी कालेज हो। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र और तहसील मुख्यालय पर मेरी एक विशेष मांग है। बहुत-बहुत बधाई देता हूं हमारी सरकार को और सभी मंत्रीगण को कि वे वास्तव में जनता के प्रति संवेदनशील हैं।

भाषणों में तो सब कुछ कहते हैं वाहवाही लेने के लिए कि हमने वो किया, वो किया। एक सपना है यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का कि अपना प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो। यह वास्तव में कांग्रेस मुक्त होगा। भारत मुक्त कांग्रेस तो हो गया लेकिन यह प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त जरूर होगा और यह सपना साकार होगा, जनता कह रही है।

जिस प्रकार से पूर्व सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वास्तव मैई गडेड़ो मतीरो ही हो कोई।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): पूर्व मुख्य मंत्री महोदय हमारे एस.टी. क्षेत्र के अन्दर शहीद स्मारक बनाने के लिए आये थे, मैंने सोचा कि अब की बार कोई न कोई नया काम करेंगे। नरेगा के सारे मजदूरों को इकट्ठा किया। भोली है जनता, आदिवासी जनता आ गयी किसी के कहने से कि भई मुख्य मंत्री आये हैं, कोई देकर जाएंगे। लेकिन वहां एक शिला लगायी गयी शहीद स्मारक। जिस प्रकार अंग्रेजों के समय में गोली खायी थी, वह शहीद स्मारक कोरा पत्थर का पत्थर साबित हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया जी को और जनजाति मंत्री नन्दलाल मीणा जी को कि जहां उन्होंने शिला लगायी थी वहां जनजाति आवासीय बालिका छात्रावास 3

(श्री समाराम गरासिया)

करोड़ 29 लाख का भूमि पूजन हुआ और वह जल्द ही बनने के लिए तैयार है। इस तरह से हमारी सरकार शिला लगाने पर विश्वास नहीं कर काम करके दिखाती है। पत्थरों पर नाम कोरे पत्थर के पत्थर रह जाते हैं लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम पर विश्वास रखती है। राष्ट्रवादी, और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये भी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन कांग्रेसी अपने आप को तुष्टीकरण के हिसाब से समझते हैं, खाली वोट लेते हैं इसके अलावा और कोई नाम नहीं। अपन कहते हैं, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं और कभी भी अपन जाकर देखते हैं किसी आफिस के अन्दर कि भारतीय जनता पार्टी वाले सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन इनका एक ही मकसद है वोट लेना। कभी अपन आफिस में जाकर यह देख नहीं सकते कि रामचन्द्र जी की तस्वीर क्या होती है, ओम का बिल्ला क्या होता है। यह अपने आप में कभी इन्होंने महसूस नहीं किया होगा। अपन समझते हैं कि अपने-अपने धर्म को मानने वाले लोग हर धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये एक ही मात्र धर्म समझते हैं, अपना तो बस तुष्टीकरण।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकारें आती हैं, असामाजिक तत्व फैलते हैं। लेकिन जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी आयी है वहां-वहां असामाजिक तत्व खत्म हुए हैं। मैं गृह मंत्रीजी को बधाई देता हूं। कई वर्षों पहले बहुत सारी घटनाएं होती थीं, लेकिन पांच साल में जितनी घटनाएं गिनायी जाएं तो अपन मान नहीं सकते। हमारे आदिवासी बैल्ट के अन्दर भी आपने कुछ कंट्रोल किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं, इस प्रकार का इन्होंने सपना साकार किया।

अब अंत में, जिस प्रकार से आपने यह बजट दिया है, मैं यशस्वी मुख्य मंत्री का और पूरे मंत्रीगण का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रेम चन्द बैरवा।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बजट 2016 और 2017 के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हुआ उनकी

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। महोदय, यह बजट राजस्थान प्रदेश की आर्थिक प्रगति व विकास को प्रदर्शित करता है जो आधुनिक व प्रगतिशील राजस्थान की आधारशिला को मजबूती प्रदान करेगा।

इस बजट में आम जन की भावना को समझते हुए बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह राजस्थान के उत्थान, विकास तथा राजस्थान को हिन्दुस्तान के राज्यों में अग्रणी बनाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है, उनका विजन है। राजस्थान की अवाम के लिए 'सब जन विकास सब जन उत्थान' के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है।

महोदय, राजस्थान की जनता आज भी आदरणीय वसुन्धरा जी की पूर्ववर्ती सरकार को याद करती है क्योंकि गत कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे-समझे कई घोषणाएं कर राजस्थान सरकार को कर्ज में डुबो दिया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने दो साल के सुशासन में कर्ज से उबारते हुए प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, महिला, व्यापारी, श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने वाला बजट पेश कर अपना विजन प्रस्तुत किया है।

महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों के तहत ही राज्य की अर्थव्यवस्था का विश्व में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना है। देशी ही नहीं विदेशी कंपनियों ने भी सकारात्मक रूख अपनाकर सरकार के साथ नवम्बर, 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान में कुल 3 लाख 21 हजार करोड़ निवेश के 295 एमओयू तथा उसके 3 माह बाद 531 करोड़ रुपये के 51 एमओयू किये। इससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति तो होगी ही, साथ ही युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा।

महोदय, गत वर्ष पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया था, इन पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों में सशक्त बनाने व ग्राम पंचायतों के विकास के लिए करीब 15,378 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना, मुक्ति धाम विकास योजना व आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण सहित 7 नई योजनाओं की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में अग्नि शमन वाहन योजना प्रारम्भ की गयी है तथा पंचायतों में ई-पंचायत लागू कर पंचायत की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

जो प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर राजस्थान के गांवों में रहने वाले गरीब किसान व मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने की ओर ध्यान दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए करीब 5 हजार स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे उन बच्चों को तो लाभ मिलेगा ही, सबसे ज्यादा लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जो दसवीं के बाद अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देती थीं। आज वे अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय नहीं मिलने पर शहरी क्षेत्र में अध्ययन हेतु ट्रांसफर वाउचर का लाभ भी दिया जाएगा।

शिक्षा के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच की बात करें तो उन्होंने गत पंचायती राज चुनावों में, 2015 में, शिक्षा को अनिवार्य कर एक दूरगामी सोच का परिचय दिया था जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य को शिक्षित जन-प्रतिनिधि प्राप्त हुए हैं जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को गांव एवं ढाणी के हर वर्ग तक पहुंचाते हुए प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने और प्राथमिकता से इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने इस बजट भाषण में राज्य की स्कूल शिक्षा के लिए 23,127 करोड़ रुपये दिये हैं। जयपुर जिले के 13 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कृषि या कामर्स संकाय खोलने की घोषणा की है तथा 108 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि एक प्रशंसनीय कदम है, इसकी मैं सराहना करता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 28 स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है जिससे आने वाले समय में मेरे क्षेत्र के बालक और बालिकाएं हमारे राज्य और देश को अपनी प्रतिभा से रोशन करेंगे तथा देश के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऐसी सोच एक मात्र हमारी मुख्य मंत्रीजी की ही हो सकती है जो प्रदेश के हर वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं।

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

महोदय, प्रदेश के आम जन की मांग व चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं विस्तार को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री और चिकित्सा मंत्रीजी द्वारा प्रदेश में 5 नये प्राथमिक केन्द्र व 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त इस बजट में चिकित्सा सेवाओं के लिए 8,742 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार तो होगा ही, साथ ही प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

मेडिकल विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज में 350 सीटों का इजाफा किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों, शिक्षकों व अस्पतालों के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर चिकित्सा क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है।

महोदय, राज्य के गांवों को शहर जैसी सुविधा के लिए गांवों में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा ग्रामीण गौरव पथ व मिसिंग लिंकों का जाल बिछाकर गांवों को सुन्दर व विकसित बनाया गया है जिससे आज गांवों में खुशहाली का माहौल है। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग देना हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य मंत्रीजी द्वारा राज्य में इसी साल 8,803 किलोमीटर सड़क, 29 रेलवे ओवर ब्रिज एवं 2 अंडर रेलवे ब्रिज निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48- दूदू-सांभर-नरेना-कुचामन सिटी होते हुए छोटी खाटू तक के निर्माण की घोषणा इस बजट में की है, मैं इसका स्वागत करता हूं तथा समस्त विधान सभावासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन यह मेरी आधी रोड है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट दूदू से चाकसू, फागी एवं लालसोट रह गया है। 60 साल पहले यह स्टेट हाई-वे थी और आज भी केवल 3 मीटर रोड ही बनी हुई है। यह 21 किलोमीटर की रोड जो बची हुई है, 7 मीटर चौड़ाई कर इसका सुदृढ़ीकरण कर दिया जाए। यह रोड फागी, चाकसू नेशनल हाई-वे नम्बर 8 और नेशनल हाई-वे 12 नम्बर को जोड़ती है। इससे इन गांवों को विशेष लाभ मिलेगा। मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इसके आधे पार्ट की भी स्वीकृति कराएं एवं आगे जाकर इसकी चौड़ाई 7 मीटर कराकर इसका सुदृढ़ीकरण कराएं।

महोदय, आज विद्युत के क्षेत्र में इतना बदलाव है। पूर्ववर्ती सरकार ने

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

बिजली बोर्ड को घाटे में डाल दिया था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में राज्य को विद्युत घाटे से उबारते हुए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य के किसानों को 40 हजार नये कनेक्शन देने तथा राज्य के करीब-करीब 8 लाख ग्रामीण आवासों के लिए नयी योजनाओं के तहत बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा कर हर घर को रोशन करने का कार्य इस बजट में लिया गया है।

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रदेश में कम वर्षा होने तथा गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारम्भ किया है। मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के लिए 440 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। प्रदेश की आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की जनता के लिए अपने बजट भाषण में पेयजल प्रोजैक्ट हेतु 2,950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 24 जिलों में 3,461 करोड़ की लागत से वाटर सैक्टर के लिए उन्नयन परियोजना की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में मेरे क्षेत्र में वर्षों से लम्बित चल रही परियोजना बीसलपुर-फुलेरा पेयजल परियोजना तथा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, तहसील फागी स्वीकृत की है।

इस बजट भाषण में मेरे क्षेत्र को दी गयी सौगातों के लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.29 बजे शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के सरकारी मंदिरों में चढ़ावे से प्राप्त राशि

137. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने मन्दिर सरकार के अधीन हैं एवं उक्त मंदिरों में विगत 2 वर्षों में कितना चढ़ावा प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में प्राप्त भेंट राशि का क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निम्न मंदिर देवस्थान विभाग के अधीनस्थ आते हैं:-

क्र सं.	श्रेणी	संख्या
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी	365
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	188
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	342
	योग	**895**

इन मंदिरों में विगत दो वर्षों में प्राप्त चढ़ावे का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिरों में प्राप्त चढ़ावा सम्बन्धित सुपुर्दगार पुजारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(2) विगत दो वर्षों में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों से प्राप्त भेंट राशि राजकीय आय मद 0250 में जमा कराई जाती है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट अनुसार उपयोग की जाती है।

राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों से प्राप्त आय को विभाग के पी.डी. खाते में जमा कराई जाती है। उक्त राशि का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट अनुसार राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों में भोगराग, कार्यरत कर्मचारीगण के वेतन भुगतान, मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत में उपयोग किया जाता है।

चढ़ावे में प्राप्त जेवर इन्वेंट्री में दर्ज कर मंदिरों में सिंगल लाक/ट्रेजरी में जमा है जिनको मंदिरों में उत्सवों/त्यौहारों पर उपयोग में लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाएं

138. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में श्रमिकों के हितार्थ क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? प्रत्येक योजना में लाभ पाने हेतु क्या-क्या नियम एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए दिये जाने का प्रावधान है? योजनावार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन एवं पाली जिले में उक्त योजनाओं में किन-किन व्यक्तियों ने पंजीयन कराया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त मण्डल द्वारा विगत 2 वर्षों में मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के हितार्थ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पाने हेतु पात्रता व शर्तों, देय राशि व कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"क" प्रस्तुत है।

(2) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन एवं पाली जिले में मण्डल की योजनाओं में कुल 794 हिताधिकारियों ने आवेदन प्रस्तुत किये।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। विगत दो वर्षों में मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में मण्डल की योजनाओं से 5 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में नान पेचेबल सड़कों का निर्माण

139. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की नान पेचेबल

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
सड़कों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा संधारित की जाने वाली कुल 73.30 किमी लम्बाई की 25 सड़कें हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1)

इनमें से 12.13 किमी लम्बाई की 7 नान पेचेबल शहरी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। (संलग्न परिशिष्ट-2)

(2) उक्त नान पेचबल शहरी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिक

140. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना अन्तर्गत कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं? उनको देय वेतन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत कितने नये कार्मिक किस-किस पद पर नियुक्त किये गये हैं? उनको देय वेतन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में मां-बाड़ी योजना व क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में तीन कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

1. परियोजना अधिकारी मानदेय रु. 39635 प्रतिमाह

2. सहायक परियोजना अधिकारी मानदेय रु. 28270 प्रतिमाह

3. वाहन चालक मानदेय रु. 22014 प्रतिमाह

उपरोक्त के अतिरिक्त 6 कॉर्डिनेटर संविदा पर कार्यरत हैं जिन्हें मानदेय रु. 7000 प्रतिमाह मिलता है। इन्हे अतिरिक्त कार्य अनुसार कुछ भत्ता भी दिया जाता है। ये स्वच्छ परियोजना के स्थायी कर्मचारी नहीं है।

इनके अतिरिक्त मां-बाडी योजना व जनश्री बीमा योजना में 10 सुपरवाइजर प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से लगे हुए हैं।

(2) सत्र 2013-14 व सत्र 2014-15 में कोई भी कर्मचारी नियुक्त नही किया गया। परियोजना के कार्यों के वृद्धि/कमी होने पर आवश्यकता अनुसार प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारियों का लगना व हटना होता है ।

बहरोड़ में किसानों को वितरित बीज

141. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किसानों को बीज किट किस आधार पर बांटे जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु कौन-कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में कुल कितना बीज, कितने किसानों को किस दर पर बांटा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में बीज की गुणवत्ता व अंकुरित नहीं होने के सम्बन्ध में गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों, अन्त्योदय परिवारों एवं आस्थाधारी कार्ड वाले कृषकों को नि:शुल्क मिनिकिट वितरण किया जाता है। मिनिकिट वितरण के दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट (A), (B) पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त बीजों की गुणवत्ता की जांच हेतु बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 के तहत अधिसूचित बीज निरीक्षकों द्वारा विधिवत नियमानुसार बीज नमूना लेकर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाता है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीजों की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्द्रता, अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता तथा कीट एवं पौध व्याधि सम्बन्धी जांच भारत सरकार द्वारा प्रमाणित पुस्तक "हैण्ड बुक आफ सीड्स टेस्टिंग" में वर्णित प्रक्रिया एवं विधि से नियमानुसार की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्ष में कुल 744.30 क्विंटल बीज 9735 किसानों को नि:शुल्क तथा 499.50 क्विंटल बीज 865 कृषकों को अनुदान पर बांटा गया है। विवरण परिशिष्ट-II पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में बीज की गुणवत्ता व अंकुरित नहीं होने के सम्बन्ध में गत दो वर्ष में जिलेवार प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-III पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में उद्योगों को स्थापित करने की योजना

142. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर एवं सराड़ा तथा सेमारी क्षेत्र में किसी तरह के उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से लोगों को अपने परिवार के पालन-पोषण हेतु गुजरात, महाराष्ट्र अथवा विदेशों में रोजगार हेतु पलायन करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है। उद्यमियों द्वारा अपने लाभ हानि के आधार पर उद्योग स्थापित किये जाते हैं। सम्पूर्ण राज्य में (जिसमें विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर एवं सराड़ा तथा सेमारी क्षेत्र स्वत: ही शामिल है) उद्योग स्थापना हेतु सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में उद्यम सहयोगी नीतियों के माध्यम से

(उद्योग मंत्री)

सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है, ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सके एवं राज्य के बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर एवं सराड़ा तथा सेमारी में 445 इकाइयां पंजीकृत हैं जिनमें 1197 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है।

जनता जल योजना को पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरित करने की योजना

143. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जनता जल योजना को सरकार द्वारा पंचायतीराज विभाग को सुपुर्द करने के कारण उक्त योजना बन्द है तथा इस मद में राशि व्यय करने के पश्चात् भी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को लाभान्वित करने के लिए उक्त योजना को पंचायती राज विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जनता जल योजना पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरण के कारण बन्द नहीं है। कतिपय योजनायें जल स्रोत सूख जाने एवं अन्य तकनीकी कारणों से बन्द हैं।

ग्राम पंचायतों का प्राप्त अनुदान राशि को प्रथम चार्ज के रूप में पेयजल व्यवस्था पर व्यय करने का प्रावधान है।

साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के क्रम में यह उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को दिया जाना तर्कसंगत है।

पंचायती राज संस्थायें जनप्रतिनिधियों एवं जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुडी हुई स्थानीय स्तर की संस्थायें हैं, जो जनता जल योजनाओं का संचालन सहजता एवं शीघ्रता से कर सकती हैं।

जनता जल योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त संसाधन एवं कार्मिक भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अतः जनता जल योजनाओं का हस्तान्तरण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

अलवर जिले में शुद्ध जल हेतु डी-फ्लोराइड यूनिट की स्थापना

144. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में जिला अलवर में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल की जांच करवाई गयी थी? यदि हां, तो कब-कब एवं किस संस्था द्वारा? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कहां-कहां पर फ्लोराइड की कितनी-कितनी मात्रा पाई गयी एवं इसके निदान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस हेतु गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक योगदान दिया गया था? यदि हां, तो उक्त राशि में से कितनी राशि जिला अलवर में शुद्ध पेयजल हेतु कहां-कहां पर व्यय की गयी? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में पंचायत स्तर पर पेयजल की शुद्धता की जांच कर डी-फ्लोराइड यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला अलवर में गत 5 वर्षों में विभागीय प्रयोगाशाला द्वारा 7 शहरी जल योजनाओं के 3064 जल नमूनों की जांच की गई।

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रम के तहत विभागीय प्रयोगशाला द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में विभाग द्वारा तथा वर्ष 2014-15 में ब्लाक स्तरीय प्रयोगशाला (मैसर्स एल-टानिक्स, जयपुर) एवं विभाग द्वारा ग्राम/ढाणियों के कुल 57395 जल नमूनों की जांच की गई है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 60,459 जल नमूनों का तहसीलवार एवं वर्षवार वांछित पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्त जांच में अलवर जिले के 7 शहर/कस्बों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में पाई गई है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत उक्तानुसार विश्लेषित किये गये कुल 57395 जल नमूनों में से 517 ग्राम/ढाणियों के 687 जल नमूनों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई है।

फ्लोराइड प्रभावित उक्त 517 ग्राम/ढाणियों में से 71 ग्राम/ढाणियों को दूरस्थ एवं 372 ग्राम/ढाणियों को स्थानीय अन्य सही गुणवत्ता के जल स्रोत से निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.ग्राम/ढाणियों की योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, 54 ग्राम/ढाणियों हेतु 45 आर.ओ. संयंत्र एवं एक ढाणी हेतु सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप मय डि-फ्लोराइड यूनिट के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं । शेष 16 ग्राम/ढाणियों हेतु समुचित जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इनकी योजनाएं बनाई जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति पर विचार किया जायेगा । विवरण संलग्न परिशिष्ट-स में निहित है।

(3) जी हां। जिला अलवर में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि में फ्लोराइड की आधिक्य मात्रा से प्रभावित 22 ग्राम/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 924.31 लाख (केन्द्र एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: रुपये 463.66 लाख एवं 460.65 लाख) के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई । इस स्वीकृति के विरुद्ध रुपये 654.44 लाख (केन्द्रीय एवं राज्यमद में क्रमश: रूपये 327.25 लाख एवं 329.19 लाख) की राशि व्यय की जाकर 21 ग्राम/ढाणियों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है । वर्षवार किये गये व्यय एवं लाभान्वित ग्राम/ढाणियों का संलग्न विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। अलवर जिले में पंचायत स्तर पर ग्राम एवं ढाणियों के जल स्रोतों की सतत प्रक्रिया के तहत रासायनिक जांच जिला प्रयोगशाला द्वारा की जा रही है । जिले में फ्लोराइड प्रभावित एक ढाणी में सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूप मय डि-फ्लोराइड यूनिट के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 14.05 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर निविदा आमंत्रित की जा रही है ।

फ्लोराईड एवं अन्य अशुद्धियों से प्रभावित 141 ग्राम/ढाणियों हेतु 131 आर.ओ. संयंत्र (जिसमें फ्लोराइड प्रभावित उपरोक्त 54 ग्राम/ढाणियों में 45 आर.ओ. संयंत्र स्वीकृत हैं) के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

30.49 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई । इस स्वीकृति के विरुद्ध दिनांक 11.02.2016 को राशि रुपये 20.79 करोड़ के जारी संयुक्त कार्यादेश में अलवर जिले के 35 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण का कार्य सम्मिलित है तथा शेष 96 संयंत्रों के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । सौर ऊर्जा आधारित स्वीकृत एक सिंगल फेज नलकूप एवं 45 आर.ओ. संयंत्रों का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सम्भागीय आयुक्त/कलक्टर कार्यालयों में कार्यरत निजी स्टाफ के स्थानान्तरण की नीति

145. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों एवं जिला कलक्टर्स कार्यालयों में कार्यरत निजी स्टाफ को निश्चित समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरण हेतु कोई पत्र/परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब -कब? आदेशों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला कलक्टर्स कार्यालयों में पदस्थापित निजी स्टाफ को पांच वर्ष से अधिक समय होने के उपरान्त भी स्थानान्तरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिलों से तथा किन-किन कर्मचारियो को? जिलेवार एवं कर्मचारीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभिन्न जिला कलक्टर्स कार्यालयों में पदस्थापित निजी स्टाफ को सरकार के आदेशों के उपरान्त भी नहीं हटाये जाने के क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार जारी किये गये आदेशों की पालना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आदेशों की पालना नहीं करने के लिए किसी को दोषी/जिम्मेदार मानती है? यदि हां, तो किन-किन जिलों के किन-किन अधिकारियों को तथा क्या सरकार उक्त दोषी/जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स कार्यालयों में

(राजस्व राज्य मंत्री)

कार्यरत निजी स्टाफ के निश्चित समयावधि के पश्चात स्थानान्तरण हेतु राज्य स्तर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्तर से जारी किये गये पत्र/परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के जिला कलक्टर्स कार्यालयों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-ख पर सलंग्न है।

(3) विभिन्न जिला कलक्टर्स कार्यालयों में पदस्थापित निजी स्टाफ को हटाये जाने तथा नहीं हटाये जाने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

राज्य स्तर पर जिला कलक्टर्स से प्राप्त सूचना की समीक्षा की जा रही हैं। जिन प्रकरणों में आदेशों की पालना नहीं करवायी गई है उनमें शीघ्र पालना करवायी जावेगी।

(4) जारी निर्देशों की पालना की समीक्षा में यदि बिना किसी विशेष कारण के कार्मिकों को नहीं हटाया जाना पाया गया तो ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार

146. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में जिन 43 एजेन्सियों के साथ जुलाई व अगस्त, 2014 में एम.ओ.यू. किया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एजेन्सियों द्वारा किस-किस जिले में कौन-कौनसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अब तक शुरू किये गये तथा उन कार्यक्रमों के तहत अब तक कितने प्रशिक्षणार्थी को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एजेन्सियों के द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के फलस्वरूप अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त हो गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में जिन 43 एजेन्सियों के साथ जुलाई व अगस्त, 2014 में एम.ओ.यू. किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त एजेन्सियों में से 36 एजेंसियों द्वारा अब तक (31 जनवरी, 2016) तक प्रारम्भ किये गए कौशल प्रशिक्षण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक (31 जनवरी, 2016) कुल 23954 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) उक्त एजेन्सियों द्वारा संप्रेषित सूचना के आधार पर अब तक (31 जनवरी, 2016) तक दिये गये प्रशिक्षण के फलस्वरूप राज्य एवं राज्य के बाहर कुल 8477 प्रशिक्षणार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं।

जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु स्वीकृत राशि

147. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले से गुजरने वाले कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हैं एवं इनकी स्वीकृति कब-कब जारी की गई तथा उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को कौन-कौनसे नंबर दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने स्वीकृत की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु टेण्डर जारी करने की कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब एवं किन-किन मार्गों की व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले से गुजरने वाले स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-709 विस्तार (हरियाणा सीमा से राजगढ़ तक वाया पिलानी) एवं एन.एच.-11 (फतेहपुर-झुन्झुनूं-हरियाणा सीमा तक) हैं। इनकी स्वीकृति भारत सरकार के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गजट अधिसूचना क्रमशः दिनांक 22.02.2012 एवं 06.03.2014 द्वारा जारी की गई है। अधिसूचना की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच.-709 विस्तार पर नवीनीकरण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार ने दिनांक 15.10.2014 को राशि रु. 428.90 लाख की स्वीकृति जारी की है (परिशिष्ट-3) एवं एन.एच.-11 पर कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने इन मार्गों पर कोई स्वीकृति जारी नहीं की है।

(3) जी नहीं, मोर्थ, नई दिल्ली द्वारा दोनों नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-709 विस्तार की हरियाणा सीमा से राजगढ़ तक वाया पिलानी एवं एन.एच.-11 की फतेहपुर-झुन्झुनूं-हरियाणा सीमा तक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने का कार्य स्वीकृत होकर प्रगति पर है। मोर्थ, नई दिल्ली द्वारा डी.पी.आर. रिपोर्ट पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात् ही राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु टेण्डर की कार्यवाही सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा में वनाधिकार कानून के तहत जारी पट्टे

148. श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में वन अधिकार कानून लागू होने की तिथि से अब तक वन अधिकार के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त व कितने लोगों को पट्टे जारी किये गये तथा कितने आवेदकों को पट्टे जारी करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष बचे हुए वनाधिकार पट्टों को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बासंवाड़ा में उक्त अधिनियम लागू होने की तिथि से अब तक (दिनांक 31.01.2016 तक) वनाधिकार प्राप्त करने हेतु कुल 5988 दावे ग्राम सभा में प्रस्तुत हुए। जिसमें से 3576 दावे स्वीकृत कर नियमानुसार वनाधिकार पत्र जारी किये जा चुके है वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कुल 24 दावे लम्बित हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) शेष बचे हुए वनाधिकार दावों पर नियमानुसार कार्यवाही कर पात्र व्यक्तियों को अतिशीघ्र वनाधिकार पत्र जारी कर दिये जावेंगे।

कोटडा (उदयपुर) में गौण मण्डी की स्थापना

149. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय, कोटडा में गौण मण्डी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर से उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ा को गौण मण्डी घोषित कराने हेतु प्रस्ताव दिनांक 18.2.16 प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में अवैध रूप से संचालित टायरों की फैक्ट्रियों पर कार्यवाही

150. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में अवैध रूप से संचालित किन-किन टायरों की फैक्ट्रियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त अवैध रूप से संचालित टायर की फैक्ट्रियों के विरुद्ध जहरीली गैसों के रिसाव व प्रदूषण फैलाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त टायरों की फैक्ट्रियां मूल स्वामी द्वारा संचालित नहीं कर अन्य व्यक्तियों द्वारा संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी कब-कब क्या-क्या जांच की गई और उक्त फैक्ट्रियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अवैध रूप से संचालित उक्त फैक्ट्रियों को बंद करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में टायर पायरोलाइसिस 12 उद्योगों में से 02 उद्योग बंद हो चुके हैं एवं वर्तमान में 10 उद्योग संचालित है। औद्योगिक क्षेत्र बगरू में संचालित टायर पायरोलाइसिस के उद्योग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा जारी की गई सम्मति प्रबंधन के अनुसार संचालित होना होता है। सदस्य सचिव/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र क्रमांक एफ 14 (25 वि.स.)/फरवरी-16 राप्रनिम/योजना/2051 52 दिनांक 03.03.2016 (संलग्नक अ) के अनुसार रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सम्मति प्रबंधन के बिना कोई भी टायर पायरोलाइसिस का उद्योग कार्यरत नहीं है। यद्यपि रीको के इकाई कार्यालय में संधारित रिकार्ड के अनुसार 5 इकाइयों के पास सम्मति प्रबंधन दिनांक 29.02.2016 तक ही प्राप्त थी।

औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की सूची व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक-ब में दी गई है।

(2) जी हां औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार में संचालित इन टायर पायरोलाइसिस उद्योगों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर रीको से सम्बन्धित इकाई कार्यालय द्वारा सम्बन्धित उद्योग/पट्टाशुदा को नोटिस जारी किये गये हैं तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। रीको के सम्बन्धित इकाई कार्यालय द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशानुसार समय-समय पर ऐसी इकाइयों के जल सम्बन्ध विच्छेद किये गये हैं।

शिव व्यापार मण्डल समिति बगरू नगरपालिका बगरू मैसर्स वी.के. प्लास्ट बगरू विस्तार औद्योगिक क्षेत्र तथा मैसर्स उमस क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, बगरू विस्तार औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार-द्वितीय चरण द्वारा ऐसे उद्योगो के विरूद् शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ताओं की सूची संलग्नक-स में दी गई है।

(3) टायर पायरोलाइसिस के 10 उद्योग औद्योगिक क्षेत्र बगरू में किरायेदार उद्यमियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। रीको भू निपटान नियम अधिनियम 1979 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार 8 आबंटियों को अपने पट्टाशुदा परिसर किराये पर देने की स्वीकृति रीको इकाई कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा जारी की गई है। शेष बचे 2 उद्यमियों के द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के कारण किराये पर चलाने की इजाजत जारी

(उद्योग मंत्री)

नहीं की जा सकी। इनके विरुद्ध रीको इकाई कार्यालय द्वारा बिना स्वीकृति के परिसर किराये पर देने पर लीजडीड के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी किये जा चुके हैं। नोटिसों की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी हां। यदि टायर पायरोलाइसिस का उद्योग अवैध रूप से संचालित पाया जाता है तो नियमानुसार बंद करवाया जा सकता है यद्यपि औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण सम्बन्धित जांच एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण का अधिकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का है। अत: उक्त संचालित टायर प्लांट से होने वाले प्रदूषण सम्बन्धी कार्यवाही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा सम्बन्धित अधिनियमों के तहत की जा सकती है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुशंसा पर आबंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही रीको द्वारा की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में जलग्रहण योजनान्तर्गत कराये गए कार्य

151. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जिला अलवर की किस-किस ग्राम पंचायत को जलग्रहण योजनान्तर्गत चयनित किया गया एवं किस-किस ग्राम पंचायत में जलग्रहण समितियों का गठन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत तीन वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने कार्य जलग्रहण योजना के तहत स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों पर वर्षवार कितनी राशि का आबंटन एवं व्यय किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति एवं राशि आबंटन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति और राशि आबंटन में असमानता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जलग्रहण कार्यों में मानदण्डों के अनुसार निर्माण नहीं होने एवं घटिया निर्माण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(6) क्या सरकार द्वारा उक्त सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया

(श्री रामहेत सिंह यादव)

गया था? यदि हां, तो निम्न स्तरीय निर्माण हेतु कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिला अलवर में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जलग्रहण परियोजनाओं का परियोजनावार, ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

गत तीन वर्षों में जिला अलवर में जलग्रहण परियोजनाओं में चयनित ग्राम पंचायतों में जलग्रहण समितियों (उपसमितियों) के गठन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जिला अलवर में गत तीन वर्षों में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत किये गये कार्यो की संख्या, कार्यों हेतु राशि आबंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार की समान मार्गदर्शिका के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली जलग्रहण परियोजनाओं में मरुस्थलीय क्षेत्र हेतु रु. 15000/- प्रति हेक्टेयर एवं गैर मरुस्थलीय क्षेत्र हेतु रु. 12000/- प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। अलवर जिला गैर मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के कारण प्रति हैक्टेयर राशि रु. 12000/- निर्धारित है।

इसी दर के आधार पर ग्राम पंचायतों में आने वाले क्षेत्रफल के अनुपात के आधार पर कार्यों की स्वीकृति एवं राशि आबंटन किया जाता है।

(4) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृति एवं राशि आबंटन में असमानता है, क्योंकि कार्य स्वीकृति और राशि आबंटन ग्राम पंचायत में आने वाले क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाता है।

(5) जी हां। सचिव, जलग्रहण क्षेत्र लुहादेरा, जलग्रहण कमेटी ग्राम पंचायत ईशरौदा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के विरुद्ध ईशरौदा बांध में निर्माण कार्य नहीं कराने की एक शिकायत ग्रामवासी ग्राम ईशरौदा द्वारा लोकायुक्त सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुई है। मूल शिकायत की फोटोप्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(6) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र लुहादेरा, ग्राम पंचायत ईशरौदा, तहसील तिजारा, जिला अलवर में किये गये सभी निर्माण कार्यो का निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग जयपुर के पत्रांक 2151 दिनांक 04.08.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद अलवर को शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जो कि परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद अलवर द्वारा प्रेषित अन्तरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर शिकायत करना पाया गया है, जो कि परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद अलवर द्वारा प्रेषित अन्तिम जांच रिपोर्ट अनुसार ईशरौदा बांध में कराये गये निर्माण कार्य भौतिक रूप से मौके पर पाये गये तथा मौके पर ली गई माप आदि का माप पुस्तिका (एम.बी.) में अंकित मिलान करने पर मिट्टी कार्य की माप में 10-20 प्रतिशत तक अन्तर पाया गया है, जिसका कारण निर्माण कार्य का 2 वर्ष पुराना होना, भूमि का साधारण मिट्टी का होना, वर्षा एवं वायु से मिट्टी का क्षरण होना, साथ ही मिट्टी का सेटलमेन्ट होना भी है। ईशरौदा बांघ के एक तरफ कृषक फसल उत्पादन कर रहे हैं, जिससे प्रतिवर्ष कृषकों द्वारा ट्रैक्टर से बांघ के आधार को काटकर कमजोर कर देते हैं बाघ के दुसरी तरफ भी कृषकों ने 5-10 फीट चौड़ाई में खेतों में जाने का रास्ता बनाया है, जिस कारण गत दो वर्षो में मिट्टी का काफी क्षरण हुआ है। अन्तिम जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद अलवर से प्राप्त अन्तिम जांच रिपोर्ट आयुक्तालय के पत्रांक 2450-51 दिनांक 16.02.2016 द्वारा संयुक्त सचिव-चतुर्थ लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई है, जो कि परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खैरवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति हेतु संचालित योजनाएं

152. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति हेतु उपखण्डवार ग्राम पंचायतों में गत दो वर्षों में जनता जल व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं पनघट योजना स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उक्त योजनाएं किसके द्वारा संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अन्तर्गत 7 जनता जल योजनाओं तथा राज्य मद (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 सिंगल फेज नलकूप मय पी.वी.सी. टैंक (पनघट) के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प से परिवर्तित 4 जनता जल योजनाओं एवं 58 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृत योजनाएं, इनकी वर्तमान स्थिति/प्रगति एवं इनके संचालन के सम्बन्ध में उपखण्डवार वांछित पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त उक्त वित्तीय वर्षों में राज्य मद (ग्रामीण) एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.) के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य योजनाओं/कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी में नवीन राजस्व गांव

153. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011 में 250 की आबादी वाले ग्रामों को नियमानुसार राजस्व ग्राम बनाने की नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी के 250 की आबादी वाले कौन-कौन से ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मान सिंह)

(2) क्या सरकार राजस्व ग्राम घोषित करने की निर्धारित नीति की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजस्व ग्राम घोषित होने वाले गांवों को राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी की तहसील गंगापुरसिटी व वजीरपुर में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 250 से अधिक आबादी वाले ढाणी/मजरे इस प्रकार हैं -

तहसील	मूल राजस्व ग्राम	ढाणी/मजरे का नाम
गंगापुरसिटी	विदरखां	कांकर रेती
	आस्ट्रोली	सोनपुर
वजीरपुर	खेडला	विजयापुरा
	मालपुरा	नवाजीपुरा

उक्त मजरे ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदार से चाहे गये हैं। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिला कलक्टर के प्रस्ताव परीक्षणोंपरांत राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त होने पर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्व ग्राम घोषित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिला कलक्टर के प्रस्ताव परीक्षणोंपरांत राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त होने पर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी के माडा योजना में सम्मिलित गांव

168. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना में कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा माडा योजना में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत 3 वर्षो में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए तथा वर्तमान में कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के द्वारा माडा योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के 105 ग्राम सम्मिलित हैं जिसकी विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा माडा योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा गत 3 वर्षो में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना में स्वीकृत किए गए कार्यो की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों में विकास कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता, योजनान्तर्गत अनुमत होने पर ही कार्यो को स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद (बारां) के आवासीय विद्यालयों को मरम्मत कराने की योजना

169. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित कुमार)

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबद क्षेत्र में कितने आवासीय विद्यालय/छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में संचालित कई आवासीय विद्यालय/छात्रावास मरम्मत करवाये जाने योग्य हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य उक्त क्षेत्र में जनजाति परिवारों के लिए कोई कारगर कार्य योजना बनवाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबद क्षेत्र में कुल 4 आवासीय विद्यालय एवं 24 सहरिया आश्रम छात्रावास संचालित हैं जिनकी स्थानवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) शैक्षणिक संस्थाओं में बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में संचालित मरम्मत करवाये जाने योग्य दस छात्रावासों में मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है, ग्यारह स्थानों पर कार्य प्रगति पर है तथा शेष तीन छात्रावासों के एवं चार आवासीय विद्यालयों के मरम्मत प्रस्ताव तैयार करवाये जा रहे हैं।

(4) बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में जनजाति के परिवारों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी में जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्य

170. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुशील कटारा)

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013 से 2015 तक सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यों की विभागवार सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) आगामी वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं? कार्यवार, विभागवार मय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2015 तक जनजाति विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना, सडकें, सामुदायिक हाल, हैण्डपम्प, आश्रम छात्रावासों का निर्माण पी एण्ड टी योजना के कार्य करवाये गए। विवरण की सूची **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न है।

(2) आगामी वर्ष 2016-17 में योजनाओं में राशि प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता एवं योजनान्तर्गत कार्य अनुमत होने पर कार्य स्वीकृत किए जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौ-पालन को बढ़ावा देने हेतु गाय के दूध की समर्थन मूल्य पर खरीद

171. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गौ संवर्धन एवं गौं पालन को बढ़ावा देने हेतु गाय के दूध को सरकारी स्तर पर सहकारी डेयरी के माध्यम से खरीद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गौपालकों द्वारा गाय के दूध पर 6 रुपये प्रति फैट की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी डेयरी द्वारा खरीदे जाने वाले गाय के दूध पर 6 रुपये प्रति फैट की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सभी सहकारी दुग्ध संघों से सम्बद्ध दुग्ध समितियों पर गाय का दूध क्रय किया जा रहा है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में दुग्ध की मांगापूर्ति, स्थानीय विपणन, प्रतिस्पर्धी डेयरियों की दुग्ध क्रय दर दुग्ध संघ की आर्थिक सक्षमता एवं इससे संघ के लाभ-हानि पर पडने वाले सम्भावित परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए दुग्ध उत्पादकों को यथासम्भव अधिकतम दुग्ध क्रय दर दी जाती है।

बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत सड़कें

172. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी द्वारा कुल कितनी सडकें कहां-कहां कब-कब स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त सड़कों के निर्माण में कितनी राशि व्यय हुई? यदि नहीं, तो अब कितनी सड़कें कहां-कहां बनना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु मण्डी विकास निधि के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 2 सड़कों की स्वीकृति जारी हुई है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) मण्डी विकास निधि द्वारा स्वीकृत उक्त दोनों सडकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर 60.25 लाख रुपये व्यय हुए हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट अ

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में निर्मित सड़कों का ब्यौरा

योजना मण्डी विकास निधि (एम.डी.एफ.)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत		स्वीकृत लम्बाई	व्यय	कार्यपूर्णता की दिनांक
		राशि	दिनांक			
1	एन.एच. 8 से तसिंग रोड के मध्य क्षतिग्रस्त भाग (स्कूल व हनुमान मन्दिर के पास) में सी.सी. सड़क का निर्माण	31.92	14.10.2014	0.160	27.76	04.05.2015
2	ग्राम दहमीकलां में राजेन्द्र मास्टर से दीना लम्बरदार एवं जयसिंह के तिबारे से धर्मचन्द के मकान तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	35.00	22.12.2014	0.700	32.49	02.01.2016
	योग	**66.92**		**0.86**	**60.25**	

सरस घी विक्रय हेतु नवीन डीलरों का चयन

173. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन (RCDF) बड़ी मात्रा में अपने द्वारा उत्पादित घी "सरस" को डीलर्स की मार्फत बाजार में विक्रय करता है? यदि हां, तो फैडरेशन ने गत दो वर्षों में अपने द्वारा उत्पादित कितना सरस घी, कितने डीलर्स की मार्फत बाजार में विक्रय किया?

(2) क्या यह सही है कि फैडरेशन द्वारा उत्पादित वस्तुओं में गत 10 वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत 10 वर्षों में फैडरेशन ने अपने द्वारा उत्पादित सरस घी व अन्य उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु कोई नया डीलर नियुक्त नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या फैडरेशन अब अपने द्वारा उत्पादित सरस घी व अन्य उत्पादनों के विक्रय हेतु नए डीलर नियुक्त करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक व कितने व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने गत दीपावली के अवसर पर अपने यहां स्टाक में जमा करीब 10 हजार मीट्रिक टन सरस घी स्कीम के तहत एक महीने में तय रेट से भी 30 से 35 रुपये प्रति लीटर कम रेट में डीलर्स को विक्रय किया? यदि हां, तो उक्त स्कीम क्या थी? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि आरसीडीएफ अपने एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों द्वारा नियुक्त वितरकों एवं दुग्ध समितियों के माध्यम से सरस घी का विक्रय करता है।

वर्तमान में आरसीडीएफ के द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कुल 109 वितरक नियुक्त एवं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त दुग्ध संघ स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्रामीण वितरक एवं डेयरी को-आपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से भी सरस डेयरी उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

गत दो वित्तीय वर्षों में आरसीडीएफ से सम्बद्ध दुग्ध संघों के द्वारा बिक्री किये गये कुल घी की मात्रा निम्न प्रकार है :-

(डेयरी मंत्री)

2013-2014 कुल 20273 मैट्रिक टन

2014-2015 कुल 18549 मैट्रिक टन

2015 16 (जनवरी 2016 तक) कुल-19852 मैट्रिक टन

(2) जी हां। पिछले 10 वर्षों में डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा व वृद्धि ह्रास (प्रतिशत में) प्रदर्श 1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2005 से वर्तमान तक समय-समय पर समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराके निर्धारित प्रपत्र पर जिला मुख्यालयों पर सरस घी एवं लोंग लाईफ डेयरी उत्पादों के विक्रय हेतु वितरक बनने के सम्बन्ध में इच्छुक प्रत्याशियों से आवेदन आमन्त्रित किये जाते रहे हैं। इस प्रकिया द्वारा पूर्व में वर्ष 2005 2006 2007 2008 एवं 2011-12 में वितरक नियुक्त किये गये हैं । इस वित्तीय वर्ष के माह नवम्बर 2015 में 109 वितरक नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जिला मुख्यालय जहां कोई भी वितरक हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, के लिए पुन: समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

(4) जी हां। इसके लिये समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में माह नवम्बर 2015 में 109 वितरक नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जिला मुख्यालय जहां कोई भी वितरक हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है के लिये पुन: समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर वितरक नियुक्ति की कार्यवाही संघों की आवश्यकतानुसार प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं। गत दीपावली के अवसर पर आरसीडीएफ द्वारा स्कीम के तहत वितरकों के माध्यम से 675.51 मैट्रिक टन घी ही विक्रय किया गया था तथा स्कीम पर रुपये 30 से 35 प्रति लीटर कम नहीं किया गया था। स्कीम मात्रात्मक थी, जिसका वित्तीय प्रभाव लगभग रुपये 10 प्रति लीटर ही था तथा यह स्कीम केवल निकट एक्सपायर होने वाले घी पर ही थी अर्थात् जो घी माह जनवरी एवं फरवरी, 2015 में निर्मित था तथा माह अक्टूबर व नवम्बर, 2015 में एक्सपायर होने वाला था। उक्त स्कीम भी पूर्ण रूप से खुली थी। अत: स्कीम किसी भी व्यक्ति व्यापारी, वितरक एवं दुग्ध संघ के लिये लागू थी। उक्त स्कीम के तहत वितरकों ने मात्र 675.51 मैट्रिक टन घी उठाया था, इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर एवं अन्य पक्षों द्वारा कुल लगभग 1025

(डेयरी मंत्री)

मैट्रिक टन घी उठाया गया था। अतः इस प्रकार लगभग 1700 मैट्रिक टन घी का विक्रय ही स्कीम के तहत किया गया था।

स्कीम हेतु जारी आदेश में इसका विवरण उपलब्ध है। आदेश की प्रति प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

उक्त विषय की विस्तृत जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार के अनुमोदनापरान्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्कीम के अन्तर्गत घी विक्रय में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में गौवंश के संवर्धन हेतु अभयारण्य खोलने की योजना

174. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा गौ-पालन विभाग की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब एवं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में गौ संवर्धन हेतु कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा हेतु कोई कारगर कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या सरकार अलवर जिले में गौवंश के संवर्धन व सुरक्षा हेतु अभयारण्य खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)जी हां। गौवंशीय पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं नस्ल सुधार हेतु प्रदेश में दिनांक 13.03.2014 से गोपालन विभाग का सृजन किया गया है।

(2) गोपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) जी हां। प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा हेतु ''राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995'' प्रभावी है जिसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। वृद्ध, अपंग/निराश्रित बछड़ों एवं बैलों की बढती संख्या व गौ तस्करों से मुक्त करवाये गये गौवंश के रखरखाव, भरण, पोषण, उपचार, संरक्षण एवं संवर्धन के लिये सम्भाग स्तर पर गौअभ्यारण्य स्थापित करने हेतु नीति का प्रारूपण प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोपालन विभाग द्वारा संचालित योजनायें निम्नानुसार हैं :—

1. वध से बचाये गोवंश को सहायता :—वध से बचाये गये गोवंश के भरण-पोषण हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से बड़े गोवंश के लिये रु. 32/- एवं छोटे गोवंश के लिये रु. 16/ प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम एक वर्ष (जो भी कम हो) तक के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
2. सांड पंजीकरण एवं नकारा बछड़ों/सांडों का पंजीकरण :— प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं/गौसदन/गोपुनर्वास केन्द्रों में प्रजनन एवं नस्ल सुधार हेतु प्रजनन योग्य सांडों का पंजीकरण तथा नकारा बछड़ों/सांडों का बधियाकरण किया जाना।
3. गौशाला प्रतिनिधियों एवं गोपालकों को एक दिवसीय एक्सपोजर विजिट एवं छह दिवसीय सैद्धान्तिक एवं प्रायोजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4. उत्कृष्ट गौशालाओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम।
5. गौशाला प्रबंधकों, पंचगव्य विशेषज्ञों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों के एक दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम।

प्रदेश में हैण्डीक्राफ्ट उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कार्य योजना

175. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में प्रदेश के टैक्सटाइल, हैण्डमेड ज्वैलरी, कारपेट, दरी, ब्लु पाटरी, वुडन फर्नीचर, जयपुरी रजाइयां, मार्बल क्राफ्ट्स एवं राजस्थानी पेंटिंग्स सहित अन्य स्थानीय उद्योगों के विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाकर इनके विकास हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्योगों के विकास हेतु एम.ओ.यू. किया गया है या अन्य कोई विशेष योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के स्थानीय उद्योगों की विकास दर में विगत दो वर्षों में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सभी प्रकार के उद्योगों के विकास/प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 राजस्थान एमएसएमई नीति, 2015, राजस्थान एमएसएमई सहायता योजना 2015 एवं राजस्थान सिक माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज (रिवाइवल एण्ड रीहेबिलिटेशन) स्कीम 2015 जारी की गई है। साथ ही राज्य सरकार कलस्टर, हाथकरघा, हस्तशिल्प विकास योजनाओं के माध्यम से भी स्थानीय उद्योगों के विकास हेतु प्रयासरत है।

राज्य के प्रत्येक जिले में भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में उद्योग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से रोड शो किए गये व रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन जयपुर में दिनांक 19-20 नवम्बर, 2015 को किया गया। औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

(2) रिसर्जेंट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना है जो कि एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के

(उद्योग मंत्री)

विभिन्न विभागों एवं निकायों के द्वारा समय-समय पर एमओयू किये गये एवं भविष्य में भी किये जायेंगे। इसके अन्तर्गत 19-20 नवम्बर, 2015 को निवेशकों हेतु एक सम्मेलन रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट का आयोजन किया गया था।

अब तक हस्ताक्षरित हुये कुल एमओयूज की विभागवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त राज्य के निवेश वातावरण को अधिक आकर्षक बनाने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 (RIPS-2014) राजस्थान मिनरल पालिसी-2015 राजस्थान ट्यूरिज्म यूनिट पालिसी-2015, राजस्थान सोलन एनर्जी पालिसी-2014 तथा राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एवं एग्री मार्केटिंग प्रमोशन पालिसी 2015 जैसी नीतियां जारी की गईं।

(3) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तैयार किये जाते हैं। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग), खनन, विद्युत गैस व जलप्रदाय तथा निर्माण क्षेत्र के अनुमान तैयार किये जाते हैं। उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्द्धन (स्थिर 2011-12 कीमतों पर) वर्ष 2013-14 2014-15 एवं 2015-16 (अग्रिम अनुमान) में क्रमश: 2.70, 5.89 तथा 5.95 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-176

(स्थगित)

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर देय भत्तों का भुगतान

177. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत राज्य खेल संघों के माध्यम से आयोजित राज्य प्रतियोगिताओं एवं भारतीय खेल संघों के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग

(श्रीमती गोलमा)

लेने व इससे पूर्व आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा व दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों द्वारा राज्य खेल संघों के माध्यम से आयोजित राज्य प्रतियोगिताओं एवं भारतीय खेल संघों के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं कितने खिलाड़ियों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान कर दिया गया तथा कितनों को भुगतान करना शेष है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भुगतान से वंचित रहे शेष खिलाडियों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

वांछित नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भुगतान के आधार पर खिलाड़ियों की संख्या, राशि एवं प्रतियोगिता की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता से सम्बन्धित विवरण					
		राज्य प्रतियोगिताए			राष्ट्रीय प्रतियोगताएं		
		खिलाड़ी	राशि	प्रतियोगिता	खिलाड़ी	राशि	प्रतियोगिता
1	14-15	5575	5767819	12 खेलों में 32	609	1082242	12 खेलों में 28
2	13-14	3870	3390548	16 खेलों में 22	551	1381406	16 खेलों में 31
3	12-13	3892	3347789	9 खेलों में 22	412	724343	9 खेलों में 21
4	11-12	4439	2164523	14 खेलों में 24	513	683652	14 खेलों में 26
5	10-11	5399	2195927	14 खेलों में 27	523	552281	14 खेलों में 33
	योग	17776	16866606		2608	4423924	

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

विभिन्न प्रतियोगिताओं में दस्तावेजों की अपेक्षा अथवा कमियों के कारण जिन खिलाड़ियों को भुगतान नहीं हो सका था उनसे सम्बन्धित संघों को आक्षेपों के निराकरण सहित दावा दिनांक 30.06.2015 तक प्रस्तुत करने को लिखा गया था। नियमानुसार प्राप्त दावों को यथोचित रूप में भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार अब कोई भी दावे भुगतान के लिये शेष नहीं हैं।

(3) दिनांक 30.06.2015 तक नियमानुसार आक्षेपों के निराकरण के उपरान्त प्राप्त दावों का भुगतान कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अब कोई दावे भुगतान हेतु शेष नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बसों में राज्य से बाहर यात्रा करने पर किराये में छूट

178. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. की बसों में महिलाओं के लिए किराये में विशेष छूट का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कब व कितने प्रतिशत? इसमें कब-कब, क्या-क्या बदलाव/परिवर्तन किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या महिलाओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर आवागमन करने वाली निगम की सभी बसों में लागू है? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निगम की बसों पर चलने वाले परिचालकों द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राजस्थान के बाहर आवागमन करने वाली महिला यात्रियों को विशेष छूट नहीं देकर पूरा किराया वसूला जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को प्रदेश में एवं बाहर आवागमन पर समान रूप से किराये में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(परिवहन मंत्री)

उप शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 14 (2) परि/2007/पार्ट-II/जयपुर दिनांक 20.6.13 (संलग्न परिशिष्ट "1") के द्वारा महिलाओं को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर यात्री किराये में 30 प्रतिशत रियायत देने की स्वीकृति प्रदान की गई । इन आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ4/मुख्या/याता/लेखा (109)/2013/434 दिनांक 20.6.13 (संलग्न परिशिष्ट "2") जारी किये गये हैं। 30 प्रतिशत रियायती यात्रा सुविधा दिनांक 21.6.13 से दी जा रही है । इसमें परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एक बार संशोधन किया जाकर महिलाओं को किराये में 30 प्रतिशत रियायत को राजस्थान राज्य सीमा तक सीमित किया गया है।

(2) जी नहीं। महिलाओं को 30 प्रतिशत रियायत राजस्थान राज्य सीमा तक दी जा रही है । परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 14 (2) परि/2007/पार्ट-II/जयपुर दिनांक 25.04.14 (संलग्न परिशिष्ट "3") के द्वारा राजस्थान एवं अन्य राज्यों के मध्य सम्पन्न पारस्परिक परिवहन करारों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व आदेशों में संशोधन किया जाकर राजस्थान परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को केवल राजस्थान राज्य सीमा में ही 30 प्रतिशत छूट देने की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई । इसकी अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 348 दिनांक 28.04.14 (संलग्न परिशिष्ट '4") जारी किये गये ।

(3) जी हां। परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं को दी जा रही 30 प्रतिशत रियायत केवल राजस्थान राज्य की सीमा में ही प्रदत्त है ।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों मे दी जा रही उक्त रियायतों को अन्तर्राजीय पारस्परिक परिवहन के करार के प्रावधानों के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों मे यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्री किराया राशि में राजस्थान राज्य की सीमा में ही 30 प्रतिशत रियायत प्रदान की गयी है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ई-टेंडरिंग से टेण्डर नहीं निकालने पर कार्यवाही

179. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) प्रदेश में 5 लाख रुपये से कम के टेण्डर जारी किये जाने हेतु क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में 5 लाख रुपये से कम के टेण्डर भी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से पोर्टल से निकाल कर निविदाएं डाली जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जयपुर एवं अलवर जिले के प्रत्येक खण्ड में 1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक किस-किस अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रकार अनाधिकृत तरीके से कितने-कितने एवं कौन-कौनसे कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग अथवा पोर्टल से निकालकर स्वीकार की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों की मिली भगत से इस तरह की अनियमितता निरन्तर की जा रही हैं? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुसार 5 लाख से कम राशि की निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

कार्य की लागत	प्रचार की रीति	समय सीमा
एक लाख रुपये तक	उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड।	सात दिन
एक लाख रुपये से अधिक और पांच लाख रुपये तक	1. उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड 2. एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। 3. स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर प्रकाशन।	पन्द्रह दिन

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। नियमानुसार टेण्डर में संवेदक द्वारा स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से निविदा निकालकर (डाउनलोड करके) डाली जा सकती है।

(3) जयपुर एवं अलवर जिले में भी नियमानुसार ही कुछ कार्यों में संवेदकों द्वारा स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से निविदा निकालकर (डाउनलोड करके) डाली गई है।

(4) जी नहीं। नियमानुसार ही प्राप्त की जा रही है।

कानपुरा (खानपुर) को सड़क से जोड़ने की योजना

180. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के गागरोन पंचायत के कानपुरा गांव की आबादी 688 होने के उपरान्त भी उक्त गांव अभी तक सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार उक्त गांव को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर के गागरोन पंचायत के ग्राम कानपुरा जिसकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 688 है, को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में फेज-06 बैच 1 पैकेज संख्या आर.जे.-19-60 में नोलाव से कानपुरा तक 15.35 किमी. लम्बाई हेतु राशि रु. 333.66 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, परन्तु उक्त समस्त क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के अन्तर्गत होने के कारण सड़क निर्माण नहीं किया जा सका। एस.एल.एस.सी. (State Level Standing Committee) की 15वीं बैठक में स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत होकर राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी नई दिल्ली को स्वीकृति निरस्त करने हेतु दिनांक 29.01.2016 को भिजवा दिया गया है।

(2) उक्त सड़क माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के क्षेत्र में होने के कारण मात्र ग्रेवल सड़क का निर्माण वन विभाग द्वारा ही सम्भव है।

शेरगढ़ में शहीद आश्रित विधवाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा

181. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा युद्ध में मृत/शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं आश्रित अवयस्क संतानों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रावधानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2009 से अब तक कुल कितनी मृत/शहीद आश्रित विधवाओं एवं आश्रित अवयस्क संतानों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा हेतु परिचय पत्र जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ4/याता/लेखा/99/346 दिनांक 06.7.99 (परिशिष्ट "1") एवं आदेश क्रमांक एफ4/याता/लेखा/(98)/2013/257 दिनांक 15.4.13 (परिशिष्ट "2") द्वारा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं उन पर आश्रित अवयस्क संतानों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है।

(2) निगम के पत्रांक 3632 दिनांक 22.10.2013 (परिशिष्ट "3") द्वारा दिनांक 16.10.2013 के पश्चात पूर्व के जारी नि:शुल्क/रियायती मुद्रित परिचय पत्रों के स्थान पर RFID Smart Card के माध्यम से ही किराये में छूट दिये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहीद आश्रित विधवाओं एवं आश्रित अवयस्क सन्तानों के बने RFID Smart Card की सूची परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के धार्मिक स्थानों को डामर सड़क से जोड़ने की योजना

182. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थानों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। भविष्य में धार्मिक स्थानों को डामर सड़कों से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में मनरेगा के तहत कुओं को गहरा कराने की योजना

183. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार मनरेगा के अन्तर्गत किसानों के खेतों में कृषि कार्य करने के लिए कुआं खोदने और कुओं को गहरा करने के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 5 में वर्णित परिवारों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कुआं निर्माण का कार्य कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2015 को कुआं निर्माण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बी.पी.एल. पात्रता हेतु नवीन मानदण्ड लागू करने की योजना

184. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जो व्यक्ति वर्ष 1997 की चयनित सूची में बी.पी.एल. था और वर्ष 2002 के सर्वे लिस्ट में बी.पी.एल. नहीं पाया गया, क्या वो व्यक्ति ही अपील करके अपना नाम सर्वे लिस्ट में जुडवाने का अधिकारी है?

(2) क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002 को न्यायालय स्थगन के कारण वर्ष 2008 में लागू किया गया था? उक्त सर्वे के मानदण्ड वर्तमान परिपेक्ष्य में अप्रासंगिक हो चुके हैं? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में 14 वर्षों के लम्बे अन्तराल में काफी बी.पी.एल. परिवार विखंडित हो चुके हैं किन्तु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी वर्ष 2002 की सर्वे सूची से इतर पात्रताधारियों को बी.पी.एल. सूची में जोड़ने के आदेश जारी नहीं कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बदलते परिवेश में बी.पी.एल. पात्रता हेतु नये मानदण्ड निर्धारित करवाकर नये तरीके से सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यथा ओबीसी/एसबीसी व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भी बी.पी.एल. योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नहीं। बीपीएल सेन्सस वर्ष 2002 में सर्वे किये गये परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल होने से वंचित रह गये हैं, वे परिवार अपील के माध्यम से बीपीएल सूची में शामिल हो सकते हैं।

(2) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बीपीएल सर्वे वर्ष 2002 किया गया था जिसे सितम्बर वर्ष 2006 में लागू किया गया था। सर्वे के मापदण्ड भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस तरह का पृथक से सर्वे नहीं करवाया जाता है।

(3) बीपीएल सेन्सस वर्ष 2002 की सूची में शामिल होने के लिए उन्हीं परिवारों द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है, जिनका सर्वे बीपीएल सेन्सस वर्ष 2002 में हुआ है।

(4) भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का कार्य राज्य में सम्पन्न हो चुका है। जिलों द्वारा अन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

(5) भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का सर्वे विभिन्न सामाजिक आर्थिक आधारों पर किया गया है। यह सर्वे के आधार पर लाभ दिया जाने के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार के स्तर द्वारा लिया जावेगा।

भीण्डर पंचायत समिति में शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान

185. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीण्डर पंचायत समिति में शौचालय निर्माण में प्रस्तुत यू.सी. के भुगतान में देरी हुई है यदि हां, तो भुगतान में हुई देरी के कारणों सहित कौन जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है व कितनी यू.सी. प्रस्तुत हुई व कितनों को भुगतान किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पंचायत समिति भीण्डर में वर्ष 2015-16 के दौरान 2948 यू.सी. पेश हुई जिनका भुगतान कर दिया गया है।

अलवर जिले में मनरेगा योजना में पूर्ण हुये कार्य

186. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में मनरेगा योजना में गत दो वर्षों में विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों को प्रत्येक पंचायत समितिवार समान रूप से स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में जिला अलवर में मरनेगा योजना से कराये जाने वाले कार्यों की राशि में कमी हुई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गत दर वर्षों में विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के स्वीकृत, कराए गए पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारम्भ कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है, जिसमें कार्य की पूर्णता रोजगार की मांग पर निर्भर करती है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है, अत:

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धित पंचायत समितियों में रोजगार की मांग के अनुसार की गयी है।

(3) जी नहीं। एम. आई.एस. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 में अलवर जिले में राशि रु. 31 करोड़ का तथा वर्ष 2014-15 में राशि रु. 43 करोड़ का व्यय किया गया है।

योजना मांग आधारित होने के कारण योजनान्तर्गत व्यय रोजगार की मांग पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाजा (अजमेर) को तहसील बनाने की योजना

187. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा की 15 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय को तहसील बनाने की मांग की जा रही है?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति जवाजा को तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में तहसीलों को पंचायत समितियों के सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर समान मुख्यालय कायम किये जाने के क्रम में पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त पंचायत समिति जवाजा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जावेगा।

नागौर जिले में पानी के टैंकरों के बकाया का भुगतान

188. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गर्मी के मौसम में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है?

(श्री तरुण राय कागा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य एन.आई.टी. के अधीन ही टेण्डर जारी होकर सम्पन्न होता है?

(3) क्या जिला नागौर में जिन-जिन तहसीलों में कार्य हुआ है वह एन.आई.टी. की निर्धारित सीमा के तहत ही हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि नागौर जिले में उक्त कार्य के ठेकेदारों का भुगतान अब तक भी नहीं किया गया है?

(5) उक्त प्रकरणों में एन.ओ.सी. जारी करने का कार्य किस स्तर पर लम्बित है तथा अब कब तक एन.ओ.सी. जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल से अभावग्रस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सहायता विभाग द्वारा टैंकरों से परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है।

(2) जी हां।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नागौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये पेयजल परिवहन के कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं में वर्णित निर्धारित राशि एवं किये गये वास्तविक कार्य सम्बन्धी तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। नागौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमश: राशि रुपये 274.01 लाख एवं रुपये 170.67 लाख के पेयजल परिवहन के किये गये कार्य के विरुद्व संवेदकों को क्रमश: राशि रुपये 104.42 लाख तथा एवं रूपये 65.14 लाख का भुगतान विभाग द्वारा अब तक किया जा चुका है।

उक्त दोनों वर्षों में किये गये पेयजल परिवहन की राशि रुपये 275.12 लाख का भुगतान के बिल शेष हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(5) नागौर जिले में पेयजल परिवहन के कार्य हेतु उक्त वर्षों में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक राशि का पेयजल परिवहन का कार्य हुआ है । पेयजल परिवहन के कार्य पर उक्तानुसार हुए अतिरिक्त व्यय की कार्योतर स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाजपतनगर (जयपुर) में पेयजल लाइन बिछाने की योजना

189. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनी लाजपतनगर, जगतपुरा एवं मोनिका विहार, पृथ्वीराज नगर, जोन-18 में पेयजल की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनियों को पेयजल व्यवस्था हेतु बीसलपुर योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि लाजपतनगर, जगतपुरा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध नही कराये गये हैं? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उपलब्ध करवा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के लाजपतनगर, जगतपुरा, मोनिका विहार एवं पृथ्वीराज नगर जोन-18 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।

(2) जी हां। बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर एवं महल रोड क्षेत्र (लाजपतनगर सम्मिलित) को लाभान्वित करने हेतु आधारभूत जल संरचनाओं के निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 152.02 करोड़ की योजना की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इस स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य को तीन पैकेजों में विभाजित कर, पैकेज संख्या 1 (जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर 3 पम्पसैट्स बदलने का कार्य) के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यादेश दिनांक 31.07.2014 को राशि रुपये 2.36 करोड़ का जारी किया गया। यह कार्य दिनांक 30.04.2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

पैकेज संख्या 2 (मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, राइजिंग मेन एवं परियोजना सीमा पर रिंग मेन पाइप लाइन बिछाने-जोड़ने का कार्य) हेतु पुन: निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं।

पैकेज संख्या 3 (पम्प हाउस एवं जलाशयों के निर्माण कार्य) के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त स्वीकृत

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में पेयजल वितरण तंत्र के विकास के प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे हैं।

पृथ्वीराज नगर (दक्षिण क्षेत्र) जिसमें मोनिका विहार भी सम्मिलित है, में बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये राशि रुपये 222.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 1.12.2015 को जारी की जा चुकी है। इस कार्य हेतु सलाहकार फर्म की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

पीलीबंगा के जीर्ण-शीर्ण जी.एल.आर. की मरम्मत

190. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जी.एल.आर. व फिल्टर प्लांट जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनको दुरुस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक रिक्त पदों को भर दिया जायेगा व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के दो शहर क्रमश: पीलीबंगा एवं रावतसर की पाइप्ड जल योजनाओं में निर्मित क्रमश: 2 एवं 1 रेपिड ग्रेविटी फिल्टर संयंत्र वर्तमान में पूर्ण रूप से सही अवस्था में क्रियाशील हैं।

उक्त क्षेत्र में संचालित एवं संधारित 92 ग्रामीण पेयजल योजनाओं से 563 ग्राम वर्तमान में लाभान्वित हैं । इन ग्रामीण जल योजनाओं में निर्मित 139 भू-तल जलाशयों (जी.एल.आर.) में से 14 भू-तल जलाशय वर्तमान में बंद हैं। इनमें से 10 भू-तल जलाशय को जल स्रोत से जोड़ने वाली पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने तथा 4 भू-तल जलाशय योजना का स्वरूप बदलने/भू-तल जलाशय के स्थान पर सार्वजनिक नलों से पेयजल उपलब्ध कराने के कारण बंद हैं । इस प्रकार 10 भू-तल जलाशयों की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने हेतु इनके प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति जारी की जायेगी । विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

राज्य के वित्तीय वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा में बीकानेर सम्भाग के बीकानेर, चूरू हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाओं के विभिन्न अवयवों के पुनरुद्धार हेतु रूपये 90 करोड़ की राशि का प्रावधान लिया गया है । इस घोषणा के तहत प्रथम चरण के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की 76 जल योजनाओं में इन कार्यो के निष्पादन हेतु दिनांक 27.10.2015 को राशि रुपये 75.87 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया गया है।

इस कार्य आदेश के तहत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के 83 स्लो-सैण्ड फिल्टर संयंत्रों को रेपिड ग्रेविटी फिल्टर संयंत्र में परिवर्तित करने का कार्य किया जाना सम्मिलित है। यह कार्य माह नवम्बर, 2017 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है । विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभाग के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 243 पदों में से अधिकारी संवर्ग (सहायक अभियन्ता) का एक पद एवं कर्मचारी संवर्ग में 15 पद, इस प्रकार कुल 16 पद वर्तमान में रिक्त हैं । विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

उक्त क्षेत्र में सहायक अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत 5 पदों में से सहायक अभियन्ता उपखण्ड, गंधेली का एक पद दिनांक 23.10.2015 से रिक्त है । राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विभाग हेतु चयनित 159 सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है । विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है ।

विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पूर्व में रिक्त चल रहे 824 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है । इसके अन्तर्गत पीलीबंगा क्षेत्र में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत 10 पदों में से पूर्व में रिक्त 9 पदों पर, विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 26.06.2015 से दिनांक 05.01.2016 के मध्य समस्त 9 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन किया जा चुका है । वर्तमान में क्षेत्र में कनिष्ठ अभियन्ताओं के सभी पद भरे हुए हैं । विवरण संलग्न परिशिष्ट-द में निहित है ।

तकनीकी कर्मचारियों के 1294 पदों के लिये विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2013 को विज्ञप्ति जारी की गई थी । तत्पश्चात् राज. अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जन स्वा. शाखा), नियम 1967 के नियम 19 में दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

01.10.2013 को आवश्यक संशोधन (सीधे साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा) प्रतिस्थापित हो जाने के फलस्वरूप, तकनीकी पदों सम्बन्धी नियमों (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य) में संशोधन आवश्यक हो गया है । इस संशोधन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा वांछित संशोधन के उपरान्त भर्ती प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ की जायेगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

191. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के गांवों एवं कस्बों में बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना का प्रारम्भ कब किया गया था और उक्त योजना में किन-किन गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना को कब से प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण किया जाना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना की धीमी गति के कारण समय पर जनता को लाभान्वित नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर सम्पूर्ण फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों एवं कस्बों को बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत चार कस्बे फुलेरा, सांभर, नरेना एवं किशनगढ़-रेनवाल तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 151 ग्राम सम्मिलित हैं। बीसलपुर परियोजना से कस्बा फुलेरा, सांभर एवं नरेना को वर्ष 2009-10 में लाभान्वित किया जा चुका है तथा किशनगढ़-रेनवाल कस्बे को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त क्षेत्र के 151 ग्रामों में से 45 ग्रामों को मुख्य पाइप लाइन टी.एम.-प्रथम के नरेना आफटेक से लाभान्वित करने के कार्य हेतु मैसर्स विष्णु

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रकाश आर पुंगलिया, जोधपुर को दिनांक 03.05.2013 को राशि रुपये 52.46 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर दिनांक 13.05.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया । इस परियोजना से विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा के लाभान्वित किये गये 45 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं शेष 106 ग्रामों को सांभर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित करने हेतु मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 15.07.2013 को राशि रुपये 226.95 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर दिनांक 25.07.2013 को कार्य प्रारम्भ किया गया । इस परियोजना से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के लाभान्वित किये जाने वाले 106 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(2) बीसलपुर पेयजल परियोजना के नरेना आफटेक से 45 ग्रामों को कार्यादेश अनुसार दिनांक 13.05.2013 से प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 12.11.2014 तक लाभान्वित करना निर्धारित था । इस आफटेक की परियोजना का कार्य दिनांक 02.12.2015 को पूर्ण किया जाकर 45 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

परियोजना के सांभर पम्पिंग स्टेशन से कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं 106 ग्रामों को कार्यादेश अनुसार दिनांक 25.07.2013 से प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 24.01.2016 तक लाभान्वित करना निर्धारित था । इस परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है ।

(3) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के परियोजना में सम्मिलित 151 ग्रामों में से नरेना आफटेक से स्वीकृत समस्त 45 ग्रामों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है । सांभर पम्पिंग स्टेशन से कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं 106 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य आदेशित फर्म द्वारा धीमी गति से किये जाने के कारण रुपये 8.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रोकी जाकर नोटिस देने की कार्यवाही की गई है । तत्पश्चात् फर्म द्वारा पाइप एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति साइट पर की जाकर पाइप लाइन बिछाने एवं अन्य कार्यों की गति बढ़ाई जा रही है ।

(4) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे एवं शेष रहे 106 ग्रामों को सांभर पम्पिंग स्टेशन से दिनांक 31.12.2016 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पानी के दोहन पर अंकुश लगाने की योजना

192. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश भू-भाग में पानी की उपलब्धता बहुत कम रह गई है? यदि हां, तो ब्लाकवार भू-जल की उपलब्धता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पानी के दोहन की वर्तमान स्थिति कायम रही तो प्रदेश के सभी ब्लाक डार्क जोन में शामिल हो जायेंगे? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या कारगर उपाय कब से करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि प्रदेश के अधिकांश भू-भाग में भू-जल की उपलब्धता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। भू जल आकलन रिपोर्ट 2011 के अनुसार ब्लाकवार भू-जल की उपलब्धता का विवरण संलग्न है। (Annex.-1)

(2) हां। यह सही है कि पानी के दोहन की वर्तमान स्थिति कायर रही तो प्रदेश के अधिकांश ब्लाक डार्कजोन में शामिल हो जायेंगे। भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निम्न प्रयास किए गए :-

(1) प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति माह फरवरी 2010 में लागू कर दी गई है जल संरक्षण को बढावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है।

(2) भारत सरकार द्वारा अनुदानित कूप द्वारा भू-जल पुनर्भरण योजना के अर्न्तगत राज्य में 4396 संरचनाओं का निर्माण विगत वर्षो में किया गया। (Annex.-2)

(3) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना के तहत पायलेट परियोजना क्षेत्र, मण्डोर-ओसियां क्षेत्र जिला जोधपुर, खमनोर क्षेत्र जिला राजसमन्द एवं पीपराली क्षेत्र जिला सीकर में 319 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण पूर्व वर्षो में किया गया।

(4) मनरेगा के तहत 287 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान विभाग द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। (Annex.-3)

(भू-जल मंत्री)

(5) वर्तमान में भू-जल स्तर में बढ़ोतरी हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु जिलेवार प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं।

(6) भू-जल दोहन पर नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर गम्भीर स्थिति वाले क्षेत्रों को अधिसूचित घोषित किया जाता है । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(1) पी.एच.ई./2010-पार्ट-प्रथम दिनांक 14.7.2011 के द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को उस जिले में नये नलकूप/बोरवेल/भूजल दोहन की यूनिट खोदने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम एवं नियन्त्रक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । (Annex.-4)

(7) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों में भू-जल पुनर्भरण हेतु संरक्षण संरचनाओं के निर्माण एवं भू-जल प्रबन्धन हेतु विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के पेयजल पाइप लाइन से जोड़ने से वंचित गांव

193. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्तर्गत आने वाले कई गांव व ढाणियां आज भी पेयजल पाइप लाइन से जुडे होने से वंचित हैं। यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में जवाई पाइप लाइन परियोजना के तहत पांच पैकेज के कार्यों के तहत गांवों को पेयजल पाईप लाइन से जोडा गया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों को जवाई पाइप लाइन से जोडा गया व कितनों का कार्य चल रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सोजत तहसील की कई ग्राम पंचायतें व ग्राम तथा ढाणियां आज भी जवाई पाइप लाइन योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पेयजल पाईप लाईन से वंचित गांवों को जवांई पाइप लाइन या जोधपुर केनाल परियोजना से जोडने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती संजना आगरी)

(5) क्या सरकार ग्राम पचायंतों से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कुओं पर निवास करने वाली आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस योजना के तहत?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभागीय नीति अनुसार वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों को हैण्डपम्प योजना से, 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामो को पम्प एवं टैंक योजना से तथा 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को पाइप्ड जल योजना से जोड़ने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र सोजत के कुल 153 ग्राम (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार) एवं 261 चिह्नित ढाणियों में से 23 ग्राम एवं 173 ढाणियां विभागीय नीति अनुसार पात्रता नहीं रखने के कारण पाइप लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं तथा ये समस्त ग्राम/ढाणियां विभागीय नीति अनुरूप (जनसंख्या के हिसाब से) हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(2) जी हां। जवाई पाइप लाइन पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की दिनांक 11.10.2007 को राशि रुपये 634.79 करोड़ की संशोधित परियोजना की स्वीकृति में प्रावधित कार्यों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु पांच पैकेजों में विभक्त किया जाकर पैकेज संख्या-4 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत के 52 ग्रामों को मंडली (पाली) से सोजत तक बिछाई गई पाइप लाइन से माह नवम्बर, 2013 में लाभान्वित किया गया है।

उक्त परियोजना के द्वितीय चरण की जवाई क्लस्टर परियोजना-प्रथम के तहत उक्त क्षेत्र की तहसील सोजत के 26 ग्रामों को माह नवम्बर, 2015 में लाभान्वित किया जा चुका है।

उक्त क्षेत्र के 8 ग्रामों (सोजत तहसील के 3 एवं रायपुर तहसील के 5 ग्राम) को प्रथम चरण की परियोजना के पैकेज-5 (सोजत से रायपुर, बर, जैतारण, आनन्दपुर कालू तक मुख्य पाइप लाइन) एवं द्वितीय चरण की क्लस्टर परियोजना-तृतीय के अन्तर्गत लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । इन दोनों परियोजनाओं के कार्यों को माह अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कर ग्रामों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार लाभान्वित किये गये 78 ग्राम एवं लाभान्वित किये जाने वाले 8 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत एवं रायपुर में सम्मिलित क्रमशः 123 एवं 30, कुल 153 ग्रामों में से सोजत तहसील के 78 ग्रामों को जवाई पाइप लाइन परियोजना से लाभान्वित किया जा चुका है तथा सोजत व रायपुर तहसील के क्रमशः 3 एवं 5, कुल 8 ग्रामों को माह अप्रैल, 2017 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। तहसील सोजत एवं तहसील रायपुर के क्रमशः 42 एवं 25, कुल 67 ग्राम उक्त परियोजना की स्वीकृति में सम्मिलित नहीं हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) तहसील सोजत के शेष 42 ग्रामों में से 19 ग्राम सतही जल स्रोत गजनई बांध से वर्तमान में लाभान्वित हैं तथा रायपुर तहसील के 25 ग्रामों में से 17 ग्रामों को सतही जल स्रोत रायपुर दीपावास बांध से स्वीकृत परियोजना से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

सोजत एवं रायपुर तहसील के भू-जल आधारित पेयजल योजनाओं से लाभान्वित शेष क्रमशः 23 एवं 8, कुल 31 ग्रामों हेतु भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं में जवाई बांध अथवा राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना में जल उपलब्धता एवं आरक्षण, तकनीकी उपादेयता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना प्रस्तावित की जा सकेगी।

(5) विधान सभा क्षेत्र सोजत के वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 153 ग्रामों में से 19 ग्राम पाइप्ड, 82 ग्राम क्षेत्रीय, 29 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 23 ग्राम हैण्डपम्प योजना से तथा 261 चिन्हित ढाणियों में से 42 ढाणियां क्षेत्रीय, 46 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा शेष 173 ढाणियां हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं । इस प्रकार समस्त ग्राम एवं चिन्हित ढाणियां पेयजल सुविधा से वर्तमान में लाभान्वित हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करवाने के नियम

194. श्री भजन लाल जाटव (वैर) एवं **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काश्तकार अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर

(श्री भजन लाल जाटव)

बिना भूमि की किस्म परिवर्तन कराये निर्माण कार्य करवा सकता है? यदि हां, तो उसके स्वयं की कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर तथा किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे काश्तकार जिसकी पूर्व की कृषि भूमि जो कि वर्तमान में नगर परिषद/नगरपालिका क्षेत्र में आ चुकी है और वह अपनी उक्त भूमि पर स्वयं के उपयोगार्थ निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो उसे किस स्तर के अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र पर निवासगृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए अपनी कृषिजोत को ग्रामीण क्षेत्र में संपरिवर्तन नियम, 2007 के अधीन संपरिवर्तन प्रभार दिये बिना संपरिवर्तन कराने का हकदार होगा। इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा।

साथ ही संपरिवर्तन नियम, 2007 के अधीन यदि कोई खातेदार अभिधारी 2500 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र में अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर कोई लघु उद्योग स्थापित करता है तो संपरिवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी । इस प्रकार उपयोग में लिया गया क्षेत्र उसकी खातेदारी में बना रहेगा।

इसी प्रकार नियम 2007 के नियम 6(क) के अन्तर्गत कोई खातेदार अभिधारी उसकी खातेदारी भूमि के क्षेत्र का 5 प्रतिशत तक कृषि कारबार क्रियाकलापों के लिए उपयोग कर सकेगा और ऐसे क्रियाकलाप कृषि संक्रिया के रूप में माने जायेगे और कोई संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार उपयोग मे लिया गया क्षेत्र उसकी खातेदारी में बना रहेगा।

इसी प्रकार संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 6(बी) के अन्तर्गत कोई खातेदार अभिधारी सोलर फार्म/सोलर प्लांट /सोलर पावर प्लांट/विण्ड फार्म/विण्ड पावर प्लांट परियोजन हेतु अपनी भूमि सीलिंग सीमा तक तहसीलदार को 30 दिन पूर्व सूचित करते हुए भूमि को उर्जा संयंत्र स्थापना हेतु स्वयं उपयोग कर सकता है या पट्टे पर दे सकता है। इस हेतु संपरिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखी गई है एवं भूमि उसकी खातेदारी में बनी रहेगी। सुसंगत नियम की प्रति संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) कोई काश्तकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (A) के अन्तर्गत नगरपालिका के अधीन अपनी भूमि का Rajasthan Urban Area (permission for use of agriculture land for non-agricultural purpose and allotment) Rules, 2012 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.12 के द्वारा प्राधिकृत समस्त नगरपरिषद (उदयपुर, अलवर, भीलवाडा, भरतपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर को छोड़कर) समस्त नगरपालिका मण्डल (भिवाडी, आबूरोड, आबू पर्वत, चौमूं और बगरू को छोडकर) नगरपरिषद में पदस्थापित सम्बन्धित क्षेत्र का आयुक्त तथा सम्बन्ध नगर पालिका मण्डल के अधिशाषी अधिकारी से कृषि भूमि से अकृषि भूमि में उपयोग की स्वीकृति विहित प्रकार से प्राप्त कर तदनुसार निर्माण कार्य कर सकता है।

उदयपुर, अलवर, भीलवाडा, भरतपुर, श्रीगगानगर, भिवाडी, आबूरोड, आबूपर्वत और जैसलमेर में काश्तकार कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन में परिवर्तन की स्वीकृति सम्बन्धित नगर सुधार न्यास में पदस्थापित सचिव या उपसचिव या विशेषाधिकारी एवं चौमूं और बगरू क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण पदस्थापित सम्बन्धित क्षेत्र के उपायुक्त के समक्ष उपरोक्त स्वीकृति के लिये विहित प्रकार से आवेदन किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर उपखण्ड कार्यालय में लम्बित परिवेदनाओं का तय समय में निस्तारण

195. श्री जगसी राम (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एसडीओ कार्यालय रेवदर, तहसील रेवदर, तहसील आबूरोड एवं उप तहसील मण्डार में बिचौलियों के सक्रिय होने से आमजनों व अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कार्य लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? गत पांच वर्षों में उक्त कार्यालयों में कौन-कौन से कार्य व परिवेदना का निस्तारण तय समय सीमा में नहीं किया गया? उक्त अवधि में आवक रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों

(श्री जगसी राम)

का आमजन, जनता एवं जन प्रतिनिधियों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं होने की लिखित व मौखिक शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्यालयों में बकाया कार्यों व परिवेदनाओं के निस्तारण करने तथा अनुचित कार्य एवं व्यवहार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपखण्ड कार्यालय रेवदर, तहसील रेवदर, तहसील आबूरोड एवं उपतहसील मण्डार में कोई दलाल प्रथा नहीं हैं। न ही किसी आमजन, गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के कार्य लम्बित रखे जाते हैं। सभी वर्गो के कार्य समय पर सम्पादित किये जा रहे हैं। लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले परिवादों का भी समय-समय पर ही निस्तारण किया जा रहा है।

(2) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रार्थी श्री हीरा पुत्र लाला निवासी मोरड तहसील आबूरोड के द्वारा सहायक कलक्टर आबू पर्वत व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत मण्डल को भेजी गई है। जिस पर कार्यवाही कर मण्डल के पत्र दिनांक 29.12.2015 से जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु जिला कलक्टर सिरोही को लिखा गया है।
2. श्री गोपाल लाल स्वर्णकार तत्कालीन तहसीलदार, आबूरोड के विरुद्ध ग्राम ओरियां की कृषि भूमि में रूपान्तरण होने पर इन्तकाल नहीं खोलने की शिकायत मण्डल को की गई है जिसमें मण्डल के पत्र दिनांक 14.05.2013 से जिला कलक्टर, सिरोही से शिकायत की जांच रिपोर्ट चाही गई है। अभी तक जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) बिन्दु संख्या 2 में वर्णित शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मावली में देवस्थान के मंदिर

196. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के अधीन मंदिरों को दर्ज करवाने हेतु क्या नियम निर्धारित हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली के कौन-कौन से मंदिर विभाग के अधीन हैं? तथा इनके विकास हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग में प्रबंधित एवं नियंत्रित वर्तमान में निम्न श्रेणी के मंदिर हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी	390
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	204
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	342
	योग	**936**

उपरोक्त मंदिरों के अतिरिक्त अन्य किसी मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र मावली में निम्न मंदिर देवस्थान विभाग के हैं:-

क्र. सं.	मंदिर की श्रेणी	नाम मंदिर	स्थान
1	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	श्री चतुर्भुजजी	ग्राम गुडली तह. मावली

इनके विकास करने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भू-अभिलेख कार्मिकों को सर्वे कार्य हेतु नवीन तकनीक का प्रशिक्षण योजना

197. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा भू-अभिलेख कार्मिकों को भू-सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रचलित नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण

(श्री भंवरसिंह)

देकर जी.पी.एस. दी गई है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपनिवेशन विभाग बीकानेर द्वारा भी भू-सर्वेक्षण किया जाता है? यदि हां, तो विभाग में उक्त तकनीक में कितने कार्मिक प्रशिक्षित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तकनीक में अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के बिन्दु संख्या 210 के तहत राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से राज्य के समस्त जिला कलक्टर कार्यालयों तथा भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालयों को राजकोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड द्वारा 300 जिनोटेन/जीएनएनएस/जीआईएस हैण्ड हेल्ट (जीपीएस) उपलब्ध कराये जाकर आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। इस विभाग में जीपीएस तकनीक से प्रशिक्षित कोई कार्मिक नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा आयोजित उक्त प्रशिक्षण में उपनिवेशन क्षेत्र के कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रशिक्षण सभी जिला कलक्टर कार्यालयों तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालयों के कार्मिकों को सम्मिलित किया गया था।

(3) राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजकोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड के माध्यम से अब तक सभी जिलो के 1781 कार्मिकों को उक्त प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह हेतु सहायता

198. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर विवाह किये जाने पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अजीत सिंह)

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु गत दो वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने आवेदकों को सहायता राशि अब तक उपलब्ध करवा दी गई है? शेष को किन कारणों से राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है? लाभान्वित एवं शेष आवेदकों के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान की "हिताधिकारी की पुत्री अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अन्तर्गत 51 हजार रुपये सहायता राशि अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए दी जाती रही है। इस योजना के स्थान पर 01.01.2016 से शुभशक्ति योजना प्रारम्भ की गयी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक में गत दो वर्षों में "हिताधिकारी की पुत्री अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अन्तर्गत कुल 234 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 118 पात्र आवेदकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी है। शेष आवेदन योजना की पात्रता, शर्तें या मापदण्ड पूरा नहीं करने के कारण निरस्त किए गए हैं। लाभान्वित तथा शेष आवेदक, जिनके आवेदन निरस्त किये गये हैं, के अस्वीकृति के कारण और नाम पते सहित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

199. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में बाल श्रमिकों का अंतिम बार सर्वे कब करवाया गया?

(2) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उक्त जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाओं के तहत गत तीन वर्षों में कितने बाल श्रमिक को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जिले में गत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु किस-किस संस्थान द्वारा कब-कब व किन-किन स्थानों पर विद्यालय संचालित किये गये?

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(4) उक्त संस्थाओं द्वारा चलाये गये विद्यालयों एवं बाल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि का भुगतान कब-कब किया गया?

(5) क्या वर्तमान में बाल श्रमिक कल्याण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कितने बाल श्रमिकों के लिए व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर जिले में बाल श्रमिकों का सर्वे अन्तिम बार वर्ष 2012 में करवाया गया जिसमें कोई बाल श्रमिक नहीं पाया गया।

(2) गत तीन वर्षों में (2015-16, 2014-15, 2013-14 में) जालौर जिले में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ परियोजना संचालित नहीं होने के कारण किसी भी बाल श्रमिक को लाभान्वित नहीं किया जा सका।

(3) सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(4) सूचना परिशिष्ट-"ब" व "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित बाल श्रम परियोजना 31.03.2017 तक लागू है। परियोजना में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सर्वे के सम्बन्ध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है जो प्राप्त होते ही सर्वे के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

सर्वे के उपरान्त पाये गये बाल श्रमिकों की संख्या के आधार पर ही यह निर्धारित किया जायेगा कि कितने बाल श्रमिकों के लिए योजना लागू होगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना

200. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में बाल श्रम को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये?

(2) गत 5 वर्षों में कितने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर

(श्री संदीप शर्मा)

उनका पुनर्वास किया गया? जिलेवार मुक्त कराये गये बच्चों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाल श्रम करवाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध क्या-क्या कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? गत 5 वर्षों में इसके लिए दोषी कितने व्यक्तियों/संस्थानों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई आवासीय विद्यालय एवं उनके आर्थिक विकास के लिए कोई योजना आरम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिकों एवं भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1. बाल श्रम की रोकथाम के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 लागू है जिसके तहत 18 व्यवसायों व 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। इस अधिनियम के तहत श्रम विभाग के समस्त श्रम निरीक्षक, निरीक्षक नियुक्त हैं।

2. राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय एवं विशेष अधिनियम "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम,2000" एवं "राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास एवं मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त) गठित है। बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना भी लागू की गयी है जिसके तहत राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयां गठित की गयी हैं।

3. बाल श्रम से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर जिलों में स्थित बाल कल्याण समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही कर पुलिस

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

विभाग, प्रशासन, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के सहयोग से कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाता है एवं उनका पुनर्वास किया जाता है। मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 21.08.2012 के अनुसार पुनर्वासित किए जाने की कार्यवाही की जाती है। एसओपी की प्रति परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ.16( ) बा.श्र./जन/2014/687-719 दिनांक 11.01.2016 द्वारा राज्य के समस्त जिला कलक्टरों को आदेश दिनांक 21.08.2012 की अक्षरशः पालना के साथ जिला स्तर पर बाल श्रम एवं तस्करी की प्रभावी तरीके से रोकथाम हेतु दिनांक 15.01.2016 से 15.03.2016 तक विशेष अभियान प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं जिसकी अनुपालना में जिला स्तरों पर कार्यवाही जारी है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में बाल श्रम से मुक्त कराकर पुनर्वास कराये गये बच्चों की सूची परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बाल श्रम कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही (प्रावधान) का विवरण एवं विगत 5 वर्षों में किए गए निरीक्षण, चालानों की सूचना परिशिष्ट-"4" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार राज्य सरकार के समक्ष नहीं है।

(5) ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष की उम्र से अधिक के श्रमिक ही व्याप्ति योग्य होते हैं। अतः 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों (बाल श्रमिकों) को ई.एस.आई. अस्पताल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

अधिसूचित क्षेत्र में ई.एस.आई. के अधीन पंजीकृत भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण संस्थानों के श्रमिकों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को ई.एस.आई. अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कौशल विकास एवं आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाएं

201. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कौशल विकास एवं आजीविका मिशन द्वारा वर्तमान में कितनी योजनाएं किस-किस संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही हैं एवं उक्त योजनान्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना के प्रारम्भ से अब तक उक्त योजना के मद में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्व-रोजगार से जोड़ा जा चुका है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) तथा कौशल विकास पहल योजना (SDIS) संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में योजनावार निगम में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-अ (1, 2, 3, 4) पर संलग्न हैं।

13 दिसम्बर 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) के अन्तर्गत 75001, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) के अन्तर्गत 5773, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के अन्तर्गत 23954 तथा कौशल विकास पहल योजना (SDIS) के अन्तर्गत 2274 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) उक्त योजनाओं के मद में व्यय की गई राशि का योजनानुसार जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब (1, 2) पर संलग्न है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों को अनुमोदित लक्ष्य की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाती है। उक्त राशि का आबंटन जिलेवार नहीं किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को अग्रिम भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब (3) पर संलग्न है।

(3) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) योजना प्रशिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने से सम्बन्धित है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 1406 युवाओं को स्व-रोजगार का अवसर प्रदान किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)